



शोधन अक्षमता: वर्तमान एवं भविष्य

(शोधन अक्षमता प्रशासन पर एक विचार नेतृत्व पुस्तिका)

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
और
फ़ॉरेन कॉमनवैलथ डेवलपमेंट ऑफिस, यूके
का संयुक्त प्रकाशन



भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India



शोधन अक्षमता: वर्तमान एवं भविष्य

(शोधन अक्षमता प्रशासन पर एक विचार नेतृत्व पुस्तिका)

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
और
फ़ॉरेन कॉमनवैल्थ डेवलपमेंट ऑफिस, यूके
का संयुक्त प्रकाशन

अस्वीकरण: यह प्रकाशन इस विषय पर जागरूकता सृजित करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए बनाया गया है और किसी भी कार्रवाई या निर्णय, वाणिज्यिक या अन्यथा लेने या सिफारिश करने के लिए एक गाइड के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि पाठक इस प्रकाशन में शामिल मामलों में कोई कार्रवाई या निर्णय लेना चाहता है तो उसे अपना शोध स्वयं करना चाहिए और/या पेशेवर सलाह लेनी चाहिए। इस प्रकाशन के लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं। इससे होने वाली किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार की क्षति या हानि के लिए न तो प्रकाशक और न ही लेखक जिम्मेदार होंगे। मामले से संबंधित संहिता, नियम और विनियम www.ibbi.gov.in पर उपलब्ध हैं। प्रकाशन पर कोई भी विचार और प्रतिक्रिया Research@ibbi.gov.in पर मेल की जा सकती है।

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना	4
दिवाला प्रक्रिया और परिवर्जनीय समव्यवहारों (टालने योग्य लेन-देन) के दौरान निदेशकों की भूमिका क्लेटन चोंग	7
दिवाला कानून में इप्सो फैक्टो क्लॉज - एक सिंगापुर परिप्रेक्ष्य सिम क्वान कियाट	34
प्रौद्योगिकी सेवा आपूर्तिकर्ताओं के लिए दिवाला ढांचे का निर्माण: भारत और यूके से अनुभव डॉ. नीति शिखा और रेबेका पैरी प्रोफेसर	52
कार्रवाई योग्य दावों का असाइनमेंट पूजा महाजन और क्लेयर टान्नर	67
समाधान प्रक्रिया में एडीआर तकनीक केनेथ लिम ताओ चुंग और च्यू जिंग वेई	101
दिवाला पेशेवरों की देयता: भूमिकाएं, कर्तव्य और दायित्व धनंजय कुमार, क्रेग मॉटगोमरी और मिरियम फ़ैरेल्ली	125
दिवाला और परिसमापन में गोइंग कंसर्न बिक्री पीयूष मिश्रा, युशान एनजी, कुशल भीमजियानी और राजप्रीत लछर	158
पुनर्गठन और दिवाला में व्यवस्था की योजनाओं का उपयोग करना धनंजय कुमार, केट स्टीफ़ेंसन और अभिषेक मुखर्जी	186
लेखकों के बारे में	236

प्रस्तावना

किसी भी आर्थिक कानून को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल प्रयोग करते रहना आवश्यक है। भारतीय दिवाला कानून भी इससे अछूता नहीं है और एक प्रमुख आर्थिक सुधार के रूप में इसने बहुत ही कम समय में एक विश्वसनीय साधन के रूप में स्वयं को स्थापित किया है, जिससे देश में प्रचलित ऋण संस्कृति में प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन आया है। बदलती बाजार अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लगातार हो रहे विधायी हस्तक्षेप और विकसित न्यायशास्त्र से कानून को और अधिक गहराई और समझ प्राप्त हुई है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 को संकटग्रस्त देनदारों के शोधन अक्षमता समाधान हेतु एक समयबद्ध तंत्र के रूप में 2016 में अधिनियमित किया गया था ताकि देनदारों की संपत्ति का मूल्य अधिक से अधिक हो सके। शोधन अक्षमता तंत्र के चार स्तंभ, अर्थात् भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई), दिवाला संबंधी वृत्तिक, दिवाला संबंधी वृत्तिक अभिकरण, और सूचना उपयोगिताएं, सभी ने पिछले पांच वर्षों के दौरान मिलकर काम किया है और अब ये और बेहतर एवं उन्नत हो गए हैं।

संहिता का मुख्य उद्देश्य सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखते हुए वित्तीय संकट में पड़ी व्यवसाय-प्रतिष्ठान को बचाना और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। संहिता की स्थापना के बाद से प्रमुख सीखों को संहिता में शामिल करने के उद्देश्य से इसमें संशोधन करने के लिए संसद ने छह बार हस्तक्षेप किया है ताकि संहिता के प्रमुख उद्देश्यों को उन्नत व इसकी प्रक्रियों को सुदृढ़ बनाया जा सके। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐतिहासिक निर्णय दिए गए हैं, जिसमें कई वैचारिक मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया गया है और अन्य मौजूदा कानूनों तथा संहिता के बीच होने वाली किसी भी विसंगति के मामले में स्थिति स्पष्ट की है।

ज्ञान उत्पादों की भूमिका न केवल आईबीबीआई पारिस्थितिकी तंत्र और परिणामों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने में सर्वोपरि है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे प्रस्तावना में उल्लिखित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने हेतु सुधारों का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य कर रहे हैं। आईबीबीआई के सहयोग से या उसके बिना आंतरिक और अन्य हितधारकों द्वारा अब तक वितरित किए गए ज्ञान उत्पादों ने इस विषय पर उपलब्ध समृद्ध सामग्री और संसाधनों में अत्यधिक योगदान दिया है। ऐसे उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला, अर्थात् त्रैमासिक समाचार पत्र, वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक प्रकाशन और अन्य शोध पत्र आईबीबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

इस संदर्भ में, विदेशी राष्ट्रमंडल विकास कार्यालय (एफसीडीओ) और आईबीबीआई की संयुक्त पहल शोधन अक्षमता प्रशासन पर एक विचार नेतृत्व पुस्तिका " शोधन अक्षमता: वर्तमान एवं

भविष्य”, निश्चित रूप से भारत में प्रचलित दिवाला और शोधन अक्षमता व्यवस्था के उभरते मुद्दों के बारे में अपनी समझ को और बेहतर बनाने में हितधारकों की सहायता करेगी। भारत के अलावा, यह पुस्तक कुछ अन्य प्रमुख अधिकार क्षेत्रों में प्रचलित दिवाला कानूनों की विभिन्न प्रक्रियात्मक समस्याओं को प्रस्तुत करती है।

पुस्तक वैचारिक और प्रक्रियात्मक मामलों के विविध पहलुओं और विभिन्न मुद्दों की पेचीदगियों जैसे कि दिवाला प्रक्रिया के दौरान निदेशकों की भूमिका और परिवर्जनीय संव्यवहार (ऐसे लेन-देन जिनसे बचा जाना चाहिए), दिवाला कानून में ईपसो फैक्टो क्लॉज, कार्रवाई योग्य दावे, समाधान प्रक्रिया में एडीआर तकनीक, संबन्धित बिक्री और पुनर्गठन में व्यवस्था की योजनाएँ। पुस्तक अपनी सभी बारीकियों के साथ विकसित दिवाला कानून को समझने का प्रयास करती है और इसका उद्देश्य उन हितधारकों के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शक बनना है, जो कानून और अभ्यास के इस उभरते क्षेत्र में अधिक अध्ययन करना और तल्लीन होना चाहते हैं।

मैं एफसीडीओ, यूके और उन सभी लेखकों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इस पुस्तक को तैयार करने में योगदान दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि नीति निर्माताओं, दिवाला संबंधी वृत्तिक, लेनदारों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और छात्रों सहित दिवाला और शोधन अक्षमता पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारक इस पुस्तक को उपयोगी पाएंगे।

सुधाकर शुक्ला

पूर्णकालिक सदस्य, आईबीबीआई

दिवाला प्रक्रिया और परिवर्जनीय समव्यवहारों (टालने योग्य लेन-देन) के दौरान निदेशकों की भूमिका

क्लेटन चोंग

दिवाला प्रक्रिया और परिवर्जनीय समव्यवहारों (टालने योग्य लेन-देन) के दौरान निदेशकों की भूमिका

क्लेटन चोंग

वरिष्ठ सहयोगी, वॉंग पार्टनरशिप एलएलपी¹

7

सारांश

मुख्य रूप से सिंगापुर दिवाला व्यवस्था (दोनों संविधि और मुकदमे आधारित कानून) से प्रेरित होने के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में हुए परिवर्तनों और वहाँ की प्रथाओं का उल्लेख करते हुए, यह पेपर दिवाला प्रक्रिया और परिवर्जनीय संव्यवहार के दौरान निदेशकों की भूमिका से संबंधित तीन मुख्य मुद्दों अर्थात् (1) कंपनी के लिए निर्णय लेते समय निदेशकों को व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए उचित छूट दिया जाना (2) गलत व्यापार व्यवस्था में बचाव संस्कृति को बढ़ावा देने और लेनदारों के हितों की रक्षा दोनों के लिए सही संतुलन और (3) एक प्रभावी प्रवर्तन ढांचे को स्थापित करने के महत्व पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ने से पहले प्रासंगिक सिंगापुर कानून के एक संक्षिप्त विवरण के साथ शुरू होता है। तीसरे विषय के तहत दो क्षेत्रों पर चर्चा की गई है; दिवाला प्रक्रिया के लिए मुकदमेबाज़ी के वित्तपोषण की व्यवस्था करते समय परिवर्जनीय कार्य और सीमा-पार दिवाला संबंधी निर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन।

यथा आवश्यक स्थानों पर यह पेपर दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत प्रासंगिक प्रावधानों और एक स्पष्ट संदर्भ और बेहतर तुलना प्रदान करने के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की रिपोर्टों को भी संदर्भित करता है।

जब कोई ऐसे काल्पनिक निदेशक की परिकल्पना करता है जिसे दिवाला कानून विनियमित करने की कोशिश करे, तो तीन लोग दिमाग में आते हैं: संस्थापक, स्वतंत्र निदेशक और कपटी व्यक्ति।

¹ लेखक स्मिता मेनन, पार्टनर और वॉंगपार्टनरशिप एलएलपी के रिस्ट्रक्चरिंग एंड इन्सॉल्वेंसी प्रैक्टिस के उप प्रमुख और एशियन बिजनेस लॉ इंस्टीट्यूट के प्रोजेक्ट मैनेजर कैथरीन शेन हाओयू को इस पेपर के पहले के मसौदे को पढ़ने और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं।

संस्थापक अपने कारोबार पर शुरुआत से मेहनत करता है और कंपनी में एक प्रमुख हिस्सेदारी रखता है। जब कंपनी दिवालियेपन के करीब पहुंच रही होती है, तो संस्थापक हर कीमत पर व्यवसाय को बचाने की कोशिश करता है, न केवल अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को बचाने के लिए बल्कि जीवनभर कमाए गौरव और विरासत को बचाने के लिए भी।

स्वतंत्र निदेशक एक पेशेवर की तरह अपना काम करता है। वह मुख्य रूप से जवाबदेह तरीके से और कानून के दायरे में रहकर कार्य करता है। फिर भी, वह कंपनी को बचाने के लिए व्यक्तिगत कारणों से भी प्रेरित हो सकता है - उदाहरण के लिए, अपनी आय के स्रोत के रूप में अपनी निदेशक पद की फीस को संरक्षित करने के लिए या अपनी पेशेवर प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए - लेकिन वह खुद अपराधी बनने या सिविल लायबिलिटी का खतरा मोल नहीं लेता।

दूसरी ओर, कपटी व्यक्ति को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि कोई व्यवसाय आगे बढ़े या न बढ़े। वह विशुद्ध रूप से स्वार्थी है और अन्य हितधारकों की कीमत पर खुद को लाभ पहुंचाने के लिए कानून को मोड़ने या तोड़ने के लिए तैयार रहता है।

निश्चित रूप से, वास्तविकता इन तीनों की तुलना में कहीं अधिक जटिल है। लेकिन वे यह विचार करने के लिए एक उपयोगी आधार प्रदान करते हैं कि जब कोई कंपनी दिवाला हो रही हो, तो निदेशकों के आचरण को कैसे विनियमित किया जाए।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून को कपटी व्यक्ति पर लगाम लगानी चाहिए और उसके द्वारा संभव किसी भी बुरे कार्य को रोकने के लिए भारी प्रतिबंध लगाना चाहिए। लेकिन चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि कपटी व्यक्ति के गले में बांधा गया पट्टा उद्यमी संस्थापक या मेहनती स्वतंत्र निदेशक के गले का फंदा बनकर न रह जाए। फिर भी, संस्थापक कोई संत नहीं है और उसे व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के लिए जुआ खेलने से रोकना चाहिए, खासकर अगर इससे लेनदारों का नुकसान हो रहा हो। अंततः कानून इतना सख्त भी नहीं होना चाहिए कि यह स्वतंत्र निदेशक को रक्षात्मक रूप से कार्य करने के लिए मजबूर करे और वह ऐसे कार्य ही न कर पाये जिससे लेनदारों और अन्य हितधारकों को लाभ हो रहा हो।

इसलिए एक संतुलन और समझौता किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक देश के लिए कोई सही तरीका या आदर्श समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि संतुलन और समझौते के लिए देश की सामाजिक मान्यताओं के साथ उन्नीस बीस करना आवश्यक है। किसी देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य उन नियमों को तैयार करने का एक उचित और न्यायसंगत आधार हैं जो यह नियंत्रित करे कि निदेशकों और कंपनियों को कैसे व्यवहार करना चाहिए। इससे वे मुद्दे आड़े नहीं आते जो एक राज्य के संगठन के लिए मौलिक हैं - जैसे समुदाय के लिए कॉर्पोरेट

जिम्मेदारी, अर्थव्यवस्था में व्यापार और वाणिज्य का कुशल कामकाज, नौकरियों का सृजन और संरक्षण, और उद्यमशीलता जोखिम लेने की लागत और लाभों का वितरण।

इसी कारण से वर्तमान पेपर, समाधानों का अत्यधिक प्रयास नहीं करता है क्योंकि हर देश तो छोड़िए, प्रत्येक उद्योग के लिए "राम बाण औषधि" जैसी कोई व्यवस्था संभव नहीं है। कुछ उद्योगों को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए अधिक जोखिम लेने की आवश्यकता होती है और जहां समाज के कमजोर क्षेत्र हितधारक होते हैं वहाँ अधिक विनियमन की आवश्यकता होती है। इससे इतर, हम सिंगापुर दिवाला व्यवस्था की चुनौतियों और सफलताओं का वर्णन करेंगे, जिसका उद्देश्य भारत के खुद के दिवाला कानून सुधारों के लिए अंतर्दृष्टि और विचार प्रदान करना है। इस बात पर प्रकाश डालने के लिए कि भविष्य में सिंगापुर की व्यवस्था किस प्रकार उन्नत होगी, हमने अन्य क्षेत्रों के विकास और नवाचारों का अध्ययन किया है। हम आशा करते हैं कि अपनाए गए दृष्टिकोणों से हम एशियाई दिवाला कानूनों में सामंजस्य बिठाने और उन्हें एक साथ लाने में मदद करेंगे।

I. सिंगापुर कानून का विवरण

सिंगापुर व्यवस्था पर चर्चा करने से पूर्व, दिवाला और परिवर्जनीय संव्यवहार में निदेशकों के कर्तव्यों पर सिंगापुर के कानूनों का विवरण देना उचित होगा। इसके बाद के सारांश में, यह स्पष्ट होगा कि भारत और सिंगापुर के कानून में कई समानताएं हैं, जो एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से बदलते और विकसित होते दोनों ही व्यवस्था के लिए अच्छा है।

दिवाला होने की स्थिति में लेनदारों के हितों को ध्यान में रखने के लिये निदेशकों के सामान्य कर्तव्य

सिंगापुर के कानून के तहत, जब कोई कंपनी दिवाला या खराब वित्तीय स्थिति में होती है, तो उसके निदेशकों को कंपनी के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए अपने कर्तव्य स्वरूप लेनदारों के हितों को ध्यान में रखना होता है।² इस कर्तव्य के लिए निदेशकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे लेनदारों के पूर्वाग्रह से कंपनी की संपत्ति का अपने स्वयं के लाभ के लिए दुरुपयोग या शोषण न करे।³ कंपनी का वित्तीय स्वास्थ्य जितना खराब होगा, उतना ही अधिक

² लिक्विडेटर्स ऑफ प्रोजेन इंजीनियरिंग पीटीई लिमिटेड बनाम प्रोजेन होल्डिंग्स लिमिटेड [2010] 4 एसएलआर 1089 (सिंगापुर) [48] पर।

³ प्राइमा बल्कशिप पीटीई लिमिटेड बनाम लिम से वान [2017] 3 एसएलआर 839 (सिंगापुर) [62] पर।

ध्यान निदेशकों को शेयरधारकों के हितों की तुलना में लेनदारों के हितों पर देना होगा।⁴ लेनदारों के हितों को प्राथमिकता देने का तर्क यह है कि कंपनी प्रभावी ढंग से व्यापार और अपना व्यवसाय लेनदारों के पैसे से ही चला रही है।⁵ लेनदारों के प्रति यह कर्तव्य निदेशकों का नहीं, बल्कि सीधे कंपनी का होता है।

गलत ट्रेडिंग और कपटपूर्ण ट्रेडिंग

यदि कंपनी गलत व्यापार और धोखाधड़ी संबंधी व्यापार में संलग्न है, तो कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों को आपराधिक प्रतिबंधों और व्यक्तिगत देयता का सामना करना पड़ सकता है। एक कंपनी गलत तरीके से व्यापार में संलग्न मानी जाती है यदि वह दिवालिया होने पर पूरी तरह से ऋण चुका पाने की उचित संभावना के बिना ऋण लेती है या इन ऋणों के परिणामस्वरूप दिवालिया हो जाती है।⁶ यदि किसी निदेशक को पता था या उसे पता होना चाहिए था कि कंपनी गलत तरीके से व्यापार कर रही है, तो अदालत ऐसे निदेशक को कंपनी के सभी या किसी भी ऋण के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहरा सकती है।⁷

एक कंपनी धोखाधड़ी के व्यापार में संलग्न मानी जाती है यदि वह अपने लेनदारों या किसी अन्य व्यक्ति के लेनदारों को धोखा देने के इरादे से या किसी धोखाधड़ी के उद्देश्य से अपना व्यवसाय करती है।⁸ यदि कोई निदेशक जानबूझकर कंपनी के व्यवसाय को इस तरह से चला रहा था, तो अदालत ऐसे निदेशक को कंपनी के सभी या किसी भी ऋण के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार घोषित कर सकती है।⁹

परिवर्जनीय संव्यवहार

सिंगापुर दिवाला कानून दिवाला कार्यवाही (यानी, न्यायिक प्रबंधन और परिसमापन) शुरू होने से पहले देनदार द्वारा किए जा रहे कुछ संव्यवहारों को रोकने का प्रावधान प्रदान करता है। परिवर्जनीय संव्यवहार की श्रेणियों में शामिल हैं:

- कम मूल्यांकित संव्यवहार;¹⁰
- अनुचित वरीयताएँ;¹¹

⁴ डाइनेस्टी लाइन लिमिटेड बनाम सुकामतो सिया [2014] 3 एसएलआर 277 (सिंगापुर) [34] पर।

⁵ ईसीआरसी लैंड पीटीई लिमिटेड बनाम हो विंग ऑन क्रिस्टोफर [2004] 1 एसएलआर (आर) 105 (सिंगापुर) [49] पर।

⁶ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 239(12)।

⁷ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 239(1)।

⁸ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 238(1)।

⁹ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 238(4)।

¹⁰ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 224।

¹¹ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 225।

- जबरन क्रेडिट संव्यवहार;¹²
- संव्यवहार जो पिछले मूल्य के लिए फ्लोटिंग प्रभार बनाते हैं; और¹³
- लेनदारों को धोखा देने वाले संव्यवहार।¹⁴

कम मूल्यांकित संव्यवहार

कम मूल्यांकित संव्यवहार ऐसे संव्यवहार हैं जिनमें कंपनी को प्रतिपक्ष से कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है या कंपनी द्वारा प्रतिपक्ष को प्रदान किए गए मूल्य से काफी कम मूल्य प्राप्त होता है।¹⁵ एक निदेशक द्वारा कम मूल्य के संव्यवहार की खरीद करने पर संभावना है कि यह पाया जाए कि उसने भी अपने वैश्वसिक कर्तव्यों (विश्वास आधारित कर्तव्य) का उल्लंघन किया है।¹⁶ कम मूल्यांकित संव्यवहार से बचा जा सकता है यदि वे ऐसे समय में किए गए हों जब कंपनी दिवालिया थी या यदि लेनदेन के परिणामस्वरूप कंपनी दिवालिया हो गई थी।¹⁷ यदि संव्यवहार कंपनी से जुड़े किसी व्यक्ति के साथ किया गया था,¹⁸ तो यह माना जाएगा कि कंपनी उस समय दिवालिया थी या लेन-देन के परिणामस्वरूप दिवालिया हो गई थी।¹⁹ "लुक बैक" अवधि जिसमें इस तरह के संव्यवहार से बचा जा सकता है, कंपनी के समापन या न्यायिक प्रबंधन के शुरू होने से तीन साल पहले की अवधि है।²⁰

इससे बचाव हो सकता है यदि यह दिखाया जा सके कि संव्यवहार कंपनी के व्यवसाय को चलाने के उद्देश्य से सद्भाव में किया गया था, और यह विश्वास करने के लिए उचित आधार थे कि संव्यवहार से कंपनी को लाभ होगा।²¹ इसके अलावा, संपत्ति प्राप्त करने वाला तीसरा पक्ष जो कम मूल्य के संव्यवहार का केंद्र है, वैधानिक रूप से संरक्षित है यदि ऐसा तीसरा पक्ष संपत्ति को सद्भाव

¹² दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 228।

¹³ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 229।

¹⁴ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 438।

¹⁵ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 224(3)।

¹⁶ लिविंग द लिंक पीटीई लिमिटेड (लेनदारों के स्वैच्छिक समापन में) और अन्य बनाम टैन ले टिन टीना और अन्य [2016] 3 एसएलआर 621 (सिंगापुर)

¹⁷ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 224 और 226।

¹⁸ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 217। ऐसे विस्तृत और जटिल नियम हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ शामिल हैं जिसमें एक व्यक्ति या कंपनी को एक संबन्धित व्यक्ति माना जाएगा। कुछ उदाहरणों में एक निदेशक के पति या पत्नी और रिश्तेदार, और एक निदेशक के सामान्य नियंत्रण की कंपनियाँ शामिल हैं।

¹⁹ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 226(3)।

²⁰ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 226(1)(ए)।

²¹ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 224(4)।

में, मूल्य के लिए और प्रासंगिक तथ्यों की सूचना के बिना प्राप्त करता है।²² ऐसी संपत्ति से प्राप्त कोई भी ब्याज सुरक्षित रहता है।²³

एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि कोई संव्यवहार कम मूल्य पर किया गया है, तो अदालत के पास प्रभावित कंपनी को उस स्थिति तक वापस लाने की व्यापक शक्तियां होती हैं, जिस स्थिति में वह कंपनी संव्यवहार करने से पहले होती। अन्य बातों के अलावा, अदालत इस तरह के संव्यवहार के तहत हस्तांतरित किसी भी संपत्ति को प्रभावित कंपनी को वापस स्थानांतरित करने के लिए कह सकती है, प्रतिभूति जमा जारी करने का आदेश दे सकती है, और उस व्यक्ति को कंपनी को ऐसी रकम का भुगतान करने का आदेश दे सकती है जिसे कंपनी से लाभ मिला है।²⁴

अनुचित प्राथमिकताएं

यह माना जाएगा कि कंपनी ने अनुचित वरीयता दी है यदि वह कोई भी ऐसा कार्य करती है या उस कार्य के परिणामस्वरूप कोई ऐसी बात होती है जिससे लेनदार कंपनी के काल्पनिक समापन की तुलना में बेहतर स्थिति में आ जाए। एक निदेशक जिसने अनुचित वरीयता दी है, उसे भी अपने वैश्वसिक कर्तव्यों का उल्लंघन करता पाया जाएगा।²⁵

अनुचित प्राथमिकताओं से बचा जा सकता है यदि उन्हें ऐसे समय पर किया जाए जब कंपनी दिवाला थी या संव्यवहार के परिणामस्वरूप कंपनी दिवाला हो गई थी।²⁶ "लुक बैक" अवधि, जिसमें अनुचित प्राथमिकताओं से बचा जा सकता है, कंपनी के समापन या न्यायिक प्रबंधन के शुरू होने से पहले एक वर्ष की अवधि है²⁷ और कंपनी के समापन या न्यायिक प्रबंधन के शुरू होने से पहले दो साल की लंबी अवधि है, यदि अनुचित वरीयता कंपनी से जुड़े किसी व्यक्ति को दी गई थी।²⁸

²² दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 227(3)।

²³ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 227(3)।

²⁴ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 227(1)।

²⁵ लिविंग द लिंक पीटीई लिमिटेड (लेनदारों के स्वैच्छिक समापन में) और अन्य बनाम टैन ले टिन टीना और अन्य [2016] 3 एसएलआर 621 (सिंगापुर)

²⁶ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 224 और 226।

²⁷ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 226(1)(सी)।

²⁸ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 226(1)(बी)।

अनुचित वरीयता से बचने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि यह दिखाया जाए कि कंपनी लेनदार को वरीयता देने की इच्छा से प्रभावित थी।²⁹ दूसरे शब्दों में, यह तथ्य कि कंपनी एक लेनदार को वरीयता देती है, इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि अनुचित वरीयता दी गई है - यह लेनदार को वरीयता देने की व्यक्तिपरक इच्छा है जो वरीयता को "अनुचित" बनाती है। जहां लेनदार को वरीयता देने में कंपनी की मंशा विशुद्ध रूप से उचित व्यावसायिक विचारों से प्रेरित है, ऐसे कार्यों को अनुचित वरीयता नहीं माना जाता है।³⁰

यदि संव्यवहार कंपनी से जुड़े किसी व्यक्ति के साथ किया गया था,³¹ तो यह माना जाएगा कि कंपनी संबंधित व्यक्ति को वरीयता देने की इच्छा से प्रभावित थी। इस धारणा का खंडन करने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि संव्यवहार दिवाला कंपनी की इस इच्छा से प्रभावित नहीं था कि व्यक्ति को वरीयता दी जाए।³²

कम मूल्यांकित संव्यवहार के तहत यदि एक बार यह स्थापित हो जाए कि संव्यवहार एक अनुचित वरीयता है, तो अदालत के पास प्रभावित कंपनी को उस स्थिति में बहाल करने के लिए व्यापक उपचारात्मक विवेकाधिकार है, जिस स्थिति में वह तब होती यदि संव्यवहार न किया गया होता। इस प्रकार अदालत के पास कम मूल्यांकित संव्यवहार के संबंध में ऊपर वर्णित शक्तियां हैं।

जबरन क्रेडिट संव्यवहार

जबरन क्रेडिट संव्यवहार से भी बचा जा सकता है। एक संव्यवहार को जबरन वसूली माना जाता है, क्रेडिट प्रदान करने वाले व्यक्ति द्वारा स्वीकार किए गए जोखिम का ध्यान रखते हुए, यदि इस तरह के क्रेडिट की शर्तों में असाधारण रूप से अधिक भुगतान करना शामिल हो (चाहे बिना शर्त के या कुछ आकस्मिकताओं के साथ), या वे कठोर और अचेतन या बिलकुल अनुचित हों।³³ "लुक बैक" अवधि, कंपनी के समापन या न्यायिक प्रबंधन के शुरू होने से तीन साल पहले की अवधि है। इस समय जबरन वसूली के संव्यवहार से बचा जाना सकता है

एक बार यदि यह स्थापित हो जाए कि संव्यवहार एक जबरन क्रेडिट संव्यवहार है, तो अदालत अन्य आदेशों के साथ, संव्यवहार को अवैध घोषित कर सकती है या बदल सकती है या प्रतिपक्ष

²⁹ लिक्विडेटर्स ऑफ प्रोजेन इंजीनियरिंग पीटीई लिमिटेड बनाम प्रोजेन होल्डिंग्स लिमिटेड [2010] 4 एसएलआर 1089 (सिंगापुर)।

³⁰ कोओपरेटिव सेंट्रल राइफिसिन- बोरेनलीनबैंक बीए बनाम जूरॉंग टेक्नोलोजीज़ इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड [2011] 4 एसएलआर 977 (सिंगापुर) [24]

³¹ फुटनोट 18 देखें।

³² लिक्विडेटर्स ऑफ प्रोजेन इंजीनियरिंग पीटीई लिमिटेड बनाम प्रोजेन होल्डिंग्स लिमिटेड [2010] 4 एसएलआर 1089 (सिंगापुर)[36] पर।

³³ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 228।

को उसे भुगतान की गई किसी भी राशि का समर्पण करने के लिए कह सकती है। भुगतान या समर्पण करने के लिए आवश्यक कोई भी राशि या संपत्ति दिवाला कंपनी की संपत्ति का हिस्सा बनेगी।³⁴

पूर्व मूल्य के लिए फ्लोटिंग प्रभार

फ्लोटिंग प्रभार से बचा जा सकता है यदि यह कंपनी की ओर से प्रतिपक्ष द्वारा लगाए गए पूर्व मूल्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिपक्ष को प्रदान किया जाए। "लुक बैक" अवधि के दौरान लगाया गया फ्लोटिंग प्रभार उसी समय पर या फ्लोटिंग प्रभार लगाने के बाद कंपनी सूचित मूल्य का प्रभार बनाते समय (जिसमें भुगतान की गई राशि, प्रदान किया गया सामान या सेवाएं, ऋण का निर्वहन या कमी और ऐसी किसी भी राशि पर देय कोई ब्याज शामिल है) निश्चित मूल्य के समग्र मूल्य की सीमा तक मान्य है।³⁵

ऐसी स्थिति में जहां किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में फ्लोटिंग प्रभार बनाया जाता है जो कंपनी से जुड़ा नहीं है, वहाँ फ्लोटिंग प्रभार केवल तभी टाला जा सकता है यदि कंपनी प्रभार बनाते समय दिवाला हो या कंपनी उस संव्यवहार के परिणामस्वरूप दिवाला हो गई हो जिसके अंतर्गत प्रभार लगाया गया

था;³⁶ इस मामले में "लुक बैक" अवधि कंपनी के समापन या न्यायिक प्रबंधन के शुरू होने से एक वर्ष पहले की अवधि है।³⁷ जहां कंपनी से जुड़े व्यक्ति के पक्ष में फ्लोटिंग प्रभार लगाया जाता है,³⁸ वहाँ "लुक बैक" अवधि कंपनी के समापन या न्यायिक प्रबंधन के शुरू होने से दो साल पहले की अवधि है,³⁹ और यह दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कंपनी दिवाला थी या उस संव्यवहार के परिणामस्वरूप दिवाला हो गई, जिसके तहत प्रभार लगाया गया था।

लेनदारों को धोखा देने वाले संव्यवहार

जहां संव्यवहार कम मूल्य पर इस उद्देश्य से किया जाता है कि या तो (i) संपत्ति को उस व्यक्ति की पहुंच से दूर रखा जाए जो देनदार के खिलाफ दावा कर रहा है, या किसी समय कर सकता है, या (ii) अन्यथा उस व्यक्ति के हितों को नज़रअंदाज़ किया जाए जो देनदार के खिलाफ दावा कर

³⁴ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 228।

³⁵ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 229।

³⁶ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 229(3)।

³⁷ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 229(2)(बी)।

³⁸ फुटनोट 17 देखें।

³⁹ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 229(2)(ए)।

रहा है या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति जो संव्यवहार से पूर्वाग्रहित है, या हो सकता है (सांविधिक प्रावधानों में "संव्यवहार से पीड़ित" के रूप में संदर्भित) संव्यवहार को रोकने के लिए आवेदन कर सकता है।⁴⁰ संव्यवहार से पीड़ित व्यक्ति ऐसा आवेदन कर सकता है चाहे कंपनी की दिवाला कार्यवाही शुरू हुई हो या न हुई हो।⁴¹ इसके अतिरिक्त, ऐसे मामले में जहां देनदार कंपनी को बंद किया जा रहा है या वह न्यायिक प्रबंधन में है, आधिकारिक रिसीवर, या समापक या न्यायिक प्रबंधक (जो भी लागू हो), ऐसे संव्यवहार को रोकने के लिए आवेदन भी कर सकता है।⁴²

परिवर्जनीय संव्यवहार करने के लिए वैश्वसिक कर्तव्यों का उल्लंघन

यदि कोई निदेशक कंपनी को परिवर्जनीय संव्यवहार करने के उद्देश्य से खरीदता है, तो उसे उसके वैश्वसिक कर्तव्यों का उल्लंघन माना जाएगा। लिविंग द लिंक पीटीई लिमिटेड (लेनदारों के स्वैच्छिक समापन में) बनाम टैन ले टिन टीना [2016] 3 एसएलआर 621 में, सिंगापुर उच्च न्यायालय ने एक निदेशक को अपने नियंत्रणाधीन कंपनी को अनुचित वरीयता देकर अपने वैश्वसिक कर्तव्यों का उल्लंघन करने के लिए उत्तरदायी पाया। अदालत ने स्थापित सिद्धांत का उल्लेख किया कि, जब कोई कंपनी दिवाला थी या दिवाला होने के करीब थी, तो यह सुनिश्चित करना निदेशक का कर्तव्य था कि कंपनी की संपत्ति लेनदारों के हितों के पूर्वाग्रह के लिए गलत तरीके से उपयोग न हो। इस कर्तव्य का उद्देश्य कंपनी के लेनदारों को दिवाला तंत्र के माध्यम से

कंपनी की संपत्ति को वितरण के लिए संरक्षित करना है।⁴³ क्योंकि निदेशक के वैश्वसिक कर्तव्य वैधानिक परिवर्जनीय प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं, अदालत ने माना कि यह हर मामले में "व्यावहारिक रूप से अपरिहार्य" था कि अनुचित वरीयता देने वाला निदेशक अपने वैश्वसिक कर्तव्यों का उल्लंघन करते हुए पाया जाए।⁴⁴

इसके अलावा, समापन (वाईडिंग अप / लिक्विडेशन) में एक कंपनी अनुचित वरीयता और वैश्वसिक कर्तव्यों के उल्लंघन दोनों के लिए समवर्ती और अलग-अलग दावे कर सकती है। इससे समापक (लिक्विडेटर) को वरीयता प्राप्त करने वाले व्यक्ति और दुर्यवहारिक निदेशक के खिलाफ

⁴⁰ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 438-439।

⁴¹ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 438(5)(डी)।

⁴² दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 438(5)(सी)।

⁴³ लिक्विडेटर्स ऑफ प्रोजेन इंजीनियरिंग पीटीई लिमिटेड बनाम प्रोजेन होल्डिंग्स लिमिटेड [2010] 4 एसएलआर 1089 (सिंगापुर) [48] पर।

⁴⁴ लिविंग द लिंक पीटीई लिमिटेड (लेनदारों के स्वैच्छिक समापन में) और अन्य बनाम टैन ले टिन टीना और अन्य [2016] 3 एसएलआर 621 (सिंगापुर) [78]।

दावे करने की अनुमति मिलती है, जिससे संपत्ति की अधिक से अधिक वसूली करने में मदद होती है। यह वहाँ भी महत्वपूर्ण है जहाँ एक अनुचित वरीयता के लिए क्लॉबैक अवधि समाप्त हो गई है, क्योंकि कंपनी कम से कम अपने वैश्वसिक कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए निदेशक के खिलाफ एक अलग दावा कर सकती है (जिसकी सीमा अवधि लंबी है)।⁴⁵

II व्यावसायिक निर्णय का अक्षांश - यह कितनी अधिक या कम होनी चाहिए?

इस पेपर में हम जिस पहले मुद्दे पर चर्चा करेंगे, वह उस स्वतन्त्रता की सीमा से संबंधित है जो निदेशकों को कंपनी के लिए निर्णय लेते समय व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए दी जानी चाहिए।

सिंगापुर दिवाला कानून के तहत, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें निदेशकों को ऐसी स्वतन्त्रता दी जाती है। उदाहरण के लिए, कम मूल्यांकित संव्यवहार से संबंधित कानून के तहत, यह बचाव (डिफेंस) है यदि कंपनी ने सद्भाव में और अपने व्यवसाय को चलाने के उद्देश्य से संव्यवहार किया, और जिस समय कंपनी ने संव्यवहार किया, उस समय यह विश्वास करने के लिए उचित आधार थे कि संव्यवहार से कंपनी को लाभ होगा।⁴⁶ इसी तरह, अनुचित वरीयताओं से संबंधित कानून के तहत, यदि लेनदार को वरीयता देने में कंपनी की मंशा विशुद्ध रूप से उचित व्यावसायिक विचारों से प्रेरित थी, तो ऐसी कार्रवाई अनुचित वरीयता नहीं मानी जाएगी।⁴⁷

ये अपवाद भारत के दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 (आईबीसी) में पाए गए अपवादों से भिन्न नहीं हैं। आईबीसी के अनुसार निगमित देनदार या अंतरिती (ट्रांसफ़री) के व्यवसाय या वित्तीय कार्यों के सामान्य विधि से किए गए अंतरण परिवर्जनीय वरीयताएँ नहीं होते।⁴⁸ इसी तरह, कम मूल्यांकित संव्यवहार से संबंधित कानून के तहत, आईबीसी यह निर्धारित करता है कि संव्यवहार को कम मूल्यांकित माने जाने के लिए, यह निगमित देनदार के व्यापार की सामान्य विधि के दायरे से बाहर होना चाहिए।⁴⁹

⁴⁵ पैराकाऊ इनवेस्टमेंट होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड और अन्य बनाम पैराकाऊ शिपिंग पीटीई लिमिटेड (परिसमापन में) और अन्य अपील [2018] 1 एसएलआर 271 (सिंगापुर) [109] से [110] तक।

⁴⁶ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 224(4)।

⁴⁷ कोओपरेटिव सेंट्रल राइफिसिन- बोरेनलीनबैंक बीए बनाम जूरॉग टेक्नोलोजीज़ इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड [2011] 4 एसएलआर 977 (सिंगापुर) [24] पर।

⁴⁸ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 (भारत), धारा 43(3)(ए)।

⁴⁹ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 (भारत), धारा 45(2)।

दोनों न्यायालयों में एक मान्यता है कि व्यावसायिक निर्णय के लिए कुछ हद तक स्वतंत्रता आवश्यक है,⁵⁰ लेकिन इससे एक कठिन प्रश्न यह खड़ा होता है कि स्वतन्त्रता कितनी अधिक (या कम) होनी चाहिए। इस पेपर की प्रस्तावना में प्रस्तुत किए गए ढांचे का उपयोग करते हुए, स्वतन्त्रता को इस हद तक कैसे निर्धारित किया जाए कि यह संस्थापक को अविवेकपूर्ण रूप से कार्य करने से रोके, स्वतंत्र निदेशक को निश्चितता दे, और कपटी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले दुरुपयोग को रोक सके?

भारत और सिंगापुर में विधायी दृष्टिकोण में एक दिलचस्प अंतर है। एक व्यापक सामान्यीकरण के रूप में, भारतीय दृष्टिकोण मुख्य रूप से एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण (कि क्या संव्यवहार व्यवसाय की सामान्य विधि से हुआ था) पर निर्भर करता है, जबकि सिंगापुर के दृष्टिकोण में व्यक्तिपरक तत्व शामिल होते हैं (कि क्या संव्यवहार सद्भाव से किया गया या उचित व्यावसायिक विचारों से प्रेरित था)।

दोनों ही पक्षों के मामले इस अंतर का उदाहरण देते हैं। जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर, अनुज जैन बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड, 2019 की सिविल अपील संख्या 8512-8527 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाला में संव्यवहार से बचाव से संबंधित सिद्धांत का व्यापक विश्लेषण करने के बाद, आईबीसी की धारा 43(3)(ए) के तहत "व्यापार की सामान्य विधि" के बचाव के दायरे पर मार्गदर्शन दिया। अदालत ने माना कि संव्यवहार को निगमित देनदार के "व्यापार की सामान्य विधि" का हिस्सा होने के लिए, "किए गए व्यापार के विशिष्ट सामान्य प्रवाह" का हिस्सा होना चाहिए और "किसी विशेष या विशिष्ट स्थिति" से उत्पन्न नहीं होना चाहिए।⁵¹ इस मामले में पूछताछ वस्तुनिष्ठ है जो देनदार कंपनी के व्यवसाय की पिछली प्रथाओं पर ध्यान देती है।

इसके विपरीत, कोओपरेटिव सेंटरेल राइफिसे- बोरेन्लीनबैंक बीए (रबोबैंक इंटरनेशनल, सिंगापुर शाखा के रूप में व्यापार) बनाम जूरॉंग टेक्नोलोजीज़ इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (न्यायिक

⁵⁰ जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के लिए अनुज जैन इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड, 2019 की सिविल अपील संख्या 8512-8527(भारत) में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वरीयता समव्यवहार से बचने से संबंधित प्रावधानों की आधारभूत थियरी और सिद्धान्त की परीक्षा करते हुए यूएनसीआईटीआरएएल लेजिस्लेटिव गाइड ऑन इनसोल्वेन्सी लॉ के पैराग्राफ 17.5 का हवाला दिया। यूएनसीआईटीआरएएल लेजिस्लेटिव गाइड ऑन इनसोल्वेन्सी लॉ के पैराग्राफ 179 में बताया गया है कि "व्यापार की सामान्य विधि" रक्षा "माल और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को एक देनदार के साथ व्यापार करना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है जिसे वित्तीय समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन जिसके साथ संभावित रूप से व्यापार व्यावहारिक है"।

⁵¹ जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के लिए अनुज जैन इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड, 2019 की सिविल अपील संख्या 8512-8527 (भारत) पैरा 25.6.2 पर।

प्रबंधन के तहत) [2011] 4 एसएलआर 977 में, सिंगापुर कोर्ट ऑफ अपील ने जांच की मुख्य रूप से व्यक्तिपरक प्रकृति का समर्थन किया कि क्या कोई संव्यवहार अनुचित वरीयता है। अदालत ने माना कि मूल्यांकन यह है कि क्या देनदार की लेनदार की स्थिति में सुधार करने की इच्छा (मन की एक व्यक्तिपरक स्थिति) थी। एक संव्यवहार जो उचित व्यावसायिक विचारों से किया गया है, परिवर्जनीय वरीयता नहीं हो सकती है। एक उल्लेखनीय बात यह है कि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि एक उचित व्यावसायिक विचार होने में पूर्ण विश्वास पर्याप्त हो सकता है, भले ही, तथ्यात्मक रूप से, ऐसा विश्वास टिकाऊ न हो।⁵²

इन विभिन्न दृष्टिकोणों के तहत फायदे भी हैं और नुकसान भी। भारत में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का लाभ यह है कि इसकी स्पष्ट सीमा निर्धारित है कि कंपनी का दिवाला होने पर कौन से संव्यवहार की अनुमति है। ऐसा करने में, यह स्वतंत्र निदेशक को उस दायरे के बारे में अधिक निश्चितता देता है जिसके अंदर उसे कार्य करने की अनुमति है। यह कंपनी के संव्यवहार की जांच करने वाले समाधान पेशेवर या समापक के लिए इस बात का निर्णय लेना आसान और स्पष्ट बना देता है कि क्या संव्यवहार से बचा जा सकता था या नहीं। क्या कोई संव्यवहार "व्यापार की सामान्य विधि" में किया गया था, यह कंपनी की स्थापित प्रथाओं की जांच करके निर्धारित किया जा सकता है और ऐसा कंपनी के लेखा रिकॉर्ड से भी स्पष्ट होने की संभावना है।

सिंगापुर में व्यक्तिपरक दृष्टिकोण, जो संव्यवहार के लिए पार्टियों के इरादे की जांच करता है, में पार्टियों के इरादे साबित करना मुश्किल होता है और संव्यवहार को रोकने की कार्यवाही (आवोइडेंस प्रोसीडिंग्स) जटिल, अप्रत्याशित और लंबी बनाता है (जैसा कि पैरा 179 पर दिवाला कानून पर यूएनसीआईटीआरएएल विधायी गाइड में उल्लेख किया गया है)।

बचाव संस्कृति को बढ़ावा देने और प्रेरित करने के लिए सिंगापुर शासन व्यक्तिपरक दृष्टिकोण के इन नुकसानों को स्वीकार करता है। इस अंतर्निहित दर्शन को प्रोजेन इंजीनियरिंग पीटीई लिमिटेड बनाम प्रोजेन होल्डिंग्स लिमिटेड [2010] 4 एसएलआर 1089 ("प्रोजेन") के सिंगापुर कोर्ट ऑफ अपील के समापक निर्णय में देखा जा सकता है, जिसमें अदालत ने कहा कि वित्तीय कठिनाई से जूझ रही कंपनी को बचाने या उसका विस्तार करने के उद्देश्य से किए व्यावसायिक रूप से विवेकशील संव्यवहार पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, और अदालत को ऐसे मामलों में निदेशकों के विषय में निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जहां उन्होंने किसी कंपनी के

⁵² कोओपरेटिव सेंट्रल राइफिसिन- बोरेनलीनबैंक बीए (रेबो बैंक इंटरनेशनल, सिंगापुर ब्रांच के रूप में ट्रेडिंग) बनाम जूरॉंग टेक्नोलोजीज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (न्यायिक प्रबंधन के तहत) [2011] 4 एसएलआर 977 (सिंगापुर) [24] पर।

संरक्षण या पुनर्वास के लिए सद्भाव से प्रयास किए और जहाँ उनके पास यह विश्वास करने के लिए उचित व्यावसायिक आधार हैं कि संव्यवहार से कंपनी को लाभ होगा।⁵³

इस दृष्टिकोण से जब कंपनी दिवाला होने वाली हो या दीवाला हो तो संस्थापक और स्वतंत्र निदेशक को कंपनी के लाभ हेतु व्यापार की सामान्य विधि से बाहर जाकर संव्यवहार करने और पुनर्गठन विकल्प लेने की अधिक स्वतन्त्रता मिल जाती है। (निश्चित रूप से, निदेशकों को दिवाला होने के समय में ऐसे निर्णय लेते समय लेनदारों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए।) आखिरकार, अधिकांश कंपनियों के लिए दिवाला प्रक्रिया कोई सामान्य बात नहीं है, और एक कंपनी को इससे बाहर आने के लिए सामान्य व्यवसाय विधि से बाहर जाकर कदम उठाना पड़ सकता है। अगले भाग में, हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि सिंगापुर में अनुचित व्यापार व्यवस्था के संबंध में निदेशकों के आचरण का विनियमन बचाव संस्कृति को बढ़ावा देने के व्यापक नीतिगत उद्देश्य के साथ कैसे मेल खाता है।

इस खंड पर एक अंतिम विचार के साथ यह ध्यान देने योग्य है कि सिंगापुर में व्यक्तिपरक दृष्टिकोण का मतलब यह नहीं है कि अनुचित वरीयताओं को रोकने के लिए यह दृष्टिकोण अधिक उदार या कमजोर है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां वरीयता भुगतान जो "व्यापार की सामान्य विधि" के तहत संरक्षित है, व्यक्तिपरक दृष्टिकोण के तहत रोका जा सकता है। प्रोजेन मामले में, वरीयता भुगतान के प्राप्तकर्ता (जो देनदार कंपनी की एक संबंधित कंपनी थी) ने तर्क दिया कि भुगतान एक स्थापित प्रथा के अनुसार किए गए थे, लेकिन अपील की अदालत ने माना कि एक विशेष प्रकार के स्थापित पिछले अभ्यास के मात्र अस्तित्व से संव्यवहार का बचाव नहीं किया जा सकता है। संव्यवहार के पीछे के इरादे का विश्लेषण करना अभी भी आवश्यक है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि संव्यवहार लेनदार को वरीयता देने की इच्छा से किया गया था।⁵⁴ इसका मतलब यह है कि एक देनदार कंपनी इस तथ्य के पीछे नहीं छिप सकती है कि संव्यवहार अपने सामान्य व्यवसाय विधि के अनुसार था, और यह आवश्यक है कि संव्यवहार सही उद्देश्यों (लेनदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए) के साथ किया गया हो। उपर्युक्त को देखते हुए व्यक्तिपरक दृष्टिकोण कानून के शाब्दिक अर्थ के पीछे छिपकर अवसरवादी रूप से कार्य करने के लिए कपटी व्यक्ति को कम आसरा देता है।

⁵³ लिक्विडेटर्स ऑफ प्रोजेन इंजीनियरिंग पीटीई लिमिटेड बनाम प्रोजेन होल्डिंग्स लिमिटेड [2010] 4 एसएलआर 1089 [3] पर।

⁵⁴ लिक्विडेटर्स ऑफ प्रोजेन इंजीनियरिंग पीटीई लिमिटेड बनाम प्रोजेन होल्डिंग्स लिमिटेड [2010] 4 एसएलआर 1089 [57] पर।

III. अनुचित व्यापारिक व्यवस्था के तहत ध्यानपूर्वक आगे बढ़ना - लेनदारों के हितों की रक्षा करते हुए बचाव संस्कृति को कैसे बढ़ावा दिया जाए?

जैसा कि ऊपर के खंड में संक्षेप में बताया गया है, कानून का ढांचा जो दिवाला प्रक्रिया में निदेशकों के आचरण को नियंत्रित करता है, राज्य के व्यापक नीति उद्देश्यों के साथ भी मेल खाता है। सिंगापुर के संदर्भ में, बचाव संस्कृति को बढ़ावा देने का उद्देश्य लेनदारों के हितों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता के साथ संतुलित है। इस खंड में, हम सिंगापुर में अनुचित व्यापार व्यवस्था के संदर्भ में इस संतुलन को बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करेंगे।

पहली बार में ऐसा लग सकता है कि यह कठिनाई भारत के मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत अधिक नहीं है, यह देखते हुए कि आईबीसी के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया ("सीआईआरपी") में मुख्य रूप से "नियंत्रण में लेनदार" (जोकि "कब्जे में देनदार" के विपरीत है) मॉडल है।⁵⁵ वर्तमान में आईबीसी के मौजूदा सीआईआरपी ढांचे के तहत निदेशकों की भूमिका ज्यादा नहीं है। हालांकि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस ("पीआईआरपी") के तहत, जो अप्रैल 2021 में लागू हुई,⁵⁶ जिसमें एक क्रांतिकारी हाइब्रिड मॉडल शामिल है जिसमें "कब्जे में कर्जदार" और "नियंत्रण में लेनदार" तत्व शामिल हैं।⁵⁷ हाइब्रिड दृष्टिकोण के तहत, यह परिकल्पना की गई है कि निगमित देनदार के मामलों का प्रबंधन उसके निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा,⁵⁸ जो लेनदारों की समिति के नियंत्रण और अन्य सुरक्षा उपायों के अधीन होगा।⁵⁹

⁵⁵ एशियन बिजनेस लॉ इंस्टीट्यूट्स कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड इन्सॉल्वेंसी इन एशिया 2020, क्षेत्राधिकार रिपोर्ट: भारत, पैराग्राफ 4।

⁵⁶ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016, अध्याय III-ए में। प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया) पर दिवाला कानून समिति की रिपोर्ट, अध्याय 5 भी देखें।

⁵⁷ अध्याय 5

⁵⁸ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016, धारा 54एच पर।

⁵⁹ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016, धारा 54एफ और 54जे पर। उदाहरण के लिए, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 की धारा 54जे के तहत, लेनदारों की समिति, प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस के दौरान किसी भी समय, वोटिंग शेयरों के कम से कम छियासठ प्रतिशत वोट द्वारा, कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंधन को रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के साथ मिलाने का संकल्प कर सकती है, इस मामले में रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल इस उद्देश्य के लिए निर्णायक प्राधिकरण को आवेदन करेगा। यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की राय है कि प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस के दौरान: (ए) कॉर्पोरेट देनदार के मामलों को कपटपूर्ण तरीके से संचालित किया गया है; या (बी) कॉर्पोरेट देनदार के मामलों का घोर कुप्रबंधन किया गया है, तो यह पेशेवर के साथ कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंधन को निहित करने का आदेश पारित करेगा। पैरा 5.16 पर प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया) पर इन्सॉल्वेंसी लॉ कमेटी की रिपोर्ट भी देखें।

इन घटनाक्रमों के साथ, भारत में पुनर्गठन समुदाय को वांछित नीतिगत उद्देश्यों के अनुरूप आईबीसी के तहत अनुचित व्यापार व्यवस्था को संतुलित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

सिंगापुर कानून के तहत स्थिति को पुनः देखें तो, यदि कंपनी अनुचित व्यापार में संलग्न होती है तो कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों को आपराधिक प्रतिबंधों और व्यक्तिगत दायित्व का सामना करना पड़ सकता है। एक कंपनी अनुचित तरीके से व्यापार में संलग्न पाई जाती है यदि वह दिवाला होने पर पूरी तरह से ऋण चुकाने की उचित संभावना के बिना ऋण लेती है या इन ऋणों के परिणामस्वरूप दिवाला हो जाती है।⁶⁰ यदि किसी निदेशक को पता था या उसे पता होना चाहिए था कि कंपनी अनुचित तरीके से व्यापार कर रही है, तो अदालत ऐसे निदेशक को कंपनी के सभी या किसी भी ऋण के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार घोषित कर सकती है।⁶¹

अनुचित व्यापार पर निषेध तब भी लागू होता है जब कंपनी पुनर्गठन के प्रयास कर रही होती है (चाहे एक सहमति से अदालत के बाहर या व्यवस्था की एक योजना के माध्यम से)।⁶² यह किसी कंपनी का पुनर्गठन करने की इच्छा रखने वाले किसी भी संस्थापक या स्वतंत्र निदेशक के लिए एक चुनौती है। एक सफल पुनर्गठन अक्सर कंपनी के व्यवसाय की निरंतरता पर निर्भर करता है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी ऋण ही न ले, फिर भी निदेशक व्यक्तिगत देयता का जोखिम उठाते हैं। कंपनी के पुनर्गठन की कोशिश करते समय वे "कड़ाई से चलने" और सावधानी से चलने के लिए मजबूर होते हैं।

सिंगापुर में अनुचित व्यापार व्यवस्था से कुछ शिक्षाएं मिलती हैं। एक निदेशक को व्यक्तिगत दायित्व से मुक्त किया जा सकता है यदि वह अदालत को संतुष्ट कर दे कि उसने ईमानदारी से काम किया है, और मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसे व्यक्तिगत दायित्व से मुक्त किया जाना उचित है।⁶³ एक विकल्प यह है कि कंपनी अदालत से अग्रिम निर्णय ले सकती है कि क्या आचरण या संव्यवहार की एक प्रस्तावित विधि को अनुचित व्यापार माना जाएगा।⁶⁴ सैद्धांतिक रूप से आकर्षक होते हुए भी इस शिक्षा का व्यवहार में अभी तक परीक्षण नहीं हुआ है क्योंकि ये अभी 2020 में ही सामने आई हैं।

⁶⁰ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 239(12)।

⁶¹ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 239(1)।

⁶² सिंगापुर में एक कंपनी के पुनर्गठन की संभावना के बारे में अधिक जानकारी के लिए, एशियन बिजनेस लॉ इंस्टीट्यूट के कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड इन्सॉल्वेंसी इन एशिया 2020 के सिंगापुर चैप्टर को देखें।

⁶³ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 239(2)।

⁶⁴ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) (सिंगापुर) धारा 239(10)।

सिंगापुर में अनुचित व्यापार व्यवस्था को दिवाला कानून और अभ्यास (1982) पर यूनाइटेड किंगडम ("यूके") सीएमएनडी 8558 की समीक्षा समिति की रिपोर्ट (आमतौर पर "कॉर्क रिपोर्ट" के रूप में संदर्भित) द्वारा सुझाए गए विधायी प्रावधानों के मसौदे से अपनाया गया था। यह उल्लेखनीय है कि ये प्रावधान यूके के कानून में अपनी जगह नहीं बना पाए। 1986 का यूके इन्सॉल्वेंसी एक्ट सिंगापुर कानून की तुलना में यकीनन सख्त मानक निर्धारित करता है। यूके के कानून के तहत, एक निदेशक अनुचित व्यापार के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है यदि उसे ज्ञात था या उसे यह ज्ञात होना चाहिए था कि इस बात की कोई संभावना नहीं है कि कंपनी दिवालिया समापन में जाने से बच जाएगी और यदि वह कंपनी के लेनदार के संभावित नुकसान को कम करने की दृष्टि से हर कदम उठाने में विफल रहा।⁶⁵

सिंगापुर दिवाला कानून समीक्षा समिति ने अपनी 2013 की रिपोर्ट में, कॉर्क रिपोर्ट के अनुचित व्यापार ढांचे को अपनाने की सिफारिश की थी, क्योंकि इसे जिम्मेदार उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और कंपनियों का प्रबंधन करने वालों द्वारा कॉर्पोरेट फॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के बीच सबसे अच्छा संतुलन माना गया था।⁶⁶ कॉर्क रिपोर्ट के ढांचे को यूके और ऑस्ट्रेलियाई विधायी ढांचे पर प्राथमिकता दी गई थी क्योंकि समिति ने माना की पहले में ठोस अर्थ या सकारात्मक मार्गदर्शन की कमी थी⁶⁷ और दूसरे में बहुत सख्ती थी, जिसके कारण यदि इस बात के "संदेह के लिए उचित आधार" हैं कि कंपनी दिवाला है तो यह प्रभावी रूप से व्यापार को रोक देता है।⁶⁸ समिति ने पाया कि दिवाला कार्यवाही शुरू होने से पहले ही व्यापार की एक व्यापक काल्पनिक समाप्ति आर्थिक रूप से संकटग्रस्त कंपनी की संकट की अवधि के दौरान व्यापार करने की क्षमता को और खतरे में डाल सकती है, और इस प्रकार कंपनी की वित्तीय कठिनाइयों को और बढ़ा सकती है। इससे एक दिवाला कंपनी द्वारा लापरवाह या अनुचित रूप से ऋण लेने के खिलाफ लेनदारों की रक्षा करने को प्राथमिकता देने और एक संकटग्रस्त कंपनी के निदेशकों को कंपनी की वित्तीय बर्बादी से बचाने के लिए उचित कदम उठाने का उचित अवसर देने की प्राथमिकता के बीच उचित संतुलन नहीं बनता।

2013 में सिंगापुर दिवाला कानून समीक्षा समिति की रिपोर्ट के बाद से, इस क्षेत्र के अन्य क्षेत्राधिकारों में काफी कुछ बदला है। इन घटनाक्रमों में सबसे प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई दिवाला शासन

⁶⁵ दिवाला अधिनियम 1986 (यूके), एस 214।

⁶⁶ दिवाला कानून समीक्षा समिति (2013) (सिंगापुर) की रिपोर्ट, अध्याय 9 पैराग्राफ 21।

⁶⁷ दिवाला कानून समीक्षा समिति (2013) (सिंगापुर), अध्याय 9 पैराग्राफ 12 की रिपोर्ट।

⁶⁸ दिवाला कानून समीक्षा समिति (2013) (सिंगापुर), अध्याय 9 पैराग्राफ 18 की रिपोर्ट।

के तहत एक "सुरक्षित आश्रय" (सेफ हार्बर) की शुरुआत है, जो कंपनियों को व्यक्तिगत दायित्व से बचने के लिए समय से पहले प्रशासन या समापन करने से रोकता है।⁶⁹ ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षित आश्रय प्रावधानों के तहत, कंपनी के दिवाला होने के दौरान लिए गए ऋणों के लिए निदेशक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होंगे, यदि यह दिखाया जा सके कि कंपनी को तुरंत प्रशासन या समापन की ओर ले जाने की तुलना में विकास योजना बनाने या कार्रवाई करने से कंपनी के लिए बेहतर परिणाम आने की संभावना थी।⁷⁰ प्रावधानों को इस तरह लचीला बनाया गया था कि कार्रवाई की विधि ऐसी हो कि सुरक्षित आश्रय का संरक्षण हो सके, क्योंकि इस बात की स्वीकृति थी कि तार्किक रूप से जिससे बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है वह प्रत्येक मामले में अलग अलग हो सकता है।⁷¹ इस मूल्यांकन में कई कारकों पर विचार किया गया है, जिसमें क्या कंपनी के निदेशकों ने उचित रूप से योग्य सलाहकार से सलाह प्राप्त की है, और क्या कंपनी के पुनर्गठन के लिए एक योजना विकसित करने या लागू करने के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं आदि भी शामिल है।⁷²

उपरोक्त चर्चा विभिन्न अधिकार क्षेत्रों के दृष्टिकोणों में एक बड़ी विविधता दर्शाती है और उदाहरण देती है कि कैसे कानूनी ढांचे को प्रत्येक देश की जरूरतों और उद्देश्यों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। सिंगापुर में, बड़ी संख्या में कंपनियां (सूचीबद्ध कंपनियों सहित) परिवार के स्वामित्व वाली या परिवार द्वारा संचालित हैं।⁷³ जहां ऐसी कंपनियों का संबंध है, कानून के लिए संस्थापक के उत्साह को सीमित करना तुलनात्मक रूप से यकीनन अधिक महत्वपूर्ण है (क्योंकि वह पहले से ही कंपनी को बचाने के लिए वित्तीय और भावनात्मक रूप से प्रेरित होगा) बजाए कि वह स्वतंत्र निदेशक को कम संरक्षणवादी या रक्षात्मक होने के लिए प्रेरित करे।

भारत में अनुचित तरीके से व्यापार हेतु कानूनी ढांचे को तैयार करने में भी अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि देनदार के कब्जे वाली व्यवस्था में ऐतिहासिक रूप से

⁶⁹ इनसोल्वेंट ट्रेडिंग सेफ हार्बर (ऑस्ट्रेलिया) की समीक्षा पर परामर्श, <https://treasury.gov.au/sites/default/files/2021-09/25011-safeharbourreviewconsultationpaper.pdf>

⁷⁰ निगम अधिनियम 2001 (ऑस्ट्रेलिया), धारा 588GA।

⁷¹ इनसोल्वेंट ट्रेडिंग सेफ हार्बर (ऑस्ट्रेलिया) की समीक्षा पर परामर्श, <https://treasury.gov.au/sites/default/files/2021-09/25011-safeharbourreviewconsultationpaper.pdf>

⁷² निगम अधिनियम 2001 (ऑस्ट्रेलिया), धारा 588GA।

⁷³ मार्लिन डायलमैन एट अल., सक्सेस एंड सक्सेशन : एसजीएक्स-सूचीबद्ध परिवार फर्मों का एक अध्ययन, एनयूएस सेंटर फॉर गवर्नेंस, इन्स्टीट्यूशन एंड ओर्गनाइजेशन (2013), <https://bschool.nus.edu.sg/cgs/wp-content/uploads/sites/7/2018/10/Success-and-Success-2013.pdf>

अविश्वास रहा हो सकता है,⁷⁴ भारत में संस्थागत ढांचे और दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र ने हाल के वर्षों में काफी प्रगति की है।⁷⁵ यह देश को अपने लाभों का दोहन करते हुए, कब्जे में देनदार व्यवस्था के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा के लिए प्रभावी जांच और संतुलन की प्रणाली बनाने के लिए और अधिक अच्छी स्थिति में रखता है।

IV प्रवर्तन के लिए एक प्रभावी ढांचे का निर्माण

प्रवर्तन के लिए एक प्रभावी ढांचे का निर्माण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार करना जो देश की जरूरतों और उद्देश्यों के लिए सबसे उपयुक्त हो। अन्यथा, कानून एक फंदे के अलावा और कुछ नहीं है - यह खतरनाक प्रतीत होता है, लेकिन इसका कोई वास्तविक महत्व नहीं है।

इस खंड में, हम दो क्षेत्रों की बात करेंगे जिन्हें एक प्रभावी प्रवर्तन ढांचे का निर्माण करते समय परिष्कृत किया और सुधारा जा सकता है। पहला विषय दिवाला होने से रोकने के कार्यों के लिए मुकदमेबाजी के वित्तपोषण से संबंधित है और दूसरा सीमा-पार दिवाला संबंधी निर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन से संबंधित है।

दिवाला होने से रोकने की कार्रवाइयों के लिए मुकदमेबाजी का वित्तपोषण

दिवाला होने की पद्धति में यह देखने से ज्यादा अजीब कुछ भी नहीं है कि गलत काम करने वाले कंपनी की संपत्ति को निचोड़ लेते हैं और कंपनी के पास गबन की गई संपत्ति की वसूली का दावा करने के लिए वितीय संसाधन तक नहीं होते। लेनदार अक्सर मुकदमेबाजी के कार्यों को वित्तपोषित करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि वे पहले ही काफी नुकसान झेल चुके होते हैं और अपने खोये पैसे की वसूली के लिए और पैसा लगाने से डरते हैं। मुकदमेबाजी का वित्त-पोषण इस समस्या को हल करने में मदद करता है। मुकदमेबाजी के लिए वित्त-पोषण का एक स्पष्ट और निर्धारित ढांचा आवश्यक है ताकि गलत काम करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ वैध और व्यावहारिक दावों को बढ़ावा दिया जा सके, जिन्होंने कंपनी की संपत्ति को शून्य किया है।

⁷⁴ आईबीबीआई ने प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस पर इन्सॉल्वेंसी लॉ कमेटी की अपनी रिपोर्ट (पैरा 5.12 पर) में नोट किया कि सीआईआरपी के तहत प्रबंधन को विस्थापित करने की नियम सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट (स्पेशल प्रोविज़न) 1985 के अंतर्गत डेटर इन पोजेशन व्यवस्था के भूतपूर्व नकारात्मक के अनुभवों के कारण पेश किया गया था। यह दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 के विधेयक के खंडों पर टिप्पणियों में देखा गया था कि पिछले अनुभव ने संकेत दिया था कि मौजूदा प्रबंधन को नियंत्रण देने से जोखिम भरे बचाव का प्रस्ताव और कार्यान्वयन करने के लिए प्रबंधन को प्रोत्साहन मिला है और प्रबंधन द्वारा संपत्ति के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया है।

⁷⁵ प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (इंडिया) पर इन्सॉल्वेंसी लॉ कमेटी की रिपोर्ट, पैरा 5.13 पर।

भारत में पुनर्गठन और दिवाला प्रैक्टिशनर्स ने मुकदमेबाजी वित्तपोषण की व्यवस्था बनाने की मांग की है। आईबीबीआई की 2021 की रिपोर्ट, क्विनक्वेनियल ऑफ़ इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 में मुकदमेबाजी के वित्त-पोषण के विषय पर दो पेपर दिये गए थे, जिनमें से दोनों ने भारत में मुकदमेबाजी के वित्त-पोषण के लिए एक वैधानिक और नियामक ढांचे की स्थापना की वांछनीयता पर ज़ोर दिया। इसी तरह, निगमित समापन प्रक्रिया (26 अगस्त 2020) पर आईबीबीआई के चर्चा पत्र ने सुझाव दिया कि ऐसे मामले में जहां समापन की जाने वाली संपत्ति वसूली के कार्यों को निधि देने के लिए अपर्याप्त है, क्या वहाँ समापकों को कार्रवाई के कुछ वैधानिक अधिकारों (जैसे परिवर्जनीय संव्यवहार कार्रवाई, आकस्मिक दावे आदि) को तीसरे पक्ष को सौंपने के लिए अधिकृत किया जाना चाहिए।⁷⁶

सिंगापुर में, जुलाई 2020 में दिवाला, पुनर्गठन और विघटन (असाइनमेंट ऑफ़ प्रोसीड्स ऑफ़ एन एक्शन) विनियम 2020 के अधिनियमन के माध्यम से परिवर्जनीय कार्यों हेतु मुकदमेबाजी के वित्तपोषण के लिए एक वैधानिक ढांचा पेश किया गया था।

अविश्वसनीय रूप से, इन विनियमों की शुरुआत से पहले, मुकदमेबाजी के वित्त-पोषण ढांचे के मूल सिद्धांतों और संरचना को केस कानून के माध्यम से क्रमिक रूप से बनाया गया था। रे वैनगार्ड एनर्जी पीटीई लिमिटेड [2015] 4 एसएलआर 597 एक मौलिक मामला था जिसमें सिंगापुर उच्च न्यायालय ने माना कि एक समापक के पास कंपनी के कौज़ ऑफ़ एक्शन (एज़ वेल एज़ द प्रोसीड्स फ़्रम ऑफ़ सच एन एक्शन) को बेचने की शक्ति थी। अदालत का तर्क था कि कौज़ ऑफ़ एक्शन कंपनी की संपत्ति थी, जिसे कंपनी की किसी भी संपत्ति की तरह समापक द्वारा उसकी वैधानिक शक्तियों के तहत बेचा जा सकता था।⁷⁷ वित्त-पोषण व्यवस्था को वित्त-पोषकों को कौज़ ऑफ़ एक्शन बेचने के लिए बनाया गया था, लेकिन कंपनी के पास संविदात्मक अधिकार था कि वित्त-पोषकों को उनके द्वारा वित्त-पोषित राशि लौटाने के बाद शेष वसूली को कंपनी अपने पास रख सके,⁷⁸ जिससे सफल दावे की स्थिति में कंपनी को लाभ प्राप्त हो सके।

सोलवाडिस कमोडिटी केमिकल्स जीएमबीएच बनाम एफ़र्ट रिसोर्सज पीटीई लिमिटेड [2018] 5 एसएलआर 1337 में, सिंगापुर उच्च न्यायालय ने उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान किया और यह माना कि अदालत मुकदमेबाजी का वित्त-पोषण समझौता करने में समापक के विवेक के साथ हस्तक्षेप

⁷⁶ पैराग्राफ 10 पर।

⁷⁷ रे वैनगार्ड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड [2015] 4 एसएलआर 597 (सिंगापुर) [23] से [24] पर।

⁷⁸ रे वैनगार्ड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड [2015] 4 एसएलआर 597 (सिंगापुर) [7] पर।

नहीं करेगी जब तक कि वह ऐसा काम न कर रहा हो जो पूरी तरह से अनुचित हो या उसमें प्रामाणिकता की कमी हो।⁷⁹ अदालत ने गैर-संपूर्ण कारकों की एक सूची बताई, जिनका उपयोग यह निश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि क्या समापक ने वास्तव में प्रयास किया है जैसे कि समापक ने वित्त पोषण के अन्य विकल्प ढूँढने का और कंपनी के लेनदारों के साथ परामर्श करने का कितना प्रयास किया, वित्त पोषण समझौते का कंपनी के लेनदारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कार्यवाहियों पर समापक का कितना नियंत्रण है।⁸⁰

अंत में, रे फैन कोउ हिन [2019] 3 एसएलआर 861 केस में, सिंगापुर उच्च न्यायालय ने माना कि परिवर्जनीय दावों को एक समापक द्वारा भी बेचा जा सकता है (पिछले मामले केवल सीधे मौद्रिक दावों की बिक्री से संबंधित थे)। वित्त-पोषण व्यवस्था में परिवर्जनीय दावों की प्रोसीड्स के एक हिस्से को प्रदान करना शामिल था,⁸¹ जिससे कंपनी सफल होने पर मुकदमे से प्राप्त लाभ का हिस्सा बचा सकती थी। इन सभी मामलों से यह स्पष्ट हुआ कि, बशर्ते कुछ सुरक्षा उपाय उपयुक्त हों, दिवाला के संदर्भ में मुकदमेबाजी का वित्त-पोषण न्याय और जनहित के उद्देश्यों की पूर्ति करने में मदद करता है।⁸²

नए विनियमों की शुरुआत के साथ, परिवर्जनीय कार्यों की मुकदमेबाजी के वित्त-पोषण को अब वैधानिक स्तर दिया गया है। विनियमों के तहत, किसी कंपनी का समापक या न्यायिक प्रबंधक एक या एक से अधिक लेनदारों या कंपनी के सदस्यों, या एक या एक से अधिक तीसरे पक्ष के वित्त-पोषकों से एक प्रस्ताव मांगने के लिए अधिकृत है, ताकि संबंधित कार्रवाई की आय या संभावित आय में एक शेयर या अन्य हित प्रदान करने, जिसकी कंपनी हकदार हो सकती है, के बदले में संबंधित कार्रवाई की लागत के पूरे या कुछ हिस्से का वित्त पोषण किया जा सके।⁸³ इस तरह के प्रस्ताव का अनुरोध करते समय, समापक या न्यायिक प्रबंधक को एक लिखित नोटिस देना चाहिए, जिसमें सभी आवश्यक जानकारी शामिल हो, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं:⁸⁴

(क) प्रासंगिक कार्रवाई या अपेक्षित प्रासंगिक कार्रवाई की प्रकृति;

⁷⁹ सोलवाडिस कमोडिटी केमिकल्स जीएमबीएच बनाम एफर्ट रिसोर्सेज पीटीई लिमिटेड [2018] 5 एसएलआर 1337 (सिंगापुर) [34] और [35] पर।

⁸⁰ सोलवाडिस कमोडिटी केमिकल्स जीएमबीएच बनाम एफर्ट रिसोर्सेज पीटीई लिमिटेड [2018] 5 एसएलआर 1337 (सिंगापुर) [38] पर।

⁸¹ रे फैन को हिन [2019] 3 एसएलआर 861 (सिंगापुर) [2] पर।

⁸² रे वेनगार्ड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड [2015] 4 एसएलआर 597 (सिंगापुर) [43] से [49] पर; सोलवाडिस कमोडिटी केमिकल्स जीएमबीएच बनाम एफर्ट रिसोर्सेज पीटीई लिमिटेड [2018] 5 एसएलआर 1337 (सिंगापुर) [60] पर; रे फैन को हिन [2019] 3 एसएलआर 861 (सिंगापुर) [22] पर।

⁸³ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन (असाइनमेंट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ एन एक्शन) विनियम 2020 (सिंगापुर), आरईजी 4(1)।

⁸⁴ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन (असाइनमेंट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ एन एक्शन) विनियम 2020 (सिंगापुर), आरईजी 4(3)।

- (ख) सदस्य पार्टियां या संभावित पार्टियां;
- (ग) प्रासंगिक कार्रवाई या अपेक्षित प्रासंगिक कार्रवाई की अनुमानित संभावित आय;
- (घ) मांगे गए वित्त-पोषण की अनुमानित राशि; और
- (ङ) वह तारीख जब तक संबंधित दिवाला प्रैकटीशनर द्वारा वित्त-पोषण का प्रस्ताव प्राप्त किया जाना है।

हितों के टकराव को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय किए गए हैं। संभावित वित्त-पोषक को प्रस्ताव देते समय लिखित पुष्टि देनी होगी कि संभावित वित्त-पोषक और कार्रवाई के पक्ष या पार्टियों के लिए काम करने वाले वकीलों के बीच हितों का कोई वास्तविक या संभावित टकराव नहीं है।⁸⁵ संभावित वित्त-पोषक को या तो यह भी पुष्टि करनी चाहिए कि संभावित वित्त-पोषक और समापक या न्यायिक प्रबंधक के बीच हितों का कोई वास्तविक या संभावित टकराव नहीं है, या यदि यह है तो वह वास्तविक या संभावित हितों के टकराव की घोषणा करे।⁸⁶ समापक या न्यायिक प्रबंधक का कर्तव्य है कि यदि वह वास्तविक या संभावित हितों के टकराव से अवगत है, तो वह किसी वित्त-पोषण समझौते को मंजूरी न दे।⁸⁷

संभावित वित्त-पोषक के साथ वित्त-पोषण समझौता होने से पहले, समापक या न्यायिक प्रबंधक को संबंधित अनुमोदन निकाय (जैसे निरीक्षण समिति या अदालत) से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए, जो कि दिवाला कार्यवाही की प्रकृति के आधार पर भिन्न होता है।⁸⁸ वित्त-पोषण समझौते की स्वीकृति प्राप्त करते समय, समापक या न्यायिक प्रबंधक को प्रस्ताव से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करनी चाहिए, जिसमें प्रस्ताव मांगने के लिए किए गए प्रयास, संभावित वित्त-पोषक की पहचान और प्रस्ताव की महत्वपूर्ण शर्तों का सारांश शामिल है। (वित्त पोषण की राशि, संव्यवहार का प्राथमिकता क्रम या इसकी संरचना, और संभावित आय से दिये जाने वाला हिस्सा शामिल है)।

एक लेनदार या कंपनी का सदस्य जो विचाराधीन कार्रवाई में प्रतिवादी है या जिसने कार्रवाई को वित्त-पोषित करने का प्रस्ताव दिया है, वह वित्त-पोषण समझौते को मंजूरी देने के लिए बुलाई गई बैठक में न तो भाग ले सकता है और न ही मतदान कर सकता है।⁸⁹

⁸⁵ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन (असाइनमेंट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ एन एक्शन) विनियम 2020 (सिंगापुर), आरईजी 4(4)(सी)।

⁸⁶ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन (असाइनमेंट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ एन एक्शन) विनियम 2020 (सिंगापुर), आरईजी 4(4)(डी)।

⁸⁷ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन (असाइनमेंट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ एन एक्शन) विनियम 2020 (सिंगापुर), आरईजी 4(7)।

⁸⁸ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन (असाइनमेंट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ एन एक्शन) विनियम 2020 (सिंगापुर), आरईजी 4(6)।

⁸⁹ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन (असाइनमेंट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ एन एक्शन) विनियम 2020 (सिंगापुर), आरईजी 4(10)।

मुकदमे के वित्त-पोषण ढांचे के तहत समापक या न्यायिक प्रबंधक के कई तरह के कर्तव्य होते हैं। एक समापक या न्यायिक प्रबंधक को किसी तीसरे पक्ष के वित्त-पोषक से प्रस्ताव नहीं मांगना चाहिए जिसमें वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शेयर या अन्य स्वामित्व हित रखता है।⁹⁰ उसे किसी ऐसे तृतीय-पक्ष के वित्त-पोषक से कोई कमीशन, शुल्क या आय का हिस्सा भी नहीं लेना चाहिए, जिसका कंपनी के साथ वित्त-पोषण अनुबंध है।⁹¹

समापक या न्यायिक प्रबंधक को संबंधित कार्रवाई के संचालन पर नियंत्रण और निगरानी बनाए रखनी चाहिए, जिसके संबंध में वित्त-पोषण समझौता किया गया था और उसे संबंधित कार्रवाई के संचालन पर वित्त-पोषक से निर्देश नहीं लेना चाहिए।⁹²

एक व्यापक सुरक्षा के रूप में, विनियम एक कंपनी के सदस्यों और लेनदारों को न्यायालय से ऐसी स्थिति में राहत पाने का अधिकार प्रदान करते हैं, जहां नियमों का उल्लंघन होने से कंपनी या कंपनी के सदस्यों या लेनदारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अदालत के पास यह आदेश देने की शक्ति है कि वह वित्त-पोषण समझौता को अमान्य घोषित कर सकती है और ऐसे परिणामी आदेश या निर्देश दे सकती है जो वह उचित समझे, बशर्ते कि इसमें उस व्यक्ति की पहचान का ध्यान रखा जाए जिसकी गलती के परिणामस्वरूप संबंधित उल्लंघन हुआ।⁹³

सीमा-पार (करोस बॉर्डर) दिवाला संबंधी निर्णयों का प्रवर्तन

सीमा-पार दिवाला प्रक्रिया के लिए परस्पर सहयोग आवश्यक है। किसी देश के लिए अपने कानूनों के तहत एक प्रभावी पुनर्गठन या दिवाला कार्यवाही करने के लिए यह आवश्यक है कि अन्य देश इसे मान्यता दे और लागू करें। जेट एयरवेज की दिवाला कार्रवाई में बनाए गए सीमा-पार सहयोग प्रोटोकॉल जैसे मोर्चे पर अभूतपूर्व विकास के बावजूद, भारत के प्रैक्टिशनर्स ने सीमा-पार दिवाला कानून बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है।⁹⁴

परिवर्जनीय कार्यों के संबंध में, कोई भी आसानी से देख सकता है कि सीमा-पार प्रवर्तन के लिए एक मजबूत ढांचा क्यों आवश्यक है। एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जहां गलत काम करने

⁹⁰ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन (असाइनमेंट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ एन एक्शन) विनियम 2020 (सिंगापुर), आरईजी 5(1)।

⁹¹ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन (असाइनमेंट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ एन एक्शन) विनियम 2020 (सिंगापुर), आरईजी 5(3)।

⁹² दिवाला, पुनर्गठन और विघटन (असाइनमेंट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ एन एक्शन) विनियम 2020 (सिंगापुर), आरईजी 5(4) और (5)।

⁹³ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन (असाइनमेंट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ एन एक्शन) विनियम 2020 (सिंगापुर), आरईजी 6(2) और (3)।

⁹⁴ आईबीबीआई की 2021 रिपोर्ट, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का क्विडक्वेनियल, 2016, अध्याय 43।

वाला व्यक्ति किसी कंपनी की संपत्ति को एक विदेशी अधिकार क्षेत्र में छिपा देता है। गलत करने वाला व्यक्ति तो गायब हो जाता है और समापक गलत काम करने वाले के खिलाफ गलत संपत्ति को वापस लेने के लिए एक डिफ़ॉल्ट निर्णय चाहता है। ऐसे में समापक निर्णय को विदेशी अदालतों के अधिकार क्षेत्र में ले जाता है जहां संपत्ति स्थित होती है और निर्णय को मान्य और लागू करने के लिए अदालतों की सहायता लेता है। क्या इस तरह के फैसले को मान्यता दी जाएगी और लागू किया जाएगा?

यह संक्षेप में, रुबिन बनाम यूरोफाइनेंस एसए [2013] 1 एसी 236 ("रुबिन") में यूके के सर्वोच्च न्यायालय के सामने आई स्थिति थी। यूके सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत निर्णयों के प्रवर्तन को नियंत्रित करने वाले ब्रिटिश निजी अंतरराष्ट्रीय कानून नियमों को लागू करते हुए कहा कि गलत करने वाले के खिलाफ डिफ़ॉल्ट निर्णय लागू नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि आम कानून में, व्यक्तिगत रूप से एक विदेशी निर्णय केवल तभी लागू किया जा सकता था जब निर्णय का देनदार उपस्थित हो या विदेशी क्षेत्राधिकार का निवासी हो या उसने उस अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया हो, लेकिन मामले के तथ्यों के अनुसार इनमें से कुछ भी संभव नहीं था।⁹⁵ अदालत ने यह भी माना कि सीमा-पार दिवाला संबंधी यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून ("एमएलसीबीआई") (यूके क्रॉस-बॉर्डर इन्सॉल्वेंसी रेगुलेशन 2006 के तहत अपनाया गया) से भी कोई समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि एमएलसीबीआई में तीसरे पक्ष के खिलाफ निर्णयों को लागू करने का कोई उल्लेख नहीं है।⁹⁶

यह निश्चित नहीं है कि सिंगापुर की अदालतें उन मामलों पर निर्णय कैसे देगी जिनमें समान तरह के तथ्य शामिल हों। सिंगापुर में व्यक्तिगत निर्णयों को लागू करने के लिए सामान्य कानून नियम मूल रूप से पारंपरिक ब्रिटिश नियमों के समान ही हैं,⁹⁷ और भारत के मामले में भी ऐसा ही प्रतीत होता है।⁹⁸ फिर भी, सिंगापुर की अदालतों ने ब्रिटिश कानून का अनुसरण नहीं छोड़ा (विशेषकर री पैसिफिक एंडीज रिसोर्सज डेवलपमेंट लिमिटेड [2018] 5 एसएलआर 125 में गिब्स सिद्धांत के पुनर्गठन में)।

⁹⁵ रुबिन बनाम यूरोफाइनेंस एसए [2013] 1 एसी 236 (यूनाइटेड किंगडम) [6]

⁹⁶ रुबिन बनाम यूरोफाइनेंस एसए [2013] 1 एसी 236 (यूनाइटेड किंगडम) [142]

⁹⁷ हम्पस सी ट्रांसपोर्ट पीटीई लिमिटेड (अनिवार्य समापन में) बनाम पीटी हम्पस इंटरमोडा ट्रांसपोर्टसी टीबीके [2016] 5 एसएलआर 1322 (सिंगापुर) [67] से [85] पर।

⁹⁸ सलोनी खंडेरिया (2021): भारत और दक्षिण अफ्रीका में विदेशी नागरिक और वाणिज्यिक निर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन में 'क्षेत्राधिकार' का प्रसार: एक तुलनात्मक विश्लेषण, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कॉमनवेल्थ लॉ जर्नल, डीओआई: 10.1080/14729342.2021.1934298, खंड 2.2.1.2. पर।

हालांकि, कानून आगे स्पष्ट रास्ता प्रदान करता है। सामयिक विकास के तहत, भारत के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 24 नवंबर 2021 को एक प्रस्तावित सीमा-पार दिवाला कानून पर सार्वजनिक टिप्पणियों को आमंत्रित करते हुए एक नोटिस जारी किया। नोटिस ने रुबिन द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों पर प्रकाश डाला, और उल्लेख किया कि "रुबिन में अपनाई गई व्याख्या की कई प्रैक्टिशनर्स ने आलोचना की है क्योंकि निर्णयों को लागू किए बिना कार्यवाही को मान्यता मात्र देने [एमएलसीबीआई] का कोई महत्व नहीं है"।⁹⁹ इस समस्या का समाधान करने के लिए, नोटिस का प्रस्ताव है कि भारत के सीमा-पार दिवाला कानून को स्पष्ट करना चाहिए कि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण एक विदेशी कार्यवाही, जिसे भारत में मान्यता दी गई है, के निर्णय को लागू करने का आदेश दे सकता है।

दिवाला-संबंधित निर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन पर यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून ("एम एलआईआईजे") (इसे एमएलसीबीआई न समझा जाए) भी समस्या का एक अन्य संभावित समाधान है। एमएलआईआईजे को रुबिन द्वारा उत्पन्न अनिश्चितता की प्रतिक्रिया स्वरूप तैयार किया गया था।¹⁰⁰ एमएलआईआईजे सीमा-पार दिवाला कार्यवाही के संचालन में एमएलसीबीआई की सहायता के उद्देश्य से तैयार किया गया है।¹⁰¹

एमएलआईआईजे के तहत, परिवर्जनीय निर्णय उन विभिन्न दिवाला-संबंधी निर्णयों में से हैं जिन्हें मान्यता दी जा सकती है और लागू किया जा सकता है।¹⁰² एमएलआईआईजे ऐसे अधिक व्यापक आधार प्रदान करता है जिन पर पारंपरिक ब्रिटिश कानून की तुलना में विदेशी व्यक्तिगत निर्णय को मान्यता दी जा सकती है और लागू किया जा सकता है। ब्रिटिश कानून की तरह, एमएलआईआईजे के तहत, एक विदेशी निर्णय को मान्यता दी जा सकती है यदि निर्णय संबंधी देनदार स्पष्ट रूप से सहमति देता है या अदालत के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करता है। हालांकि, एमएलआईआईजे के तहत यह पर्याप्त है यदि विदेशी न्यायालय या तो उस आधार पर अधिकार

⁹⁹ भारत सरकार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, नोटिस - दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत सीमा-पार दिवाला पर जनता से टिप्पणियों का आमंत्रण, फ़ाइल संख्या 30/27/2018 (24 नवंबर 2021)।

¹⁰⁰ गाइड टू इनएक्टमेंट के साथ दिवाला-संबंधित निर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन पर यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून, भाग दो, अध्याय 1, पैराग्राफ 2.

¹⁰¹ गाइड टू इनएक्टमेंट के साथ दिवाला-संबंधित निर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन पर यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून, भाग दो, अध्याय 1, पैराग्राफ 1।

¹⁰² गाइड टू इनएक्टमेंट के साथ दिवाला-संबंधित निर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन पर यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून, भाग दो, अध्याय 5, पैराग्राफ 60(बी)।

क्षेत्र का प्रयोग करे जिसके आधार पर मान्यता देने वाला न्यायालय क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है या ऐसे आधार पर जो मान्यता प्राप्त राज्य के कानून के साथ असंगत न हो।¹⁰³

एमएलआरईआईजे में मान्यता प्राप्त राज्य के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न सुरक्षा उपाय किये गए हैं। इसमें एक सार्वजनिक नीति अपवाद शामिल है जिसके तहत मान्यता देने वाली अदालत कार्रवाई करने से इनकार कर सकती है यदि ऐसा करना राज्य की सार्वजनिक नीति के विपरीत हो,¹⁰⁴ और समान पक्षों से जुड़े मामले में मान्यता और प्रवर्तन से इनकार करने का विवेक, यदि निर्णय मान्यता देने वाले राज्य के निर्णय से भिन्न हो।¹⁰⁵

संभवतः एमएलआरईआईजे सीमा-पार दिवाला के विकास के अगले चरण का प्रतिनिधित्व करेगा और परिवर्तनीय निर्णयों को लागू करने के लिए एक प्रभावी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करने में मदद करेगा।

V. निष्कर्ष

हम आईबीबीआई की 2021 की रिपोर्ट, क्विनक्वेनियल ऑफ़ इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 में डॉ. साहू के परिचयात्मक संदेश में प्रयुक्त एक उद्धरण को हवाला देते हुए बात को विराम देंगे: "यदि आप रुकते नहीं हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी धीमी गति से चल रहे हैं।" यह संदेश सिंगापुर में भी उतना ही प्रासंगिक है। पर्याप्त सुधार किए जाने के बावजूद ऐसे क्षेत्र शेष हैं जिनमें परिष्करण और सुधार आवश्यक है।

पहले चर्चित दो मुद्दे – व्यावसायिक निर्णय के लिए उपयुक्त स्वतन्त्रता और अनुचित व्यापार व्यवस्था के तहत सही संतुलन - प्रत्येक देश के नीतिगत उद्देश्यों के अनुरूप कानूनी ढांचे को निर्धारित करने में आने वाली कठिनाई का उदाहरण देते हैं। एमएलसीबीआई को अपनाने के बावजूद एक स्पष्ट सीमा-पार प्रवर्तन ढांचे की आवश्यकता है।

दोनों क्षेत्राधिकारों ने हाल के वर्षों में अपने पुनर्गठन और दिवाला व्यवस्थाओं को सुधारने और पुनर्जीवित करने के लिए समानांतर प्रयास किए हैं। हो सकता है कि समय के साथ इनके रास्ते

¹⁰³ दिवाला-संबंधित निर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन पर यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून, अनुच्छेद 14(जी)। गाइड टू इनएक्टमेंट के साथ दिवाला-संबंधित निर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन पर यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून, भाग दो, अध्याय 5, पैराग्राफ 110 से 115।

¹⁰⁴ दिवाला-संबंधित निर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन पर यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून, अनुच्छेद 7।

¹⁰⁵ दिवाला-संबंधित निर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन पर यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून, अनुच्छेद 14(सी)।

आपस में मिलें क्योंकि इस क्षेत्र के नियम एक जैसे हैं और एक साथ आगे बढ़ते हैं।¹⁰⁶ हमें उम्मीद है कि इस पेपर ने सिंगापुर दिवाला व्यवस्था के विषय में उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान की होगी जो भारत की व्यवस्था में सुधार के प्रयासों में सहायता कर सकती है।

¹⁰⁶ एशिया में कॉर्पोरेट दिवाला कानूनों और प्रथाओं की एकरूपता को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय पहलों में एशियन बिजनेस लॉ इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल इनसोल्वेन्सी इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई व्यापार पुनर्गठन परियोजना के एशियाई सिद्धांत शामिल हैं, जिनके तहत एशिया में कॉर्पोरेट पुनर्गठन मामलों के संबंध में कई सर्वोत्तम अभ्यास गाइड तैयार किए जा रहे हैं।

**दिवाला कानून में इप्सो फैक्टो/ipso
facto क्लॉज - एक सिंगापुर परिप्रेक्ष्य**

सिम क्वान किआट

दिवाला कानून में इप्सो फैक्टो/ipso facto क्लॉज - एक सिंगापुर परिप्रेक्ष्य

सिम क्वान किआट

प्रमुख, पुनर्गठन & दिवाला अभ्यास समूह

राजा & टैन सिंगापुर एलएलपी

सारांश

दिवालियेपन और पुनर्चना के संदर्भ में *इप्सो फैक्टो* क्लॉज का संचालन अक्सर इस तरह के क्लॉज द्वारा दी गई सुरक्षा का उपयोग करने की स्वतंत्रता और ऋण पुनर्गठन और देनदार के अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव के बीच विरोधाभासका कारण बनता है। मुख्य रूप से सिंगापुर द्वारा अपने पुनर्गठन और दिवाला शासन के तहत *इप्सो फैक्टो* क्लॉज पर प्रतिबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जहां प्रासंगिक हो, यह लेख ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथाओं के संदर्भ में इन प्रतिबंधों, प्रतिबंधों के दायरे और लागू अपवादों को लागू करने की पृष्ठभूमि की पड़ताल करता है।

लेख इन प्रतिबंधों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर भी चर्चा करता है साथ ही कानून इन संघर्षों को कैसे हल करना चाहता है, एवं प्रावधानों के संचालन के संबंध में अनिश्चितताओं और बकाया प्रश्नों पर भी चर्चा करता है। भारत के दिवाला शासन के तहत *इप्सो फैक्टो* क्लॉज का उल्लेख किया गया है जहां अधिक व्यापक तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक है।

परिचय

इप्सो फैक्टो क्लॉज संविदात्मक खंड हैं जो किसी पक्ष को अनुबंध को समाप्त करने या संशोधित करने, या डिफ़ॉल्ट की निर्धारित घटनाओं की स्थिति पर कुछ दायित्वों को तेज करने की अनुमति देते हैं। डिफ़ॉल्ट की ऐसी घटनाओं के लिए प्रतिपक्ष की दिवाला, या पुनर्गठन या परिसमापन कार्यवाही की शुरुआत को शामिल करना आम बात है।

इप्सो फैक्टो/ipso facto वाक्यांश का अर्थ है "तथ्य से ही", और एक *इप्सो फैक्टो*/ ipso facto क्लॉज को आमतौर पर क्लॉज को ट्रिगर/ (चालू कर देने) करने के लिए निर्धारित घटना के घटित होने से परे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह के खंड वाणिज्यिक दुनिया में असामान्य नहीं हैं, और उस पक्ष या वादी के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों के रूप में काम कर सकते हैं जिसके पक्ष में खंड तैयार किए गए हैं। जहां डिफ़ॉल्ट की घटना प्रतिपक्षकार की दिवाला है, एक उचित रूप से शब्दबद्ध *इप्सो फैक्टो* क्लॉज संरक्षित पार्टी को अनुबंध को समाप्त करने या अन्यथा अपने अधिकारों को संशोधित करने के बजाय मूल समझौते के लिए बाध्य रहने की अनुमति देगा। एक संरक्षित पक्ष चिंतित हो सकता है कि दिवालिया प्रतिपक्ष भुगतान करने में सक्षम नहीं हो सकता है या अन्यथा अपने प्रदर्शन दायित्वों को पूरा नहीं कर सकता है। *इप्सो फैक्टो* क्लॉज उपयोगी होते हैं क्योंकि वे अनुबंध के वास्तविक उल्लंघन को दिखाने के बजाय संरक्षित पार्टी को अकेले दिवालियेपन पर भरोसा करने की अनुमति देते हैं।

दूसरी ओर, *इप्सो फैक्टो* क्लॉज ऋण पुनर्गठन और देनदार पुनर्वास के उद्देश्य से अच्छी तरह से सामंजस्य नहीं बैठा सकते हैं। *इप्सो फैक्टो* क्लॉज के अनुसार प्रमुख अनुबंधों की एकतरफा समाप्ति से कंपनी के पुनर्गठन के प्रयासों में बाधा आने की संभावना है, खासकर जब ऐसे अनुबंध कंपनी के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

सिंगापुर का कानून *इप्सो फैक्टो* क्लॉज के संचालन पर वैधानिक प्रतिबंध लगाकर इस तनाव को दूर करने का प्रयास करता है। जुलाई 2020 में कानून में प्रभावी होने वाले प्रावधान अनिवार्य रूप से कुछ *इप्सो फैक्टो* क्लॉज के संचालन को प्रतिबंधित करते हैं, जब एक देनदार कंपनी पुनर्गठन की कार्यवाही से गुजर रही होती है।

इस लेख में, हम सिंगापुर में पुनर्गठन और दिवाला शासन के संदर्भ में *इप्सो फैक्टो* क्लॉज पर प्रतिबंधों का पता लगाते हैं, जिसमें प्रावधानों की पृष्ठभूमि, प्रतिबंधों का दायरा और लागू अपवाद शामिल हैं। हम इन प्रतिबंधों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं/ करेंगे और कानून इन

संघर्षों को कैसे हल करना चाहता है, साथ ही प्रावधानों के संचालन के संबंध में अनिश्चितताओं और बकाया/उठे हुए प्रश्नों पर भी चर्चा करता है।

सिंगापुर में इप्सो फैक्टो फ़्रेमवर्क का अवलोकन

इप्सो फैक्टो क्लॉज द्वारा दी गई सुरक्षा का उपयोग करने की स्वतंत्रता और ऋण पुनर्गठन और देनदार के अस्तित्व पर इस तरह के क्लॉज के प्रतिकूल प्रभाव के बीच एक विरोधाभास है। सिंगापुर में, तत्कालीन वरिष्ठ कानून राज्य मंत्री ने 2018 में संसद में दिवाला, पुनर्गठन और विघटन विधेयक की दूसरी रीडिंग/ पठन में, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी हाइफ्लक्स लिमिटेड/Hyflux Ltd के मामले का उल्लेख किया।¹ वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने पर, हाइफ्लक्स ने अपने ऋणों का पुनर्गठन करने की मांग की ताकि यह एक चालू चालित उद्यम के रूप में जारी रहे। अधिस्थगन के लिए इसके आवेदन पर, इसके लेनदारों ने पुनर्भुगतान शर्तों में तेजी लाने के लिए इप्सो फैक्टो क्लॉज के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग किया, इस प्रकार हाइफ्लक्स के पहले से ही तनावपूर्ण नकदी प्रवाह को प्रतिबंधित किया और इसकी वित्तीय स्थिति को और चिंताजनक बना दिया।

36

इप्सो फैक्टो क्लॉज के संचालन को प्रतिबंधित करने के मुद्दे पर बहुत बहस हुई है। विशेष रूप से, 2013 में, दिवाला कानून समीक्षा समिति ने इप्सो फैक्टो क्लॉज पर प्रतिबंधों के पक्ष और विपक्ष में तर्कों पर विचार किया, लेकिन अंततः ऐसा करने की सिफारिश करने से इनकार कर दिया।²

इस मुद्दे को अंततः दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 ("IRDA") में संबोधित किया गया था, जो 30 जुलाई 2020 को लागू हुआ। IRDA/ आईआरडीए ने सिंगापुर कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत दिवाला व्यवस्थाओं को समेकित किया और पुनर्गठन और दिवाला ढांचे को अद्यतन किया। विशेष रूप से, जब कंपनी के पुनर्गठन की कार्यवाही चल रही हो, तो ऐसे मामलों में इसने कुछ इप्सो फैक्टो क्लॉज के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया।

जैसा कि IRDA/आईआरडीए पर संसदीय बहस में तत्कालीन वरिष्ठ कानून राज्य मंत्री ने कहा था, इन प्रतिबंधों की शुरुआत संभावित अवरोध के जवाब में थी जो कंपनी के अपने व्यवसाय के

¹ संसदीय बहस, आधिकारिक रिपोर्ट (1 अक्टूबर 2018), खंड 94 (श्री एडविन टॉग चुन फई, स्वास्थ्य और कानून राज्य के वरिष्ठ मंत्री)

² दिवाला कानून समीक्षा समिति, दिवाला कानून समीक्षा समिति की रिपोर्ट: अध्याय 6 पर अंतिम रिपोर्ट (2013), पैराग्राफ 84-90

पुनर्गठन और पुनर्जीवित करने के प्रयासमें सम्मिलित है।³ तदनुसार, उक्त संशोधन एक पुनर्गठन और दिवाला केंद्र के रूप में सिंगापुर की स्थिति और क्षमताओं को भी बढ़ाते हैं।

इप्सो फैक्टोक्लॉज पर प्रतिबंध IRDA/आईआरडीए की धारा 440 में प्रदान किया गया है:

440.(1) कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी द्वारा किसी भी कार्यवाही के प्रारंभ होने के बाद और समापन से पहले किसी भी समय—

- कंपनी के साथ किसी भी समझौते (एक सुरक्षा समझौते सहित) के तहत समाप्त या संशोधित, या त्वरित भुगतान या अवधि की समाप्ति का दावा कर सकता है; या
- (b) कंपनी के साथ किसी भी समझौते (सुरक्षा समझौते सहित) के तहत किसी भी अधिकार या दायित्व को समाप्त या संशोधित करें, केवल इस कारण से कि कार्यवाही शुरू हो गई है या कंपनी दिवालिया है।

(2) इस खंड में कुछ भी अर्थ नहीं माना जाना है: -

- कार्यवाही शुरू होने के बाद प्रदान की गई वस्तुओं, सेवाओं, पट्टे पर दी गई संपत्ति के उपयोग या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए नकद भुगतान की आवश्यकता से किसी व्यक्ति को प्रतिबंधित करना; या
- पैसे या क्रेडिट की अग्रिम आवश्यकता।

(3) एक समझौते में कोई भी प्रावधान, जिसका प्रभाव ऐसा कुछ भी प्रदान करने, या अनुमति देने से संबंधित है, जो कि इस धारा के विपरीत है, कोई बल या प्रभाव का नहीं है।

(4) एक पक्ष द्वारा एक समझौते के लिए एक आवेदन पर, न्यायालय यह घोषणा कर सकता है कि यह धारा लागू नहीं होती है, या केवल न्यायालय द्वारा घोषित सीमा तक लागू होती है, यदि आवेदक न्यायालय को संतुष्ट करता है कि इस धारा के संचालन की संभावना है आवेदक को महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई।

(5) उपधारा (1) के तहत किसी कानूनी अधिकार के संबंध में लागू नहीं होता है—

- कोई भी पात्र वित्तीय अनुबंध जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;
- कोई भी अनुबंध जो सरकार या वैधानिक निकाय द्वारा जारी लाइसेंस, परमिट या अनुमोदन है;
- कोई भी अनुबंध जो सिंगापुर के राष्ट्रीय हित, या आर्थिक हित को प्रभावित करने की संभावना है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है;

³ संसदीय बहस, आधिकारिक रिपोर्ट (1 अक्टूबर 2018), खंड 94 (श्री एडविन टॉग चुन फई, स्वास्थ्य और कानून राज्य के वरिष्ठ मंत्री)

- जहाज का कोई वाणिज्यिक चार्टर;
- विमान उपकरण अधिनियम (कैप. 144बी) में अंतर्राष्ट्रीय हितों की धारा 2(1) में परिभाषित कन्वेंशन के अर्थ के भीतर कोई समझौता; या
- कोई भी समझौता जो एक संधि का विषय है जिसमें सिंगापुर पक्ष है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

(6) इस खंड में -

- "कंपनी" का अर्थ इस अधिनियम के तहत समाप्त होने के लिए उत्तरदायी कोई भी निगम है, लेकिन ऐसी कंपनी या कंपनियों के वर्ग को शामिल नहीं करता है जैसा कि मंत्री, राजपत्र में आदेश द्वारा निर्धारित कर सकते हैं।
- "आवश्यक सेवा" का अर्थ साइबर सुरक्षा अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 9) की धारा 2(1) द्वारा दिया गया है।
- "राष्ट्रीय हित" में राष्ट्रीय रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा और किसी भी आवश्यक सेवा का रखरखाव शामिल है।
- "कार्रवाई" से अभिप्रेत निम्न में से उत्पन्न होने वाली कोई भी कार्रवाई है -
 - (a) कंपनी और उसके लेनदारों या उन लेनदारों के किसी भी वर्ग के बीच किसी भी समझौते या व्यवस्था के संबंध में अदालत के अनुमोदन के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 210(1) के तहत कोई आवेदन।
 - (b) किसी समझौते या व्यवस्था के संबंध में न्यायालय के अनुमोदन के लिए धारा 71 के तहत कोई आवेदन।
 - (c) धारा 64 या 65 के तहत आदेश के लिए कोई आवेदन।
 - (d) धारा 91 के तहत न्यायिक प्रबंधन आदेश के लिए कोई आवेदन; या
 - (e) धारा 94(5)(a) के तहत एक अंतरिम न्यायिक प्रबंधक की नियुक्ति के लिए एक लिखित नोटिस का दाखिल होना।

धारा 440 को अन्य पुनर्गठन और दिवाला व्यवस्थाओं में इप्सो फैक्टो क्लॉज पर मौजूदा प्रतिबंधों की पृष्ठभूमि के परिपेक्ष में विकसित किया गया है। यह खंड काफी हद तक कनाडाई कंपनियों के लेनदारों की व्यवस्था अधिनियम⁴ ("कनाडाई सीसीएए")⁴ की धारा 34 पर आधारित है। इसके

⁴ आर.एस.सी, 1985, सी. सी-36

अलावा, सिंगापुर में इप्सो फैक्टो शासन की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य प्रमुख न्यायालयों के अनुरूप अपनी स्थिति लाती है।

चूंकि सिंगापुर में धारा 440 अभी भी अपेक्षाकृत नई है, इसलिए इसके प्रावधानों के संचालन पर निर्णय विधि/case law सीमित है। जैसे-जैसे कि हम इस धारा के बिंदुओं की विवेचना करते हैं, वैसे वैसे हम न्यायिक क्षेत्राधिकारों से संबंधित प्रासंगिक केस लॉ देखेंगे।

धारा 440 का दायरा

इसकी व्यावहारिक उपयोगिता के बावजूद, इप्सो फैक्टो क्लॉज पर प्रतिबंध, अनुबंध की स्वतंत्रता में घुसपैठ का प्रतिनिधित्व करता है, और अपने हितों की रक्षा करने के लिए एक पार्टी की क्षमता को कम करता है। धारा 440 के लागू होने का दायरा इस प्रकार महत्वपूर्ण है कि यह प्रतिस्पर्धी हितों के बीच कैसे संतुलन बनाता है, जबकि इसके संचालन की सीमाओं को अपने वैधानिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक क्षेत्रों तक सीमित करता है।

हम पहले देखते हैं/ देखेंगे कि धारा 440 में प्रतिबंध कब और कैसे लागू होते हैं, और किस प्रकार के इप्सो फैक्टो क्लॉज को कवर किया जाता है।

धारा 440 कब सक्रिय होती है?

धारा 440 केवल निर्धारित दिवाला और पुनर्गठन कार्यवाही के संदर्भ में लागू होती है। धारा 440(1) में कहा गया है कि यह प्रावधान कंपनी द्वारा "शुरुआत के बाद किसी भी समय, और निष्कर्ष से पहले, किसी भी कार्रवाई के लिए" शुरू किया गया है। " कार्रवाई " को कंपनी को न्यायिक प्रबंधन में रखने के लिए या एक अंतरिम न्यायिक प्रबंधक नियुक्त करने के लिए आवेदनों को शामिल करने के लिए परिभाषित⁵ किया गया है, साथ ही साथ एक व्यवस्था की योजना लेनदारों की बैठक आयोजित करने के लिए एक व्यवस्था की योजना का प्रस्ताव करने के लिए या एक कंपनी के लिए अधिस्थगन आदेश के लिए एक प्रस्ताव देने का इरादा होता है।

" कार्रवाई " की निर्धारित श्रेणियां न्यायिक प्रबंधन और व्यवस्था की योजनाओं से संबंधित हैं, न कि अन्य दिवाला प्रक्रियाओं जैसे कि समापन या प्राप्ति/receivership से। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यायिक प्रबंधन और व्यवस्था की योजनाएं वित्तीय संकट में कंपनियों के पुनर्वास के उद्देश्य से

⁵ दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (2018 का अधिनियम 40) धारा 440 (6)

पुनर्गठन की प्रक्रियाएं हैं, और यह इस संदर्भ में है कि इप्सो फैक्टो क्लॉज का निर्बाध संचालन ऋण पुनर्गठन के उद्देश्य में बाधा उत्पन्न करेगा।

किस प्रकार के इप्सो फैक्टो क्लॉज प्रतिबंधित हैं?

धारा 440 सभी इप्सो फैक्टो क्लॉज के संचालन को प्रतिबंधित नहीं करती है; यह केवल उन इप्सो फैक्टो क्लॉज के संचालन को प्रतिबंधित करता है जो केवल एक अनुबंध पार्टी के दिवालिया होने या कॉर्पोरेट बचाव कार्यवाही - अर्थात्, न्यायिक प्रबंधन के लिए की गई कार्रवाई और व्यवस्था की योजनाएं शुरू होने के कारण सक्रिय होते हैं।

इसलिए, धारा 440 पार्टियों/ पक्षों को अन्य घटनाओं के आधार पर अनुबंधों को समाप्त करने या संशोधित करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोकता है। इस तरह की घटनाओं में अनुबंध का उल्लंघन, कुछ अनुबंधों या दायित्वों का पालन करने में विफलता, बकाया राशि का भुगतान करने में देनदार की विफलता, या अन्य निर्दिष्ट चूक जैसे कि प्राप्तकर्ता/रिसीवर की नियुक्ति या देनदार को समाप्त करने के प्रस्तावों को पारित करना शामिल हो सकता है। पार्टियां उन घटनाओं पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं, जो दिवाला या ऋण पुनर्गठन कार्यवाही शुरू होने पर आधारित नहीं हैं, जो अनुबंध को समाप्त करने या संविदात्मक अधिकारों के संशोधन की अनुमति देते हैं।

40

इप्सो फैक्टो क्लॉज पर प्रतिबंध का दायरा क्या है?

धारा 440(1) पार्टियों/ पक्षों को संबंधित इप्सो फैक्टो क्लॉज पर भरोसा करने से प्रतिबंधित करता है:

- (a) कंपनी के साथ किसी भी समझौते (एक सुरक्षा समझौते सहित) के तहत समाप्त या संशोधित, या त्वरित भुगतान या भुगतान अवधि की समाप्ति का दावा; या
- (b) कंपनी के साथ किसी भी समझौते (सुरक्षा समझौते सहित) के तहत किसी भी अधिकार या दायित्व को समाप्त या संशोधित करना।

ये प्रतिबंध विशिष्ट और लक्षित हैं। उनका उद्देश्य कंपनी को एक प्रकार की स्थिरता प्रदान करना है क्योंकि यह पुनर्गठन से गुजरती है।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिबंधों का दायरा अन्य प्रमुख न्यायालयों के अधिकार क्षेत्रों, अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मौजूदा समकक्ष कानून से अपनाया गया है। धारा 440(1)(a) में प्रतिबंध कनाडाई CCAA की धारा 34(1) के शब्दों को प्रतिबिंबित करता है, जबकि धारा 440(1)(b)

अमेरिकी शोधन अक्षमता कोड/ संहिता की धारा 365(e)(1) के शब्दों को प्रतिबिम्बित करता है। कनाडाई सीसीएए और यूएस शोधन अक्षमता संहिता में समान प्रावधानों से संबंधित निर्णय विधि/case law धारा 440(1)(a) और (b) की व्याख्या में प्रासंगिक हो सकती है।

हाला कि धारा 440(1) का शब्दांकन आम तौर पर काफी सीधा है, लेकिन समझौते में संशोधन या किसी अधिकार या दायित्व को संशोधित करने के विषय में अनिश्चितता उत्पन्न करता है। अमेरिकी निर्णय विधि /case law अधिकारों और दायित्वों के "संशोधन" पर कुछ मार्गदर्शन प्रदान करती है।

लीमैन ब्रदर्स स्पेशल फाइनेंसिंग इंक बनाम बैंक ऑफ अमेरिका नेशनल एसोसिएशन 553 बीआर/BR 476 के प्रकरण में, न्यूयॉर्क दक्षिणी जिले के यूनाइटेड स्टेट्स बैंकरप्सी कोर्ट को यह तय करने के लिए कहा गया था कि क्या कुछ "फिलिप क्लॉज" इप्सो फैक्टो क्लॉज थे जो दिवालियापन में अप्रवर्तनीय थे। मामले में स्वैप/swap समझौते शामिल थे जिसमें पार्टियों को कुछ संपार्श्विक के परिसमापन की आय से भुगतान किया जाना था। लीमैन ब्रदर्स स्पेशल फाइनेंसिंग ("एलबीएसएफ") और लीमैन ब्रदर्स नोटहोल्डर्स ("नोटहोल्डर्स") सहित पार्टियों को भुगतान की प्राथमिकता या समझौतों में वाटरफॉल प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जाना था। फिलिप क्लॉज ने भुगतान वाटरफॉल में पार्टियों की प्राथमिकता को बदलने का काम किया।

इस मामले में अदालत ने समझौतों में दो अलग वाटरफॉल प्रावधानों की पहचान की:

- टाइप 1 लेनदेन –शुरुआत में एलबीएसएफ/LBSF की नोटधारकों/noteholders के सापेक्ष भुगतान में प्राथमिकता थी। हालाँकि, स्वैप के तहत LBSF के डिफॉल्ट होने पर, फिलिप क्लॉज इस तरह सक्रिय हो गया था कि नोटधारकों ने तब LBSF पर भुगतान की प्राथमिकता रखी थी। अदालत ने पाया कि ये वास्तव में अप्रवर्तनीय खंड थे क्योंकि ये LBSF के अधिकारों को संशोधित करने के लिए काम करते थे, LBSF को उसकी मौजूदा भुगतान प्राथमिकता से अलग कर देते थे। (हालांकि, वितरण को अंततः यूएस शोधन अक्षमता संहिता के सेफ हार्वर प्रावधानों के तहत संरक्षित पाया गया।)
- टाइप 2 लेनदेन - इन लेनदेन में, न तो एलबीएसएफ और न ही नोटधारकों ने शुरुआत में भुगतान प्राथमिकता रखी। समाप्ति की घटना होने के बाद ही प्राथमिकता का क्रम स्थापित किया गया। इस "टॉगल" के अनुसरण में, नोटधारकों की प्राथमिकता होती यदि स्वैप के तहत LBSF के डिफॉल्ट का परिणाम जल्दी समाप्त हो गया होता ।

अदालत ने पाया कि उक्त सभी एलबीएसएफ के अधिकारों में संशोधन का गठन नहीं करते थे क्योंकि एलबीएसएफ के पास शुरू में भुगतान प्राथमिकता का मौजूदा अधिकार नहीं था, और केवल परिस्थितियों के आधार पर प्राथमिकता का एक आकस्मिक अधिकार था। जैसे, की ये इप्सो फैक्टो प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित थे।

इस फैसले में अदालत के निर्णय से पता चलता है कि इप्सो फैक्टो प्रावधानों के तहत अधिकार का "संशोधन" दिवालियेपन या पुनर्गठन की स्थिति में निवर्तमान अधिकार में बदलाव को भी सम्मिलित करता है।, ऊपर वर्णित टाइप 2 लेनदेन में आकस्मिक अधिकार के विपरीत निवर्तमान अधिकार को ट्रिगरिंग की घटना के घटित होने से पहले परिभाषित और क्रिस्टलीकृत किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, यह देखा जा सकता है कि "संशोधन" को स्पष्ट रूप से प्रदान करने के लिए इप्सो फैक्टो क्लॉज के अंतर्गत ये आवश्यक नहीं है कि एक ट्रिगरिंग घटना होने पर पार्टी के अधिकारों को एक निश्चित तरीके से बदल दिया जाए। एक अनुबंध जो शुरू में पार्टियों की सापेक्ष स्थिति

निर्धारित करता है (जब पार्टियां सॉल्वेंट होती हैं) और पार्टी की दिवाला कार्यवाही पर एक अलग स्थिति निर्धारित करती है, एक इप्सो फैक्टो क्लॉज के रूप में माना जा सकता है जो प्रतिबंध के अधीन है यदि वह पार्टी खुद को ट्रिगरिंग/ चालू करने वाली घटना के बाद एक कम लाभप्रद स्थिति में पाता है।

क्या धारा 440 संबंधित कंपनियों के दिवालियेपन से उत्पन्न इप्सो फैक्टो क्लॉज को कवर/cover करती है?

सवाल यहा है कि क्या धारा 440 में इप्सो फैक्टो क्लॉज शामिल हैं जो अनुबंध के पक्ष से संबंधित कंपनी की दिवालियेपन पर प्रभावी होते हैं, न कि संविदात्मक पक्ष के बजाय। कॉरपोरेट समूहों के संदर्भ में, इप्सो फैक्टो क्लॉज को क्रॉस-डिफॉल्ट द्वारा ट्रिगर किया जाना आम बात है।

धारा 440 को सीधे तौर पर पढ़ने पर, इप्सो फैक्टो क्लॉज पर प्रतिबंध केवल अनुबंध के पक्षों के बीच लागू होता है, न कि संबंधित कंपनियों जैसे कि सहायक कंपनियों, मूल कंपनियों या एक ही मूल कंपनी के तहत कंपनियों के लिए। हालांकि, अगर ऐसा होता, तो यह चिंता पैदा करता कि पार्टियां इप्सो फैक्टो क्लॉज को लागू करके धारा 440 प्रतिबंध से बचने में सक्षम हो सकती हैं जो संबंधित कंपनी की दिवालियेपन पर प्रभावी होती हैं जो अनुबंध के लिए एक पार्टी नहीं है, खासकर जहां संबंधित कंपनियों के वित्तीय संचालन निकटता से जुड़े हुए हैं।

क्या धारा 440 में संबंधित कंपनी के दिवालियेपन से संबंधित इप्सो फैक्टो क्लॉज शामिल हैं, इस प्रकार एक ऐसा मामला है जो या तो विधायी स्पष्टीकरण या न्यायिक घोषणा द्वारा अधिक स्पष्टता से लाभान्वित होगा ।

क्या धारा 440 में अग्रिम उल्लंघन/anticipatory breach शामिल है?

एक अन्य मुद्दा अग्रिम उल्लंघन का है। प्रत्याशित उल्लंघन के सिद्धांत के तहत, एक अनुबंध के लिए एक पार्टी अपने दायित्वों को पूरा नहीं करने के अपने इरादे का संकेत दे सकती है, इस प्रकार प्रदर्शन के कारण अनुबंध को अस्वीकार कर दिया जाता है। प्रतिपक्ष उक्त अस्वीकार्यता को स्वीकार कर सकता है और अनुबंध से बाध्य नहीं होने का विकल्प चुन सकता है।

एक काल्पनिक परिदृश्य में, दो कंपनियां एक अनुबंध में प्रवेश करती हैं जिसमें एक संविदात्मक पक्ष के दिवालिया होने पर अनुबंध को समाप्त करने की अनुमति देने वाला एक इप्सो फाक्टो क्लॉज होता है। इप्सो फैक्टो क्लॉज धारा 440 के तहत प्रतिबंधित है, केवल उन कंपनियों के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है जो पुनर्गठन या दिवाला से गुजरती हैं। प्रतिपक्ष अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में पहली कंपनी की अक्षमता के संकेत के रूप में मानता है। प्रतिपक्ष प्रत्याशित उल्लंघन का आरोप लगाता है और अनुबंध को समाप्त करता है, प्रभावी रूप से इप्सो फैक्टो क्लॉज के समान परिणाम प्राप्त करता है।

धारा 440 वास्तविक उल्लंघन के आधार पर अनुबंध की समाप्ति को रोकता नहीं है, और अग्रिम उल्लंघन के आधार पर अनुबंध की समाप्ति को रोकने की संभावना नहीं है। क्या प्रत्याशित उल्लंघन तब वैकल्पिक मार्ग/ साइड डोर के रूप में काम करेगा जो किसी पार्टी/ पक्ष के दिवालियेपन के आधार पर अनुबंध को समाप्त करने की अनुमति देता है?

इसमें से बहुत कुछ तथ्यों पर निर्भर करेगा। एक कंपनी का दिवाला अनिवार्य रूप से अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा नहीं करने के इरादे को प्रकट नहीं करता है; इसका वित्तीय संकट इसे संविदात्मक भुगतान करने या अन्यथा अपने दायित्वों को पूरा करने से नहीं रोक सकता है। विशेष रूप से, न्यायिक प्रबंधन या व्यवस्था की योजनाओं के अनुसार पुनर्गठन व्यवस्था एक कंपनी को पुनर्भुगतान की अनुसूची को फिर से समायोजित करने की अनुमति दे सकती है ताकि निरंतर संचालन के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह की अनुमति मिल सके, और ऐसी परिस्थितियों में कंपनियां बचाव वित्तपोषण प्राप्त करने में भी सक्षम हो सकती हैं।

संक्षेप में, जरूरी नहीं है कि दिवाला अपने आप में एक अग्रिम उल्लंघन है। हालांकि, जहां प्रतिपक्ष दिवालिया कार्यवाही से गुजर रही कंपनी के संदर्भ में एक इप्सो फैक्टो क्लॉज पर भरोसा किए बिना एक अग्रिम उल्लंघन स्थापित करने में सक्षम हैं, उन्हें इस तरह के उल्लंघन पर भरोसा करने का अधिकार होना चाहिए। यह, निश्चित रूप से, प्रतिपक्षकार द्वारा प्रत्याशित उल्लंघन साबित करने की कानूनी और साक्ष्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होने के अधीन है।

धारा 440 में छूट

धारा 440 में इप्सो फैक्टो क्लॉज पर प्रतिबंध आम तौर पर अधिकांश वाणिज्यिक अनुबंधों पर लागू होता है। हालांकि, प्रावधानों को इस जागरूकता के साथ तैयार किया गया है कि कुछ उद्योगों या अनुबंधों के प्रकार के मामले में प्रतिबंध उचित नहीं हो सकता है। इसे धारा 440 की छूट में संबोधित किया गया है, जो धारा 440(4) और धारा 440(5) में निर्धारित हैं। धारा 440(4) "महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई" के आधार पर छूट के लिए आवेदन करने के लिए एक वास्तविक खंड पर भरोसा करने की मांग करने वाली पार्टी के लिए एक तंत्र प्रदान करती है, और धारा 440(5) उन समझौतों की एक सूची निर्धारित करती है जिन पर धारा 440(1) के प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं।

ये छूटें एक नीतिगत मामले के रूप में मानती हैं कि इप्सो फैक्टो क्लॉज पर प्रतिबंध पहचान किए गए उद्योगों और समझौतों के संदर्भ में लागू नहीं होना चाहिए।

महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई/Significant Financial Hardship

कोई व्यथित महसूस कर सकता है कि यह विशेष रूप से प्रतिपक्ष के दिवालिया होने की आकस्मिकता के लिए किए गए संविदात्मक सौदे पर भरोसा करने में असमर्थ है। ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं जहां इप्सो फैक्टो क्लॉज पर प्रतिबंध उस पार्टी के लिए पूर्वाग्रह या कठिनाई का कारण बनता है जो क्लॉज पर भरोसा करना चाहता है।

धारा 440(4) में प्रावधान है कि संबंधित समझौते का एक पक्ष अदालत में एक घोषणा के लिए आवेदन कर सकता है कि इप्सो फैक्टो क्लॉज पर प्रतिबंध लागू नहीं होता है, या केवल एक सीमित सीमा तक लागू होता है जैसा कि अदालत द्वारा तय किया जा सकता है। आवेदक को पहले अदालत को संतुष्ट करना होगा कि धारा 440 के संचालन से आवेदक को महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई हो सकती है।

"महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई" का कारक क्या हो सकता है ? जबकि IRDA महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई के तत्वों को परिभाषित नहीं करता है, कनाडा की निर्णय विधि/case law स कुछ मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कनाडाई सीसीएए में एक समान प्रावधान है जो महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई के लिए छूट की अनुमति देता है, और कनाडाई अदालतों को यह विचार करने का अवसर मिला है कि महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई क्या है।

सामान्य तौर पर, ऐसा लगता है कि कनाडा की अदालतों ने 'महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई' के लिए सबूत की एक उच्च सीमा को अपनाया है। यह समझ में आता है कि उच्च सीमा की आवश्यकता क्यों है। किसी दिवालिया प्रतिपक्षकार के खिलाफ इप्सो फैक्टो क्लॉज पर भरोसा करने से रोके गए किसी भी पक्ष को किसी न किसी रूप में वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। एक अनुचित रूप से कम सीमा पहली बार में प्रतिबंध के उद्देश्य को धराशायी कर देगी।

टोरंटो डोमिनियन बैंक बनाम टीवाई (कनाडा) इंक/ Inc 42 सीबीआर (चौथा) 142, 2003 कैनएलआईआई/CanL II 43355 ("टोरंटो डोमिनियन बैंक") के मामले में, ऑंटारियो सुपीरियर कोर्ट ने माना कि महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई क्या है। निर्णय महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई और हितधारक हितों के लिए लागू परीक्षण पर प्रकाश डालता है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इस मामले में आवेदक ने प्रतिपक्षकार के साथ डिस्ट्रीब्यूटरशिप और लाइसेंसिंग करार किया था। पक्षों के बीच विवाद के बाद, आवेदक ने उनके बीच समझौतों को समाप्त करने की मांग की। हालाँकि, प्रतिपक्ष वित्तीय कठिनाइयों में था और उसने शोधन अक्षमता और दिवाला अधिनियम के अनुसार एक प्रस्ताव दायर करने के इरादे का नोटिस दायर किया था। आवेदक ने अदालत से कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की और समझौते को समाप्त करने की अनुमति के लिए, दूसरी और बातों के बीच, कहा कि यदि उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई और सीधे कनाडाई बाजार में अपने नए माल को बेचने की अनुमति नहीं दी तो गई आवेदक को महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

कोर्ट ने स्टे/stay देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि आवेदक को "मात्रात्मक रूप से पूर्वाग्रह दिखाने में सक्षम होना चाहिए कि अगर स्टे नहीं हटाया गया तो उसे नुकसान होगा"। तथ्यों पर, अदालत ने पाया कि आवेदक ने मात्रात्मक रूप से किसी भी भौतिक पूर्वाग्रह का प्रदर्शन नहीं किया था, अगर उसे कनाडा के ग्राहकों को सीधे बिक्री की अपनी रणनीति को आगे बढ़ाने में देरी के अलावा समझौतों को समाप्त करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

टोरंटो डोमिनियन बैंक में न्यायालय के निर्णय से पता चलता है कि एक आवेदक जो महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई का आरोप लगाता है, वह उस पूर्वाग्रह के मूल आरोपों से छूट का उपयोग करने में सक्षम होने की संभावना नहीं है जो इसे भुगतना होगा। इसके बजाय, परिणामी पूर्वाग्रह की सीमा को भौतिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए मात्रात्मक विश्लेषण का कुछ रूप होना चाहिए।

टोरंटो डोमिनियन बैंक में अदालत के फैसले से दो अन्य बिंदु उठते हैं। सबसे पहले, अदालत ने फैसला किया कि विचार योग्य पूर्वाग्रह "वस्तुनिष्ठ पूर्वाग्रह है, ना कि व्यक्तिपरक पूर्वाग्रह"। दिवाला, पुनर्गठन और विघटन विधेयक की दूसरी रीडिंग में, संसद में कहा गया था कि IRDA की धारा 440(4) का उद्देश्य कुछ हद तक लचीलेपन को पेश करना था और यह कि इसका आवेदन उस प्रभाव पर निर्भर करेगा जो प्रतिबंध पर विशेष लेनदार या विशेष स्थिति⁶ में होगा। यदि सिंगापुर की अदालतें कनाडा के दृष्टिकोण को अपनाती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि विशेष लेनदार पर प्रभाव का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जा सकता है।

दूसरा, टोरंटो डोमिनियन बैंक की अदालत ने कहा कि उसे "सभी प्रभावित पक्षों के हितों के संतुलन पर भी विचार करना चाहिए" एवं उक्त रोक को हटाने से संपत्ति के प्रशासन एवं अन्य हितधारकों के पूर्वाग्रह पर होने वाले प्रभाव को ध्यान में रखना होगा"। इसका तात्पर्य यह है कि, महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई पर विचार करते हुए, भले ही आवेदक यह प्रदर्शित करता है कि इप्सो फैक्टो क्लॉज को लागू करने में असमर्थता के कारण उसे पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा, अदालत अन्य इच्छुक हितधारकों के हितों के खिलाफ इस तरह के पूर्वाग्रह को संतुलित कर सकती है। यह स्थिति सिंगापुर में अपनाई जाएगी या नहीं, यह अनिश्चित है, क्योंकि एक सामान्य पठन पर, धारा 440(4) के शब्दों में आवेदक के अलावा किसी अन्य पक्ष के हितों का उल्लेख नहीं है, और इस संबंध में अदालत के विचार का दायरा उतना व्यापक प्रतीत नहीं होता जितना कि इस निर्णय में निहित है।

निर्धारित छूट

धारा 440(5) में प्रावधान है कि अनुबंधों की निम्नलिखित श्रेणियां धारा 440(1) के प्रतिबंध के अधीन नहीं हैं:

- योग्य वित्तीय अनुबंध।
- सरकार या एक वैधानिक निकाय द्वारा जारी एक लाइसेंस, परमिट या अनुमोदन।

⁶ संसदीय बहस, आधिकारिक रिपोर्ट (1 अक्टूबर 2018), खंड 94 (श्री एडविन टॉग चुन फई, स्वास्थ्य और कानून राज्य के वरिष्ठ मंत्री)

- कोई भी अनुबंध जिसके द्वारा सिंगापुर के राष्ट्रीय या आर्थिक हित प्रभावित करने की संभावना है।
- एक जहाज का एक वाणिज्यिक चार्टर।
- विमान उपकरण अधिनियम में अंतर्राष्ट्रीय हितों के तहत समझौते; और
- समझौता जो एक संधि का विषय है जिसमें सिंगापुर पक्ष है।

दिवाला, पुनर्गठन और विघटन (धारा 44044 विनियम 2020 ("निर्धारित अनुबंध विनियम") के तहत निर्धारित अनुबंध उपरोक्त अनुच्छेद/ पैराग्राफ (a) के तहत "योग्य वित्तीय अनुबंध" निर्धारित करने का कार्य करता है, जिसमें शामिल हैं:

- कोई डेरिवेटिव अनुबंध, मार्जिन उधार समझौता या प्रतिभूति अनुबंध।
- कोई मास्टर नेटिंग समझौता, प्रतिभूतियां/वस्तु उधार या पुनर्खरीद समझौता, या स्पॉट अनुबंध, जिसमें नेटिंग व्यवस्था या सेट-ऑफ व्यवस्था शामिल है।
- एक कवर बांड या जुड़े समझौते।
- एक डिबेंचर या जुड़े समझौते।
- डेरिवेटिव अनुबंध से संबंधित लेनदेन को साफ़ करने या निपटाने के लिए कोई समझौता; और
- एक अनुमोदित एक्सचेंज, एक लाइसेंस प्राप्त व्यापार भंडार, एक अनुमोदित या मान्यता प्राप्त समाशोधन गृह या एक मान्यता प्राप्त बाजार ऑपरेटर के व्यापार नियम।

जैसा कि IRDA/आईआरडीए पर संसदीय बहस में तत्कालीन वरिष्ठ कानून राज्य मंत्री ने कहा था, ये छूटें मानती हैं कि कुछ श्रेणियों के लेनदेन या अनुबंधों में इप्सो फैक्टो क्लॉज के आवेदन को प्रतिबंधित करने से कुछ बाजारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जबकि साथ ही प्रतिबंध की प्रभावशीलता⁷ का संतुलन भी होगा।

छूट प्राप्त श्रेणियों में सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी "योग्य वित्तीय अनुबंध" होगी। निर्धारित अनुबंध विनियमों में निर्धारित वित्तीय अनुबंधों की एक विस्तृत सूची है, और यह आगे के प्रकार के वित्तीय अनुबंधों को सूची में जोड़ने के लिए खुला रहता है। इरादा ऐसे अनुबंधों पर भरोसा करने वाले उद्योगों

⁷ संसदीय बहस, आधिकारिक रिपोर्ट (1 अक्टूबर 2018), खंड 94 (श्री एडविन टॉग चुन फई, स्वास्थ्य और कानून राज्य के वरिष्ठ मंत्री)

पर किसी भी संभावित नकारात्मक प्रभाव को कम करना है, जहां वास्तव में खंड अच्छी तरह से स्थापित हो सकते हैं और उद्योग के मानदंडों के रूप में माना जा सकता है।

सिंगापुर के कानून मंत्रालय ("मिनलॉ") द्वारा सार्वजनिक परामर्श के बाद निर्धारित अनुबंध विनियमों में योग्य वित्तीय अनुबंधों की सूची तैयार की गई थी। मिनलॉ ने योग्य वित्तीय अनुबंधों की एक प्रस्तावित सूची प्रकाशित की और टिप्पणियों और प्रतिक्रिया को आमंत्रित किया। इसके बाद मिनलॉ ने छूट प्राप्त अनुबंधों की कुछ श्रेणियों में संशोधन करके और अंतिम निर्धारित अनुबंध विनियमों में नई श्रेणियों को जोड़कर प्रतिक्रिया का जवाब दिया। हालांकि, सार्वजनिक परामर्श में उद्योग दलों द्वारा निर्धारित अनुबंध विनियमों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित छूट की कुछ श्रेणियां भी थीं जिन्हें मिनलॉ द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। इसमें शामिल हैं⁸:

- कोई भी अनुबंध या समझौता जो सीधे किसी वस्तु से जुड़ा हुआ है - इस प्रस्तावित श्रेणी को बहुत व्यापक और उचित नहीं होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। इसके अलावा, "वस्तु उधार/lending या पुनर्खरीद अनुबंध" की एक संकीर्ण श्रेणी को पहले ही बाहर रखा गया है।
- ऋण अनुबंध - इस प्रस्तावित श्रेणी को बहुत व्यापक और उचित नहीं होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। इसके अलावा, वित्तीय संस्थानों के लिए पहले से ही विभिन्न सुरक्षा उपाय मौजूद हैं।
- आउटसोर्सिंग अनुबंध - इस प्रस्तावित श्रेणी को बहुत व्यापक और उचित नहीं होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। इस श्रेणी के दायरे में आने वाले अनुबंधों के प्रकार आम तौर पर वित्तीय अनुबंधों की प्रकृति के नहीं होते हैं जिन्हें छूट के रूप में निर्धारित किया जा सकता है।
- कैश पूलिंग - कैश पूलिंग कंपनियों के एक समूह के लिए वित्तपोषण को संरचित करने का एक तरीका है और यह प्रति वित्तीय अनुबंध का एक प्रकार/श्रेणी प्रतीत नहीं होता है।
- बैंकों और बीमाकर्ताओं के लिए इकाई-स्तरीय बहिष्करण - यह फीडबैक में प्रस्तुत किया गया था कि समाधान व्यवस्था बैंकों और बीमाकर्ताओं के लिए पुनर्गठन का अधिक उपयुक्त रूप है क्योंकि इसे विशेष रूप से उन विचारों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है जो बैंकों और बीमा कंपनियों का दिवाला और इसके संबंध में उत्पन्न होते हैं। हालांकि, मिनलॉ ने कहा कि धारा 440 न तो पूर्वाग्रहों और न ही प्रतिकूल रूप से किसी बैंक

⁸ कानून मंत्रालय, दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 (23 जुलाई 2020) की धारा 440(5)(5) के तहत बहिष्करण पर सार्वजनिक परामर्श से प्राप्त प्रतिक्रिया पर मंत्रालय की प्रतिक्रिया

या बीमाकर्ता को समाधान व्यवस्था में रखे जाने की संभावना को रोकता है। इसके अलावा, यदि बैंक या बीमाकर्ता को समाधान व्यवस्था में नहीं रखा जाता है, तो वह विशेष बैंक या बीमाकर्ता व्यवस्था की एक योजना के माध्यम से पुनर्गठन का प्रयास कर सकता है।

तुलनात्मक मूल्यांकन

धारा 440 से छूट प्राप्त समझौतों की श्रेणियां काफी मानक मानी जा सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया में, अनुबंधों की एक विस्तृत श्रृंखला को ऑस्ट्रेलियाई निगम अधिनियम और निगम विनियम 2001 (Cth) के तहत छूट प्राप्त समझौतों की सूची में शामिल किया गया है। इसमें शामिल हैं (i) ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा सुरक्षा या रक्षा क्षमता से संबंधित कोई अनुबंध, व्यवस्था या समझौता; और (ii) किसी सार्वजनिक अस्पताल या सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को माल और सेवाओं की आपूर्ति के लिए कोई समझौता।⁹

इस दृष्टिकोण ने सवाल उठाया है कि क्या छूट का दायरा बहुत व्यापक हो सकता है, जिससे अनिश्चितता पैदा हो सकती है और इप्सो फैक्टो शासन की प्रभावशीलता कम हो सकती है। इसके विपरीत, उद्योग की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, सिंगापुर की स्थिति छूट की निर्धारित श्रेणियों में अधिक विशिष्टता की ओर अग्रसर है।

उल्लेखनीय है कि भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 ("IBC") को हाल ही में दिवाला और शोधन अक्षमता (संशोधन) अधिनियम 2020 के अनुसार संशोधित किया गया था ताकि दिवाला के आधार पर समाप्ति या निलंबन के संविदात्मक अधिकारों पर कुछ संभावित प्रतिबंध लगाए जा सकें¹⁰। विशेष रूप से, संभावित प्रतिबंध अनुबंधों की कुछ श्रेणियों पर लागू होते हैं, जैसे कि सरकार या राज्य प्राधिकरण द्वारा दिए गए लाइसेंस, परमिट और पंजीकरण आदि, और महत्वपूर्ण आपूर्ति के लिए अनुबंध। इसके अलावा, एक बार दिवाला व्यवसायी की नियुक्ति हो जाने के बाद, माल या सेवाओं की कोई अन्य आपूर्ति, जिसे वह "कॉर्पोरेट देनदार के मूल्य की रक्षा और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण मानता है ... चालित उद्यम के रूप में" को भी संरक्षित किया जाएगा।¹¹ यह दृष्टिकोण यूके दिवाला अधिनियम 1986 की धारा 233 से 233B के समान है, जो

⁹ निगम विनियम 2001 (Cth) Reg 5.3A.50

¹⁰ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 की धारा 14(1)

¹¹ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 की धारा 14(2A)

इप्सो फैक्टो क्लॉज के प्रयोग पर सामान्य प्रतिबंध के बजाय आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की सुरक्षा पर केंद्रित है।

गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम अमित गुप्ता और अन्य (सिविल अपील संख्या 9241/2019) ("अमित गुप्ता") के फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का विभिन्न न्यायालयों के अधिकार क्षेत्रों में इप्सो फैक्टो क्लॉज से संबंधित व्यवस्थाओं की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के बाद का विचार था कि इप्सो फैक्टो क्लॉज की वैधता पर मुद्दों के समाधान के लिए असंख्य जटिल प्रश्नों के संतुलन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, इप्सो फैक्टो क्लॉज के प्रयोग पर किसी भी प्रतिबंध के संभावनाओं और दायरे पर बेहतर फैसला करने के लिए विधायिका पर छोड़ दिया गया था।

निष्कर्ष

50

आईआरडीए की धारा 440 के तहत ipso facto क्लॉज पर प्रतिबंधों की शुरुआत ने सिंगापुर में कानूनी और व्यावसायिक समुदायों का बहुत ध्यान आकर्षित किया है। आगे बढ़ते हुए, इस तरह के प्रतिबंध अनुबंधों के प्रारूपण को भी प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि पार्टियां धारा 440 के प्रभाव को दूर करने की कोशिश करती हैं, और संविदात्मक पार्टियों के बीच जोखिमों को फिर से आवंटित करने के तरीके ढूंढती हैं।

इप्सो फैक्टो फ्रेमवर्क की वैधानिक स्थापना सिंगापुर में पुनर्गठन और दिवाला कानून में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व करती है। सिंगापुर सरकार इप्सो फैक्टो क्लॉज द्वारा लाए गए पुनर्गठन प्रयासों के लिए अद्वितीय चुनौतियों से अच्छी तरह वाकिफ है, और कुछ परिस्थितियों में इप्सो फैक्टो क्लॉज के आवेदन की सीमा निर्धारित करने के लिए अग्रसर है जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अमित गुप्ता मामले में सही समुचित टिप्पणी कि है कि उकेटी विषयपर अलग-अलग और कभी-कभी परस्पर विरोधी विचार हैं कि क्या दिवालियापन के संदर्भ में संविदात्मक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए या नहीं। अंततः और यह विधायिका पर निर्भर है कि वह संतुलन बनाने का प्रयास करे।

सिंगापुर में इप्सो फैक्टो शासन अभी भी अपेक्षाकृत नया है। यह उम्मीद की जाती है कि मौजूदा मुद्दों और अनिश्चितताओं को भविष्य के केस लॉ (निर्णय विधि) में संबोधित किया जाएगा, जो सिंगापुर में इप्सो फैक्टो क्लॉज पर कानून को और विकसित करने का काम करेगा।

प्रौद्योगिकी सेवा आपूर्तिकर्ताओं के लिए दिवाला ढांचे का निर्माण: भारत और यूके से अनुभव

डॉ. नीति शिखा और रेबेका पैरी

प्रौद्योगिकी सेवा आपूर्तिकर्ताओं के लिए दिवाला ढांचे का निर्माण: भारत और यूके से अनुभव

डॉ. नीति शिखा, एसोसिएट डीन, इंडियनस्कूल लॉफ पब्लिक पॉलिसी

रेबेका पैर, प्रोफेसर नॉटिंघमलॉस्कूल

परिचय

आधुनिक समाज, विशेष रूप से कोविड-19 युग में, डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर अधिक से अधिक निर्भर होता जा रहा है और जीवन को रूपांतरित किया जा रहा है, उदाहरण के लिए अधिक सामाजिक समावेश, बेहतर व्यावसायिक अवसर, चिकित्सा में प्रगति और व्यापक शैक्षिक अवसर के द्वारा। भारत इन विकासों में सबसे आगे खड़ा है और उल्लेखनीय उपलब्धियों और महान संभावनाओं पर सही ही ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके बावजूद व्यवसाय और व्यक्ति सेवाओं के लिये जिन पर भरोसा करते हैं, वे कंपनियां हैं और जब ये दिवालिया हो जाती हैं तो ऐसे मामलों में समस्याएं अपरिहार्य हो जाती हैं। इस क्षेत्र में दिवाला होने से जटिल चुनौतियों और महत्वपूर्ण सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना होती है। फिर भी इस बात पर बहुत कम विचार किया गया है कि कानून कैसे स्थिरता का समर्थन कर सकता है, साथ ही दिवाला कानून सार्वजनिक हित में कैसे काम कर सकता है ताकि दिवाला के प्रभाव को कम किया जा सके। कानून और प्रौद्योगिकी के कटाव बिंदु पर स्थित, प्रस्तावित अंतःविषय और तुलनात्मक परियोजना भारत में प्रौद्योगिकी के उदय पर विचार करेगी, साथ ही विशेष रूप से दिवाला में इसे समर्थन देने में कानून की भूमिका के अनदेखे पहलुओं पर विचार करेगी और सतत सार्वजनिक सेवाओं के लिए यूके के दृष्टिकोण से गहरी पहुंच बनाएगी।

प्रौद्योगिकी सेवाओं का उदय

इक्कीसवीं सदी की दुनिया में सूचना प्रौद्योगिकी का उदय हुआ। भारत विश्व ध्यान के केंद्र में है और इसे पहले से ही ज्ञान शक्ति का भंडार माना जाता है। आईटी सेवाएं, आईटी-सक्षम सेवाएं, ई-

कॉमर्स, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सामग्री सभी आईटी क्षेत्र का हिस्सा हैं और ऐसी अंतर्निहित प्रौद्योगिकियां हैं जिनके अस्तित्व की व्यापक रूप से सराहना नहीं की जाती है। सूचना प्रौद्योगिकी ने न केवल देश की आर्थिक सफलता में योगदान दिया है, बल्कि इसने शासन प्रणाली को अधिक सक्षम और सुलभ बनाया है। इसने सरकारी सेवाओं और सूचनाओं को प्राप्त करने की लागत को सरल और कम कर दिया है। यह हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो इसे बड़े पैमाने पर विकसित करने और लाखों रोजगार प्रदान करने की अनुमति देती है। भारत में आईटी उद्योग के बाजार का आकार 2008-09 में लगभग 67 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2019-20 में 191 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।¹

नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम) और मैकिन्से ने 2015 में अनुमान लगाया था कि भारतीय प्रौद्योगिकी सेवा उद्योग 300-350 बिलियन डॉलर² का हो सकता है। 'फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज विनिंग इन दिस डिकेड' शीर्षक वाली रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अगर भारत क्लाउड, साइबर सुरक्षा, एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में आगे निकलता है, तो देश का आईटी सेवा उद्योग अगले पांच वर्षों में 2-4% तक बढ़ सकता है। आईटी उद्योग ने भी 2017-18 में भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8% का योगदान दिया है और 2019-20 में इसका योगदान 7.7% है।³

प्रौद्योगिकी का उपयोग सरकार द्वारा ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाकर और देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डिजिटल रूप से सशक्त बनाकर नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। भारत की आगामी नीति रचना इसकी तकनीकी आधार पर टिकी हुई है। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल आईडी कार्यक्रम, आधार विकसित किया है, जिसमें 1.2 बिलियन से अधिक लोग नामांकित हैं। ई-गवर्नेंस विकास के इस उल्लेखनीय उदाहरण की पहचान सरकारी सेवाओं के वितरण के लिए बढ़ी हुई संभावनाओं की पेशकश के रूप में की गई है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने और कर आधार को विस्तृत करने में सक्षम बनाने

¹ <https://diplomatist.com/2020/08/29/it-industry-boosting-indias-growth/>

² https://www.business-standard.com/article/companies/indian-tech-services-can-touch-revenues-of-300-350-bn-in-next-5-years-121033101271_1.html

³ आईबीईएफ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
<https://diplomatist.com/2020/08/29/it-industry-boosting-indias-growth/>

के रूप में भी पहचाना गया है।⁴ इसने सामाजिक समावेश को बढ़ावा दिया है, साथ ही उन लोगों तक पहुंच गया है जिनकी पहले बैंक खातों⁵ तक पहुंच नहीं थी। सार्वजनिक स्वास्थ्य के संदर्भ में भी इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन सुरक्षित हैं और कोविड-19 महामारी के जवाब में मौजूदा औपचारिकताओं के स्थान पर इसका तेजी से उपयोग किया जा रहा है, उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर भारतीय कानून⁶ के तहत मान्य हैं और लिखने के किसी भी औपचारिकता का वैध रूप से अनुपालन इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकता है।⁷

प्रौद्योगिकी के इस प्रवेश ने प्रौद्योगिकी कंपनियों और उनके व्यवसाय करने में आसानी के महत्व को बढ़ा दिया है। व्यापार वृद्धि और सेवाओं के निर्यात प्रावधान के अवसरों से अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ है। डिजिटलीकरण के लाभ व्यावसायिक दृष्टिकोण से आकर्षक हैं क्योंकि वे वित्त तक पहुंच को बेहतर और लेनदेन की लागत को कम करने में सक्षम हैं।⁸ उन्हें पहले से ही सफलताएं मिली हैं और डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत में बढ़ती समृद्धि में योगदान दे रही है। उद्यमियों ने समान अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीनी व्यवसायों की तुलना में स्टार्ट-अप परियोजनाओं के लिए रिकॉर्ड मात्रा में धन प्राप्त किया है।⁹ विकास आईटी कंपनियों के आसान प्रवेश और निकास की आवश्यकता पर जोर देता है जो इसके विकास को बढ़ावा दे सकते हैं और प्रतिस्पर्धी बाजारों की प्राकृतिक रचनात्मक विनाश प्रक्रियाओं का दोहन कर सकते हैं। व्यवसाय कानून के एक बड़े ढांचे के भीतर काम करते हैं और नए कठोर और नरम कानून दृष्टिकोण विकसित करते समय, प्रौद्योगिकी क्षेत्र मौजूदा कानूनों के लिए नई चुनौतियां पेश करता है और

⁴ बी. रमीजा, 'इंडियन डिजिटल इकोनॉमी: अपॉर्च्युनिटीज एंड चैलेंजेज' (2018) 10 इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करेंट रिसर्च 74338, <https://www.journalcra.com/article/indian-digital-economy-%E2%80%93-opportunities-and-challenges> पर उपलब्ध है।

⁵ के.आर. बाबू, ए.बी. सागर, पी. कोठारी (2020) सोशल इनक्लुशन एंड ई-गवर्नेंस: ए केस सस्टडी इन अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट. एस. रौतरे, जी. आइक्लर, सी. एरफुर्थ, जी. फाहरनबर्गर (इड्स) इनोवेशन फॉर कम्युनिटी सर्विसेज. 14CS 2020. कम्युनिकेशन इन कंप्यूटर एंड इनफॉर्मेशन साइंस, वॉल्यूम 1139. स्प्रिंगर, चैम. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37484-6_16. अंतराल की पहचान करने वाले अध्ययन के लिए अनुषा गोयल का, ऐन इम्पीरिकल स्टडी ऑफ जन धन - आधार - मोबाइल ट्रिनिटी एंड फाइनेंशियल इनक्लुशन देखें। (2020) 8 इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बैंकिंग, रिस्क एंड इश्योरेंस 62-79, SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3603272> पर उपलब्ध।

⁶ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, धारा 3, जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा संशोधित किया गया है।

⁷ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, एसएस 4-10.

⁸ लेओरा क्लैपर, "हाऊ डिजिटल पेमेंट्स कैन बेनिफिट इंटरप्रेन्योर्स " आईजेडए वर्ल्ड ऑफ लेबर 2017:396 <https://wol.iza.org/uploads/articles/396/pdfs/how-digital-payments-can-benefit-entrepreneurs.pdf? v=1>.

⁹ बेंजामिन पार्किन एंड मर्सिडीज रूहल, "चाइनीज इनवेस्टर्स मिस आउट ऑन रिकॉर्ड इयर फॉर इंडियन टेक फंडरेजिंग " फाइनेंशियल टाइम्स 12 जुलाई 2021, <https://www.ft.com/content/94ad2e3e-e2f0-4333-b105-c980cddb212b>

कुछ को अद्यतन करने के लिए एक परिस्थिति उत्पन्न करता है। सेवा आपूर्तिकर्ता द्वारा वित्तीय संकट का सामना करने की स्थिति में व्यवसायों की स्थिरता का समर्थन करने और ग्राहकों की रक्षा करने के लिए कानून की आवश्यकता की विशेष रूप से उपेक्षा की गई है।

आर्थिक विकास के लिए कानून का शासन महत्वपूर्ण है। एक आधुनिक राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि संपत्ति और अनुबंध अधिकारों के संरक्षण पर केंद्रित एक मामूली कानूनी बुनियादी ढांचे के साथ शुरू होती है।¹⁰ उस बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए आवश्यक कानूनी सुधार अपेक्षाकृत सटीक कानूनी नियमों की प्रणाली को अपनाया जा सकता है, जो कि अधिक खुले मानकों या देश की न्यायपालिका के उन्नयन में भारी निवेश से अलग है।¹¹ जबकि भारत में एक विकसित कानूनी प्रणाली है, न्यायिक अवसंरचना अभी भी खराब है। इसके अलावा, हालांकि भारत में दिवाला कानूनों को क्षेत्र संशयवादी माना जाता है, मौजूदा दिवाला ढांचे में अंतर्निहित चुनौती है जो प्रौद्योगिकी दिवाला से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस पृष्ठभूमि में, इस पेपर में आगे के विकास के लिए एक अन्य संभावित आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया है, अर्थात् एक स्थायी तरीके से आधुनिक, डिजिटल-सेवा केंद्रित प्रवृत्तियों के लिए आवश्यक कानूनी ढांचा। लेकिन इससे पहले, आइए इस बात पर विचार करें कि कैसे इस क्षेत्र ने महामारी के बाद व्यापार करने के तरीके को बदल दिया है और इस तरह यूके और भारत दोनों के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं।

भारत और ब्रिटेन के लिए संभावनाएं

महामारी ने हमारे व्यापार करने के तरीके को बदल दिया है; दुनिया भर की सरकारों और उद्योग ने स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था में व्यापक चुनौतियों का समाधान करने के लिए कोविड-19 से संबंधित डेटा साझा करने में सहयोग किया है; परिणामस्वरूप, इस तरह की द्विपक्षीय चर्चाओं में डेटा तक पहुंच और साझा करने से प्राप्त सबक और प्राप्त लाभों को शामिल करना महत्वपूर्ण है। क्रॉस-बॉर्डर डेटा ट्रांसफर सभी क्षेत्रों में नवाचार और नौकरी की वृद्धि को सक्षम बनाता है। सेवाओं की सुरक्षा जो इसे सक्षम करती है, व्यवसायों को सुदूर से काम करते हुए लचीला और उत्पादक बनने में मदद करती है और वैश्विक आरएंडडी और नैदानिक परीक्षण डेटा तक पहुंच में सुधार करती है। क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर में अभिनव प्रौद्योगिकियों तक पहुंच और वैश्विक आपूर्ति

¹⁰ रिचर्ड पॉस्नर क्रिएटिंग ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट

<https://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1093/wbro/13.1.1>. अंतिम बार 30 नवंबर 2021 को एक्सेस किया गया।

¹¹ ibid

श्रृंखलाओं में भागीदारी के साथ-साथ विभिन्न संस्थाओं में इन्वेंट्री, बिक्री, मांग पूर्वानुमान, ऑर्डर की स्थिति, उत्पादन कार्यक्रम आदि पर वास्तविक समय में डेटा स्थानांतरित कर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की क्षमता है। ।

यूके और भारत ने हाल ही में 2030 तक व्यापार को दोगुना करने के लिए 10 वर्ष के रोडमैप के हिस्से के रूप में एक बढ़ी हुई व्यापार साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता की और यूके-भारत मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत करने के अपने उद्देश्य जाहिर किए।¹² इससे यूके और भारत के बीच डिजिटल व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। यह भारत-यूके प्रौद्योगिकी व्यापार एक दूसरे की ताकत का पूरक होगा। प्रौद्योगिकी कूटनीति¹³ की बदौलत, भारत अपनी तकनीकी प्रतिभा से एआई, स्वच्छ विकास और बीच में भविष्य की गतिशीलता पर यूके की यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद की ताकत को पूरा कर सकता है। भारत मोदी की प्रमुख आयुष्मान भारत योजना को यूके की हेल्थकेयर एआई कंपनियों से जोड़कर अपनी ताकत से खेल सकता है, ब्रिटेन के तकनीक, आर्थिक और रोजगार सृजन के साथ भारत के प्रतिस्पर्धी संघवाद का लाभ उठाकर उत्तरी पावरहाउस और मिडलैंड्स इंजन जैसे क्षेत्रों में काम कर सकता है।

चूंकि व्यापार, विशेष रूप से, दोनों देशों में डिजिटल व्यापार बढ़ रहा है, अतः इसने दोनों देशों के लिए कई नए अवसर खोले हैं। यह संबंध अर्थव्यवस्था और लोगों को और मजबूत और सुरक्षित बनाएंगे। 2009 और 2019 के बीच टेक निवेश सौदों के साथ, लंदन में भारतीय निवेश 523 मिलियन पाउंड से अधिक का था, जिसमें 22 भारतीय कंपनियों द्वारा 36 परियोजनाएं शामिल थीं, जिससे नौकरियों, अर्थव्यवस्था, यात्रा, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी में वृद्धि हुई।¹⁴ इंसोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एम्फेसिस, विप्रो जैसी टेक कंपनियों ने यूके में 3000 से अधिक नौकरियां पैदा कीं।¹⁵

इसी प्रकार, लंदन टेक कंपनियों के लिए भारत शीर्ष 5 स्थानों में से एक है जो यूके के बाहर विस्तार करना चाह रहे हैं। यह प्रौद्योगिकी के लिए चौथा सबसे बड़ा बाजार है और विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी स्टार्ट-अप अर्थव्यवस्था है।¹⁶ पूरे काम से निवेश, विशेष रूप से यूके से भारतीय तकनीकी

¹² <https://www.financialexpress.com/opinion/india-uk-fta-talks-should-champion-digital-trade/2362151/>

¹³ <https://www.ukibc.com/blog-digital-trade-an-important-element-of-uk-india-fta/>

¹⁴ <https://economictimes.indiatimes.com/tech/ites/india-among-top-destinations-for-london-tech-firms-report/articleshow/69726058.cms?from=mdr>

¹⁵ <https://www.uktech.news/news/uk-india-trade-deal-20210505>

¹⁶ <https://inc42.com/resources/the-uk-will-be-a-co-star-in-indias-tech-blockbuster/>

स्टार्ट-अप और कंपनियों में आ रहा है। हाल ही में, इंटरप्रिन्योर फर्स्ट (ईएफ), जो यूके स्थित वैश्विक कौशल निवेशक है, ने भारत से 6 टेक स्टार्ट-अप में निवेश की घोषणा की है।¹⁷

एचएमजी का भारत नेटवर्क, जो दुनिया का सबसे बड़ा और व्यावसायिक रूप से कुशल नेटवर्क है, ने गारंटी दी है कि ओला, ओयो रूम्स, टेक महिंद्रा और फर्स्टसोर्स जैसे घरेलू नामों ने यूके को अपने होम-फ्रॉम-होम के रूप में चुना है, जिसके परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में हजारों रोजगारों का सृजन हुआ है। उन्होंने यूके को इसलिए चुना क्योंकि यह डिजिटल व्यवसाय के लिए दुनिया में सर्वोत्तम जगह है, जिसमें कौशल, नवाचार, आरएंडडी और जोखिम पूंजी की असमानांतर पहुंच है।¹⁸

दोनों सरकारों को एफटीए के माध्यम से एक साथ काम करना चाहिए ताकि नैतिक मूल्यों के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण स्थापित किया जा सके, जो निष्पक्षता, जवाबदेही, स्थिरता और पारदर्शिता जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत सिद्धांतों के निर्माण पर आधारित है। यह प्रस्तावित किया गया है कि कानून को स्थिरता के पहलू और विशेष रूप से विफलता की रोकथाम में कॉर्पोरेट शासन की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, साथ ही साथ वित्तीय संकट को हल करने में दिवालिया कानून की भूमिका भी होनी चाहिए। ग्राहकों की निर्भरता और सेवा की निरंतरता की आवश्यकता को देखते हुए डिजिटल सेवा दिवालियापन कठिन चुनौतियां पेश करता है। इस पेपर में इस बात पर विचार किया गया है कि इन पहलुओं को कैसे संबोधित किया जा सकता है।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव - टेक कंपनियों का दिवाला

57

दुनिया भर में डिजिटल अर्थव्यवस्था के तेजी से उदय को देखते हुए, और इस तथ्य को देखते हुए कि अधिकांश भारतीय व्यवसाय प्रौद्योगिकी समर्थन पर केंद्रित है, दिवाला टेक कंपनियों और तकनीकी सेवा प्रदाताओं के प्रभाव पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। दिवाला कानून पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है, इसकी जांच करने से पहले यह भाग डिजिटल सेवाओं की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालेगा।

- आसान पहुंच: मौजूदा सेवाओं को और अधिक सहायक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी एक माध्यम के रूप में कार्य करती है। उदाहरण के लिए, ग्राहक इंटरनेट-आधारित बिल भुगतान सेवा की सुविधा से लाभान्वित होते हैं। कारों में मैप और रूटिंग सॉफ्टवेयर

¹⁷ <https://www.outlookindia.com/website/amp/entrepreneur-first-announces-investment-in-six-indian-tech-start-ups/396147>

¹⁸ <https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/startups/newsbuzz/india-the-uk-its-a-lot-more-than-cricket/articleshow/69986624.cms?from=mdr>

इंस्टॉल किया जाता है, जो ड्राइवों को मार्ग बताता है। एक क्लिक पर, किराने का सामान हमारे दरवाजे पर पहुंचा दिया जाता है।

- डेटा/सेवाओं की वैश्विक पहुंच: इंटरनेट एक बड़ी सेवा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सूचना, सेवाएं, लेनदेन पूरे देश में पहुंच सकते हैं। दुनिया भर में रहने वाले ग्राहकों के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित सेवा का विस्तार किया जा सकता है।
- रोजगार सृजन: जैसे-जैसे आईटी उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, यह अधिक से अधिक रोजगार पैदा कर रहा है।
- ग्राहकों के साथ घनिष्ठ संबंध: ग्राहक और कर्मचारी दोनों सेवा प्राप्त करने और प्रदान करने के मामले में प्रौद्योगिकी से लाभ उठा सकते हैं। ग्राहक संबंध प्रबंधन और बिक्री सहायता सॉफ्टवेयर बेहतर सेवा प्रदान करने में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की सहायता करते हैं।

उपरोक्त तथ्य प्रौद्योगिकी उद्योग के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। आईटी सेवा कंपनियां अन्य व्यवसायों को ऑन-डिमांड सेवा सेवाएं प्रदान करती हैं। कई व्यवसाय अपने स्वयं के आईटी विभाग के बजाय इन कंपनियों को आउटसोर्स करते हैं क्योंकि यह लागत दक्षता में मदद करता है। साइबर सुरक्षा सभी व्यवसायों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। अतः संभावित खतरों का मूल्यांकन और प्रतिक्रिया करना बहुत सारे आईटी व्यवसायों के लिए एक लोकप्रिय सेवा है। डेटाबेस वह प्रणाली है जिसका उपयोग व्यवसाय पूरे जीवनचक्र में अपने डेटा की निगरानी और प्रयोग करने के लिए करता है।¹⁹ विभिन्न कंपनियों को आईटी सेवाएं प्रदान करने वाली टेक कंपनियों का अर्थव्यवस्था और इससे जुड़े कई अन्य व्यवसायों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। सेवाओं में व्यवधान आने की स्थिति में कई कंपनियों की सेवाएं और कामकाज ठप हो जाएगा।

आईटी उद्योग विभिन्न कानूनों के माध्यम से शासित होता है और इस प्रकार कई कानूनी चुनौतियों का सामना करता है, जो डेटा ट्रांसफर, बौद्धिक संपदा मुद्दों, कर निहितार्थ, डेटा सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि से सम्बंधित होता है।

तकनीकी सेवाओं में आर्थिक चुनौतियां

चूंकि तकनीकी सेवाओं की लोकप्रियता बढ़ रही है, जैसे डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉक-चेन में काम करने वाले स्टार्ट-अप, जिससे उल्लेखनीय सफलताएँ मिली हैं। कुछ ने फंडिंग प्राप्त करने के साथ-साथ फेसबुक, ऐप्पल और गूगल जैसे वैश्विक तकनीकी प्लेटफार्मों द्वारा अधिग्रहित किए जाने के लिए सुर्खियां बटोरीं। भारतीय छोटी और मध्यम फर्मों,

¹⁹ <https://smallbiztrends.com/2018/08/types-of-it-services.html#comments>

जिन्हें विमुद्रीकरण और जीएसटी कार्यान्वयन के दोहरे झटकों के परिणामस्वरूप व्यापार के संचालन के ऑनलाइन, हमेशा जुड़े हुए तरीकों के अनुकूल होने के लिए प्रेरित किया गया है, की तकनीकी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसमें और भी बड़ी विकास क्षमता है। जैसे-जैसे ये कंपनियां अपने दैनिक कार्यों में प्रौद्योगिकी को शामिल करने में अधिक सहज हो जाएंगी, भारतीय तकनीकी फर्मों के लिए एक बड़ा अवसर खुल जाएगा।

हालांकि, बाजार का माहौल भारतीय टेक कंपनियों के लिए अनुकूल प्रतीत होता है, लेकिन आमतौर पर सुखियों के पीछे भारी मुश्किलें छिपी रहती हैं। जैसा कि दुनिया ने एक महामारी का सामना किया है, व्यापक चिंता और आर्थिक कठिनाइयां सामने आई हैं। टेक उद्योग को बढ़ावा मिला है, क्योंकि सभी कार्य ऑनलाइन हो गए हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

तकनीकी सेवा प्रदाता कंपनी हैकिंग, कुप्रबंधन, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दों, आर्थिक कठिनाइयों के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं के कारण समस्याओं का सामना कर सकती है, जिससे वित्तीय कठिनाइयों के साथ-साथ दिवाला भी हो सकता है।

हाल के वर्षों में साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण हो गई है। कई फर्मों के लिए डेटा सबसे कीमती वस्तु बन गया है, और मॉलवेयर जैसी आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। डेटा अतिक्रमण की घटनाएं आम होती जा रही हैं। व्यापार निरंतरता और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा बनाए रखने के लिए, आईटी व्यवसाय अपने साइबर सुरक्षा प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं। साइबर सुरक्षा जोखिम में वृद्धि हुई क्योंकि अधिक लोग सुदूर से काम कर रहे हैं।

प्रौद्योगिकी हमारे लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त करने में मदद करती है, व्यापार करने की सुविधा, उत्पादकता को बढ़ावा देती है, लेकिन यह केवल तब तक ही अच्छा है जब तक इसके उपयोग का प्रबंधन करें। एक शोध के अनुसार, 93 प्रतिशत व्यवसाय अपने आईटी कर्मचारियों में कौशल अंतर की रिपोर्ट करते हैं,²⁰ जो आवश्यक और मौजूदा कौशल समूह के बीच एक बेमेल का संकेत देता है। इससे पहले कि वे नवाचार और नई तकनीकों का उपयोग कर सकें, आईटी अधिकारियों को, सीआईओ से शुरू, उपकरणों को बढ़ाने के लिए आईटी टीम के लिए आवश्यक प्रतिभा को

²⁰[https://www.comptia.org/content/research/state-of-the-it-skills-gap?utm_source=blog&utm_medium=incopy&utm_campaign=Top IT Issues](https://www.comptia.org/content/research/state-of-the-it-skills-gap?utm_source=blog&utm_medium=incopy&utm_campaign=Top%20IT%20Issues)

शामिल करना चाहिए। जब आईटी रणनीति समग्र व्यावसायिक रणनीति में अधिक एकीकृत हो जाती है, तकनीकी प्रतिभा में निवेश करना आपकी कंपनी के दीर्घकालिक लक्ष्यों में एक निवेश है।

प्रत्येक वर्ष, वरिष्ठ लोगों और जटिल सॉफ्टवेयर सिस्टम तक पहुंच की कमी के कारण सॉफ्टवेयर विकास उत्पादकता में लगभग \$ 300 बिलियन का नुकसान होता है।²¹ इसका तकनीकी अधिकारियों और उनके व्यवसायों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर वितरण की सीमांत लागत बढ़ जाती है। यह समझना कि कैसे स्वचालन उनकी टीमों को बड़े पैमाने पर बेहतर सॉफ्टवेयर देने में मदद कर सकता है, तकनीकी लीडर के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या है।

लॉकडाउन के कारण, भारत में आईटी कंपनियों को अपने कर्मियों को दूरस्थ-कार्य वातावरण में काम करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कंपनियों ने सैकड़ों हजारों श्रमिकों को कंप्यूटर देने, कम इंटरनेट बैंडविड्थ पर काबू पाने और घर से काम करने की अनुमति देने के लिए ग्राहक प्राधिकार प्राप्त करने के लिए जल्दबाजी की, जो पहले सुरक्षा चिंताओं के कारण प्रतिबंधित था।²²

22 उद्योगों में 20 देशों में 3,450 अधिकारियों के सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार, कॉर्पोरेट प्राथमिकताएं दो वर्ष पहले की तुलना में संकट प्रबंधन, कार्यस्थल सुरक्षा और सुरक्षा पर अधिक केंद्रित हैं। साइबर सुरक्षा की चिंताएं भी तेजी से बढ़ रही हैं, कुछ उद्योगों में 90% से अधिक की बढ़ी हुई प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर, 76% अधिकारी अगले दो वर्षों में साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देने की योजना बना रहे हैं, साथ ही 46% एक ही समय सीमा में साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एआई का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। यह आज की तैनात तकनीक से दोगुना है।²³

टेक कंपनियों के लिए दिवाला ढांचा

महामारी, बाजार की स्थितियों और अन्य जोखिमों के कारण, इन तकनीकी सेवा आपूर्तिकर्ता कंपनियों को व्यावसायिक विफलता के जोखिम का सामना करना पड़ता है। जब टेक कंपनी / सेवा प्रदाता वित्तीय कठिनाइयों में पड़ जाता है, और अपने ऋणों का भुगतान करने में सक्षम नहीं होता है, तो इसे या तो परिसमापन किया जा सकता है या पुनर्जीवित (पुनर्गठन) किया जा सकता है।

²¹ <https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/09/03/12-tech-leaders-on-the-biggest-challenges-facing-their-industry/?sh=6cd918de1bce>

²² <https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/global-hr/pages/coronavirus-india-it-challenges.aspx>

²³ <https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/covid-19-future-business>

बाहर निकलने की प्रक्रियाएं उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि व्यवसायों के लिए स्टार्ट-अप प्रक्रियाएं। गैर-लाभकारी उद्यमों को बंद करने और नए शुरू करने में उद्यमियों की सहायता के लिए दुनिया भर में दिवाला कार्यवाही का उपयोग किया जाता है। दिवाला कानून समाज को कंपनी की विफलताओं को समझने के तरीके को बदल रहा है क्योंकि यह बाहर निकलने की स्वतंत्रता के लिए एक जबरदस्त असंतुष्ट भूख से प्रेरित, उनके लिए, और हितधारकों के लिए एक सुधार बन जाता है

एक प्रौद्योगिकी कंपनी के कई पहलू हैं, वे अन्य कंपनियों को सेवा प्रदान करने में शामिल हो सकते हैं, या विपणन संबंधी गतिविधियों से जुड़ सकते हैं आदि। क्लाउड सेवाएं प्रदान करना एक अन्य गतिविधि है जिसमें वे शामिल हो सकते हैं। क्लाउड सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा का प्रावधान एक ऐसी चीज है जिसे संभावित रूप से विभिन्न न्यायालयों द्वारा बेहतर ढंग से संबोधित किया जा सकता है। डिजिटल अर्थव्यवस्थाएं महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकती हैं और विकासशील देशों सहित कई देश इस पर निर्माण कर रहे हैं। एक कानूनी ढांचा जो दिवाला की स्थिति में डेटा की सुरक्षा और सेवा की निरंतरता प्रदान कर सकता है, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं के विकास का समर्थन कर सकता है, क्योंकि यह क्लाउड सेवा प्रदाताओं को आकर्षित कर सकता है जो तब ग्राहकों को विश्वास दिला सकता है कि सेवाओं और सामग्री का अचानक और विनाशकारी नुकसान नहीं होगा। क्लाउड सेवा प्रदाताओं के लिए एक विशेष प्रक्रिया, प्रबंधित क्लोजडाउन को सक्षम करना, एक संभावना होगी।

क्लाउड कंप्यूटिंग दिवाला के मौजूदा प्रावधान का एक उदाहरण लक्ज़मबर्ग कोड डी कॉमर्स का अनुच्छेद 567 है। जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, इस कानून ने देनदार के दिवाला होने पर देनदारों को सौंपे गए सामानों की वसूली को सक्षम किया और 2012 में क्लाउड कंप्यूटिंग के बढ़ते महत्व की मान्यता में सॉफ्टवेयर जैसे अमूर्त संपत्ति को शामिल करने के लिए इसे बढ़ाया गया। ऐसा कानून अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि क्लाउड सेवा प्रदाता के दिवाला होने की स्थिति में सामग्री को पुनर्प्राप्त करने का अधिकार होना केवल एक समस्या है और सामग्री की पुनर्प्राप्ति को सक्षम करने के लिए सेवा की अस्थायी निरंतरता की भी आवश्यकता है।

विशिष्ट प्रावधानों के अभाव में, क्लाउड कंप्यूटिंग इनसॉल्वेंसी को हल करना मुश्किल हो सकता है। जब क्लाउड प्रदाता शोधन अक्षमता की कार्यवाही के अधीन हो जाता है तो डेटा का क्या होता है? क्या शोधन अक्षमता के मामले की शुरुआत में लगाया गया स्वतः ठहराव क्लाउड प्रदाताओं, जो

डेटा होस्ट करते हैं, के ग्राहकों को अपने डेटा तक पहुंचने या पुनर्प्राप्त करने से रोकता है? यह एक शैक्षिक प्रश्न नहीं है - क्लाउड प्रदाताओं के कई हालिया उदाहरण हैं जो विफलता के निकट हैं।

अधिकांश क्षेत्राधिकार में, शोधन अक्षमता के लिए याचिका दायर करने से स्वतः रोक लग जाती है जो देनदार के खिलाफ की गई सभी प्रतिकूल कार्रवाइयों को प्रतिबंधित करती है। अमेरिकी कानूनों के तहत, शोधन अक्षमता संहिता की धारा 362 (ए) के तहत इसके लिए प्रावधान है। भारतीय दिवाला संहिता की धारा 14 समान राहत प्रदान करती है। जब कोई कंपनी अध्याय 7 के तहत शोधन अक्षमता के लिए दायर करती है, तो व्यवसाय के सभी प्रबंधन शेरधारकों या बोर्ड (निगम के साथ) या उसके सदस्यों और प्रबंधकों (सीमित देयता कंपनी या साझेदारी के साथ) से नियुक्त अध्याय 7 ट्रस्टी के पास स्थानांतरित हो जाते हैं, जो देनदार की संपत्ति पर नियंत्रण रखता है।

अध्याय 11 के मामले में, देनदार आम तौर पर अपनी संपत्ति के नियंत्रण में रहता है। तब सवाल यह है कि क्या शोधन अक्षमता संहिता की धारा 541 के तहत डेटा "एस्टेट की संपत्ति" है, या क्या डेटा उपयोगकर्ताओं या ग्राहकों से संबंधित है? यदि डेटा एस्टेट की संपत्ति है, तो स्वचालित रोक पहले स्वचालित रोक से राहत मांगे बिना डेटा पर नियंत्रण प्राप्त करने के किसी भी प्रयास को प्रतिबंधित करता है। क्लाउड प्रदाता के साथ, ग्राहक अपने डेटा तक पहुंच जारी रखना चाहते हैं।

हालांकि, अगर देनदार डेटा या जानकारी का "मालिक" है, तो शोधन अक्षमता की स्थिति में डेटा का क्या होता है? भले ही स्वामित्व स्थापित हो गया हो, ग्राहक डेटा पुनर्प्राप्त करते समय और वैकल्पिक व्यवस्था करते समय क्लाउड सेवा को कैसे चालू रखा जा सकता है? व्यवसाय को अस्थायी रूप से चालू रखना लेनदारों के हितों के साथ एक तनाव प्रस्तुत करता है, जो चाहते हैं कि मामले को जल्दी और बिना खर्च के हल किया जाए। इस प्रकार, एक प्रौद्योगिकी कंपनी के दिवाला होने की स्थिति में कई चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। ये चुनौतियाँ न केवल उस प्रक्रिया तक सीमित हैं जिसे दिवाला कानून अपनाता है, बल्कि ऐसे कानून भी हैं जो दिवाला कानूनों के दायरे से बाहर आते हैं।

यह उम्मीद की जा सकती है कि डिजिटल सेवा उपयोगकर्ता दिवाला पहलुओं को संबोधित करने के लिए अपने अनुबंधों में प्रावधान करेंगे। पूरी तरह से वित्तीय परिश्रम करना, जिसमें ग्राहकों की एकाग्रता से प्रदाता को जोखिम का आकलन करना और पूंजी तक पहुंचने की उसकी क्षमता शामिल है, ऐसा ही एक तरीका हो सकता है। अनुबंध की शर्तें यह प्रदान कर सकती हैं कि होस्ट को डेटा की डिलीवरी स्वामित्व के किसी भी तत्व को स्थानांतरित नहीं करती है; और, ग्राहक और डेटा होस्ट के बीच, ग्राहक डेटा में सभी अधिकार, शीर्षक और रुचि बरकरार रखता है। यह स्पष्ट करना चाहिए

कि डेटा के संबंध में प्रदाता की भूमिका होस्टिंग सेवाएं प्रदान करने के अपने दायित्व को पूरा करने के लिए स्टोरेज फ़ंक्शन तक सीमित है, और प्रदाता ग्राहक की पहुंच में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सही मायने में, प्रदाता डेटा के संबंध में "किराया के लिए जमानतदार" है (अर्थात, एक व्यक्ति को संपत्ति को जमानत के रूप में रखने के लिए मुआवजा दिया जाता है)।

एक बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि अनुबंध उन संभावित मुद्दों को संबोधित करे जो दिवाला के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं। अनुबंध किसी प्रदाता के शोधन अक्षमता या आपदा वसूली योजना में विफलता से डेटा तक पहुंच में संभावित नुकसान या रुकावट को प्राकृतिक आपदा के समान ही संबोधित कर सकता है। हालांकि, प्रदान किया गया कोई भी नुकसान असुरक्षित आधार पर होगा और इसलिए दिवाला में किसी भी मूल्य के होने की संभावना नहीं है। व्यवसाय की रुकावटों से सुरक्षा प्रदान करने वाले बीमा की खोज करने से नुकसान कम होगा और ग्राहक को डेटा उपलब्ध कराने में प्रदाता की अक्षमता से भी बचाया जा सकेगा।

यूएस अध्याय 11 के तहत, देनदार अभी भी व्यवसाय में है और काम करना जारी रखता है, इसलिए व्यवसाय को बाधित करने के किसी भी प्रयास को प्रतिकूल रूप से देखा जाएगा। यह एक ऐसा उदाहरण है जहां क्षमा के बजाय "अनुमति मांगना" बेहतर हो सकता है, और स्वचालित रोक से राहत की मांग की जा सकती है, भले ही डेटा तकनीकी रूप से "भूसंपत्ति की संपत्ति" न हो।

अध्याय 11 मामले के दौरान, अनुबंध के निपटान पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि शोधन अक्षमता संहिता की धारा 363 के तहत देनदार की संपत्ति की बिक्री होती है, तो अनुबंध माना जा सकता है और धारा 365 के तहत संपत्ति के खरीदार को सौंपा जा सकता है। हालांकि, निष्पादन अनुबंधों को "मान लेने और सौंपने" की क्षमता को नियंत्रित करने वाले नियम करते हैं पेटेंट और कॉपीराइट लाइसेंस तक विस्तारित नहीं है। अतः, बौद्धिक संपदा वकीलों से भी परामर्श किया जाना चाहिए।

शोधन अक्षमता के मामले में डेटा गोपनीयता भी एक मुद्दा बन सकता है जब व्यावसायिक संपत्ति बेची जा रही हो और उन संपत्तियों में निजी उपभोक्ता डेटा शामिल हो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स तकनीक का उपयोग करने वाली संपत्तियां विशेष कठिनाइयां खड़ी कर सकती हैं। शोधन अक्षमता की बिक्री में निजी उपभोक्ता डेटा की बिक्री को लेकर कई न्यायालय चिंतित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, धारा 332 अदालत के समक्ष उपभोक्ता के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए "उपभोक्ता गोपनीयता लोकपाल" की नियुक्ति की अनुमति देता है।

शोधन अक्षमता अदालत यू.एस. ट्रस्टी को एक "अपक्षपाती" व्यक्ति नियुक्त करने का आदेश दे सकती है जो उपभोक्ता गोपनीयता लोकपाल के रूप में कार्य कर सकता है। ये व्यक्ति अदालत को आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। इस जानकारी में देनदार की गोपनीयता नीति, उपभोक्ताओं को संभावित नुकसान या गोपनीयता का लाभ शामिल हो सकता है यदि बिक्री को अदालत द्वारा अनुमोदित किया जाता है, उपभोक्ताओं को संभावित लागत यदि बिक्री अदालत द्वारा अनुमोदित है; और संभावित विकल्प जो उपभोक्ताओं को संभावित गोपनीयता हानियों या गोपनीयता लागतों को कम करेंगे।

शोधन अक्षमता की स्थिति में, लेनदारों के अंतिम लाभ के लिए देनदार की संपत्ति की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, हालांकि डिजिटल सेवा दिवाला में ग्राहकों को अचानक बंद होने की स्थिति में बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रौद्योगिकी कंपनियों के ग्राहक किस हद तक पूरी तरह से झड़प से बाहर रह सकते हैं या सावधानीपूर्वक योजना और कानून की सहायता से जल्दी से बच सकते हैं, इसकी एक सीमा है। कानूनी ढांचे को ग्राहकों को अधिक से अधिक आश्वासन प्रदान करने की आवश्यकता है कि उनके डेटा और व्यावसायिक प्रक्रियाओं की रक्षा की जाएगी। लेकिन यूके और भारत दोनों को एक ऐसा ढांचा तैयार करने की जरूरत है जो अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान करे।

भारत के लिए आगे की राह

हाल ही में कुछ फिनटेक कंपनियां परिसमापन का सामना कर रही हैं। रूबिक टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी फिनटेक कंपनी जो वर्तमान में लिक्विडेशन में जा रही है। वेतन का भुगतान न करने पर IBC की धारा 9 के तहत याचिका लाया गया था। टीएमडब्ल्यू फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के एक अन्य मामले में, एक वॉलेट स्टार्ट-अप कंपनी जिसने एमसीटी कार्ड्स एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से बायोमेट्रिक पहचान और भुगतान सुविधा के लिए सिम कार्ड और स्मार्ट कार्ड के सामान खरीदे, सीआईआरपी में चले गए। 2019 में, एमसीटी कार्ड्स (ऑपरेशनल क्रेडिटर) टीडब्ल्यूएम फिनटेक (कॉर्पोरेट देनदार) को ऋण के पुनर्भुगतान में चूक के लिए एनसीएलटी में ले गए और इसके परिसमापन के लिए दबाव डाला।

न्यायालय ने कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ याचिका को मंजूर कर लिया। जहां दोनों मामले अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं, वहीं प्रौद्योगिकी कंपनियों के दिवाला होने का सवाल अब हकीकत बन गया है। ऐसी कंपनियों की अनूठी प्रकृति को कानून द्वारा मान्यता देने की आवश्यकता है और भारत में दिवाला कानूनों को चुनौती का सामना करने के लिए कदम बढ़ाना होगा। इसके अलावा,

संकटग्रस्त तकनीकी कंपनियों के लिए बिक्री को डिजाइन करने के कई नए तरीके हैं जैसे "एक्वी-हायर" - लाइसेंस और छूट, लेनदारों के लाभ के लिए असाइनमेंट आदि जो अन्य कंपनियों में सामान्य अभ्यास नहीं हैं। समाधान योजना तैयार करते समय इस तरह की नवीन प्रथाओं को अपनाने की अनुमति देने के लिए कानून को लचीला बनाए रखने की आवश्यकता है।

तकनीकी कंपनियों के दिवाला होने की कुछ चुनौतियों में संपत्ति का मूल्यांकन, डेटा के स्वामित्व का निर्धारण, डेटा की सुरक्षा और तीसरे पक्ष के अधिकार शामिल हैं। साथ ही, ऐसी कंपनियों की संपत्ति पर रोक से संबंधित कंपनियों के कारोबार के लिए खतरा पैदा हो सकता है, जिनके लिए प्रौद्योगिकी कंपनी सेवाएं दे रही थी।

हालांकि सभी चुनौतियों को सूचीबद्ध करना संभव नहीं है, कानून में एक बेहतर तरीका यह हो सकता है कि संबंधित पक्षों के हितों को समायोजित करने और सीआईआरपी प्रक्रिया को सुचारू बनाने में मदद करने के लिए आईबीसी के तहत कुछ नियमों को आसान बनाने की गुंजाइश दी जाए।

कंपनियों के विकास के लिए भारत को सुदृढ़ नियामक प्रणाली विकसित करना जारी रखना चाहिए। कंपनियों के विकास के लिए ऐसी कंपनियों के आसान प्रवेश और निकास की आवश्यकता होगी, जिसके लिए नियामक ढांचे को परिभाषित किया जाना चाहिए। भारत में दिवाला कानून अपने मौजूदा स्वरूप में प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। तकनीकी कंपनियों का दिवाला जटिल हो गया है, जिससे परिसंपत्ति स्थान, अधिकार क्षेत्र, सामूहिक अधिस्थगन, वास्तविक मूल्यांकन आदि से संबंधित नियामक मुद्दे उत्पन्न हो गए हैं। समाधान योजना को डिजाइन करते समय इस तरह की नवीन प्रथाओं को अपनाने की अनुमति देने के लिए कानून को लचीला बनाए रखने की आवश्यकता है। भारत में दिवाला कानूनों के प्रमुख प्रावधानों की पहचान करने की आवश्यकता है जिनमें कुछ बदलाव की आवश्यकता हो सकती है।

कार्रवाई योग्य दावों का असाइनमेंट

पूजा महाजन और क्लेयर टान्नर

कार्रवाई योग्य दावों का असाइनमेंट

पूजा महाजन, मैनेजिंग पार्टनर, चंडीओक और महाजन

क्लेयर टान्नर, स्पेशल काउंसल, के एंड एल गेट्स

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 ("आईबीसी") भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता से संबंधित न्यायशास्त्र में एक संरचनात्मक बदलाव लाती है। आईबीसी की प्रमुख विशेषताओं में से एक, जो कि इसके पूर्ववर्ती कानूनों के विपरीत है, कॉर्पोरेट ऋणी की परिसंपत्तियों के मूल्य को समयबद्ध तरीके से अधिकतम करने पर इसका जोर देना है। जब आईबीसी अधिनियमित किया गया था, मुख्य रूप से वसूली प्रक्रिया में देरी के कारण भारत दुनिया में सबसे कम वसूली दर वाले देशों में से एक था। लेनदारों के लिए वसूली, चाहे वह एक कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया या परिसमापन में हो, कॉर्पोरेट ऋणी की संपत्ति से समय पर मूल्य की प्राप्ति पर निर्भर करती है। कॉर्पोरेट ऋणी की संपत्ति में 'कार्रवाई में चुना गया' शामिल हो सकता है जिसका शाब्दिक अर्थ है 'कार्रवाई का विषय' या एक ऐसी वस्तु जिसे कार्रवाई द्वारा पुनर्प्राप्त किया जा सकता है (जो कि वास्तविक रूप में कब्जा लेने के विपरीत है)¹। 'कार्रवाई में चुना गया' में अनिवार्य रूप से दावा किया जाता है कि एक कॉर्पोरेट ऋणी संपत्ति, ऋण या धन के लिए तीसरे पक्ष के खिलाफ हो सकता है। यह कार्रवाई योग्य दावों के रूप में हो सकते हैं जैसे कि ऋण, प्राप्य राशियां, जो कब्जे में नहीं है उस संपत्ति के लिए दावा या मुकदमा चलाने और धन या दावों को पुनर्प्राप्त करने का अधिकार है जो समाधान व्यावसायिक या परिसमापक तीसरे पक्ष के खिलाफ परिहार लेनदेन के लिए या धोखाधड़ी या गलत व्यापार के लिए हो सकता है।

समाधान व्यावसायिक या परिसमापक द्वारा इस तरह के दावों की वसूली के परिणामस्वरूप अपने लेनदारों के लाभ के लिए कॉर्पोरेट ऋणी की साझी निधि में वृद्धि होगी। हालांकि, पिछले पांच से अधिक वर्षों में आईबीसी के कामकाज ने इस तरह के 'कार्रवाई में चुने गए' की उगाही में कठिनाई देखी गई। 'कार्रवाई में चुने गए' की उगाही के

¹ इंग्लैंड के हल्सबरी के नियम, खंड 13 (2017)

लिए अक्सर तीसरे पक्ष के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के रूप में समाधान व्यावसायिक या परिसमापक द्वारा कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता होती है, जो महंगा और समय लेने वाला हो सकता है। धन की कमी के कारण, समाधान व्यावसायिक या परिसमापक लेनदारों के लाभ के लिए इस तरह के दावों की प्रभावी ढंग से उगाही करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा, यहां तक कि जहां वित्त पोषण उपलब्ध होता है, वहां भी भारत में कानूनी कार्यवाही की लंबी प्रकृति को देखते हुए, उगाही में अनिश्चित समय लग सकता है। प्रासंगिक रूप से, जैसा कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ("आईबीबीआई") द्वारा अपने 'कॉर्पोरेट परिसमापन प्रक्रिया पर चर्चा पत्र' में मान्यता प्रदान की है, वसूली योग्य राशि, सबसे बेहतर, एक अनुमान है।²

एक समयबद्ध तरीके से समाधान व्यावसायिक या परिसमापक द्वारा इस तरह के 'कार्रवाई में चुने गए' की उगाही नहीं होना आईबीसी के दोहरे उद्देश्यों - समयबद्ध तरीके से मूल्य अधिकतमीकरण के लिए हानिकारक साबित हो रही है। इस समस्या को हल करने के समाधानों में से एक समाधान व्यावसायिक या परिसमापक को इन दावों पर विचार के लिए तीसरे पक्ष को सौंपने की अनुमति देना होगा। इस तरह के कार्य सौंपने के परिणामस्वरूप लेनदारों के लिए मूल्य का दायरा खुलेगा। हालांकि, जबकि असाइनमेंट एक आकर्षक विकल्प है, ऐसे में असाइनमेंट का परिणाम लेनदारों के लिए मूल्य अधिकतमीकरण के तौर पर हो और साथ ही समाधान व्यावसायिक या परिसमापक द्वारा प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं किया जाए यह सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण और संतुलन रखना चाहिए।

भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता के संदर्भ में 'कार्रवाई में चुने गए' के असाइनमेंट के सीमित उदाहरण हैं। दूसरी ओर, ब्रिटेन में 'कार्रवाई में चुने गए' के हस्तांतरण यानी अधिकारी के दावों सहित कार्रवाई के कारणों पर विचार किया गया है और यह कानून के तहत और साथ ही न्यायिक उदाहरणों दोनों के माध्यम से स्थापित है।

इस आर्टिकल का उद्देश्य शोधन अक्षमता के संदर्भ में ब्रिटेन और भारत में 'कार्रवाई में चुने गए' के असाइनमेंट पर कानूनी स्थिति का अध्ययन करना है। अध्ययन के आधार पर, यदि शोधन अक्षमता और परिसमापन प्रक्रिया में कार्रवाई में चुने गए असाइनमेंट को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत में कानून / विनियमन में किसी भी संशोधन की

² चर्चा पत्र LIQUIDATION.pdf (ibbi.gov.in)

आवश्यकता होती है और ऐसे दावों के असाइनमेंट पर विचार करते समय समाधान व्यावसायिक/परिसमापक द्वारा कौन सी श्रेष्ठ परिपाटी का पालन किया जा सकता है, इसके बारे में यह आर्टिकल सिफारिशे करेगा।

ब्रिटिश कानून का एक परिप्रेक्ष्य

सामान्य नियम

ब्रिटिश कानून के अनुसार, कार्रवाई करने का कारण कथित असाइनमेंट खत्म हो जाएगा यदि इसमें गैरकानूनी रखरखाव और/या एक विशिष्ट प्रकार का रखरखाव शामिल है जिसे चैम्पर्टी कहा जाता है।³ इसके अतिरिक्त, 1967 तक, रखरखाव और चैम्पर्टी आपराधिक कृत्य थे और टोट में दावों को पैदा किया। *Re Trepca Mines (No 2)* [1963] Ch 199 में, लॉर्ड डेनिंग ने इन दो सिद्धांतों को निम्नानुसार वर्णित किया है:

"मुझे लगता है, रखरखाव को एक पार्टी को सहायता देने के रूप में आजकल अनुचित रूप से मुकदमेबाजी और संघर्ष के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है ताकि वह बिना किसी कारण या बहाने के दावे का बचाव कर सके। एक समय में, "केवल कारण या बहाने" की सीमाओं को बहुत संकीर्ण रूप से परिभाषित किया गया था। लेकिन बाद में कानून ने उन्हें बहुत अधिक व्यापक बना दिया है... और मुझे आशा है कि उन्हें फिर से किसी संकीर्ण दायरे में कभी नहीं रखा जाएगा। लेकिन रखरखाव का एक प्रकार है जिसके लिए आम कानून शायद ही कभी किसी भी उचित कारण या बहाने को स्वीकार करता है, और वह है चैम्पर्टी। चैम्पर्टी की उत्पत्ति कैम्पी पार्टिओ (क्षेत्र का विभाजन) से हुआ है। यह तब होता है जब किसी अन्य का रखरखाव करने वाला व्यक्ति आय का हिस्सा निर्धारित करता है... सामान्य कानून द्वारा चैम्पर्टी की निंदा करने का कारण वो दुर्यवहार हैं जो इसके कारण उत्पन्न हो सकते हैं। सामान्य कानून को डर है कि चैंपियनस मेंटेनर को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, नुकसान को बढ़ाने, सबूतों को दबाने के लिए, या यहां तक कि झूठे गवाहों के लिए भी लुभाया जा सकता है। यह आशंकाएं और भी बढ़ सकती हैं; लेकिन, ऐसा हो या न हो, सदियों से कानून ने चैम्पर्टी को गैरकानूनी घोषित किया है"

रखरखाव और चैम्पर्टी के लंबे इतिहास को जाइल्स बनाम थॉम्पसन [1994] 1 A.C 142 में वर्णित किया गया था, जहां लॉर्ड मस्टिल ने "15 वीं शताब्दी में मैग्नेट्स को अधिक बुनकर

³ स्नेल्स इक्विटी - पैरा 3-38

द्वारा अभ्यास किए गए स्थानीय उत्पीड़न" का उल्लेख किया था और निम्नलिखित शब्दों में आपराधिक कृत्य के लिए तर्क को रेखांकित किया था:

"... रखरखाव और चैंपर्टी के अपराध इतने पुराने हैं कि उनकी उत्पत्ति का अब पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन मध्ययुगीन काल में उनका महत्व काफी स्पष्ट है। न्याय तंत्र में सत्ता के बेईमान लोगों द्वारा उकसाए गए और बनाए रखने वाले मुकदमों के माध्यम से निजी व्यक्तियों के उत्पीड़न का विरोध करने के लिए आंतरिक शक्ति का अभाव था। चैंपर्टी विशेष रूप से खराब थी, क्योंकि मुकदमेबाजी में एक हिस्से की खरीद ने न्यायाधीशों और गवाहों के झूठे और बेकार दावों के शोषण के लिए एक स्पष्ट प्रलोभन प्रस्तुत किया, जिसे प्रतिवादी के पास संसाधनों और प्रभाव का सामना करने की कमी थी। तथ्य यह है कि इस तरह के आचरण को आपराधिक और अन्यायपूर्ण दोनों के रूप में माना जाता था, जो एक अमूल्य बाहरी अनुशासन प्रदान करता है, जैसा कि रिकॉर्ड से पता चलता है, सहायता अक्सर आवश्यक थी।"

आपराधिक विधि अधिनियम, 1967⁴ ने अपराध और भरण-पोषण और चोरी के अपराधों को समाप्त कर दिया लेकिन कानून ने स्पष्ट रूप से कानून के शासन को संरक्षित कर रखा था कि ऐसे मामलों में जिनमें किसी अनुबंध को सार्वजनिक नीति के विपरीत या अन्यथा अवैध माना जाना था⁵। ट्रेडटेक्स ट्रेडिंग कॉर्प और अन्य बनाम क्रेडिट सुइस [1982] A.C 679 में, लॉर्ड विल्बरफोर्स ने स्पष्ट किया है कि:

"यद्यपि इसकी उत्पत्ति प्राचीन है और इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रयोज्य अस्पष्टताओं के साथ संलग्न है, [चैंपर्टी] को आपराधिक कानून अधिनियम 1967 की धारा 13 और 14 द्वारा वैधानिक मान्यता दी गई है, जो कि चैंपर्टी के लिए आपराधिक और अत्याचारी देयता को समाप्त करते हुए, स्पष्ट रूप से उन मामलों के तौर पर कानून के किसी भी नियम को संरक्षित करता है जिसमें चैंपर्टी से जुड़े अनुबंध को सार्वजनिक नीति और/या अन्यथा अवैध के विपरीत माना जाता है।"

ब्रिटिश कानून के अनुसार, कार्रवाई का कारण का असाइनमेंट हमेशा रखरखाव और चैंपर्टी के खिलाफ नियम का उल्लंघन नहीं करेगा, जिसमें शामिल हैं: (i) समनुदेशिती को

⁴ धारा 13 और 14(1) आपराधिक कानून अधिनियम 1967

⁵ धारा 14(2) आपराधिक कानून अधिनियम 1967

मुकदमेबाजी की सफलता में एक वास्तविक और पर्याप्त रुचि हो⁶; (ii) कार्रवाई का कारण किसी संपत्ति के अधिकार के असाइनमेंट के लिए प्रासंगिक हो⁷; (iii) असाइनमेंट संपत्ति के किसी प्रकार के रूप में, किसी परिसमापन ऋण का हो⁸; या, इस पेपर के लिए विशेष नोट, (iii) शोधन अक्षमता के संदर्भ में हो।

शोधन अक्षमता का संदर्भ

ब्रिटिश कानून के अनुसार, किसी परिसमापक के पास कंपनी के बंद होते समय (यानी संपत्ति के किसी भी हस्तांतरण से अलग मुकदमा करने का एकल अधिकार⁹) इसमें निहित कार्रवाई करने का कारण असाइन करने की वैधानिक शक्ति होती है।¹⁰

प्रासंगिक सांविधिक प्रावधान क्रमशः स्वैच्छिक और अनिवार्य समापन के मामले में, दिवाला अधिनियम 1986 ("**1986 अधिनियम**") के धारा 165 (2) और 167 (1) पर पाए जाते हैं, और परिसमापक को 1986 अधिनियम की अनुसूची 4 में निर्दिष्ट शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति देते हैं, जिसमें पैरा ग्राफ 6 में, "*सार्वजनिक नीलामी या निजी अनुबंध द्वारा कंपनी की किसी भी संपत्ति को बेचने" इसे किसी भी व्यक्ति को पूरा स्थानांतरित करने या टुकड़ों में बेचने की शक्ति है।*"

जहां कोई कंपनी प्रशासन में प्रवेश करती है¹¹ या जहां किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से दिवालिया होता है¹², तो इसी तरह के प्रावधान लागू होते हैं। संपत्ति की परिभाषा 1986 के अधिनियम के धारा 436 में मिलती है और इसमें "*धन, माल, कार्रवाई वाली वस्तुएं, भूमि और संपत्ति का हर विवरण जहां भी स्थित है और दायित्वों और ब्याज का हर विवरण,*

⁶ ट्रेडटेक्स, 694(E) पर

⁷ ट्रेडटेक्स, 703 पर

⁸ कैमडेक्स इंटरनेशनल बनाम बैंक ऑफ ज़ाम्बिया [1998] क्यूबी 22

⁹ ब्राउनटन लिमिटेड बनाम एडवर्ड मूर इनबुकोन लिमिटेड [1985] 3 सभी ईआर 499

¹⁰ रे लॉन्गमीड लिमिटेड (परिसमापन में) [2016] ईडब्ल्यूएचसी 356 (सीएच) में कंपनी के परिसमापन के प्रारंभ में संपत्ति में उस पर बकाया ऋण शामिल था, जिसने बाद में यूनाइटेड में एक अध्याय 11 योजना के तहत दावा करने के अधिकार को जन्म दिया। राज्यों और, जब वह दावा दायर नहीं किया गया था, तो फाइल करने में विफलता से उत्पन्न होने वाले नुकसान के लिए किसी तीसरे पक्ष से नुकसान का दावा करने का अधिकार। स्नोडेन जे ने पूर्ण तर्क सुने बिना एक अनंतिम दृष्टिकोण व्यक्त किया, कि यह बहुत अजीब होगा यदि परिसमापक द्वारा नुकसान के लिए दावा नहीं सौंपा जा सकता है।

¹¹ अनुसूची बी 1 के पैराग्राफ 60 और अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 2

¹² धारा 314(1) और अनुसूची 5, अधिनियम के अनुच्छेद 9

चाहे वह वर्तमान या भविष्य या निहित या आकस्मिक हो, संपत्ति से उत्पन्न होता है, या उसके लिए प्रासंगिक है, शामिल हैं।

जैसा कि LF2 Limited बनाम सपरस्टोन [2018] EWHC 1776 (Ch) में न्यायाधीश द्वारा प्रशासन के संदर्भ में स्पष्ट किया गया था: "कार्रवाई का कारण असाइन करने के लिए प्रशासक की शक्ति 1986 अधिनियम की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 2 द्वारा प्रदान की गई है, क्योंकि उस पैराग्राफ में कार्रवाई का कारण "संपत्ति" है।

दिवाला के संदर्भ में कार्रवाई के एकल कारणों को असाइन करने की वैधानिक शक्ति, 1986 के अधिनियम से बहुत पहले की से है। 1880 की शुरुआत में, सीयर बनाम लॉसन (1880) 15 Ch D 426 में कोर्ट ऑफ अपील ने उन कारणों पर विचार किया कि शोधन अक्षमता में कोई ट्रस्टी एक दावा क्यों असाइन करना चाहता है:

"ट्रस्टी का कार्यालय लेनदारों के बीच आय को वितरित करने के लिए संपत्ति की उगाही करेगा। हमें नीति के मामले के रूप में क्यों मानना चाहिए कि उसके लिए अपने नाम पर मुकदमा करना आवश्यक है? उसके पास कोई धन नहीं हो, या वह लागत का भुगतान करने का जोखिम लेने के लिए अनिच्छुक हो सकता है, या वह मुकदमेबाजी के अंत तक शोधन अक्षमता प्रक्रिया के समापन में देरी को अवांछनीय मान सकता है।"

कोर्ट ऑफ अपील ने पाया कि शोधन अक्षमता अधिनियम 1869¹³ के प्रासंगिक प्रावधानों ने ट्रस्टी को कार्रवाई का एकल कारण आवंटित करने की अनुमति दी। Re Park Gate Waggon Works Co (1881) 17 Ch D 234 में, कोर्ट ऑफ अपील ने कंपनी अधिनियम 1862¹⁴ के प्रासंगिक प्रावधानों पर निर्भरता में परिसमापन में एक कंपनी के संबंध में एक समान खोज की. सीयर और री पार्क गेट दोनों में असाइनी द्वारा भुगतान किया गया विचार मुकदमेबाजी के परिणाम से प्रासंगिक नहीं था, लेकिन गाय बनाम चर्चिल (1888) 40 सीएच डी 481 में अदालत ने फैसला दिया कि एक आकस्मिक व्यवस्था की अनुमति थी। गाय के मामले में किसी लेनदार ने शर्तों पर एक असाइनमेंट लिया कि वह दिवाला संपत्ति को किसी भी शुद्ध वसूली का 25% भुगतान करेगा और चिट्ठी जे ने पाया कि:

¹³ धारा 4, 17 और 25 दिवाला अधिनियम 1869

¹⁴ धारा 95 कंपनी अधिनियम 1862

“[शोधन अक्षमता अधिनियम] की नीति समिति की मंजूरी के साथ ट्रस्टी को शक्ति देने के लिए प्रतीत होती है, जो कार्रवाई में चुने गए विकल्पों के संदर्भ में व्यवस्था करने के लिए होती है जिसे लेनदारों के लिए फायदेमंद माना जाता है। यह कहने के लिए एक अजीब और असंगत परिणाम होगा कि हालांकि कार्रवाई के अधिकार को बेचा जा सकता है और इसे इन शर्तों पर निपटाया नहीं जा सकता है कि कार्रवाई के परिणाम का कुछ हिस्सा यदि सफल होता है तो वह अपने लेनदारों के बीच विभाजन के लिए दिवालिया की संपत्ति में वापस आ जाएगा।”

1986 के अधिनियम के लागू होने के बाद, असाइन करने के लिए वैधानिक शक्ति के निरंतर आवेदन की पुष्टि हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा नॉरग्लेन लिमिटेड (परिसमापन में) बनाम रीड्स रेन्स प्रूडेंशियल लिमिटेड और अन्य [1999] 2 AC 1 में की गई थी। उस मामले में, लॉर्ड हॉफमैन¹⁵ ने स्पष्ट किया कि:

“कानून पारंपरिक रूप से आय के एक हिस्से के बदले में कार्रवाई के कारणों के असाइनमेंट के विरुद्ध है... शोधन अक्षमता में परिसमापक और ट्रस्टियों की स्थिति काफी अलग है। अदालतों ने स्वीकार किया है कि उनके पास अक्सर मुकदमेबाजी को निधि देने के लिए कोई संपत्ति नहीं होती है और इस तरह के मामले में एकमात्र व्यावहारिक तरीका जिसमें वे कार्रवाई के कारण को पैसे में बदल सकते हैं, इसे बेचना है, या तो एक निश्चित राशि या आय के हिस्से के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपने नाम पर कार्यवाही करने के लिए तैयार हो। इस संबंध में वे निश्चित रूप से कई अन्य लोगों से अलग नहीं हैं। लेकिन क्योंकि ट्रस्टी और परिसमापक लेनदारों की ओर से कार्य करते हैं, अदालतों ने पिछली शताब्दी के लिए अपनी वैधानिक शक्तियों को उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति में रखने के रूप में माना है।”

2015 से पहले, असाइनमेंट की अनुमति देने वाली वैधानिक शक्ति उनके कार्यालय के कारण पदाधिकारियों में निहित कार्रवाई के कारणों के लिए नहीं थी। *Re Oasis Merchandising Services Limited* [1998] Ch 170 में, कोर्ट ऑफ अपील ने इसके बीच में एक

¹⁵ लॉर्ड हॉफमैन का निर्णय रखरखाव और चेंपर्टी के सिद्धांतों के कारणों पर एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है क्योंकि वह नोट करता है कि: "न्यायाधीशों ने कहा कि यह दुर्भावनापूर्ण मुकदमों को प्रोत्साहित करेगा, लेकिन इस तरह की व्यवस्था को आपराधिक मानना भी था ... गरीब लोगों को प्राप्त करने से रोकने का एक प्रभावी तरीका कानूनी निवारण।”

अंतर स्पष्ट किया: (क) परिसंपत्तियां जो परिसमापन की शुरुआत के समय कंपनी की संपत्ति थीं (और उसी का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति); और (ख) परिसंपत्तियां जो केवल कंपनी के परिसमापन के बाद उत्पन्न हुई थीं और जो वैधानिक शक्तियों (जैसे धोखाधड़ी या गलत व्यापारिक दावों) के अनुसार केवल परिसमापक द्वारा वसूली योग्य थीं। यह केवल पूर्ववर्ती था जो "कंपनी की संपत्ति" के अंतर्गत आता था जिसे कोई अधिकारी बेच सकता था।

लघु व्यवसाय उद्यम और रोजगार अधिनियम 2015 ("SBEEA") की धारा 118 - 119 के प्रभाव में आने के साथ स्थिति बदल गई, जिसने 1986 के अधिनियम के धारा 246ZD और धारा 176ZB को लागू किया। इस उपाय ने परिसमापकों और प्रशासकों को धोखाधड़ी¹⁶ या गलत तरीके से व्यापार करने¹⁷, कम मूल्य पर लेनदेन¹⁸, अधिमानी¹⁹ या अतिशय क्रेडिट लेनदेनों और दिवालिया संपत्ति²⁰ को उपलब्ध कराए गए असाइनमेंट की आय से उत्पन्न होने वाले कार्रवाई के कारणों को असाइन करने की अनुमति दी है, न कि फ्लोटिंग चार्ज धारक द्वारा किए गए दावों की संतुष्टि के लिए। Re Oasis में न्यायिक टिप्पणी ने अधिकारी के दावे के आचरण और नियंत्रण को बनाए रखने वाले को अधिकारी के अधीन धारा 246ZD को लागू करने का अनुमान लगाया²¹, लेकिन, इसमें, SBEEA ने अयोग्य आधार पर असाइनमेंट प्रदान किया है।

जैसा कि प्रस्तावित कानून के साथ आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन ("ईआईए")²² में स्पष्ट किया गया था: "... इनमें से कई कार्रवाइयों को अतीत में आगे नहीं बढ़ाया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है कि सभी अवसरों को अधिकारियों को दिया जाए, उन व्यक्तियों से धन की वसूली करने के लिए जो सीमित देयता के

¹⁶ धारा 213 और धारा 246ZA 1986 अधिनियम

¹⁷ धारा 214 और धारा 246ZB 1986 अधिनियम

¹⁸ धारा 238 1986 अधिनियम

¹⁹ धारा 239 1986 अधिनियम

²⁰ धारा 244 1986 अधिनियम

²¹ नीति के एक मामले के रूप में हम सोचते हैं कि एक परिसमापक को कार्रवाई के फल को बेचने की अनुमति देने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है ... बशर्ते कि यह क्रेता को परिसमापक के आचरण को प्रभावित करने या हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देता है।, कार्यवाही। अदालत के एक अधिकारी के रूप में परिसमापक कार्यवाही को आगे बढ़ाने में वैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए तदनुसार व्यवहार करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए।" रे ओएसिस मर्चेडाइजिंग सर्विसेज लिमिटेड [1998] अध्याय 170

²² दिवाला सेवा द्वारा निर्मित - दिवाला संबंधी मुद्दों पर मंत्रियों और अन्य सरकारी विभागों और एजेंसियों को सलाह देने के लिए जिम्मेदार सरकारी एजेंसी

विशेषाधिकार का लाभ उठाकर लेनदारों (विशेष रूप से असुरक्षित लेनदारों) को नुकसान पहुंचाते हैं, जहां कदाचार हुआ है।”²³ यह उम्मीद की गई थी कि कानून का निवारक प्रभाव होगा।²⁴ ईआईए ने काल्पनिक या अवसरवादी दावों के जोखिम की पहचान की लेकिन निष्कर्ष निकाला कि: “यह जोखिम छोटा होना चाहिए क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि दिवाला पेशवरों को कार्रवाई के कारणों को असाइन करने के लिए मौजूदा पेशवर और नैतिक मानकों के अनुसार होना चाहिए। इस तरह के दावे का एक असाइनमेंट उस व्यक्ति द्वारा अदालत में चुनौती देने में भी सक्षम होना चाहिए जिसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, यानी इस तरह के असाइनमेंट से पीड़ित व्यक्ति, जैसे कि कोई निदेशक।”²⁵

Re Totalbrand Ltd [2020] EWHC 2917 (Ch) में, अपील करने की अनुमति के लिए एक आवेदन में (1986 अधिनियम के धारा 246ZD पर पहला रिपोर्ट किया गया मामला माना जाता है), स्नोडेन जे ने पाया कि अन्य बातों के अलावा, प्रावधान के साफ शब्दों से परिकल्पना होती है कि, “कार्रवाई के पूरे अधिकार और असाइनी को सभी प्राप्तियां देने का एकमुश्त असाइनमेंट”। यदि यह अन्यथा था: “किसी परिसमापक या प्रशासक द्वारा कार्रवाई का अधिकार सौंपे जाने के बाद, कंपनी को कृत्रिम रूप से जीवित रखना होगा और दिवाला कार्यवाही को खुला रखना होगा, जबकि दावा मौजूद था ताकि असाइनी द्वारा की गई कार्रवाई की किसी भी आय के लेनदारों को रसीद और वितरण के लिए एक साधन और तंत्र प्रदान किया जा सके। इस प्रकार, जहां उपयुक्त, लागू पदाधिकारी दावों और उनकी आय को एकमुश्त सौंपा जा सकता है और दिवाला कार्यवाही के जल्दी बंद होने से प्राप्त दक्षताओं को पूरा किया जा सकता है।

असाइनमेंट से पहले दिवाला प्रैक्टिसनर्स के लिए सलाह

²³

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/322337/Enabling_Liquidators_and_Administrators_to_assign_to_third_parties_certain_rights_of_action_that_only_they_can_bring_under_the_Insolvency_Act_1986.pdf

²⁴ वही - पैरा 29: “हम अनुमान लगाते हैं कि इन कार्यों में एक बाजार विकसित होगा, और जहां कदाचार हुआ है, वहां निदेशकों के खिलाफ कार्रवाई की संभावना अधिक होगी।

²⁵ वही - पैरा 79

जबकि ब्रिटिश कानून शोधन अक्षमता के संदर्भ में कार्रवाई के कुछ कारणों का असाइनमेंट प्रदान करता है, असाइनमेंट हर मामले में सही जवाब नहीं होगा।

1. असाइनमेंट के लिए दिवाला प्रैक्टिसनर्स का दृष्टिकोण

आम तौर पर, अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे लेनदारों के लाभ के लिए एक दिवालिया कंपनी या व्यक्ति की संपत्ति की उगाही करें, लेकिन, जैसा कि ईआईए में उल्लेख किया गया था, कार्रवाई के कारण के असाइनमेंट के तीसरे पक्ष के लिए परिणाम हो सकते हैं। इस प्रकार, अतिरिक्त विचार तब उत्पन्न होते हैं जब एक अधिकारी कार्रवाई के कारण के असाइनमेंट पर विचार कर रहा होता है।

Re Papaloizou [1999] BPIR 106 में, ब्राउन-जैकबसन जे, जब शोधन अक्षमता के असाइनमेंट में कार्रवाई के किसी एकल कारण के लिए किसी ट्रस्टी पर विचार कर रहे थे, तब "ट्रस्टियों को चेतावनी वाला नोट" लिखा। न्यायाधीश ने स्वीकार किया कि असाइनमेंट सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं था, लेकिन सोचा कि: "इस तरह का कदम उठाने के लिए ट्रस्टियों को बड़ी सावधानी के साथ अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा करके वे शोधन अक्षमता को तीसरे पक्ष के खिलाफ संभवतः परेशानी भरी मुकदमेबाजी करने में सक्षम बना रहे हैं, जिनके पास उसके खिलाफ लागत में कोई प्रभावी उपाय नहीं होगा, क्योंकि उसकी सभी संपत्तियां ट्रस्टी में निहित हैं।" न्यायाधीश ने विचार किया कि लेनदारों के लिए स्पष्ट और कुछ लाभ प्राप्त न होने तक कोई असाइनमेंट नहीं होना चाहिए। इस निर्णय का पालन *कमिंग्स बनाम द ऑफिशियल रिसीवर* [2002] EWHC 2894 (Ch) में किया गया था, जहां ब्लैकबर्न जे ने संकेत दिया था कि यह असाइनमेंट की मांग करने वाले दिवालिया के लिए था ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि कार्रवाई के कारण तुच्छ या तंग करने वाले नहीं थे। *डिक्सन बनाम मायर्स* [2020] EWHC 2803 (Ch) में, न्यायाधीश ने पाया कि "तुच्छ या तंग करना" अभिव्यक्ति नागरिक प्रक्रिया नियमों के भाग 24 के तहत सारांश निर्णय के लिए परीक्षण का पर्याय थी अर्थात् दावेदार के पास दावे पर सफल होने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है और कोई अन्य सम्मोहक कारण नहीं है कि मामले की सुनवाई क्यों की जानी चाहिए।

Hockin v Marden [2014] EWHC 763 (Ch) में, न्यायाधीश ने मामले को इस आधार पर आगे बढ़ाया कि अदालत को दावे के असाइनमेंट को निर्देशित नहीं करना चाहिए यदि यह

सार्वजनिक नीति के आधार सहित तुच्छ या तंग करने वाला था। विशेष रूप से, यह एक असाइनमेंट को निर्देशित करने के लिए अन्यायपूर्ण होगा यदि परिणाम एक तीसरे पक्ष, प्रस्तावित प्रतिवादी को प्रस्तुत करना था, तो सफलता की कोई गंभीर संभावना नहीं होने के दावे के साथ परेशान किया जा रहा था। इसके अलावा, न्यायाधीश ने कहा कि यह बोझ संभावित असाइनी पर यह स्थापित करने के लिए था कि दावा तुच्छ या तंग करने वाला नहीं था।

इन अधिकारियों को LF2 लिमिटेड में मॉर्गन जे द्वारा माना जाता था, जिन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था (रे पापालोइजू के आधार पर) कि एक प्रशासक एक सकारात्मक कर्तव्य के तहत था कि वह बिना योग्यता वाला कार्रवाई का कारण न असाइन करे। इसके अतिरिक्त, मॉर्गन जे ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि जब यह स्पष्ट नहीं है कि कार्रवाई के कारण में योग्यता है, तो प्रशासक को इसे असाइन नहीं करना चाहिए और इसके बजाय यह प्रदर्शित करने के लिए असाइनमेंट की मांग करने वाली पार्टी पर दबाव डालना चाहिए कि दावा तुच्छ या तंग करने वाला नहीं है। मॉर्गन जे सिटीकॉर्प ऑस्ट्रेलिया बनाम शोधन अक्षमता में आधिकारिक ट्रस्टी [1996] FCA 1115 में ऑस्ट्रेलिया के फेडरल न्यायालय के निष्कर्षों को प्राथमिकता दी:

“जहां एक लेनदार या हस्तक्षेप करने वाले पक्ष का तर्क है कि एक असाइनमेंट को अधिकृत नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि प्रस्तावित दावे में सफलता की कोई संभावना नहीं है, तो यह उस पक्ष के लिए सफलता की किसी भी संभावना की अनुपस्थिति को प्रदर्शित करने के लिए है। यह सामान्य सिद्धांत का अनुसरण करता है कि कोई पक्ष जो किसी प्रस्ताव पर जोर देता है, वह इसका समर्थन करने के लिए आवश्यक तथ्यों को स्थापित करने की स्पष्ट जिम्मेदारी वहन करता है।”

LF2 Limited में, मॉर्गन जे पहचान के लिए चला गया, हालांकि एक ओर्बिटर के आधार पर, जब प्रशासक कार्रवाई के किसी कारण के असाइनमेंट पर विचार करते हैं तो कई सारे सिद्धांत लागू होते हैं।:

- वैधानिक शक्ति (ऊपर चर्चा की गई) एक प्रशासक को कार्रवाई का कारण असाइन करने की अनुमति देना किसी भी शब्द द्वारा सीमित नहीं था, जिसके लिए

प्रशासक को कार्रवाई के कथित कारण की तर्कशीलता के रूप में संतुष्ट होने की आवश्यकता होती है।

- किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ किसी कंपनी द्वारा कंपनी की एक संपत्ति का एक व्यवहार्य दावा है। एक दावा जो यकीनन व्यवहार्य है, कंपनी की एक संभावित संपत्ति है और एक प्रशासक को यह जांचना चाहिए कि क्या इस तरह की संपत्ति को संरक्षित और अनुसरण किया जाना चाहिए। यदि प्रशासक के पास कानूनी सलाह लेने के लिए कोई धन नहीं है, तो यह आवश्यक धन लेनदारों के निकाय से ले सकता है।
- यदि प्रशासक के पास किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ संभावित दावे की जांच करने के लिए कोई धन नहीं है और एक असाइनमेंट के लिए भुगतान करने के दावे के संभावित असाइनी से कोई प्रस्ताव प्राप्त करता है, तो वह प्रस्ताव संभावित रूप से कंपनी की एक संपत्ति बनेगा। आमतौर पर प्रशासक को उस संपत्ति को संरक्षित और पाने की कोशिश करनी चाहिए।
- यदि प्रशासक को यह स्पष्ट रूप से पता है कि दावा निराशाजनक रहेगा और संभावित असाइनी तीसरे पक्ष को परेशान करने के लिए एक निराशाजनक दावे का अनुसरण करने पर तुला हुआ है, तो प्रशासक को आमतौर पर निराशाजनक दावे को असाइन करने से इनकार करना चाहिए। प्रशासक अदालत का एक अधिकारी होता है और अदालत उसे ईमानदारी और निष्पक्ष व्यवहार करने की उम्मीद करती है। ऐसे मामले में, प्रशासक को अदालत से निर्देश लेने की आवश्यकता नहीं है।
- यदि प्रशासक का यह स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है कि प्रस्तावित दावा परेशान करने वाला होगा और उसे दावे के असाइनमेंट के लिए कोई धनराशि की पेशकश की जाती है, तो प्रशासक को असाइनमेंट के लिए उचित भुगतान प्राप्त करना चाहिए। यदि यह स्पष्ट नहीं है कि प्रस्ताव कार्रवाई के कारण के सही मूल्य को दर्शाता है, तो प्रशासक को प्रतिद्वंद्वी बोलियों को आमंत्रित करने या कार्रवाई के कारण की नीलामी आयोजित करने की कुछ प्रक्रिया आयोजित करने की सलाह दी जा सकती है।

- व्यावहारिक विचारों और समय के दबाव को ध्यान में रखने की आवश्यकता हो सकती है। यदि कोई उच्च जोखिम है जैसे कि दावे के लिए सीमावधि समाप्त होने वाली हो सकती है, तो प्रशासक को एक सुरक्षात्मक दावा प्रपत्र जारी करना पड़ सकता है या कार्रवाई के कारण के असाइनमेंट के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए त्वरित बातचीत करनी पड़ सकती है।
- प्रशासक का ध्यान लेनदारों के लाभ के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों या संभावित परिसंपत्तियों को भुनाने पर होना चाहिए, न कि मुकदमेबाजी से किसी तीसरे पक्ष के परेशान होने की संभावना से रक्षा करने पर। यदि कथित दावा सौंपा जाता है और असाइनी तब एक दावा फॉर्म जारी करता है, तो प्रतिवादी दावा फॉर्म को निरस्त करने या रिवर्स समरी निर्णय लेने के लिए आवेदन करने में सक्षम होगा यदि प्रतिवादी यह तर्क देना चाहता है कि दावा तुच्छ या तंग करने वाला है।
- यह अदालत के लिए (जब यह एक असाइनमेंट देने के लिए एक प्रशासक के इनकार के लिए एक संभावित असाइनी द्वारा एक चुनौती से निपट रही है) एक लंबी सुनवाई करना अवांछनीय है कि क्या दावा तुच्छ या तंग करने वाला है, इसके बजाय किसी स्पष्ट मामले में बचना, प्रशासक को कार्रवाई के कथित कारण को असाइन करने की अनुमति या निर्देश देना। यह एक तर्क के लिए अधिक उपयुक्त है कि क्या दावा तुच्छ और परेशान है जो संभावित असाइनी और प्रशासक के बीच के बजाय दावे के असाइनी और तीसरे पक्ष (प्रशासक को शामिल किए बिना) के बीच सामान्य तरीके से आयोजित किया जाना है (किसी भी सुनवाई में तीसरे पक्ष द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर संभावित सीमाओं के साथ)।

LF2 Limited में मॉर्गन जे की टिप्पणियां सभी में असाइनमेंट को प्रोत्साहित कर सकती हैं, लेकिन सबसे स्पष्ट रूप से निराशाजनक, तुच्छ या परेशान करने वाले मामलों में।

2. ऐसी परिस्थितियां जिनमें किसी दिवाला प्रैक्टिसनर द्वारा कार्रवाई का कारण असाइन नहीं किया जा सकता है

कुछ मामलों में, किसी अधिकारी द्वारा कार्रवाई का कारण असाइन नहीं किया जा सकता है और, LF2 Limited में चर्चा किए गए सिद्धांतों को देखते हुए, यह बेहतर होगा कि इसे

बाद में जल्द ही पहचाना जाए। कार्रवाई का कोई कारण असाइन नहीं किया जा सकता है इन कारणों में शामिल हैं:

- असाइनमेंट के विरुद्ध कोई संविदात्मक प्रतिबंध²⁶.
- व्यक्तिगत शोधन अक्षमता के मामले में, कार्रवाई का कारण शोधन अक्षमता में ट्रस्टी में निहित नहीं होता है। *Heath v Tang* [1993] 1 WLR 1421 में, लॉर्ड जस्टिस हॉफमैन ने स्पष्ट किया है कि: "ट्रस्टी में निहित संपत्ति में 'कार्रवाई में शामिल वस्तुएं' शामिल हैं: धारा 436 देखें। इस परिभाषा की व्यापकता के बावजूद, शोधन अक्षमता के लिए व्यक्तिगत कार्रवाई के कुछ कारण हैं जो उनके ट्रस्टी में निहित नहीं हैं। इनमें ऐसे मामले शामिल हैं जिनमें 'नुकसान का अनुमान अपने शरीर, मन या चरित्र के संबंध में दिवालिया द्वारा महसूस किए गए दर्द के तत्काल संदर्भ द्वारा लगाया जाना है, और संपत्ति के अपने अधिकारों के तत्काल संदर्भ के बिना: *Beckham v Drake* (1849) 2 H.L.Cas. 579, 604, per Erle J. and *Wilson v United Counties Bank Ltd* [1920] A.C. 102" देखें। इस प्रकार, इस तरह के व्यक्तिगत दावों को असाइन नहीं किया जा सकता है। हालांकि, जहां किसी दावे का एक हिस्सा व्यक्तिगत है और दूसरा संपत्ति (एक "हाइब्रिड दावा") से संबंधित है, यह ट्रस्टी में उन नुकसानों को पुनर्प्राप्त करने के अधिकार के साथ निहित होगा जो व्यक्तिगत हैं और ट्रस्टी द्वारा दिवालिया के लिए एक रचनात्मक ट्रस्ट पर धारित किसी भी नुकसान को पुनर्प्राप्त किया गया है²⁷. इस प्रकार, एक हाइब्रिड दावे का कोई भी असाइनी आवश्यक रूप से रचनात्मक ट्रस्ट के अनुसार दिवालिया के अधिकारों के अधीन असाइनमेंट लेगा।
- जबकि SEEBA ने कुछ निर्दिष्ट अधिकारी दावों के असाइनमेंट की अनुमति दी है, 1986 के अधिनियम के अन्य प्रावधानों को अक्षम्य माना जाता है²⁸. इसके अलावा,

²⁶ रटल प्लांट हायर लिमिटेड बनाम पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मामलों के राज्य सचिव [2007] EWHC 2870 (TCC)

²⁷ ऑर्ड वी अप्टन [2000] 2 डब्ल्यूएलआर 755 जहां हाइब्रिड दावा व्यक्तिगत चोटों के लिए लापरवाही में एक कार्रवाई थी जिसमें दर्द और पीड़ा के लिए सामान्य नुकसान का दावा, व्यक्तिगत दावा, और कमाई के नुकसान का दावा शामिल था जो संपत्ति यानि दिवालियापन संपत्ति का हिस्सा था।।

²⁸ सीली एंड मिलमैन: एनोटेटेड गाइड टू दी इन्सॉल्वेंसी लेजिस्लेशन 24वां संस्करण। - 2021: "IA 1986 की अन्य धाराएं जिनका कभी-कभी उन मामलों में उल्लेख किया जाता है जो संभवतः अनिर्दिष्ट हैं (इसे प्रस्तुत किया गया है,

SEEBBA ने 1986 के अधिनियम के धारा 212 के अनुसार अपकरण दावों के असाइनमेंट के लिए प्रदान नहीं किया था। यह एक प्रक्रियात्मक तंत्र प्रदान करता है जिससे कंपनी में निहित कार्रवाई के कारणों का अधिकारी द्वारा अनुसरण किया जा सकता है। यह सोचा गया था कि गलत तरीके से दुर्व्यवहार के लिए दावा अधिकारी की वैधानिक शक्ति के अनुसार असाइन करने योग्य था²⁹ लेकिन इस पर *Manolete Partners Plc v Hayward and Barrett Holdings Limited* [2021] EWHC 1481 (Ch). में संदेह किया गया। 1986 अधिनियम की धारा 246ZD व्यक्तिगत शोधन अक्षमता के मामलों पर लागू नहीं होती है और इस प्रकार शोधन अक्षमता में एक ट्रस्टी एक अधिकारी दावा असाइन नहीं कर सकता है। ट्रस्टी इसके रूप में नुकसान का एक हिस्सा असाइन कर सकता है: "भविष्य की संपत्ति असाइन करने के लिए समझौता (यदि नुकसान हो और जब प्रदान की जाए)"³⁰.

3. वित्त पोषण विचारों और विकल्प

जैसा कि *सीयर* जैसे शुरुआती मामलों में पहचाना गया था और हाल ही में, *नॉर्गेलन* में धन की कमी एक अधिकारी के लिए कार्रवाई के कारण के असाइनमेंट पर विचार करने का एक कारण हो सकता है। EIA में इस पर चर्चा की गई थी जहां 1986 और 2013 के बीच की अवधि में अधिकारी दावों की अपेक्षाकृत मामूली संख्या के कारणों (औसतन एक वर्ष में लगभग छह मामले) को शामिल करने पर विचार किया गया था: "दिवाला कंपनी में अपर्याप्त संपत्ति जिसके साथ अधिकारी और लेनदारों द्वारा किसी कार्रवाई का वित्त पोषण करने के लिए उन्हें निधि देने के लिए अनिच्छुक हो जहां ऐसा मामला हो... यह मामला हो सकता है कि कार्रवाई का एक संभावित अधिकार है, लेकिन कार्रवाई के साथ आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है। एक कार्रवाई को निधि देने के लिए परिसंपत्ति प्राप्ति से पर्याप्त धन नहीं हो सकता है और लेनदार कार्रवाई को निधि देने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं क्योंकि वे पहले से ही कंपनी के दिवाला के कारण धन खो चुके हैं। चूंकि धन सीमित है, इसलिए अधिकारियों को केवल एक कार्रवाई के

ठीक है) छोड़ दिया गया है: संपत्ति के एक पोस्ट-याचिका स्वभाव को धारा 127 के तहत शून्य घोषित किया गया है, या एक अस्थायी आरोप को धारा 245 के तहत शून्य घोषित किया गया है।"

²⁹ *री टोटलब्रांड लिमिटेड* [2020] EWHC 2917 (Ch)

³⁰ *ओएसिस मर्चंडाइजिंग सर्विसेज लिमिटेड* [1998] अध्याय 170

साथ आगे बढ़ने की संभावना है जहां उनका मानना है कि मामले में सफलता का एक बहुत अच्छा मौका है और उन्हें इसे लाने के लिए वित्त पोषित किया जाता है।”

यदि कार्रवाई के कारण की खोज को निधि देने के लिए दिवालिया संपत्ति में अपर्याप्त धन उपलब्ध है, तो अधिकारी असाइनमेंट पर आगे बढ़ने से पहले धन के वैकल्पिक साधनों पर विचार करना चाह सकता है। वित्त पोषण के ऐसे साधनों में शामिल हो सकते हैं: (i) लेनदार वित्तपोषण - विशेष रूप से जहां धन की कमी नहीं होती है, वहां अधिकांश लेनदारों में मुकदमेबाजी की क्षमता होती है; (ii) एक वाणिज्यिक मुकदमेबाजी वित्त पोषक से तीसरे पक्ष का वित्त पोषण - ब्रिटिश बाज़ार में इस तरह का वित्त पोषण अच्छी तरह से स्थापित है; (iii) कानूनी या अन्य सलाहकारों के साथ वैकल्पिक वित्त पोषण व्यवस्था; (iv) प्रतिकूल लागत जोखिम को पूरा करने के लिए कार्य के बाद बीमा (नीचे और देखें); या (v) (i) से (iv) का कोई संयोजन। कुछ मामलों में, वित्त पोषण के वैकल्पिक साधन आम तौर पर दावे के असाइनमेंट की तुलना में लेनदारों के लिए एक बेहतर परिणाम प्रदान कर सकते हैं।

4. लागत निहितार्थ

यदि वित्तपोषण के वैकल्पिक साधन उपलब्ध नहीं हैं या स्वीकार्य शर्तों पर उपलब्ध नहीं हैं, तो असाइनमेंट एक अधिक आकर्षक विकल्प हो सकता है। हालांकि, एक पदाधिकारी को एक असाइनमेंट की लागत के निहितार्थ के बारे में सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होगी।

इंग्लैंड और वेल्स में, "हारने वाले भुगतान करते हैं" सिद्धांत मुकदमेबाजी में लागू होता है। विस्तृत शब्दों में, यदि कोई पक्ष जीतता है, तो वह हारने वाले पक्ष से अपनी लागत का एक अनुपात वसूल करेगी, लेकिन अगर यह हार जाता है, तो उसे जीतने वाले पक्ष की लागतों के अधिकांश भाग का भुगतान करने की उम्मीद करनी चाहिए।

वरिष्ठ न्यायालय अधिनियम 1981 की धारा 51 (1) के अनुसार, ब्रिटिश अदालत के पास लागत के रूप में एक व्यापक विवेकाधिकार है जिसमें यह निर्धारित करने की पूरी शक्ति शामिल है कि किसके द्वारा और किस हद तक लागत का भुगतान किया जाना है। इसमें तीसरे पक्ष की लागत आदेश देने की क्षमता शामिल है यानी कार्यवाही के लिए एक गैर-पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल लागत आदेश।

यदि कार्रवाई का एक कारण एकमुश्त असाइन किया गया है (यानी एक निश्चित मूल्य के लिए) तो असाइन करने वाले को तीसरे पक्ष के लागत आदेश और असाइनी द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई की लागत के लिए परिणामी देयता नहीं ली जाएगी। यह परिणाम अधिकारी को वसूली की मात्रा और लागत जोखिम के रूप में सबसे बड़ी निश्चितता प्रदान करता है³¹ लेकिन सबसे अच्छी कीमत नहीं मिल सकती है। यदि कार्रवाई का कारण उन शर्तों पर असाइन किया गया है जो असाइन करने वाले के कार्रवाई के कारण की प्राप्ति में रुचि बनाए रखता है (उदाहरण के लिए किसी भी पुनर्प्राप्ति का प्रतिशत हिस्सा लेकर) तो यह संभव है कि असाइन करने वाले के विरुद्ध एक तीसरे पक्ष का लागत आदेश दिया जा सकता है। लागत जोखिम के बावजूद, यदि दावा अंततः सफल होता है, तो प्राप्ति का एक हिस्सा रखने वाले असाइन करने वाले द्वारा एक बेहतर वसूली अच्छी तरह से प्राप्त की जा सकती है।

5. प्राप्य मूल्य

ब्रिटिश कानून के अनुसार, किसी परिसमापक का कार्य कंपनी की परिसंपत्तियों को प्राप्त करना और भुनाना और आय को कंपनी के लेनदारों को वितरित करना है³² और शोधन अक्षमता में एक ट्रस्टी का एक संबंधित कार्य है।³³ प्रशासकों को कंपनी के लेनदारों के लिए ओवरराइडिंग कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है और उन्हें 1986 अधिनियम के Sch. B1 के पैरा 3 में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने की मांग करने की आवश्यकता होती है।³⁴ किसी अधिकारी का कर्तव्य एक साधारण मानक, यथोचित कुशल और सजग दिवाला प्रैक्टिसनर के कार्यों को पूरा करने के लिए उचित सावधानी और कौशल का उपयोग करने का है।³⁵ इसके अलावा, परिसंपत्तियों का निपटान करते समय, अधिकारियों को उचित रूप से प्राप्त करने योग्य सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने के कर्तव्य का निर्वहन करना होता है।³⁶

विशेष चुनौतियां तब उत्पन्न हो सकती हैं जब कोई अधिकारी कार्रवाई के कारण में मूल्य को भुनाना चाहता है। *Faryab v Smith* [2000] 12 WLUK 340 Robert Walker LJ ने नोट किया

³¹ जहां एक दिवालिया कंपनी के खिलाफ एक प्रतिकूल लागत आदेश दिया जाता है, ऐसी लागतें कार्यालयधारकों के पारिश्रमिक से पहले एक व्यय और रैंक के रूप में देय होती हैं। *रे एमटी रियलाइजेशन लिमिटेड* [2003] ईडब्ल्यूएचसी 2895

³² अधिनियम की धारा 107 और 143

³³ वही धारा 305 में

³⁴ पीजेएससी उरालकली बनाम रौली [2020] ईडब्ल्यूएचसी 3442 (च)

³⁵ उदाहरण के लिए देखें, *रे वन ब्लैकफ्रियर्स लिमिटेड (परिसमापन में)* [2021] ईडब्ल्यूएचसी 684 (च) पैरा 205 पर

³⁶ वही

कि: "कार्रवाई के कारण की प्राप्ति (विशेष रूप से कुछ जटिलता की कार्रवाई का एक कारण) एक अलग मामला है और कम स्पष्ट रूप से व्यापार सामान्य ज्ञान के लिए एक मामला है जैसे कि फ्रीहोल्ड या लीजहोल्ड संपत्ति, व्यापार में स्टॉक या अन्य मूर्त चल संपत्ति जैसी अधिक पारंपरिक संपत्तियों की प्राप्ति की तुलना में)." न्यायाधीश ने कानूनी सलाह लेने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि: "इस तरह के मामले में एक जटिल दावे के मूल्यांकन से जुड़े [शोधन अक्षमता में ट्रस्टी] को स्वतंत्र कानूनी सलाह की बेहद आवश्यकता थी और, अपनी खुद की कोई गलती नहीं होने के कारण, वह इसे प्राप्त करने में असमर्थ था। मेरे विचार में, उसके दावे का खुद का मूल्यांकन अपर्याप्त था।"

इस तरह की कानूनी सलाह (योग्यता, क्वांटम, प्रवर्तन, लागत और असाइनमेंट पर जोखिम सहित) इस बात के आकलन में एक महत्वपूर्ण कारक होगा कि क्या दावा हो सकता है और होना चाहिए: अनुसरण करना, संपत्ति या धन के वैकल्पिक साधनों से धन का उपयोग करना; असाइन किया गया और किन शर्तों पर मूल्य के रूप में शामिल है; या परित्यक्त। उस मूल्यांकन को पूरा करने में, अधिकारी ऐसे कारकों को ध्यान में रखेगा जैसे कि: (i) क्या दिवालिया कंपनी में उपलब्ध धन कार्रवाई की लागत और प्रतिकूल लागत जोखिम को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं; (ii) "मूल्य" के साथ जुड़े और वित्त पोषण के किसी भी वैकल्पिक साधन की उपलब्धता, हालांकि संरचित; (iii) लागत के रूप में किसी भी क्षतिपूर्ति की पर्याप्तता को शामिल करने के लिए एक असाइनमेंट लेने के लिए किसी भी प्रस्ताव की शर्तें; (iv) क्या गुण-दोष, अपेक्षित वसूली और वसूली जोखिम दावे की खोज से जुड़ी लागत और लागत जोखिम को वारंट करते हैं और, विशेष रूप से क्या प्रत्याशित लागत विवाद में राशियों के आनुपातिक हैं; (v) क्या गुण-दोष, मात्रा और वसूली जोखिम पर सलाह तथ्यात्मक या अन्य अनिश्चितताओं के कारण प्रतिवादी है; और (vi) लेनदारों को प्रत्याशित प्राप्ति।

असाइनमेंट लेने के लिए प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए, अधिकारी किसी कंपनी के लेनदारों, शेयरधारकों और निदेशकों जैसे हितधारकों से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, ब्रिटिश बाजार में काम करने वाले अधिकारी आमतौर पर अच्छी तरह से स्थापित तीसरे पक्ष की कंपनियों से संपर्क करते हैं जिनके व्यवसाय मॉडल में दावों को खरीदना और उनका अनुसरण करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी / संभावित प्रतिवादी को दावा प्राप्त करने में रुचि हो सकती है। Re Edenote [1996] BCLC 389 में, कोर्ट ऑफ अपील ने कहा कि अधिकारी को इस तरह के प्रतिवादी से प्रस्ताव आमंत्रित करना चाहिए था।

यदि अधिकारी को दावे के असाइनमेंट के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त होता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि प्रस्ताव कार्रवाई के कारण के सही मूल्य को दर्शाता है, तो अधिकारी को प्रतिद्वंद्वी बोलियों को आमंत्रित करने या कार्रवाई के कारण की नीलामी आयोजित करने की प्रक्रिया आयोजित करने की सलाह दी जा सकती है।³⁷ किसी उपयुक्त मामले में, नीलामी आयोजित करके बाजार का परीक्षण करने की प्रक्रिया मूल्यांकन सलाह लेने के बिना आगे बढ़ने के लिए उचित बना सकती है, खासकर जहां दावे का मूल्यांकन करना कठिन हो।³⁸ किसी भी बोली प्रक्रिया के दौरान, सभी पक्षों को एक ही जानकारी प्रदान की जानी चाहिए ताकि बोली के संचालन में किसी भी वास्तविक अन्याय के आधार पर एक चुनौती से बचा जा सके।³⁹ कोई अधिकारी यह निर्दिष्ट करना चाह सकता है कि वह आवश्यक रूप से उच्चतम या किसी भी बोली को स्वीकार नहीं करेगा। यह अधिकारी को प्रस्ताव को राउंड में देखने और लागत जोखिम, क्षतिपूर्ति के किसी भी प्रस्ताव और क्षतिपूर्ति की ताकत जैसे मूल्य के अलावा अन्य कारकों पर विचार करने में सक्षम बनाता है। धारा 120 SBEEA के लागू होने के बाद, अब अदालत या लेनदार की मंजूरी के लिए कोई आवश्यकता नहीं है जब कोई अधिकारी एक असाइनमेंट दे रहा है, लेकिन अधिकारी लेनदारों से परामर्श करने का अवसर ले सकता है। इसके अलावा, अधिकारी को कार्रवाई के कारण में मूल्य प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करना चाहिए।

भारत में कानूनी स्थिति

भारतीय कानून के अनुसार, एक 'कार्रवाई योग्य दावे' को स्थानांतरित किया जा सकता है, हालांकि, 'मुकदमा करने के एकमात्र अधिकार' को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 ("टीपीए") की धारा 3 में एक 'कार्रवाई योग्य दावा' को परिभाषित किया गया है, जो (क) असुरक्षित ऋणों या (ख) चल संपत्ति में लाभकारी ब्याज के दावे के रूप में परिभाषित किया गया है, जो हस्तांतरणकर्ता के कब्जे में नहीं है, चाहे वह वर्तमान या भविष्य, सशर्त या आकस्मिक हो।

³⁷ पेज नं. 2 पैरा 67 पर

³⁸ री. मीम लिमिटेड (प्रशासन में) [2017] EWHC 2688 (Ch)

³⁹ हेल्डोर्न बनाम माइकल [2009] EWHC 2414 (Ch)

एक कार्रवाई योग्य दावे को संपत्ति के एक प्रकार के तौर पर माना जाता है। टीपीए की धारा 8 और धारा 130 के साथ पठित धारा 5 हस्तांतरणकर्ता या उसके विधिवत अधिकृत एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में एक लिखत के निष्पादन द्वारा एक कार्रवाई योग्य दावे के हस्तांतरण की अनुमति देती है। एक बार जब इस तरह की लिखत को निष्पादित कर दिया जाता है, तो हस्तांतरणकर्ता के सभी अधिकार और उपाय, चाहे नुकसान के माध्यम से या अन्यथा, हस्तांतरणकर्ता में निहित हो जाते हैं और हस्तांतरणी इस तरह के मुकदमे या कार्यवाही के लिए हस्तांतरणकर्ता की सहमति प्राप्त किए बिना और उसे एक पक्ष बनाए बिना अपने नाम पर मुकदमा कर सकता है या कार्रवाई कर सकता है। टीपीए की धारा 131 में यह अधिदेश दिया गया है कि कार्रवाई योग्य दावे के हस्तांतरण की प्रत्येक सूचना लिखित रूप में होगी, हस्तांतरणकर्ता या उसके एजेंट द्वारा इस संबंध में विधिवत रूप से अधिकृत, या, यदि हस्तांतरणकर्ता या उसके एजेंट द्वारा हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, और हस्तांतरणी का नाम और पता बताएगा।

जैसा कि जे रैंकिन द्वारा मेसर्स सदासुक रामप्रोटाप बनाम होयर मिलर एंड कंपनी⁴⁰ में चर्चा की गई है, धारा 130 में ब्रिटिश सामान्य कानून और समानता दोनों की विशेषताएं हैं। न्यायाधीश ने महसूस किया:

“संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 130 और 131 का अर्थ लगाते हुए, यह याद रखना होगा कि उनमें एक बहुत ही विशेष योजना है जिसे अपने आप में समग्र रूप से माना जाना चाहिए। आम कानून में कार्रवाई में चुना गया असाइन करने योग्य नहीं था, इक्विटी में यह स्वतंत्र रूप से कुछ सिद्धांतों पर नोटिस करने के लिए असाइन करने योग्य था। 1900 में भारतीय विधायिका ने एक नई योजना की रचना की है जिसमें दोनों की कुछ विशेषताएं हैं, और, जैसा कि मैंने धारा 130 पढ़ी है, यह कहती है कि कानून, एक निश्चित तरीके से लागू होने पर वैध रूप में एक कार्रवाई योग्य दावे के हस्तांतरण के संबंध में, एक ऋणी के विरुद्ध असाइनमेंट को लागू करने का कार्य नहीं करेगा, सिवाय उन शर्तों के जो ऋणी अपने मूल लेनदार के साथ व्यवस्था कर सकता है जब तक कि वह एक विशेष प्रकार की लिखित सूचना में प्राप्त नहीं हो जाता है।”

वहां एक मजबूत कानूनी मामला है जो एक कार्रवाई करने योग्य दावा बनाता है। एक असुरक्षित ऋण के लिए एक दावा कार्रवाई योग्य दावे की परिभाषा में शामिल है। हालांकि

⁴⁰ 80 इंड कैस 632

टीपीए में परिभाषित नहीं किया गया ऋण एक परिसमापन या धन की कुछ राशि का भुगतान करने के दायित्व के रूप में अच्छी तरह से समझा जाता है। दूसरी ओर, चल संपत्ति में एक लाभकारी ब्याज में बीमा राशि की वसूली का अधिकार या एक भंग साझेदारी या एक आज्ञाप्ति ऋण खाते के लिए मुकदमा करने के लिए एक भागीदार का अधिकार या बीमा राशि की वसूली का अधिकार या किसी भी देयता के साथ युग्मित नहीं होने वाले अनुबंध के लाभ का दावा करने का अधिकार शामिल होगा।⁴¹ भारतीय अदालतों द्वारा कार्रवाई योग्य दावों के रूप में किए गए दावों में किराए के बकाया के लिए दावे शामिल हैं⁴², भावी किराए के लिए दावा⁴³, निष्पादक संविदा का लाभ⁴⁴, किसी कंपनी में शेयर पर लाभांश प्राप्त करने का अधिकार।⁴⁵

धारा 130 को टीपीए की धारा 6 के साथ पढ़ा जाना चाहिए जिसमें कहा गया है कि किसी भी प्रकार की संपत्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है, सिवाय इसके कि कानून द्वारा अन्यथा प्रदान किया गया हो। धारा 6 (ई) में प्रावधान है कि मुकदमा करने के एकमात्र अधिकार को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। 1900 में अपने संशोधन से पहले, खंड में प्रावधान किया गया था कि "धोखाधड़ी के लिए मुआवजे या अवैध रूप से होने वाले नुकसान के लिए मुकदमा करने का एकमात्र अधिकार स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है"। हालांकि, एक संशोधन के माध्यम से धारा 6 (ई) को "मुकदमा करने एकमात्र अधिकार" के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए संशोधित किया गया था और न केवल धोखाधड़ी के लिए मुकदमा करने या अवैध रूप से होने वाले नुकसान के लिए मुकदमा करने के एकमात्र अधिकार का हस्तांतरण। इसलिए धारा 6 के दायरे का विस्तार किया गया था और जबकि टीपीए की धारा 130 के अनुसार एक कार्रवाई योग्य दावे को स्थानांतरित किया जा सकता है, मुकदमा करने का एकमात्र अधिकार हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। इस प्रावधान की उत्पत्ति रखरखाव में चैम्पर्टी के विरुद्ध नियम है।

जैसा कि भारत संघ बनाम श्री सारा मिल्स लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था⁴⁶, संपत्ति का असाइनमेंट वैध है, भले ही वह संपत्ति मुकदमेबाजी के बिना प्राप्त नहीं

⁴¹ भारत संघ बनाम श्री शारदा मिल्स लिमिटेड, 1973 एससीआर (2) 484

⁴² दया देवी बनाम चपला देवी, एआईआर 1960 काल 378

⁴³ चिदंबरम पिल्लै बनाम दोराईस्वामी चेट्टी, एआईआर 1916 मैड 974

⁴⁴ जहर मेहर अली बनाम बज-बज जूट मिल्स, आईएलआर 34 कैल 289

⁴⁵ दया बाई बनाम अंबा लाल, एआईआर 1981 एससी 156

⁴⁶ भारत संघ बनाम श्री शारदा मिल्स लिमिटेड, 1973 एससीआर (2) 484

की जा सकती है। हालांकि, नुकसान के लिए कार्रवाई का एकमात्र अधिकार, चाहे वह अनुबंध या टोर्ट के तहत हो, असाइन करने योग्य नहीं है क्योंकि, कानून किसी भी लेनदेन को मान्यता नहीं देगा जिसमें चैम्पर्टी के रखरखाव का आभास हो सकता है। यह केवल तब होता है जब विषय-वस्तु में रुचि होती है कि किसी लेनदेन को रखरखाव के आरोप से बचाया जा सकता है। उस हित को असाइनमेंट के अलावा मौजूद होना चाहिए और उस हद तक इससे स्वतंत्र होना चाहिए। जब कार्रवाई का अधिकार संपत्ति या अनुबंध से जुड़ी घटनाओं में से एक है, तो इसे कार्रवाई के एकमात्र अधिकार के रूप में नहीं माना जाएगा।

*गंगाराजू बनाम गोपाला में*⁴⁷, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने इस बात की जांच की कि क्या भूमि के हस्तांतरण के साथ-साथ भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ की वसूली के अधिकार का हस्तांतरण टीपीए की धारा 6 (ई) द्वारा प्रभावित होता है। न्यायालय ने कहा कि इक्विटी ने 'कार्रवाई के एकमात्र अधिकार' के असाइनमेंट की अनुमति क्यों नहीं दी, इसका वास्तविक कारण इस आधार पर था कि इसके कारण रखरखाव होने की संभावना थी। न्यायालय ने कहा कि:

"...जल्द ही कार्रवाई के एकमात्र अधिकार के नियम के लिए एक असाइन करने योग्य अपवाद मान्यता दिए जाने के लिए आया था। यह कार्रवाई का अधिकार सौंपे जाने का अपवाद प्रदान करता है यदि यह संपत्ति की सुविधा के लिए आकस्मिक या सहायक हो। उपर्युक्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से यह स्पष्ट है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 (ई) कितनी बारीकी से, जो प्रदान करती है कि मुकदमा करने का एकमात्र अधिकार हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, कार्रवाई के एकमात्र अधिकार के अपवाद से जुड़ा हुआ है जो असाइन करने योग्य नहीं है। यह समान रूप से स्पष्ट है कि प्रावधान का उद्देश्य लेन-देन के खिलाफ किया जा रहा है जो ब्रिटिश कानून के अनुसार चैम्पर्टी और रखरखाव के बराबर होगा, जब भी कोई लेनदेन इस तरह के शुल्क से मुक्त होगा तो यह वैध होगा..."

न्यायालय ने यह भी माना कि "चैम्पर्टी और रखरखाव के सिद्धांत को इस देश में पूरी तरह से नहीं अपनाया गया है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 (ई) का दायरा इससे आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए कि इसकी मंशा प्रतिबंध लगाने की थी" और और यह

⁴⁷गंगाराजू बनाम गोपाल एआईआर 1957 एपी 190

कि टीपीए की धारा 6 (ई) को लाभ की वसूली के अधिकार के उस असाइनमेंट को कवर नहीं करना चाहिए, जो संपत्ति के अलगाव द्वारा समर्थित है, जिसमें से लाभ उत्पन्न हुआ, और संपत्ति के फायदे के साथ पर्याप्त रूप से जुड़ा हुआ है।

कार्रवाई योग्य दावे के असाइनमेंट करने और दावे पर मुकदमा करने के एकमात्र अधिकार के असाइनमेंट के बीच के अंतर की जांच भारतीय अदालतों द्वारा कई मामलों में की गई है। उदाहरण के लिए, एक अनुबंध के तहत लाभों को कार्रवाई योग्य दावे माना जाता है और उन्हें असाइन किया जा सकता है, अनुबंध के उल्लंघन के मामले में नुकसान के लिए मुकदमा करने का एकमात्र अधिकार एक कार्रवाई योग्य दावा नहीं माना जाता है और इसलिए टीपीए की धारा 6 (ई) को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।⁴⁸ जहां एक संपत्ति को उस संपत्ति के संबंध में नुकसान या मुआवजे की वसूली के अधिकार के साथ स्थानांतरित किया जाता है, उस अधिकार का असाइनमेंट वैध है और टीपीए की धारा 6 (ई) द्वारा प्रभावित नहीं होता है।⁴⁹

दिवाला के संदर्भ में

आईबीसी की धारा 3 (27) के तहत, "संपत्ति" में कार्रवाई योग्य दावे शामिल हैं। धारा 35 (बी) परिसमापक को कॉर्पोरेट ऋणी की सभी परिसंपत्तियों, संपत्ति, प्रभावों और कार्रवाई योग्य दावों को अपने कब्जे या नियंत्रण में लेने के लिए सशक्त और अधिदेशित करती है। धारा 36 (3) (एफ) में प्रावधान है कि परिसमापन संपत्ति में लेन-देन से बचने के लिए कार्यवाही के माध्यम से वसूली गई कोई भी संपत्ति या उनका मूल्य शामिल होगा।

परिसमापक के पास धारा 35 (एफ) के तहत, आईबीसी की धारा 52 के अधीन, अचल और चल संपत्ति और सार्वजनिक नीलामी या निजी अनुबंध द्वारा परिसमापन में कॉर्पोरेट ऋणी के कार्रवाई योग्य दावों को बेचने की शक्ति और कर्तव्य भी है, जो आईबीसी की धारा 29 ए के तहत अयोग्य नहीं है।

यह कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत उस स्थिति के समान है जहां परिसमापक के पास परिसमापन में अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के कार्रवाई योग्य दावों को बेचने की शक्ति थी।

⁴⁸यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रमन आयरन फाउंड्री, 1974 एससीआर (3) 556

⁴⁹मुरलीधर अग्रवाल बनाम रूपेंद्र मेथेरे, एआईआर 1953 कैल 321

इसलिए, संपत्ति के एक हिस्से के रूप में कार्रवाई योग्य दावा, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 ("**परिसमापन विनियम**") के तहत निर्धारित बिक्री के तरीके और तरीके का पालन करते हुए आईबीसी के तहत परिसमापक द्वारा असाइन या स्थानांतरित किया जा सकता है। परिसमापक समग्र कंपनी या व्यवसाय के हिस्से के रूप में इस तरह के कार्रवाई योग्य दावों को बेच सकता है (कंपनी की बिक्री के मामले में एक चिंता के रूप में या व्यवसाय की बिक्री के रूप में जा रही चिंता के रूप में)। वह कॉर्पोरेट ऋणी की संपत्ति के एक हिस्से के रूप में कार्रवाई योग्य दावों को अलग से भी बेच सकती है। जब तक कॉर्पोरेट ऋणी के पास एक दावा है जो एक कार्रवाई योग्य दावा है और मुकदमा करने का एकमात्र अधिकार नहीं है, तब तक इसे टीपीए की धारा 130 के अनुसार परिसमापक द्वारा असाइन किया जा सकता है और जो सिद्धांत गैर-शोधन अक्षमता की स्थिति में कार्रवाई योग्य दावे के अर्थ और हस्तांतरण पर लागू होते हैं, वे परिसमापक द्वारा कार्रवाई योग्य दावे की बिक्री के मामले में समान रूप से लागू होंगे।

जहां तक कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया ("**सीआईआरपी**") के दौरान कार्रवाई योग्य दावों की बिक्री का संबंध है, आईबीसी की धारा 14 के तहत कॉर्पोरेट ऋणी द्वारा परिसंपत्तियों के निपटान पर रोक है, जब तक कि निपटान व्यवसाय के सामान्य तरीके से न हो या भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता (कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमों, 2016 के विनियमन 29 के तहत न हो, (जो कुछ शर्तों के अधीन बेहतर प्राप्ति के लिए आवश्यक होने पर सामान्य तरीके से अलग बिक्री की अनुमति प्रदान करता है, जिसमें लेनदारों की समिति का अनुमोदन भी शामिल है)। इसलिए, सीआईआरपी के दौरान समाधान व्यावसायिक द्वारा कार्रवाई योग्य दावों के हस्तांतरण की सीमित प्रासंगिकता है, सिवाय तरजीही लेनदेन⁵⁰, कम मूल्य वाले लेनदेन⁵¹, धोखाधड़ी वाले लेनदेन⁵², जबरन वसूली क्रेडिट लेनदेन⁵³ और धोखाधड़ी या गलत तरीके से व्यापार के दावों के लिए दावों के हस्तांतरण के संबंध में⁵⁴ ("**आधिकारिक दावे**", बाद में चर्चा की गई)।

⁵⁰ धारा 43

⁵¹ धारा 45

⁵² धारा 49

⁵³ धारा 50

⁵⁴ धारा 66

समाधान व्यावसायिक के साथ-साथ परिसमापक के पास कॉर्पोरेट ऋणी⁵⁵ की ओर से मुकदमा और कार्यवाही को स्थापित करने और/या जारी रखने की शक्ति और कर्तव्य है, हालांकि परिसमापक को कॉर्पोरेट ऋणी⁵⁶ की ओर से एक मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करने से पहले राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ("एनसीएलटी") का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए, सामान्य तौर पर, समाधान व्यावसायिक और परिसमापक से कार्रवाई करने की उम्मीद की जाएगी, यानी शुरू करें या जारी रखें (जहां पहले से ही लंबित है), कार्रवाई के कारणों के संबंध में कार्यवाही।

वास्तव में, कंपनी अधिनियम, 1956 (आईबीसी से पहले) के तहत बंद करने के मामलों में, आधिकारिक परिसमापक कार्रवाई योग्य दावों के लिए कार्यवाही करेगा और जबकि परिसमापन में आधिकारिक परिसमापक द्वारा संपत्ति अधिकारों (जैसे किरायेदारी या पट्टेदार अधिकारों) के हस्तांतरण से संबंधित उदाहरण हैं, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत परिसमापन में कार्रवाई योग्य दावों को असाइन करने वाले आधिकारिक परिसमापक के सीमित उदाहरण हैं।

हालांकि, आईबीसी के तहत परिसमापन व्यवस्था अलग है। परिसमापन प्रक्रिया एक दिवाला व्यवसायी द्वारा चलाया जाता है (और आधिकारिक परिसमापक द्वारा नहीं)। कॉर्पोरेट ऋणी की ओर से कार्रवाई के कारणों का अनुसरण करने में शामिल लागतों को छोड़ने पर भी परिसमापकों को अपनी लागतों को कवर करने में भी भारी लागत बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत बंद करने की व्यवस्था के विपरीत, आईबीसी के तहत परिसमापन प्रक्रिया समयबद्ध है। परिसमापक से उम्मीद की जाती है कि वह परिसमापन शुरू होने की तारीख के एक वर्ष में परिसमापन प्रक्रिया को पूरा करेगा जब तक कि एनसीएलटी द्वारा इस अवधि को नहीं बढ़ाया जाता है। परिसमापक द्वारा कार्रवाई के कारणों की खोज के लिए स्वयं समय और धन की आवश्यकता होगी, जिनमें परिसमापन के दौरान दोनों की आपूर्ति कम है। इसलिए, परिसमापक के लिए कार्रवाई योग्य दावों को बेचना और परिसमापन प्रक्रिया को जितनी जल्दी हो सके बंद करना वांछनीय है।

⁵⁵ धारा 25(2) और धारा 35

⁵⁶ धारा 33(5)

हालांकि, कार्रवाई के कारण हो सकते हैं जो कार्रवाई योग्य दावे की श्रेणी में नहीं आते हैं और इसके बजाय उन्हें 'मुकदमा करने के एकमात्र अधिकार' के रूप में माना जाता है (उदाहरण के लिए कॉर्पोरेट ऋणी द्वारा टोर्ट में नुकसान के लिए कोई मुकदमा)। इस तरह के दावे परिसमापक द्वारा असाइन करने योग्य नहीं होंगे और इसलिए, जहां ऐसे दावों के संबंध में कार्यवाही / मुकदमे लंबित हैं, वहां कार्यवाही / मुकदमे को विघटन से पहले परिसमापक द्वारा बंद करने की आवश्यकता हो सकती है। इसी तरह, कार्रवाई के कारण होंगे जो अपने कार्यालय (उदाहरण के पदाधिकारियों के दावे) के आधार पर समाधान व्यावसायिक या परिसमापक में निहित होंगे। ये दावे 'मुकदमा करने के एकमात्र अधिकार' की श्रेणी में भी आ सकते हैं और इसलिए टीपीए की धारा 6 (ई) के तहत निषेध के कारण असाइन करने योग्य नहीं हो सकते हैं, जब तक कि आईबीसी इस तरह के दावों के असाइनमेंट की अनुमति देने वाला ओवरराइडिंग अपवाद नहीं करता है।

परिसमापन विनियमों में संशोधन

अगस्त 2020 में, आईबीबीआई ने 'कॉर्पोरेट परिसमापन प्रक्रिया पर चर्चा पत्र' लाया था, जिसमें 'आसानी से वसूली योग्य परिसंपत्तियों' ("एनआरआरए") के असाइनमेंट के संबंध में परिसमापन विनियमों में अपने प्रस्तावित संशोधन पर टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं। इस पत्र में, आईबीबीआई ने मान्यता दी कि परिसमापन संपत्ति में ऐसी परिसंपत्तियां भी शामिल हैं जिन्हें ऐसी परिसंपत्तियों या विशेष परिस्थितियों की अजीब प्रकृति के कारण उनकी प्राप्ति के लिए अनिश्चित समय की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी परिसंपत्तियां सरकार और उसकी एजेंसियों से रिफंड सहित विभिन्न ऋणों की श्रेणी में आती हैं; आकस्मिक प्राप्य, विवादित प्राप्य, उप-न्यायिक प्राप्य, विवादित संपत्तियां (जहां, उदाहरण के लिए, कानूनी स्वामित्व स्पष्ट नहीं है), और परिहार लेनदेन के अंतर्निहित परिसंपत्तियां।

आईबीबीआई ने माना कि परिसमापन निधि में एनआरआरए की उपस्थिति आईबीसी के तहत परिकल्पित परिसमापन प्रक्रिया के समयबद्ध समापन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हानिकारक है और गतिरोध की स्थिति पैदा करती है क्योंकि वसूली योग्य राशि एक बेहतर अनुमान है। आईबीबीआई ने यह भी माना कि परिसमापक द्वारा एनआरआरए की वसूली में शामिल कानूनी खर्चों को पूरा करने के लिए धन की कमी और वसूली में देरी और अनिश्चितता परिसंपत्तियों में मूल्य को अनलॉक करने में एक बड़ी बाधा है। इसलिए, यह किसी भी राशि के लिए एनआरआरए के असाइनमेंट पर विचार करने के लायक है,

बाजार भुगतान करने के लिए तैयार है, और हितधारकों के बीच इसे वितरित करने और परिसमापन प्रक्रिया को बंद करने के लिए तैयार है।

पत्र में एनआरआरए के असाइनमेंट के लिए परिसमापक द्वारा पालन किए जाने वाले नियंत्रण और संतुलन और सिद्धांतों के साथ विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की गई थी। प्रारूप विनियमों पर टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद, आईबीबीआई ने परिसमापन विनियमों में एक संशोधन जारी किया और परिसमापन विनियमों में विनियमन 37ए जोड़ा।

विनियमन 37ए एनआरआरए को परिसमापन संपत्ति में शामिल किसी भी परिसंपत्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसे उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से बेचा नहीं जा सकता है और इसमें आकस्मिक या विवादित परिसंपत्तियां और संपत्ति शामिल हैं जो अधिमान्य, कम मूल्य वाली, जबरन वसूली क्रेडिट और धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए कार्यवाही के लिए अंतर्निहित हैं, जिन्हें आईबीसी की धारा 43 से 51 और धारा 66 में संदर्भित किया गया है।

विनियमन 37ए में प्रावधान है कि एक परिसमापक किसी भी व्यक्ति के विचार के लिए हितधारकों की परामर्श समिति के परामर्श से एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से एक एनआरआरए को असाइन या स्थानांतरित कर सकता है, जो कॉर्पोरेट ऋणी के दिवाला समाधान के लिए एक समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र है।

इसलिए विनियमन 37ए परिसमापन में एनआरआरए के असाइनमेंट के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, जिनमें से कई कार्रवाई और / या कार्रवाई योग्य दावों के कारणों के अर्थ में आते हैं। जैसा कि चर्चा की गई है, परिसमापन विनियमों के अलावा, परिसमापक के पास कार्रवाई योग्य दावों को असाइन करने की शक्ति है। महत्वपूर्ण रूप से, एनआरआरए की परिभाषा में आकस्मिक और विवादित परिसंपत्तियां और आईबीसी की धारा 43 से 51 और धारा 66 में संदर्भित तरजीही, कम मूल्य, जबरन वसूली वाले क्रेडिट और धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए अंतर्निहित कार्यवाही शामिल हैं। इसलिए एनआरआरए, सीडी की एक 'संपत्ति' है, या तो अचल या चल संपत्ति के रूप में (कुछ मामलों में परिहार कार्यवाही के अधीन) या एक अमूर्त अधिकार या एक कार्रवाई योग्य दावे के रूप में।

तथापि, टीपीए की धारा 6 (ई) के तहत निषेध के कारण मुकदमा करने का एकमात्र अधिकार अभी भी असाइन करने योग्य नहीं है और इसलिए, कंपनी/परिसमापक के दावे ऐसी श्रेणी में आते हैं, जैसे कि धारा 66 के तहत धोखाधड़ी या गलत तरीके से व्यापार के दावों को

अभी भी विनियमन 37 ए के बावजूद प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके अलावा, कोई भी दावा जो सीडी था जो मुकदमा करने के अधिकार में आता है (उदाहरण के लिए टोट में नुकसान के लिए सीडी द्वारा कोई भी मुकदमेबाजी) वह भी परिसमापक द्वारा असाइन करने योग्य नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों में, यदि ऐसे मामले लंबित हैं, तो उन्हें विघटन से पहले बंद करने की आवश्यकता होगी।

जैसा कि चर्चा की गई है, भारत में चैम्पर्टी और रखरखाव के सिद्धांत को पूरी तरह से नहीं अपनाया गया है और इसलिए, टीपीए की धारा 6 (ई) को उससे आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए जिसमें इसे प्रतिबंधित करने का इरादा था। इस नियम की उत्पत्ति सार्वजनिक नीति और दिवाला संदर्भ में हुई है, जहां परिसमापन संपदा को समाप्त करने की आवश्यकता है, हितधारकों को वितरित की गई राशि और सीडी को समयबद्ध तरीके से भंग कर दिया गया है, सभी लंबित कार्यवाही के तहत दावों का असाइनमेंट और आधिकारिक दावों के असाइनमेंट को किसी भी सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसके बजाय, इस तरह के असाइनमेंट की अनुमति देने से आईबीसी के उद्देश्य को बढ़ावा मिलेगा, जो समयबद्ध तरीके से सीडी की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करेगा।

हालांकि, इसमें शामिल दावों की प्रकृति को देखते हुए, साथ ही साथ उन चुनौतियों को देखते हुए जो बिक्री के उद्देश्य से ऐसे दावों के मूल्यांकन में उत्पन्न होने के लिए बाध्य हैं, नियामक को ऐसे दावों के असाइनमेंट के लिए एक रूपरेखा प्रदान करनी चाहिए। वास्तव में विनियम 37क के अंतर्गत कुछ रूपरेखा प्रदान की गई है जिसमें हितधारक परामर्श समिति की निगरानी का प्रावधान है।⁵⁷

एक और मुद्दा जिस पर विचार किया जाना चाहिए वह कॉर्पोरेट ऋणी के समाधान के मामले में समाधान व्यावसायिक द्वारा आधिकारिक दावों के असाइनमेंट की संभावना है। यह एक समाधान योजना के तंत्र के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और असाइनमेंट लेनदारों या समाधान आवेदक के पक्ष में हो सकता है। यह देखा गया है कि एनसीएलटी द्वारा एक समाधान योजना को अनुमोदित किए जाने तक इस तरह के दावे अक्सर असमायोजित रहते हैं और लेनदारों को शायद ही कभी इन कार्यवाही का लाभ मिलता है। यहां तक कि जहां समाधान योजना के अनुमोदन से पहले एनसीएलटी द्वारा निर्णय

⁵⁷ इस समिति में कॉर्पोरेट देनदार के विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति विशुद्ध रूप से सलाहकार है।

लिया गया था, वहां एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है जो समाधान योजना के अनुमोदन के समय लंबित रहती है। इसके अलावा, एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन पर, समाधान व्यावसायिक अधिकारहीन हो जाता है। वीनस रिक्वैटर्स⁵⁸ में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, जब तक समाधान योजना इसके लिए प्रदान नहीं करती है, तब तक समाधान व्यावसायिक को समाधान योजना के अनुमोदन के बाद ऐसी कार्यवाही जारी रखने की अनुमति नहीं है। यह भी देखा गया है कि समाधान व्यावसायिकों के पास कोई समर्थन नहीं है, विशेष रूप से समाधान योजना के अनुमोदन के बाद इन कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए धन के रूप में। ऐसी परिस्थितियों में, यह वांछनीय है कि ऐसी कार्यवाही के तहत दावों के असाइनमेंट का एक ढांचा प्रदान किया जाए।

हाल ही में आईबीबीआई ने कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में देरी को कम करने से संबंधित मुद्दों पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। परामर्श पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि आईबीबीआई के पास 28 फरवरी, 2022 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, लगभग 200,000 करोड़ रुपये मूल्य के परिहार लेनदेन के संबंध में 708 आवेदन एनसीएलटी के पास दायर किए गए हैं और इनमें से एनसीएलटी द्वारा केवल मुट्ठी भर आवेदनों का निपटान किया गया है और इन आवेदनों का निपटान करने वाले एनसीएलटी के आदेशों के खिलाफ कुछ अपीलें दायर की गई हैं। समाधान योजना के अनुमोदन और कार्यान्वयन के बाद भी ऐसे कई आवेदन लंबित हैं। आईबीबीआई ने विचार किया कि आवेदनों को किसके द्वारा और कैसे तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाएगा और उसने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 में संशोधन का सुझाव दिया है, जिसमें यह आवश्यक है कि समाधान योजना को समाधान योजना के अनुमोदन के बाद परिहार लेनदेन या धोखाधड़ी या गलत तरीके से व्यापार के संबंध में कार्यवाही को आगे बढ़ाने के तरीके प्रदान करने चाहिए।

ब्रिटिश कानून से सबक

ब्रिटिश और भारतीय दोनों कानून के तहत, एक दावे को दिवालिया / शोधन अक्षमता की संपत्ति माना जाता है और इसलिए लेनदारों के लाभ के लिए मूल्य के लिए परिसमापक द्वारा असाइन किया जा सकता है। हालांकि, जब यह कार्रवाई के कारण के असाइनमेंट

⁵⁸ मेसर्स वीनस रिक्वैटर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी. (सी) 8705/2019

की बात आती है, तो ब्रिटिश और भारतीय कानून अलग-अलग हैं जो शोधन अक्षमता के संदर्भ में संपत्ति के किसी भी हस्तांतरण से अलग होने वाले को मुकदमा चलाने का एकमात्र अधिकार है।

जबकि कार्रवाई के एकमात्र कारणों के असाइनमेंट पर प्रतिबंध गैरकानूनी रखरखाव और चैम्पर्टी के खिलाफ नियम से पैदा हुआ है, ब्रिटिश कानून परिसमापक, प्रशासकों और ट्रस्टियों की विशेष स्थिति को मान्यता देता है और उन्हें दिवाला/शोधन अक्षमता के संदर्भ में कार्रवाई के एकमात्र कारणों को असाइन करने के लिए वैधानिक शक्तियां दी गई हैं। 2015 से पहले, ब्रिटेन में, यह वैधानिक शक्ति केवल कार्रवाई के कारणों के असाइनमेंट तक ही थी जो समापन के समय कंपनी में निहित थी और प्रशासकों या परिसमापकों में निहित कार्रवाई के कारणों तक उनके अधिकार के कारण विस्तारित नहीं थी, जैसे कि परिहार लेनदेन या धोखाधड़ी या गलत व्यापार (यानी आधिकारिक दावे) से उत्पन्न होने वाली कार्रवाई के कारण। 2015 में, SBEEA के माध्यम से 1986 अधिनियम में एक संशोधन के साथ, प्रशासकों और परिसमापकों को अयोग्य आधार पर भी आधिकारिक दावों को असाइन करने की अनुमति दी गई थी।

दूसरी ओर, भारत में, जबकि चैम्पर्टी और रखरखाव के सिद्धांत को पूरी तरह से अपनाया नहीं गया है, टीपीए की धारा 6 (ई) केवल मुकदमा करने के अधिकार के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। शोधन अक्षमता के संदर्भ में मान्यता प्राप्त कोई विशिष्ट अपवाद नहीं है, या तो औपचारिक शोधन अक्षमता में प्रवेश करने के समय कंपनी में निहित कार्रवाई के स्पष्ट कारणों के असाइनमेंट के लिए या आधिकारिक दावों के लिए जो समाधान व्यावसायिक या परिसमापक में निहित हैं।

ऐसे कई कारण हैं कि एक समाधान व्यावसायिक या परिसमापक कार्रवाई योग्य दावों के साथ-साथ कार्रवाई और आधिकारिक दावों के स्पष्ट कारणों को असाइन या स्थानांतरित करना चाहता है। समाधान व्यावसायिक या परिसमापक के पास अक्सर इस तरह के दावों पर कार्रवाई करने के लिए धन नहीं होता है और जहां परिणाम अनिश्चित और लंबा होता है वहां वे धन खर्च करना पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा, यह देखते हुए कि परिसमापन एक समयबद्ध प्रक्रिया है, लंबित कार्यवाही के तहत दावों के असाइनमेंट के लिए एक तंत्र होने की आवश्यकता है ताकि परिसमापक के पास वितरण के लिए तत्काल धन हो और कंपनी को तेजी से बंद किया जा सके। एक समाधान प्रक्रिया में, समाधान व्यावसायिक

आधिकारिक दावों को असाइन करना चाह सकता है जहां समाधान योजना के अनुमोदन के समय ऐसे दावे असमायोजित रहते हैं।

चूंकि इनमें से कुछ दावों का असाइनमेंट टीपीए की धारा 6 (ई) के तहत निषिद्ध हो सकता है, इसलिए आईबीसी को अनुमति देने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए: (क) कार्रवाई के स्पष्ट कारणों का असाइनमेंट; (ख) टीपीए के बावजूद, आधिकारिक दावों का असाइनमेंट।

इसके अलावा, जबकि कानून को सामाधान व्यावसायिक और परिसमापक द्वारा कार्रवाई के कारणों के असाइनमेंट की अनुमति देनी चाहिए, असाइनमेंट हर मामले में सही जवाब नहीं हो सकता है। ब्रिटेन में न्यायिक उदाहरणों से कई सबक निकाले जा सकते हैं, दृष्टिकोण पर जो कार्रवाई का कारण असाइन करने के लिए आगे बढ़ने से पहले समाधान व्यावसायिक और परिसमापक द्वारा पालन किया जाना चाहिए। इनमें से कुछ हैं:

- समाधान व्यावसायिक / परिसमापक को कार्रवाई के सभी वर्तमान और संभावित कारणों की पहचान करनी चाहिए जो कंपनी के पास हो सकते हैं और प्रतिवादी (यों) जो कार्रवाई के कारण के पक्षकार हैं या होंगे।
- जहां दावा व्यवहार्य है, समाधान व्यावसायिक / परिसमापक को यह जांचना चाहिए कि क्या तीसरे पक्ष को दावा असाइन करने के विरोध में उसके द्वारा उसका अनुसरण किया जाना चाहिए। समाधान प्रक्रिया के संदर्भ में, समाधान व्यावसायिक को परिसंपत्तियों के निपटान पर स्थगन को भी ध्यान में रखना होगा, सिवाय इसके कि निपटान सामान्य तौर पर है या भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियमन 29 के अनुसार है।
- ऐसे विभिन्न कारक हैं जो समाधान व्यावसायिक / परिसमापक असाइनमेंट पर निर्णय लेते समय विचार कर सकते हैं - जैसे - क्या उसके पास अपने दम पर दावों की जांच करने और आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त धन है, दावों को पुनर्प्राप्त करने में लगने वाला संभावित समय, क्या असाइनमेंट पर अनुबंध निषेध जैसे असाइनमेंट पर कोई प्रतिबंध है। समाधान व्यावसायिक / परिसमापक को सीमा से जुड़े मुद्दों पर भी विचार करना चाहिए और क्या उसे दावे के लिए सीमा अवधि को संरक्षित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है (असाइनमेंट से पहले भी)।
- यदि समाधान व्यावसायिक / परिसमापक के लिए अपने दम पर कार्रवाई के कारण को आगे बढ़ाने के लिए अपर्याप्त धन हैं, तो समाधान व्यावसायिक / परिसमापक

एक असाइनमेंट पर आगे बढ़ने से पहले वित्त पोषण के वैकल्पिक साधनों पर विचार करना चाह सकता है, जैसे कि धन या तीसरे पक्ष के वित्तपोषण के लिए लेनदारों से संपर्क करना। जैसा कि भारत में तीसरे पक्ष के मुकदमेबाजी वित्तपोषण के लिए बाजार विकसित हो जाता है, यह दावों के एकमुश्त असाइनमेंट के विपरीत कुछ मामलों में एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है।

- यदि वित्तपोषण के वैकल्पिक साधन भी उपलब्ध नहीं हैं, तो कार्रवाई के कारण के असाइनमेंट पर विचार किया जाना चाहिए। असाइनमेंट के विभिन्न रूपों को समाधान व्यावसायिक / परिसमापक द्वारा माना जा सकता है जैसे कि एक निश्चित मूल्य या असाइनमेंट के लिए एकमुश्त असाइनमेंट जहां कंपनी कार्रवाई के कारण की आय में रुचि रखती है। समाधान व्यावसायिक / परिसमापक को इस बात पर विचार करना चाहिए कि इनमें से कौन सा कार्रवाई के किसी विशेष कारण के असाइनमेंट के लिए अधिक उपयुक्त होगा। उदाहरण के लिए, जहां समाधान व्यावसायिक / परिसमापक का मानना है कि प्रासंगिक कार्यवाही को बंद करने में लंबा समय लगेगा या जहां तीसरे पक्ष की लागत के आदेश का खतरा है, एकमुश्त असाइनमेंट अधिक वांछनीय हो सकता है। दूसरी ओर, जहां दावा उच्च मूल्य का है और कम समय में तय होने की संभावना है, एक बेहतर वसूली अच्छी तरह से आय का एक हिस्सा बनाए रखने वाले असाइनर द्वारा प्राप्त की जा सकती है।
- समाधान व्यावसायिक / परिसमापक को मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या दावा तुच्छ या परेशान करने वाला है। हालांकि, उनका ध्यान लेनदारों के लाभ के लिए मूल्य अधिकतमीकरण होना चाहिए, बजाय मुकदमेबाजी द्वारा परेशान किए जाने की संभावना से किसी तीसरे पक्ष की रक्षा करने पर। समाधान व्यावसायिक / परिसमापक को असाइनमेंट को केवल तभी अस्वीकार करना चाहिए जब यह स्पष्ट हो कि दावा निराशाजनक है और असाइनी केवल तीसरे पक्ष को परेशान करने के लिए दावा कर सकता है।
- कार्रवाई के कारणों के असाइनमेंट के लिए अदालत (यानी एनसीएलटी) की सहमति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और इसे समाधान व्यावसायिक / परिसमापक के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। हालांकि, असाइनमेंट पर समाधान व्यावसायिक / परिसमापक के निर्णय पर कुछ निरीक्षण होना चाहिए। दिवाला समाधान के दौरान, कार्रवाई के कारणों का असाइनमेंट लेनदारों की समिति के अनुमोदन के अधीन और परिसमापन के दौरान हितधारक परामर्श समिति के परामर्श के अधीन किया जा सकता है।

- विशेष रूप से दिवाला समाधान प्रक्रिया के संदर्भ में, समाधान योजना को एक तंत्र प्रदान करना चाहिए कि कौन अधिकारी दावों का अनुसरण करेगा। समाधान योजना या तो आधिकारिक दावों को बनाए रखने या समाधान आवेदक या लेनदारों की समिति को इसके असाइनमेंट के लिए एक तंत्र प्रदान कर सकती है। इस तरह के तंत्र पर तब चर्चा की जा सकती है और समाधान योजना के अनुमोदन के हिस्से के रूप में लेनदारों की समिति द्वारा मतदान किया जा सकता है। समाधान व्यावसायिक / परिसमापक को दावे के गुण-दोष, मात्रा और लागतों सहित स्वतंत्र कानूनी सलाह लेनी चाहिए और यह आकलन करते समय प्रवर्तन जोखिम पर विचार करना चाहिए कि क्या दावे का अनुसरण किया जा सकता है, त्याग किया जा सकता है या असाइन किया जा सकता है और यदि असाइन किया गया है, तो किन शर्तों पर।
- असाइनमेंट लेने के लिए प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए, अधिकारी कंपनी के लेनदारों, शेयरधारकों और निदेशकों या तीसरे पक्ष के वित्त पोषकों जैसे हितधारकों से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी / संभावित प्रतिवादी को दावा प्राप्त करने में रुचि हो सकती है। हालांकि, असाइनी को आईबीसी की धारा 29 ए के तहत अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।
- कार्रवाई के कारण के मूल्यांकन के संबंध में चुनौतियां उत्पन्न होने की संभावना है और शायद जटिल दावे का उचित मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता नहीं हो। समाधान व्यावसायिक / परिसमापक को मूल्यांकन सलाह की आवश्यकता पर विचार करना चाहिए और असाइनमेंट के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने के लिए एक नीलामी या अन्य प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया पर भी विचार करना चाहिए। चूंकि कार्रवाई के कारणों के असाइनमेंट में मूल्य के अलावा अन्य शर्तें हो सकती हैं (जैसे कि क्षतिपूर्ति जो प्रतिकूल लागत आदेश के मामले में अधिकारी को असाइनी द्वारा प्रदान की जा सकती है), इसलिए अधिकारी को उच्चतम ऑर्डर को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। सभी मामलों में, अधिकारी को कार्रवाई के कारण में मूल्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करना चाहिए।
- समाधान व्यावसायिक / परिसमापक को असाइनमेंट के रूप पर विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वही लिखित रूप में और उचित कानूनी रूप में है। समाधान व्यावसायिक / परिसमापक को प्रतिकूल लागतों के खिलाफ क्षतिपूर्ति की आवश्यकता पर भी विचार करना चाहिए और क्या क्षतिपूर्ति के सुदृढीकरण की तलाश करनी है।

यह कहने में कोई लाभ नहीं है कि कार्रवाई में चुने गए का असाइनमेंट लेनदारों के लिए मूल्य बना सकता है और परिसमापन प्रक्रिया को जल्दी बंद करने में मदद कर सकता है। इस तरह के असाइनमेंट को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत में एक कानूनी और नियामक ढांचा वांछनीय है। भारत के लिए एक मजबूत व्यवस्था विकसित करने के लिए ब्रिटेन का सबक अमूल्य होगा।

समाधान प्रक्रिया में एडीआर तकनीक

केनेथ लिम ताओ चुंग और च्यू जिंग वेई

समाधान प्रक्रिया में एडीआर तकनीक

केनेथ लिम ताओ चुंग, पार्टनर, एलन एंड ग्लेडहिल एलएलपी

च्यू जिंग वेई, सीनियर एसोशिएट, एलन एंड ग्लेडहिल एलएलपी

सारांश

यह पेपर परिसमापन की श्रेणियों, व्यवस्था की योजनाओं, न्यायिक प्रबंधन और प्राप्ति (receivership) की श्रेणियों में कॉर्पोरेट दिवाला के प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सिंगापुर के दिवाला शासन का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है। विशेष रूप से, दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम के तहत व्यवस्था की योजना और समझौता प्रक्रिया से संबंधित नई विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है।

इस पेपर के दूसरे भाग में सिंगापुर में वैकल्पिक विवाद समाधान, विशेष रूप से बीचबचाव और मध्यस्थता पर चर्चा की गई है। पेपर में सामान्य संदर्भ के साथ-साथ दिवाला संदर्भ में मध्यस्थता और विवाचन पर चर्चा किया गया है। जहां प्रासंगिक हो, दिवाला संदर्भ में वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) के उपयोग के संबंध में चुनौतियों पर भी चर्चा की गई है।

सिंगापुर दिवाला कानून का संक्षिप्त विवरण

परिचय

सिंगापुर में दिवाला कानून मोटे तौर पर व्यक्तिगत दिवाला (या शोधन अक्षमता) और कॉर्पोरेट दिवाला में विभाजित है। इन क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले कानून का प्राथमिक स्रोत दिवाला, पुनर्गठन और विघटन अधिनियम 2018 ("आईआरडीए") है, जैसा कि विभिन्न सहायक कानूनों और कंपनी अधिनियम द्वारा संपूरित है। पहले, व्यक्तिगत दिवाला और कॉर्पोरेट दिवाला मुख्य रूप से क्रमशः शोधन क्षमता अधिनियम और कंपनी अधिनियम द्वारा शासित होते थे, हालांकि शोधन अक्षमता अधिनियम के कुछ पहलू कॉर्पोरेट दिवाला पर भी लागू होते थे। आईआरडीए सिंगापुर के व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट दिवाला और ऋण पुनर्गठन कानूनों को समेकित करता है, कॉर्पोरेट दिवाला के कानून का आधुनिकीकरण करता है, और वित्तीय संकट में कंपनियों के

पुनर्वास के लिए अधिक अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न ऋण पुनर्गठन व्यवस्था को मजबूत करता है। कॉर्पोरेट दिवाला को निम्नलिखित चार श्रेणियों में विभाजित

किया जा सकता है: परिसमापन, व्यवस्था की योजनाएं, न्यायिक प्रबंधन और प्राप्ति। यह लेख व्यक्तिगत दिवाला के बजाय कॉर्पोरेट दिवाला पर केंद्रित है।

परिसमापन

"परिसमापन" या "समापन" एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां एक कंपनी की संपत्ति एकत्र और वसूल की जाती है। परिणामी वसूली का उपयोग कंपनी की देनदारियों का भुगतान करने के लिए किया जाता है, जिसमें अधिशेष शेयरधारकों के पास जाता है। कंपनी के गैर-तरजीही असुरक्षित लेनदारों के बीच कंपनी की संपत्ति के वितरण में, नियम आमतौर पर आनुपातिक या समान आधार पर वितरण होता है। परिसमापन या समापन का परिणाम आमतौर पर कंपनी का विघटन होता है।

परिसमापन के दो मुख्य प्रकार हैं: स्वैच्छिक और अनिवार्य। आईआरडीए के अनुसार, दोनों में मुख्य अंतर परिसमापन की प्रक्रिया शुरू करने के तरीके में और इसके शुरू होने की तारीख में है:

- स्वैच्छिक परिसमापन के लिए, कंपनी आम तौर पर कंपनी को समाप्त करने के लिए शेयरधारकों की एक आम बैठक में एक संकल्प पारित करके प्रक्रिया शुरू करती है।
- अनिवार्य परिसमापन के लिए, कंपनी, या कोई अन्य पक्ष जिसके पास अधिकार है (जैसे कि लेनदार), कंपनी को परिसमाप्त करने के लिए न्यायालय में एक आवेदन करके प्रक्रिया शुरू करता है। आईआरडीए उन आधारों की एक सूची प्रदान करता है जिन पर न्यायालय किसी कंपनी को बंद करने का आदेश दे सकता है, जिसमें यह भी शामिल है कि कंपनी "अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ" है।

भले ही परिसमापन स्वैच्छिक हो या अनिवार्य, प्रक्रिया शुरू होने के बाद कई परिणाम सामने आएंगे। सामान्य तौर पर, परिणामों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- कंपनी का कारोबार आम तौर पर बंद हो जाएगा। हालांकि, परिसमापक कंपनी के व्यवसाय को जारी रख सकता है यदि कंपनी के लाभकारी समापन के लिए यह आवश्यक है।
- आम तौर पर, परिसमापन शुरू होने और परिसमापक की नियुक्ति के बाद निदेशकों की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं।

- प्रत्येक इनवॉइस, माल आर्डर या व्यावसायिक पत्र में कंपनी के नाम के बाद "परिसमापन में" शब्द शामिल करना होता है, जो कंपनी के साथ काम करने वाले सभी लोगों के लिए एक नोटिस के रूप में कार्य करता है।
- अनिवार्य परिसमापन की शुरुआत के बाद कंपनी की संपत्ति का कोई भी निपटान तब तक शून्य होगा जब तक कि अदालत आदेश न दे। शेयरों का कोई भी हस्तांतरण या सदस्यों की स्थिति में परिवर्तन भी आम तौर पर शून्य होगा।
- समापन के प्रारंभ के बाद कानूनी कार्यवाही अधिस्थगन होती है।
- परिसमापक के पास उन संपत्तियों के संबंध में दावों को वापस लेने के लिए कुछ शक्तियां होती हैं जिन्हें तीसरे पक्ष को स्थानांतरित कर दिया गया है।
- समापन के परिणामों से बचने के लिए, दिवाला कंपनी के पास तीन विकल्प होते हैं। यह व्यवस्था की योजना में प्रवेश करने और अपने लेनदारों के साथ समझौता करने का प्रयास कर सकता है, आईआरडीए की धारा 187 के तहत अपने लेनदारों के साथ व्यवस्था में प्रवेश कर सकता है, या न्यायिक प्रबंधन के तहत रखने की मांग कर सकता है।

व्यवस्था और समझौता की योजनाएं

व्यवस्था और समझौता की योजना के तहत, कंपनी को अपने लेनदारों द्वारा विचार के लिए एक योजना प्रस्ताव तैयार करना चाहिए। आम तौर पर, इसमें विभिन्न तरीकों से कंपनी के ऋणों के समझौते का प्रस्ताव शामिल होगा, जैसे कि कम राशि का भुगतान या ऋण के लिए इक्विटी जारी करना, आदि। कंपनी को अपने लेनदारों की बैठक बुलाने के लिए अदालत की मंजूरी लेनी होगी। यदि अनुमोदन प्रदान किया जाता है, तो लेनदारों की बैठक आयोजित की जाएगी और लेनदार प्रस्ताव पर विचार करेंगे और उस पर मतदान करेंगे। लेनदारों या लेनदारों के वर्ग को मूल्य में कम से कम तीन-चौथाई बहुमत और संख्या में उपस्थित और मतदान करने वाले में बहुमत से योजना का अनुमोदन करना चाहिए (जब तक कि अदालत अन्यथा आदेश न दे)।

यदि लेनदारों या लेनदारों के वर्ग की संख्या और मूल्य में अपेक्षित बहुमत योजना को मंजूरी देता है, तो योजना को बाध्यकारी बनाने के लिए, अदालत को योजना को मंजूरी देनी होगी। इस तरह का निर्णय लेने में, अदालत प्रासंगिक कारकों पर विचार करेगी जिसमें शामिल हैं कि क्या किसी योजना को प्रभावित करने के लिए वैधानिक आवश्यकताओं का पालन किया गया है, क्या कंपनी के लेनदारों को पर्याप्त जानकारी प्रदान की गई है, क्या लेनदारों को मतदान के प्रयोजनों के लिए

संबंधित वर्गों में उचित रूप से समूहीकृत किया गया था, क्या योजना की शर्तें उचित हैं और क्या योजना की शर्तें किसी लेनदार या लेनदारों के वर्ग के साथ अनुचित भेदभाव करती हैं। यदि अदालत योजना को मंजूरी देती है और योजना को मंजूरी देने का आदेश लेखा और कॉर्पोरेट नियामक प्राधिकरण के पास दायर किया जाता है, तो यह देनदार कंपनी और उसके लेनदारों के बीच बाध्यकारी हो जाता है। न्यायिक प्रबंधन में भी योजना की मांग की जा सकती है।

23 मई 2017 को और 30 जुलाई 2020 को, नए प्रावधान लागू हुए, जिसका उद्देश्य सिंगापुर के पुनर्गठन ढांचे और उसकी अंतर्राष्ट्रीय ऋण पुनर्गठन के केंद्र के रूप में स्थिति को सुधारना था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका शोधन अक्षमता संहिता के अध्याय 11 के कुछ हिस्सों को अनुकूलित करने वाले प्रावधान शामिल थे। प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:

स्वमेव खंड प्रतिबंध: नए प्रावधान किसी पार्टी को दिवाला कंपनी के साथ अनुबंध समाप्त करने या कुछ कार्रवाई करने से रोकते हैं, उदाहरण- कंपनी के दिवाला या व्यवस्था की योजना या न्यायिक प्रबंधन कार्यवाहियों के प्रारंभ होने के कारण किसी भी अधिकार या दायित्वों को समाप्त करना या संशोधित करना, या भुगतान में तेजी लाना (स्वमेव खंड प्रतिबंध(s))। उपरोक्त निषेध पार्टियों को अनुबंध समाप्त करने या कुछ कार्रवाई करने से प्रभावित नहीं करता है (i) उन कारणों से जो दिवाला या योजना या न्यायिक प्रबंधन कार्यवाही के प्रारंभ होने पर निर्भर नहीं हैं (उदाहरण के लिए मूल भुगतान या प्रदर्शन डिफॉल्ट पर भरोसा करके), (ii) योजना या न्यायिक प्रबंधन की कार्यवाही शुरू होने से पहले, या (iii) यदि अनुबंध या कंपनी प्रश्न में कार्व-आउट की एक निर्धारित सूची के भीतर आती है, जिनमें उपरोक्त स्वमेव खंड प्रतिबंधों को लागू नहीं माना जाता है।

105

अधिस्थगन: कुछ परिस्थितियों में सीमित स्वचालित अधिस्थगन होता है और अदालत एक कंपनी के पक्ष में अधिस्थगन का आदेश आगे भी दे सकती है जो एक नई योजना का प्रस्ताव कर रही है या प्रस्तावित करने का इरादा रखती है, यह लेनदारों को, अन्य बातों के अलावा, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकती है और कंपनी को अपने पुनर्गठन प्रस्ताव को आगे रखने के लिए पर्याप्त समय देती है। यह अधिस्थगन कंपनी की होल्डिंग कंपनियों या सहायक कंपनियों तक विस्तारित हो सकता है जो एक नई योजना का प्रस्ताव करना चाहते हैं, और कुछ लेनदारों को सिंगापुर के बाहर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने से भी रोक सकते हैं।

क्रैम-डाउन प्रावधान: पहले, यदि सभी वर्गों के लेनदारों से अपेक्षित बहुमत की मंजूरी प्राप्त की गई हो तो अदालत योजना को मंजूरी दे सकती थी। नए क्रैम डाउन प्रावधानों के तहत, अदालत एक योजना को मंजूरी दे सकती है, भले ही कुछ लेनदार वर्ग असहमत हों, बशर्ते कि:

(a) उन लेनदारों का संख्या में बहुमत जो समझौते या व्यवस्था से बंधे होंगे और जो प्रासंगिक बैठक में उपस्थित और मतदान किए थे (या तो व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा), और उन लेनदारों के मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करते हुए, समझौते या व्यवस्था के लिए सहमत होना चाहिए; और (b) अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि समझौता या व्यवस्था लेनदारों के दो या दो से अधिक वर्गों के बीच अनुचित रूप से भेदभाव नहीं करती है, और प्रत्येक असंतुष्ट वर्ग के लिए उचित और न्यायसंगत है। नए प्रावधान लेनदारों के एक अल्पसंख्यक असंतुष्ट वर्ग को अनुचित रूप से पुनर्गठन को निराश करने से रोकते हैं जो लेनदारों को समग्र रूप से लाभान्वित करता है।

बचाव वित्तपोषण के लिए प्राथमिकता: अदालत को, कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन, यह आदेश देने का अधिकार है कि बचाव वित्तपोषण को समान या सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यह शक्ति IRDA की धारा 67 में पाई जाती है जो सिंगापुर की अदालत को कई आदेशों में से कोई भी आदेश देने की अनुमति देता है, अनिवार्य रूप से कंपनी के समापन की स्थिति में बचाव वित्तपोषण को प्राथमिकता देता है निम्नलिखित अनुसार:

- मानो यह समापन की लागतों और खर्चों का हिस्सा हो; सभी तरजीही ऋणों और असुरक्षित ऋणों पर प्राथमिकता, अगर कंपनी बचाव वित्तपोषण प्राप्त नहीं कर सकती थी जब तक कि यह प्राथमिकता नहीं दी जाती;
- संपत्ति पर सुरक्षा जो अन्यथा किसी सुरक्षा के अधीन नहीं है, या मौजूदा सुरक्षा के अधीन संपत्ति पर अधीनस्थ सुरक्षा, यदि ऐसी सुरक्षा के बिना बचाव वित्तपोषण प्राप्त नहीं किया जा सकता है; और
- मौजूदा सुरक्षा की तुलना में समान या उच्च प्राथमिकता वाली सुरक्षा प्राप्त करना यदि ऐसी सुरक्षा के बिना बचाव वित्तपोषण प्राप्त नहीं किया जा सकता है और मौजूदा सुरक्षा के धारक के हितों के लिए पर्याप्त सुरक्षा है।

प्री-पैकेज्ड योजना: अदालत, कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन, किसी कंपनी द्वारा प्रस्तावित समझौता या व्यवस्था को, सिंगापुर की अदालत के द्वारा लेनदारों की बैठक को बिना बुलाए जाने या कंपनी द्वारा आयोजित कराने, पर मंजूरी दे सकती है, अगर वह संतुष्ट है कि यदि लेनदारों की ऐसी बैठक बुलाई गई होती, तो लेनदारों के अपेक्षित बहुमत ने समझौते या व्यवस्था को मंजूरी दे दी होती।

आईआरडीए की धारा 187 के तहत लेनदारों के साथ व्यवस्था

एक विकल्प जो व्यवस्था और समझौता की एक योजना के लिए कुछ समानता रखता है वह आईआरडीए की धारा 187 के तहत प्रक्रिया है जिसमें कहा गया है कि किसी कंपनी, जो बंद होने वाली है या उस दौरान में है, और उसके लेनदारों के बीच की गई कोई भी व्यवस्था, इस धारा के तहत अपील के अधिकार के अधीन, कंपनी के लिए बाध्यकारी होगी यदि एक विशेष संकल्प द्वारा स्वीकृत किया जाता है, और लेनदारों के लिए बाध्यकारी होगी यदि लेनदार मूल्य में कम से कम तीन-चौथाई बहुमत और संख्या में बहुमत से स्वीकार करते हैं, जिसमें \$ 50 से कम के प्रत्येक लेनदार को केवल मूल्य में गिना जाता है।

इस प्रक्रिया का लाभ यह है कि व्यवस्था की मंजूरी के लिए अदालत में कोई आवेदन आवश्यक नहीं है, जैसा कि व्यवस्था और समझौता की योजना के मामले में होता है। लेकिन इस विकल्प का उपयोग शायद ही कभी व्यवहार में किया जाता है, क्योंकि व्यवस्था और समझौता की योजना की तुलना में इस प्रक्रिया के तहत लेनदारों से अपेक्षित सहमति प्राप्त करना काफी कठिन है।

न्यायिक प्रबंधन

परिचय

एक कंपनी को न्यायिक प्रबंधन के तहत रखने के लिए अदालत में आवेदन किया जा सकता है। न्यायिक प्रबंधन व्यवस्था का उद्देश्य एक ऐसी कंपनी, जो अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है या होने की संभावना है, को "ब्रीथिंग स्पेस" प्रदान करना है, ताकि इसे या तो वित्तीय स्थिति में वापस लाया जा सके या परिसमापन की तुलना में इसे अपनी संपत्ति की बेहतर प्राप्ति प्राप्त की जा सके।

सामान्य तौर पर, सभी कंपनियों को न्यायिक प्रबंधन के तहत रखा जा सकता है, उन कंपनियों के अपवाद के साथ जो परिसमापन में चली गई हैं, या कुछ बहिष्कृत वर्ग जिन्हें कानून द्वारा बाहर रखा गया है जैसे कि बैंक या बीमाकर्ता।

न्यायिक प्रबंधन के लिए अदालत में आवेदन करने के विकल्प के रूप में, आईआरडीए के तहत एक कंपनी अदालत में कोई आवेदन करने की आवश्यकता के बिना लेनदारों के संकल्प के माध्यम से न्यायिक प्रबंधन शुरू कर सकती है। इन-कोर्ट और आउट-ऑफ-कोर्ट प्रक्रिया के बीच कुछ समानताएं हैं। नीचे न्यायालय आधारित न्यायिक प्रबंधन प्रक्रिया का विवरण दिया गया है।

न्यायालय आधारित न्यायिक प्रबंधन प्रक्रिया प्रारंभ करना

अदालत-आधारित न्यायिक प्रबंधन प्रक्रिया एक अदालत के आवेदन से प्रारंभ होती है जिसे एक हलफनामे द्वारा समर्थित किया जाता है। हलफनामे में, अन्य बातों के अलावा, यह बताया जाता है कि कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है या होने की संभावना है और कंपनी के पुनर्वास की एक उचित संभावना है, एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में अपने सभी या उसके व्यवसाय के हिस्से का संरक्षण या अन्यथा लेनदारों के हितों का परिसमापन की तुलना में बेहतर ध्यान रखा जा सकता है। न्यायिक प्रबंधन आदेश के लिए आवेदन कंपनी या उसके निदेशकों (इसके सदस्यों या निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसार) या एक लेनदार या लेनदारों (किसी भी आकस्मिक या संभावित लेनदार या लेनदारों सहित) द्वारा किया जा सकता है।

न्यायिक प्रबंधन आदेश का अनुदान

न्यायालय किसी कंपनी के संबंध में न्यायिक प्रबंधन आदेश दे सकता है यदि वह संतुष्ट है कि कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है या होने की संभावना है और एक वास्तविक संभावना है कि आदेश निम्नलिखित तीन उद्देश्यों में से एक या अधिक प्राप्त करेगा:

- कंपनी का अस्तित्व, या उसके पूरे या उसके उपक्रम का एक भाग, एक चालू संस्था के रूप में;
- कंपनी अधिनियम या आईआरडीए के तहत समझौता या व्यवस्था का अनुमोदन लेनदारों और/या सदस्यों, या उनके किसी भी वर्ग के बीच ; या
- समापन की तुलना में कंपनी की संपत्ति की अधिक लाभप्रद प्राप्ति।

इन शर्तों को पूरा करने मात्र से ही न्यायिक प्रबंधन आदेश देना अनिवार्य नहीं होगा। उदाहरण के लिए, अदालत यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक प्रबंधन आवेदन की जांच कर सकती है कि न्यायिक प्रबंधन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निदेशकों या शेयरधारकों द्वारा लेनदारों की हानि के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है, और विशेष रूप से जिनके दावे असुरक्षित हैं। इसके अलावा, यह देखते हुए कि न्यायिक प्रबंधन का परिणाम यह है कि कंपनी के खिलाफ दावों पर रोक है (इस पर आगे चर्चा की गई है), जो लेनदारों के अधिकारों में एक अंतर्विरोध है, न्यायिक भावना व्यक्त की गई है कि इस शासन का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

असाधारण रूप से, अदालत न्यायिक प्रबंधन आदेश दे सकती है, भले ही ऊपर वर्णित न्यायिक प्रबंधन की शर्तें संतुष्ट न हों। न्यायालय के इस असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग इस आधार पर किया जा सकता है कि ऐसा करना जनहित में है।

न्यायिक प्रबंधन आदेश का प्रभाव

न्यायिक प्रबंधन के लिए कार्यवाही शुरू होने का मुख्य प्रभाव यह है कि कंपनी के खिलाफ दावों पर स्थगन लगाया जाता है। न्यायिक प्रबंधन के लिए किए जा रहे एक आवेदन पर एक वैधानिक स्थगन आमतौर पर स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है, जिसे न्यायिक प्रबंधन आदेश बनने पर बढ़ाया जाता है। अधिस्थगन का उद्देश्य कंपनी को ऊपर उल्लिखित न्यायिक प्रबंधन के घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करना है।

जब तक निर्वहन नहीं किया जाता, न्यायिक प्रबंधन आदेश 180 दिनों के लिए लागू रहेगा (जिसे अदालत द्वारा बढ़ाया जा सकता है)। एक न्यायिक प्रबंधक को कंपनी के मामलों, व्यवसाय और संपत्ति के प्रबंधन के लिए सभी चीजें करने के लिए नियुक्त और सशक्त किया जाएगा, जो न्यायिक प्रबंधन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। न्यायिक प्रबंधक को इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए न्यायिक प्रबंधन आदेश के 60 दिनों (जो अदालत द्वारा बढ़ाया जा सकता है) के भीतर लेनदारों को प्रस्ताव तैयार करना और भेजना चाहिए। यदि लेनदार प्रस्तावों को मंजूरी देते हैं, तो न्यायिक प्रबंधक को उनके अनुसार कंपनी का प्रबंधन करना चाहिए। इस तरह के प्रस्तावों में कंपनी की व्यवस्था की योजना में प्रवेश करना या अपने उपक्रम के किसी भी हिस्से को बेचना शामिल हो सकता है जो व्यवहार्य रहता है।

न्यायिक प्रबंधन आदेश का निर्वहन

न्यायिक प्रबंधक न्यायिक प्रबंधन आदेश के निर्वहन के लिए आवेदन करने के लिए एक वैधानिक दायित्व के तहत है, जब ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें निर्दिष्ट उद्देश्यों को या तो हासिल कर लिया गया है या यह उपलब्धि में असमर्थ हैं।

न्यायिक प्रबंधन के सफल समापन का परिणाम काफी हद तक न्यायिक प्रबंधक के प्रस्तावों और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि प्रस्तावों से समझौता करने की योजना बनती है, तो इसका परिणाम कंपनी के कुछ ऋणों को योजना के अनुसार समाप्त या कम किया जा सकता है। न्यायिक प्रबंधन की विफलता के परिणामस्वरूप कंपनी अपनी पूर्व-न्यायिक प्रबंधन स्थिति में वापस आ जाएगी। यह परिसमापन का कारण बन सकता है क्योंकि न्यायिक

प्रबंधन आवेदन के लिए पूर्वापेक्षाओं में से एक कंपनी की अपने ऋणों का भुगतान करने में अक्षमता या संभावित अक्षमता है, जो कंपनी के समापन के लिए आधार है।

रिसीवरशिप

सुरक्षित लेनदार रिसीवर या रिसीवर और प्रबंधकों की नियुक्ति के माध्यम से अपने सुरक्षा अधिकारों को लागू करने में सक्षम हैं। रिसीवर को न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, या सुरक्षा दस्तावेजों या उपकरणों के तहत दिए गए अधिकारों के अनुसार निजी तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा नियुक्ति का तरीका आज के व्यवहार में बहुत अधिक सामान्य है क्योंकि इस तरह की संविदा नियुक्ति की तुलनात्मक गति और सुगमता के कारण और अधिक व्यापक शक्तियां जो इस तरह के सुरक्षा दस्तावेजों या उपकरणों के तहत एक रिसीवर को प्रदान की जाती हैं।

नियुक्ति पर, रिसीवर का मुख्य कर्तव्य उन संपत्तियों को इकट्ठा करना है जो डिबेंचर की विषय वस्तु हैं, इन परिसंपत्तियों को वसूल करना है और लेनदारों की बकाया राशि का निपटान करना है। जहां रिसीवर एक प्रबंधक भी नियुक्त होता है, रिसीवर / प्रबंधक के पास कंपनी के व्यवसाय को प्रबंधित करने की अतिरिक्त शक्ति होगी। जरूरी नहीं कि रिसीवरशिप में जाने से कंपनी का अंत हो जाए; यह एक इकाई के रूप में अस्तित्व में रह सकता है।

एक रिसीवर सुरक्षा को लागू करने में कंपनी को देखभाल का सामान्य कर्तव्य नहीं देता है। हालाँकि, रिसीवर विशिष्ट कर्तव्यों का पालन करता है जैसे कि कंपनी के प्रति सद्भावना के एक सामान्य कर्तव्य से अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सुरक्षा को साकार करने और सुरक्षित ऋण का निर्वहन करना, और सुरक्षित संपत्तियों के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठाने।

सिंगापुर में वैकल्पिक विवाद समाधान

सिंगापुर पार्टियों को अदालतों के माध्यम के अलावा अपने विवादों को हल करने में मदद करने के लिए वैकल्पिक तंत्र प्रदान करता है। वैकल्पिक विवाद समाधान ("एडीआर") के सामान्य रूपों में मध्यस्थता, विवाचन और विशेषज्ञ निर्धारण शामिल हैं।

मध्यस्थता

सामान्य

मध्यस्थता सिंगापुर के विवाद समाधान सेवाओं के पूर्ण समूह का एक हिस्सा है, जो अदालती मुकदमेबाजी और मध्यस्थता के पूरक के रूप में कार्य करता है। यह लागत प्रभावी, लचीला और तेज है।

मध्यस्थता सेवाएं सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र ("एसएमसी") और सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र ("एसआईएमसी") द्वारा प्रदान की जाती हैं।

सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संस्थान ("सिमी") और एसआईएमसी को आधिकारिक तौर पर 5 नवंबर 2014 को सिंगापुर को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के केंद्र के रूप में विकसित करने की दृष्टि से लॉन्च किया गया था। मध्यस्थता के लिए एक पेशेवर मानक निकाय के रूप में, सिमी मध्यस्थों के लिए एक क्रेडेंशियल योजना को लागू करता है और ऑडिट करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उच्च मानकों को पंजीकृत भागीदारों के साथ पूरा किया जाता है जो प्रशिक्षण और/या मध्यस्थता सेवाएं चलाते हैं।

एसआईएमसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित मध्यस्थों के एक पैनल के साथ अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों की मध्यस्थता पर केंद्रित है। एसआईएमसी ने एशिया में मध्यस्थता को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए क्षेत्र के अन्य मध्यस्थता केंद्रों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

एसएमसी घरेलू वाणिज्यिक मध्यस्थता पर ध्यान केंद्रित करती है, और अन्य विवाद समाधान सेवाएं जैसे न्यायनिर्णयन भी प्रदान करती है। एसएमसी में उच्च योग्य मध्यस्थों और तटस्थों का एक पैनल है जिसमें सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, संसद सदस्य, पूर्व न्यायिक आयुक्त, वरिष्ठ वकील और विभिन्न व्यवसायों और उद्योगों के नेता शामिल हैं। पुनर्गठन में मध्यस्थता के उपयोग की सुविधा के लिए, एसएमसी ने विशेषज्ञ दिवाला मध्यस्थों का एक पैनल गठित किया है जिसमें सिंगापुर दिवाला क्षेत्र में कुछ प्रमुख व्यवसायी शामिल हैं। एसएमसी सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट के भवन में स्थित है, जो पार्टियों को न्यायिक रूप से समर्थित केंद्र¹ का विश्वास दिलाता है।

1 नवंबर 2017 को, मध्यस्थता अधिनियम लागू हुआ। मध्यस्थता अधिनियम मध्यस्थता के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करने में मध्यस्थ समझौता की प्रवर्तनीयता को मजबूत करता है। यह उन क्षेत्रों में सीमा पार मध्यस्थता उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत मूल्यवान निश्चितता

¹ माननीय न्यायमूर्ति एंड्रयू फांग, "फोर्थ एशियन मिडिएशन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, मेडिएशन एंड द कोर्ट्स - द सिंगापुर एक्सपीरिंस" (20 अक्टूबर 2016) पैरा 8 और 19 पर।

प्रदान करता है जहां सामान्य कानून की स्थिति अस्पष्ट है या अधिकार क्षेत्र से अधिकार क्षेत्र में भिन्न है।

मध्यस्थता अधिनियम पार्टियों को अदालत में आवेदन करने के लिए सहमत होने की क्षमता देता है ताकि उनके निपटान समझौते को अदालत के आदेश के रूप में दर्ज किया जा सके ताकि इसकी प्रवर्तनीयता को मजबूत किया जा सके। यह भी प्रावधान करता है कि मध्यस्थता में किए गए संचार को मध्यस्थता के लिए तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं किया जा सकता है और मध्यस्थता अधिनियम में निर्धारित परिस्थितियों को छोड़कर, अदालत या मध्यस्थ कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति मध्यस्थता के लिए किसी तीसरे पक्ष को मध्यस्थता संचार का खुलासा कर सकता है यदि प्रकटीकरण मध्यस्थता के सभी पक्षों की सहमति से किया जाता है (संचार के निर्माता सहित)। मध्यस्थता अधिनियम पार्टियों को उसी विवाद के संबंध में चल रही अदालती कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए अदालत में आवेदन करने की भी अनुमति देता है।

12 सितंबर 2020 को, मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन ("सिंगापुर कन्वेंशन") जिसे मध्यस्थता के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय निपटान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहा जाता है, को लागू किया गया जिसे अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद समाधान में एक महत्वपूर्ण विकास का चिह्नित समझा जाता है। दुनिया भर के व्यवसायों को अब मध्यस्थता के माध्यम से सीमा पार विवादों को हल करने में अधिक निश्चितता होगी, क्योंकि सिंगापुर कन्वेंशन सीमाओं के पार एक मध्यस्थता निपटान समझौते के प्रवर्तन की मांग करने वाले पक्षों को उन देशों की अदालतों में सीधे आवेदन करके ऐसा करने की अनुमति देता है जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और पुष्टि की है, बजाय इसके कि निपटान समझौते को प्रत्येक देश की घरेलू प्रक्रिया के अनुसार अनुबंध के रूप में लागू किया जाए।

दिवाला संदर्भ में मध्यस्थता 2015 में, सिंगापुर के कानून मंत्रालय ने ऋण पुनर्गठन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में सिंगापुर को मजबूत करने के लिए समिति की स्थापना की ("पुनर्गठन समिति"), जिसे सिंगापुर को ऋण पुनर्गठन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए पहल और / या कानूनी सुधारों की सिफारिश करने का काम सौंपा गया था। अंतर्राष्ट्रीय ऋण पुनर्गठन के लिए केंद्र प्रभावी पुनर्गठन समाधान खोजने के तरीके के रूप में मध्यस्थता (और मध्यस्थता) की प्रासंगिकता को एक रिपोर्ट में उजागर किया गया था जिसे

2016 में पुनर्गठन समिति ने जारी किया था। पुनर्गठन समिति ने मध्यस्थता को ऋण पुनर्गठन के लिए निमंलिखित परिस्थितियों में उपयोग में लाने का सुझाव दिया है।

सबसे पहले, मध्यस्थता का उपयोग देनदार के साथ व्यक्तिगत लेनदार विवादों को हल करने के लिए किया जा सकता है (बहु-लेनदार पुनर्गठन के संदर्भ में), या एक ही प्रकृति के कई लेनदार विवादों का प्रबंधन करने के लिए किया जा सकता है ("समान दावा मध्यस्थता")²। इसी तरह के दावों की मध्यस्थता में, आम तौर पर कानून या तथ्य के एक सामान्य गठजोड़ के साथ कई दावों के समाधान की सुविधा के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है। इसका एक उदाहरण लेहमन ब्रदर्स इंक की अमेरिकी दिवाला कार्यवाही है, जहां एक संरचित मध्यस्थता प्रोटोकॉल ने डेरिवेटिव-संबंधित दावों के बहुमत के समीचीन समाधान का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों डेरिवेटिव अनुबंध से संबंधित समाप्ति विवाद और 900,000 अंतर्निहित लेनदेन³ के साथ 6,000 से अधिक व्युत्पन्न अनुबंधों को शामिल करने वाले दावे शामिल थे।

दूसरा, मध्यस्थता देनदार और उसके लेनदारों ("योजना मध्यस्थता")⁴ के बीच पुनर्गठन योजना में आम सहमति प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। योजना मध्यस्थता में, हितधारकों को एक पुनर्गठन योजना में आम सहमति प्राप्त करने में मदद करने के लिए या उन मामलों में जहां देनदार प्रतिस्पर्धी न्यायालयों में दोहरी दिवाला कार्यवाही के अधीन हैं, एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाता है। इसका एक उदाहरण एमएफ ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड के दिवाला में हुआ, जहां मध्यस्थता ने यूएस और यूके में दिवाला कार्यवाही के बीच संभावित विवादों को सुलझाया और शोधन अक्षमता की पर्याप्त संपत्ति को (जिसका उपयोग अन्यथा न्यायालय आधारित मुकदमेबाजी में शुल्क और व्यय का भुगतान करने के लिए किया जाता) लेनदारों⁵ को वितरित किया।

योजना मध्यस्थता के लाभों को सिंगापुर उच्च न्यायालय द्वारा रे आईएम स्काउगेन एसई⁶ में न्यायिक रूप से मान्यता दी गई है, जहां माननीय न्यायमूर्ति कन्नन रमेश ने निम्न बातें कहीं:

² अंतरराष्ट्रीय ऋण पुनर्गठन केंद्र के रूप में सिंगापुर को मजबूत करने के लिए समिति की रिपोर्ट, 2016 ("2016 पुनर्गठन रिपोर्ट") पैरा 3.54 और 3.55 पर। 2016 पैरा 3.55 पर पुनर्गठन

³ रिपोर्ट। 2016 पैरा 3.54 और 3.56 पर पुनर्गठन रिपोर्ट। 2016 पैरा 3.56 पर पुनर्गठन रिपोर्ट। [2019] 3 एसएलआर 979; [2018] एसजीएचसी 259 [94] पर।

⁴ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस निर्देश पैराग्राफ 35B(2)।

⁵ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस निर्देश पैराग्राफ 35B(4)।

⁶ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस निर्देश पैराग्राफ 35बी(5)

"एक अन्य पहलू, जिसका देनदारों और लेनदारों द्वारा सहारा नहीं लिया गया है, पुनर्गठन योजना विकसित करने के लिए एक अनुभवी और कुशल दिवाला मध्यस्थ की मदद लेना है, चाहे वह एक व्यक्ति या समूह पुनर्गठन योजना हो। आमतौर पर, योजना पर चर्चा पक्षपातपूर्ण होती है, और इसलिए अपनाई गई स्थितियां उसी को प्रतिबिंबित करती हैं। मुझे मध्यस्थता तकनीकों में कुशल और प्रासंगिक डोमेन ज्ञान के साथ एक निष्पक्ष तृतीय पक्ष की सेवाओं को तैनात करने में जबरदस्त उपयोगिता दिखाई देती है। ऐसी पार्टी पुनर्गठन योजना के विकास में देनदार और लेनदारों के बीच आम सहमति बनाने और प्रक्रिया में विश्वास बनाने की अमूल्य भूमिका निभा सकती है। इस तरह, मध्यस्थ कई असमताओं को दूर करने में सहायता कर सकता है जो आमतौर पर एक पुनर्गठन में उत्पन्न होते हैं और जो शायद अदालत में अच्छी तरह से हल नहीं होते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इसे जोश के साथ खोजा जाए, क्योंकि यह मुझे स्वतः स्पष्ट प्रतीत होता है कि मतभेदों और विश्वास विभाजन को कम करना एक सफल पुनर्गठन परिणाम के लिए मूलभूत है। हालांकि झूठी लड़ाई के लिए हमेशा एक जगह होती है जो एक प्रतिकूल प्रक्रिया के लिए विशिष्ट होती है, पुनर्गठन में एक अधिक विचारशील, रचनात्मक और मापा दृष्टिकोण अक्सर शामिल सभी पक्षों के लिए बेहतर परिणाम दे सकता है। सभी को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य, आखिरकार, यह आकलन करना है कि क्या देनदार की वित्तीय समस्याओं का एक व्यवहार्य और स्वीकार्य आर्थिक समाधान संभव है, और यदि ऐसा है, तो संबंधित हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह कैसे हो सकता है। इस अंत तक, देनदार और लेनदारों, सुरक्षित और असुरक्षित, के बीच चर्चा की सुविधा और एक अधिक सहकारी, सहयोगी और पारदर्शी वातावरण को बढ़ावा देना जिसमें शामिल सभी पक्ष एक प्रभावी और टिकाऊ पुनर्गठन प्राप्त करने के एक सामान्य उद्देश्य की दिशा में काम करते हैं, काफी स्पष्ट रूप से सही दृष्टिकोण प्रतीत होता है।

मध्यस्थता आम तौर पर अनिवार्य के बजाय ऐच्छिक होती है

सिंगापुर में, अदालतें आमतौर पर पार्टियों को मध्यस्थता से गुजरने के लिए मजबूर नहीं करती हैं। व्यवहार में, हालांकि, अदालती कार्यवाही के पक्षकारों (दिवाला कार्यवाही सहित) को आम तौर पर उचित मामलों में मध्यस्थता पर विचार करने के लिए अदालत द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। दिवाला के संदर्भ में, सिंगापुर में वादियों द्वारा लेनदारों के दावों पर विवादों, ऋण के प्रमाणों के अधिनिर्णय, और दिवाला व्यवसायियों का शुल्क, आदि के संबंध में मध्यस्थता का उपयोग किया गया है। सिंगापुर की अदालतों द्वारा जारी सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट अभ्यास निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह अधिवक्ताओं और सॉलिसिटर्स का पेशेवर कर्तव्य है कि वे अपने

ग्राहकों को विभिन्न तरीकों के बारे में सलाह दें कि उनके विवादों को एडीआर के उचित रूप का उपयोग करके हल किया जा सकता है, और यह कि एडीआर⁷ को जल्द से जल्द संभव चरण में माना जाना चाहिए ताकि उसे सुविधाजनक बनाया जा सके, नागरिक मामलों का त्वरित और किफायती निपटान, विशेष रूप से जहां एडीआर लागत बचा सकता है, एक त्वरित समाधान और अपने ग्राहक की जरूरतों⁸ को पूरा करने का एक निश्चित तरीका बन सकता है। सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस डायरेक्शन में स्वयं अधिवक्ताओं और सॉलिसिटर के लिए विस्तृत दिशानिर्देश शामिल हैं जो ग्राहकों को एडीआर के बारे में सलाह दे रहे हैं। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के अलावा, मुकदमेबाजी के विकल्प के रूप में उपलब्ध एडीआर विकल्प और सबसे उपयुक्त एडीआर प्रक्रिया चुनने पर विशिष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस डायरेक्शन में कहा गया है कि अधिवक्ताओं और सॉलिसिटर्स को अपने ग्राहकों को एडीआर में शामिल होने से किसी भी अनुचित इनकार के लिए संभावित प्रतिकूल लागत आदेशों पर सलाह देनी चाहिए। न्यायालय के सिंगापुर नियमों के आदेश 59, नियम 5 (सी) में कहा गया है कि: *"लागत के रूप में अपने विवेक का उपयोग करने में अदालत, इस हद तक, यदि कोई हो, जैसा कि परिस्थितियों में उपयुक्त हो - ... मध्यस्थता या विवाद समाधान के किसी अन्य माध्यम से कारण या मामले को हल करने के किसी भी प्रयास के संबंध में पार्टियों का आचरण"* को ध्यान में रखना होगा। जैसे, यह संभव है कि सिंगापुर की अदालतें एक सफल पार्टी को लागत देने से इनकार कर सकती हैं क्योंकि हो सकता है कि उस पार्टी ने मध्यस्थता में शामिल होने से अनुचित रूप से इनकार कर दिया हो।

सिंगापुर की अदालतों के समक्ष प्रतिकूल कार्यवाही के संबंध में पूर्व-परीक्षण सम्मेलन के चरण में, अदालत नियमित रूप से पार्टियों को एडीआर⁹ पर विचार करने का निर्देश देती है, और यह आवश्यक है कि पक्ष एडीआर के माध्यम से अपने विवाद को निपटाने की दिशा में अपने प्रयासों के बारे में अदालत को अपडेट प्रदान करें। अदालती कार्यवाही के पक्षकारों के लिए सामान्य प्रक्रिया जो मध्यस्थता या विवाद समाधान के किसी अन्य माध्यम का प्रयास करना चाहते हैं, सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस डायरेक्शन में निर्धारित की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि:

⁷ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस निर्देश पैरा 35सी(1)।

⁸ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस निर्देश पैरा 35सी(2)।

⁹ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस निर्देश पैरा 35सी(3)।

- एक पक्ष जो मध्यस्थता या विवाद समाधान के किसी अन्य माध्यम का प्रयास करना चाहता है, उसे अभ्यास दिशा-निर्देशों¹⁰ के परिशिष्ट ए के फॉर्म 28 में सभी संबंधित पक्षों को एक एडीआर प्रस्ताव दाखिल करना चाहिए और प्रस्तुत करना चाहिए।
- कार्यवाही के किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक एडीआर प्रस्ताव दिया जा सकता है और इसकी सेवा के बाद 14 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा।¹¹
- एडीआर ऑफ़र की सेवा के बाद 14 दिनों के भीतर, संबंधित पक्ष अभ्यास निर्देशों के परिशिष्ट ए के फॉर्म 29 में एडीआर प्रस्ताव का जवाब दाखिल करेंगे और प्रस्तुत करेंगे, ऐसा न करने पर उन्हें बिना कोई कारण बताए एडीआर का प्रयास करने के लिए तैयार नहीं माना जाएगा।¹² . एडीआर ऑफ़र के प्रतिसाद के लिए प्रतिवादी को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करना होगा कि:¹³
- प्रतिवादी के वकील ने उसे उपलब्ध एडीआर विकल्पों के बारे में बताया है।
- प्रतिवादी एडीआर द्वारा अपना मामला निपटाने के लाभों से अवगत है।
- प्रतिवादी को सलाह दी गई है और समझता है कि न्यायाधीश यह विचार कर सकता है कि एडीआर उसके मामले के लिए उपयुक्त है, और यह कि मध्यस्थता या एडीआर के अन्य माध्यमों के माध्यम से मामले को हल करने के लिए अपनी ओर से किसी भी अनुचित इनकार से प्रतिवादी को प्रतिकूल लागत आदेश का सामना करना पड़ सकता है।
- यदि सभी पक्ष एडीआर का प्रयास करने के इच्छुक हैं, तो अदालत द्वारा संबंधित दीवानी मामले के संबंध में निर्देश दिए जा सकते हैं, जिसमें एडीआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा के साथ अदालत में लंबित कार्यवाही को स्थगित करना शामिल है।¹⁴
- किसी भी कार्यवाही या पूरी कार्रवाई में किसी भी दावे या मुद्दे की लागत सहित लागतों के संबंध में अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, अदालत मामले की सभी प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार कर सकती है, जिसमें एडीआर प्रस्ताव और एडीआर प्रस्ताव की प्रतिक्रिया शामिल है।¹⁵

विवाचन

सामान्य

¹⁰ एडीआर प्रस्ताव का जवाब, सुप्रीम कोर्ट के अभ्यास निर्देशों के परिशिष्ट ए का फॉर्म 29

सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस निर्देश पैरा 35सी(4)

¹¹ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस निर्देश पैरा 35सी(4)

¹² सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस निर्देश पैरा 35सी(5)

¹³ यी होंग पीटीई लिमिटेड बनाम टैन ची ही एंड्र्यू (हो बी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, थर्ड पार्टी) [2005] 4 एसएलआर (आर) 398; [2005] एसजीएचसी 163.

¹⁴ [2006] 3 एसएलआर (आर) 174; [2006] एसजीएचसी 78 [40] पर

¹⁵ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस निर्देश पैरा 35सी(5)

सिंगापुर में आमतौर पर विवाद समाधान तंत्र के रूप में विवाचन का उपयोग किया जाता है। सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ("एसआईएसी") द्वारा प्रशासित अंतरराष्ट्रीय मामलों की संख्या वर्ष-दर-वर्ष लगातार बढ़ रही है। सिंगापुर की अदालतें विवादों को सुलझाने के साधन के रूप में विवाचन के उपयोग को प्रोत्साहित करती हैं और यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि वे पहचानते हैं विवाचन समझौते और ऐसे समझौतों के कारण कानूनी कार्यवाही पर रोक लगा दी है।¹⁶ ऐसे मामलों में कानूनी कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए विवाचन अधिनियम (जो घरेलू विवाचन से संबंधित है) के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय विवाचन अधिनियम (जो अंतरराष्ट्रीय विवाचन से संबंधित है) के रूप में वैधानिक नियम बनाए गए हैं।

सिंगापुर में विवाचन से संबंधित विधायी ढांचे को सिंगापुर सरकार द्वारा बार-बार पुनरीक्षित किया गया है (संशोधन 2010 और 2012 में किए गए थे) ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विवाचन व्यवस्था अन्य क्षेत्राधिकार के बराबर है और सिंगापुर विवाचन के लिए एक आकर्षक स्थल बना हुआ है।

एसआईएसी को जुलाई 1991 में एक गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था, जो एशिया में एक निष्पक्ष, कुशल और विश्वसनीय विवाद समाधान संस्थान के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार समुदाय की मांगों को पूरा करता है। एसआईएसी में एक विवेचन न्यायालय शामिल है जो एसआईएसी के केस प्रशासन और विवाचक नियुक्ति कार्यों की देखरेख करता है और निदेशक मंडल है जो इसके कॉर्पोरेट और व्यावसायिक विकास कार्यों की देखरेख करता है। 30 दिसंबर 2016 को, एसआईएसी ने एसआईएसी के निवेश विवाचन नियमों ("आईए नियम") के पहले संस्करण की आधिकारिक रिलीज़ की घोषणा की, जो अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाचन के संचालन में मौजूद अद्वितीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए नियमों का एक विशेष सेट है। आईए नियम 2017 1 जनवरी 2017 को लागू हुआ।

इसके अलावा, सरकार के समर्थन से 2010 में एक विवाचन सुविधा केंद्र (मैक्सवेल चैंबर्स) शुरू किया गया था। सिंगापुर में प्रतिनिधित्व किए गए कई विवाचन निकाय हैं, जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC), इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन (ICDR) (अमेरिकन आर्बिट्रेशन एसोसिएशन का अंतरराष्ट्रीय केंद्र (एएए)), विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के विवाचन और मध्यस्थता केंद्र, सिंगापुर चैंबर ऑफ मैरीटाइम आर्बिट्रेशन (एससीएमए) और सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर।

¹⁶ [2011] 3 एसएलआर 414; [2011] एसजीसीए 21 पर [1]

एक विवाचन केंद्र के रूप में सिंगापुर के आकर्षण को और मजबूत करने के लिए यह तथ्य है कि सिंगापुर विदेशी विवाचन पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता है, जिसे आमतौर पर न्यूयॉर्क कन्वेंशन के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो विवाचन पुरस्कारों के प्रवर्तन को आसान बनाता है। न्यायपालिका ने भी लगातार न्यूनतम क्यूरिअल हस्तक्षेप की नीति के साथ विवाचन समर्थक निर्णय दिए हैं।

अमेरिका के एलो वेरा, इंक बनाम एशियन फूड (एस) पीटीई लिमिटेड और एनोर में¹⁷, सिंगापुर की अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि अदालतों को विदेशी विवाचन पुरस्कारों को प्रभावी करना चाहिए:

"[टी] यहां [10 जून 1958 को संपन्न विदेशी पंचाट पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन] में निहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय का सिद्धांत है जो विदेशी विवाचन पुरस्कारों को प्रभावी बनाने के लिए अदालतों को दृढ़ता से प्रेरित करता है।

जैसा कि लिटन पीजे ने हेबै इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्प बनाम पॉलीटेक इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड [1999] 2 एचकेसी 205 में अंतिम अपील के हांगकांग कोर्ट के निर्णय में देखा, सार्वजनिक नीति की अवधारणा में बुना क्योंकि यह विदेशी विवाचन पुरस्कारों के प्रवर्तन पर लागू होता है 'यह सिद्धांत है कि अदालतों को विदेशी विवाचन न्यायाधिकरणों के निर्णयों की वैधता को सामूहिकता के मामले के रूप में पहचानना चाहिए, और उन्हें प्रभावी करना चाहिए, जब तक कि ऐसा नहीं करना नैतिकता और न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं का उल्लंघन होगा'।

सिंगापुर में विवाचन के लिए न्यायपालिका के समर्थन का प्रमाण विशेषज्ञ न्यायाधीशों की नियुक्ति से है, जो 2003 में उच्च न्यायालय के समक्ष लाए गए सभी विवाचन मामलों की अध्यक्षता करने के लिए एक कदम था।

नागरिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2017, जो 1 मार्च 2017 को लागू हुआ, ने सिंगापुर में तीसरे पक्ष के वित्त पोषण के लिए एक ढांचा बनाने के लिए नागरिक कानून अधिनियम में संशोधन किया, जिससे व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय विवाचन के लिए एक अतिरिक्त वित्तपोषण विकल्प प्रदान किया गया। अन्य अंतरराष्ट्रीय विवाचन केंद्रों में तीसरे पक्ष के वित्त पोषण पहले से ही उपलब्ध है और यहां इसकी शुरुआत दुनिया में एक प्रमुख मध्यस्थता सीट के रूप में सिंगापुर की स्थिति को मजबूत करेगी। नागरिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2017 प्रदान करता है कि

¹⁷ [47] से [51] पर लार्सन ऑयल; बीटीवाई बनाम बीयूए और अन्य मामले [2019] 3 एसएलआर 786 [151] से [153]।

जो संस्थाएं तीसरे पक्ष को वित्त पोषण प्रदान करती हैं उन्हें कुछ विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा और यह भी कहा गया है कि सिंगापुर में सामान्य कानून की यातना और रखरखाव को समाप्त कर दिया गया है।

दिवाला संदर्भ

दिवाला दावों के संदर्भ में, शुरुआत में ही यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिवाला कानून के कुछ पहलू हैं जो गैर-मध्यस्थता योग्य हैं। इसका कारण, जैसा कि सिंगापुर की अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त है, यह है कि मध्यस्थता और दिवाला प्रक्रियाएं, एक हद तक, विपरीत नीतियों को शामिल करती हैं। लार्सन ऑयल एंड गैस पीटीई लिमिटेड बनाम पेट्रोप्रोड लिमिटेड (केमैन आइलैंड्स में आधिकारिक परिसमापन में और सिंगापुर में अनिवार्य परिसमापन में)¹⁸ ("लार्सन ऑयल"), सिंगापुर कोर्ट ऑफ अपील ने आयोजित किया:

"विवाचन और दिवाला प्रक्रियाएं, एक हद तक, कानूनी नीतियों के विपरीत हैं। एक ओर, विवाचन पार्टी स्वायत्तता के सिद्धांतों और निजी विवाद समाधान के विकेंद्रीकरण का प्रतीक है। दूसरी ओर, दिवाला प्रक्रिया एक सामूहिक वैधानिक कार्यवाही है जिसमें विवादों का सार्वजनिक केंद्रीकरण शामिल है ताकि आर्थिक दक्षता और लेनदारों के लिए इष्टतम रिटर्न प्राप्त किया जा सके।

लार्सन ऑयल में, अपील की अदालत का संबंध एक दिवाला कंपनी से जुड़े कुछ प्रकार के विवादों की गैर-विवाचन से था जो परिसमापन में थी। अपील की अदालत ने माना कि केवल दिवाला पर उत्पन्न होने वाले विवाद और केवल दिवाला शासन (दूसरे शब्दों में, दिवाला कानून विवाद) और दिवाला कंपनी के पूर्व-दिवाला अधिकारों और दायित्व से उत्पन्न विवाद के बीच अंतर किया जाना चाहिए (दूसरे शब्दों में, एक निजी कानून विवाद)¹⁹:

अपील की अदालत ने माना कि दिवाला कानून विवाद विवाचन नहीं है। दिवाला व्यवस्था के उद्देश्य का एक हिस्सा दिवालिया कंपनियों को कंपनी के लेनदारों के सामूहिक लाभ के लिए संपत्ति की वसूली में सक्षम बनाना है। इसके लिए अक्सर कंपनी के दिवाला-पूर्व प्रबंधन के खिलाफ दिवाला कानून के दावों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होती है। दिवाला शासन के उद्देश्य के इस पहलू से समझौता किया जा सकता है यदि प्रबंधन को कंपनी के दिवाला कार्यालयधारकों को दिवाला कानून विवादों में विवाचन करने के लिए बाध्य करने की अनुमति दी जाती है। इसके

¹⁸ 2016 पैरा 3.61 पर पुनर्गठन रिपोर्ट

¹⁹ 2016 पैरा 3.62 पर पुनर्गठन रिपोर्ट

अलावा, दिवाला शासन की परिकल्पना करता है कि एक एकल दिवाला कानून विवाद कई व्यक्तियों के खिलाफ उत्पन्न हो सकता है, जिनमें से कुछ दिवाला कंपनी के साथ एक विवाचन समझौते के प्रतिपक्ष हो सकते हैं, लेकिन अन्य जिनमें से अन्य दिवाला कंपनी के साथ किसी भी समझौते के प्रतिपक्ष नहीं हो सकते हैं, एक विवाचन समझौता अकेले छोड़ दें। दिवाला व्यवस्था में निर्धारित सामूहिक प्रक्रिया के तहत सभी दिवाला कानून विवादों को निर्धारित करने के बाद, मध्यस्थता समझौते की उपस्थिति या दायरे की परवाह किए बिना, विभिन्न निर्णायकों द्वारा परस्पर विरोधी निष्कर्षों को रोकता है।

दूसरी ओर, अपील की अदालत ने माना कि एक निजी कानून विवाद विवाचन है, कम से कम जहां यह लेनदारों के मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है। जहां एक विवाचन समझौता एक कंपनी के दिवाला कार्यालयधारकों को एक निजी विवाद की विवाचन करने के लिए बाध्य करता है, वहाँ आमतौर पर विवाचन समझौते को प्रभावी नहीं करने का कोई अच्छा कारण नहीं होता है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि विवाचन समझौता निम्नलिखित दो अर्थों में सभी दिवालिया कंपनी के लेनदारों के प्रक्रियात्मक अधिकारों को प्रभावित करता है। सबसे पहले, लेनदारों का सामूहिक रूप से निजी कानून विवाद के परिणाम में वास्तविक आर्थिक हित होता है, लेकिन उन्हें विवाचन के माध्यम से विवाद को हल करने के लिए प्रस्तुत करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, भले ही लेनदार किसी भी विवाचन समझौते के पक्षकार न हों। दूसरा, एक विवाचन समझौते को निजी कानून विवादों को हल करने के लिए विशेष प्रक्रिया से अनुबंध करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, जो कि दिवाला शासन द्वारा अनिवार्य है, अर्थात् ऋण के प्रमाणों के निर्धारण और अधिनिर्णय द्वारा। लेकिन जहां विवाचन समझौता लेनदारों के मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, परिसमापक को निजी कानून विवाद को मध्यस्थ करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

विवाचन विवादों के संबंध में, पुनर्गठन समिति ने माना है कि देनदार और लेनदारों के बीच विशेष रूप से कुछ प्रकार के विवाद हैं जहां विवाचन विशेष रूप से सहायक हो सकती है। इन विवादों में शामिल हैं²⁰:

- सीमा पार मुद्दों से जुड़े विवाद, क्योंकि विवाचन विभिन्न न्यायालयों में मुद्दों को फिर से मुकदमा चलाने से रोकेगी।

²⁰ 2016 पैरा 3.63 पर पुनर्गठन रिपोर्ट

- जटिल मामले (उदाहरण के लिए, अत्यधिक जटिल वित्तीय साधनों से जुड़े विवाद) जहां विषय क्षेत्र में विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है और जहां यह संभावना है कि असंगत अदालती निर्णय होंगे।
- पुनर्गठन समिति ने यह भी नोट किया कि विवाचन का उपयोग दिवाला के बाद उत्पन्न होने वाले मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए भी किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं²¹:
- एक बड़े उद्यम समूह के भीतर कई अधिकार क्षेत्र में सहयोगियों के बीच अंतरकंपनी दावों का समाधान करना।
- कई समवर्ती दिवाला कार्यवाहियों में मुद्दों का समाधान करना। उदाहरण के लिए, जहां एक बड़े बहुराष्ट्रीय उद्यम का व्यवसाय एक चालू प्रतिष्ठान के रूप में बेचा जाता है, बिक्री की आय को विभिन्न दिवाला कार्यवाही में आवंटित करना पड़ सकता है। विवाचन का उपयोग विवादों को हल करने के लिए किया जा सकता है कि बिक्री की आय का वितरण कैसे किया जाना चाहिए।
- देनदार के मुख्य हितों के केंद्र का निर्धारण, उस स्थिति से बचने के लिए जहां विभिन्न क्षेत्राधिकार दावा करते हैं कि एक पुनर्गठन कार्यवाही का प्राथमिक प्रशासन स्थानीय फोरम पर आधारित होना चाहिए।

पारंपरिक अदालत-आधारित दिवाला कार्यवाही पर विवाचन की कार्यवाही का जो लाभ है, वह अधिक प्रवर्तनीयता है²²। विवाचन पुरस्कार न्यूयॉर्क कन्वेंशन से लाभान्वित होता है जो 150 से अधिक देशों में विवाचन पुरस्कार को लागू करने की अनुमति देता है। यह एक विवाचन पुरस्कार को दिवाला-संबंधित निर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन या यूरोपीय दिवाला विनियमन पर यूएनसीआईटीआरएल मॉडल कानून की तुलना में कहीं अधिक देशों में लागू करने की अनुमति देता है। विभिन्न न्यायालयों और अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में आम मुद्दों को हल करने के लिए विवाचन का उपयोग करने से सभी न्यायालयों में असंगत अदालती फैसलों को रोका जा सकता है।

हालाँकि, दिवाला कार्यवाही में उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने के लिए विवाचन का उपयोग करने में कई चुनौतियाँ हैं। उदाहरण के लिए, सिंगापुर में यह देखा गया है कि²³:

²¹ 2016 पैरा 3.64 पर पुनर्गठन रिपोर्ट

²² एवरग्रीट कंस्ट्रक्शन कंपनी पीटीई लिमिटेड बनाम प्रेसक्रीट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड [2006] 1 एसएलआर (आर) 634; [2005] एसजीएचसी 224.

²³ यह मंजूरी सिंगापुर कंपनी अधिनियम की धारा 210(4) के तहत है।

विवाचन का उपयोग करने के लिए एक चुनौती अधिकार क्षेत्र में सामान्य स्वीकृति से उपजी है कि दिवाला कानून के कुछ "मुख्य" पहलू गैर-विवाचन योग्य हैं, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है। दिवाला मुद्दे जिन्हें दिवाला कानून का "मुख्य" पहलू नहीं माना जाता है (अर्थात "गैर-मूल" मुद्दे) विवाचन की जा सकती है। हालांकि, अधिकार क्षेत्र में "गैर-मूल" मुद्दों के उपचार के लिए कोई सुसंगत दृष्टिकोण नहीं है और एक मुद्दा जो एक क्षेत्राधिकार में मध्यस्थता योग्य है, दूसरे में मध्यस्थ नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, सिंगापुर, यूके और ऑस्ट्रेलिया में, इस मुद्दे को केस लॉ द्वारा तय किया जाता है। अन्य क्षेत्राधिकार, जैसे कि अमेरिका में, "गैर-प्रमुख" दिवाला मुद्दों की एक गैर-विस्तृत सूची है जो विवाचन हैं। अंत में, स्विट्ज़रलैंड जैसे अधिकार क्षेत्र में व्यापक रूप से शब्दबद्ध कानून हैं जो सुझाव देते हैं कि अधिकांश प्रकार के दिवाला मुद्दे विवाचन हैं। इसलिए न्यायालय असंगत निर्णयों तक पहुँच सकते हैं कि क्या विवाचन के लिए संदर्भित कुछ विवादों में "मूल" दिवाला मुद्दे शामिल हैं। यह बदले में स्पष्टता की कमी और अनिश्चितता पैदा करता है कि क्या किसी दिवाला मुद्दे के विवाचन को अन्य देशों में वैध रूप से शुरू किया गया माना जाएगा।

एक और चुनौती यह है कि विवाचन पार्टियों के बीच विवाचन के लिए एक समझौते के अस्तित्व पर आधारित है। विवाचन के लिए समझौता बनाने के लिए अनुबंधों में आम तौर पर एक विवाचन खंड शामिल होता है। हालांकि, दिवाला कानून के हिस्से के रूप में, कुछ दिवाला कार्यालयधारकों के पास अनुबंधों को अस्वीकार करने / अलग करने की शक्तियां हैं, और यह विवाचन के समझौते को प्रभावी ढंग से नष्ट कर सकता है।

इसके अलावा, कई दिवाला कार्यवाही में आमतौर पर दिवाला में हितधारकों के बीच कानूनी कार्यवाही पर रोक शामिल होती है, और इसमें विवाचन शामिल होती है। इसलिए, यह संभव है कि कार्यवाही के स्थगन के असंगत आवेदन हो सकते हैं जैसे कि कुछ विवाचन कार्यवाही को कानूनों के एक समूह के तहत जारी रखने की अनुमति दी जाती है, जबकि एक अलग कानून के तहत विवाचन कार्यवाही के दूसरे सेट पर रोक लगा दी जाती है।

विशेषज्ञ निर्धारण

विशेषज्ञ निर्धारण एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा अनुबंध के पक्ष किसी तीसरे पक्ष को किसी मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश देते हैं। तीसरा पक्ष आमतौर पर पार्टियों के बीच के मुद्दे के संबंध में अपनी विशेषज्ञता के लिए चुना गया विशेषज्ञ होगा। सिंगापुर की अदालतों ने फैसला किया है कि जहां पक्षकारों के बीच विशेषज्ञ के निर्धारण को अंतिम माना गया है, उस विशेषज्ञ का निर्धारण

उन पर बाध्यकारी होगा।²⁴ यह विवाद समाधान उपकरण शिपिंग मामलों में बहुत उपयोगी साबित हुआ है, खासकर जब अत्यधिक तकनीकी मामले मुद्दा हों।

विशेष रूप से, व्यवस्था की एक योजना के संदर्भ में, ऋण के सबूतों की अस्वीकृति के संबंध में विवादों के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति के लिए एक वैधानिक तंत्र है। आईआरडीए प्रदान करता है कि ऐसे विवादों का निर्णय एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जा सकता है: (a) विवाद के सभी पक्षों के समझौते से; या (b) यदि ऐसा कोई समझौता नहीं है, तो विवाद के किसी भी पक्ष के आवेदन पर न्यायालय द्वारा; या कंपनी (विवाद का पक्षकार है या नहीं)। जहां एक लेनदार, कंपनी या अध्यक्ष ऋण के एक सबूत के निरीक्षण, प्रवेश या अस्वीकृति के संबंध में एक निर्णय पर एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता के किसी भी निर्णय से असहमत है, लेनदार, कंपनी या अध्यक्ष (जैसा भी मामला हो सकता है) अदालत द्वारा विचार के लिए उस निर्णय के बारे में असहमति की सूचना दायर कर सकता है जब अदालत समझौते या व्यवस्था के न्यायालय के अनुमोदन के लिए आवेदन पर सुनवाई करती है।²⁵

निष्कर्ष

30 जुलाई 2020 को आईआरडीए के प्रभावी होने के साथ, सिंगापुर में अब कॉर्पोरेट देनदारों के पुनर्गठन और दिवाला को अधिक प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने के लिए एक उन्नत दिवाला व्यवस्था है, जो लेनदारों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करना भी चाहता है। हालांकि दिवाला संदर्भ में एडीआर का उपयोग अभी भी सिंगापुर में उतना व्यापक नहीं है, कम से कम ऊपर उल्लिखित कुछ चुनौतियों के कारण नहीं, न्यायिक समर्थन, कुशल बुनियादी ढांचे और प्रासंगिक कानून से युक्त एक मिलनसार पारिस्थितिकी तंत्र के साथ, एडीआर से आगे बढ़ने वाले दिवाला मामलों में एक बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद है।

जैसा कि सिंगापुर दिवाला संदर्भ में एडीआर के उपयोग का पता लगाना जारी रखता है, यह आशा की जाती है कि प्राप्त अनुभवों, और सीखे गए सबक, भारत सहित अन्य क्षेत्राधिकार के लिए कुछ संदर्भ प्रदान कर सकते हैं, जो ऋण समाधान में एडीआर की भूमिका का अध्ययन कर रहे हैं।

²⁴ यह मंजूरी सिंगापुर कंपनी अधिनियम की धारा 210(4) के तहत है।

²⁵ यह मंजूरी सिंगापुर कंपनी अधिनियम की धारा 210(4) के तहत है।

दिवाला (व्यवसायी) के दायित्व : भूमिकाएं, कर्तव्य और दायित्व

धनंजय कुमार, क्रेग मॉंटगोमरी और मिरियम फ़ैरेल्ली

दिवाला (व्यवसायी) के दायित्व : भूमिकाएं, कर्तव्य और दायित्व

धनंजय कुमार, भागीदार, सिरिल अमरचंद मंगलदास
हमराज सिंह, वरिष्ठ सहयुक्त, सिरिल अमरचंद मंगलदास
क्रेग मॉटगोमरी, भागीदार, फ्रेशफील्ड्स ब्रुकहॉस डेरिंगर एलएलपी
मिरियम फ़ैरेल्ली
सहयुक्त, फ्रेशफील्ड्स ब्रुकहॉस डेरिंगर एलएलपी

परिचय

दिवाला वृत्तिक (व्यवसायी) दुनिया भर में कई निगमित दिवाला व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दिवाला अदालत या संबंधित सरकार या कुछ देशों में दिवाला न्यायाधीशों द्वारा नियोजित अधिकारियों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के विपरीत है। परिभाषा के अनुसार दिवाला के लिए पणधारियों (हितधारकों) के हितों के संतुलन की आवश्यकता होती है (क्योंकि प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है) और इसलिए, दिवाला प्रक्रिया के परिणामों में दिवाला वृत्तिक के आचरण की महत्वपूर्ण भूमिका होने की संभावना है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की शुरुआत के साथ से ही भारत में दिवाला पेशा शुरू हुआ और तब से तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान में बहुत महत्ता प्राप्त कर ली है। इंग्लैंड और वेल्स में, दिवाला व्यवसायियों के कर्तव्यों और बाध्यताओं की रूपरेखा लंबे समय से चले आ रहे विधि और केस विधि पर आधारित है : इसमें स्पष्ट सिद्धांत हैं, लेकिन ऐसे जो अभ्युदित होते रहते हैं।

इस लेख में, एक तुलनात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए, हम भारत तथा इंग्लैंड और वेल्स, दो क्षेत्राधिकार जहां दिवाला व्यवसायी (दिवाला प्रक्रिया के केंद्र में हैं, पर नज़र डालते हैं। हमने समापन के बजाय दोनों न्यायालयों (भारत के लिए निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रक्रिया और इंग्लैंड के लिए प्रशासन) में "बचाव" प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। भाग "क" भारतीय व्यवस्था से और भाग "ख" इंग्लैंड और वेल्स में व्यवस्था से संबंधित है। भाग "ग" समापन करता है।

भाग क - दिवाला व्यवसाय के लिए भारतीय विधिक व्यवस्था

1. कार्यालयधारकों के कर्तव्यों और विभिन्न विधिक स्रोतों का अवलोकन

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 ("संहिता") की शुरुआत के साथ ही दिवाला व्यवसाय ("आईपी") का पेशा अस्तित्व में आया। दिवाला विधि सुधार समिति की 4 नवंबर, 2015 की रिपोर्ट ("बीएलआरसी रिपोर्ट") ने आईपी को एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में वर्णित किया है, जिस पर प्रभावी, समय पर कामकाज के साथ-साथ दिवाला और शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया के पूरे भवन की विश्वसनीयता टिकी हुई है। आईपी संहिता के तहत मान्यता प्राप्त व्यवसायियों के एक नए वर्ग का गठन करते हैं। वे भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ("आईबीबीआई") द्वारा विनियमित होते हैं। संहिता नई प्रारंभ प्रक्रिया में प्रशासक, समाधान व्यवसायी और परीसमापक के रूप में आईपी के कार्यों और दायित्वों, व्यक्तिगत दिवाला समाधान प्रक्रिया, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया ("सीआईआरपी"), पूर्व-पैक दिवाला समाधान प्रक्रिया ("प्री-पैक"), परिसमापन और शोधन अक्षमता प्रक्रिया को निर्धारित करती है।¹ संहिता के तहत उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया के दौरान, आईपी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उचित देखभाल और प्रतिबद्धता करने के साथ साथ संबंधित दिवाला व्यावसायिक अभिकरण पर लागू संहिता और उप-नियमों के तहत आवश्यकताओं का पालन करने के लिए भी बाध्य हैं।

आईपी सीआईआरपी एवं प्री-पैक प्रक्रिया के दौरान अंतरिम समाधान व्यवसायी /समाधान व्यवसायी ("आरपी") के रूप में अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करते हैं संहिता की धारा 5 (27) एक 'समाधान व्यवसायी' को " निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया या प्री-पैकेज दिवाला समाधान प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, का संचालन करने के लिए नियुक्त एक समाधान व्यवसायी के रूप में परिभाषित करती है, और इसमें एक अंतरिम समाधान व्यवसायी भी शामिल है"। आरपी को सभी हितधारकों के हितों को संबोधित और संतुलित करने का प्रयास करते हुए संपूर्ण समाधान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने का काम सौंपा गया है। इस संबंध में, संहिता की धारा 23 के अनुसार, समाधान व्यवसायी को सीआईआरपी अवधि के दौरान, संपूर्ण सीआईआरपी का संचालन और निगमित ऋणी ("सीडी") का संचालन एवं प्रबंधन करना चाहिए।

¹ संहिता की धारा 208

आरपी के प्राथमिक विधिक कर्तव्यों में से एक निदेशक मंडल में निहित शक्तियों को ग्रहण करना और सीडी के संचालन को एक चलित उधम के रूप में संचालित करना है। सीआईआरपी के संचालन के संबंध में आरपी के प्रमुख कर्तव्यों में दावों का सत्यापन, सूचना ज्ञापन ("आइएम") की तैयारी, मूल्यांकन कराना, संभावित समाधान आवेदकों द्वारा उध्यम हेतु सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है। आइएम तैयार करने के बाद और उसके अनुसार समाधान योजनाओं की प्राप्ति के उपरांत, सीआईआरपी विनियमों के विनियम 38 के साथ पठित कोड की धारा 30 के तहत आरपी को सुनिश्चित करना है कि प्रस्तुत समाधान योजनाएँ आईबीसी और विनियमों के अनुरूप हैं।

इसी तरह, एक परिसमापन प्रक्रिया के दौरान, एक परिसमापक को सभी लेनदारों के दावों को सत्यापित करने, सीडी की आस्ति का नियंत्रण लेने, सीडी के लाभकारी परिसमापन हेतु व्यापार का संचालन, सीडी की आस्ति को संरक्षित करने और सीडी की बिक्री, चलित उधम के रूप में या सीडी के परिसमापन आस्ति से प्राप्त प्राप्तियों के वितरण करने के लिए आवश्यक उपाय करने का कार्य सौंपा गया है।

आईपी को संहिता के तहत कर्तव्यों को नेकनीयती से पूरा करने हेतु, विधिक कार्यवाही और उसके खिलाफ कार्रवाई के डर के बिना कार्य करने की स्वतंत्रता की भी आवश्यकता होती है। संहिता की धारा 233,

स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी आईपी या परिसमापक द्वारा सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जो कि संहिता, विनियमों या तद्धीन बनाए गए नियमों के तहत किया गया तब आईपी या परिसमापक के विरुद्ध कोई मुकदमा जो कुछ भी किया गया है या होने का इरादा हो, नहीं हो सकता एवं वह अभियोजन या कानूनी कार्यवाही झूठी होगी।

ऐतिहासिक रूप से, भारत में, प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम, 1909 और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 में उक्त अधिनियमों के तहत प्रासंगिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के उद्देश्य से आधिकारिक समनुदेशी/ आधिकारिक आदाता की नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया था। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 448 में उन कंपनियों के परिसमापन के लिए उच्च न्यायालय से जुड़े सरकारी परिसमापक की नियुक्ति का प्रावधान है, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा परिसमाप्त करने का आदेश दिया गया है। कंपनी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 जो कभी लागू नहीं हुआ, में परिसमापक के रूप में नियुक्त होने की पात्रता को बढ़ाया और

पैनल-चार्टर्ड एकाउंटेंट, अधिवक्ताओं, कंपनी सचिवों, लागत और कार्य लेखाकारों, या फर्मों, या ऐसे निगमित निकायों जिसमें व्यवसायी, जो कि केंद्र सरकार के पैनल में हैं, में से एक व्यवसायी के नियुक्ति परिसमापक के रूप में की जा सकती है।, हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 275 के तहत यह परिवर्तन लाया। एक 'कंपनी परिसमापक', चाहे एनसीएलटी द्वारा परिसमापन या स्वैच्छिक परिसमापन के मामले में, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए व्यवसायियों के एक पैनल से नियुक्त किया जाना है। संहिता द्वारा किए गए संशोधनों के साथ, यह धारा अब केवल भुगतान करने में असमर्थता के आधार पर अनिवार्य परिसमापन के मामले में ही प्रासंगिक होगी।

आईपी की योग्यताएँ

एक दिवाला व्यवसायी की भूमिका को UNCITRAL² में दिवाला विधि पर विधायी मार्गदर्शिका³ ("UNCITRAL दिवाला मार्गदर्शिका") में दर्शाया गया है, जिसमें कहा गया है कि - *“एक दिवाला प्रतिनिधि एक दिवाला विधि के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, जिसमें देनदारों और उनकी आस्ति पर कुछ अधिकार होते हैं और उन आस्तियों और उनके मूल्य के साथ-साथ लेनदारों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और सुनिश्चित करने के लिए एक कर्तव्य है कि विधि को प्रभावी और निष्पक्ष रूप से लागू किया जा सके। तदनुसार, यह आवश्यक है कि दिवाला प्रतिनिधि उचित रूप से योग्य हो और ज्ञान, अनुभव और व्यक्तिगत गुणों का अधिकारी हो जो न केवल कार्यवाही के प्रभावी और कुशल संचालन को सुनिश्चित करेगा बल्कि दिवाला व्यवस्था में विश्वास भी सुनिश्चित करेगा।”*

UNCITRAL दिवाला मार्गदर्शिका के तहत निर्धारित इस योग्यता आवश्यकता को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यवसायी) विनियम, 2016⁴ (“आईपी विनियम”) के तहत प्रदान की गई योग्यता और पात्रता मानदंड में शामिल किया गया है।

एक व्यवसायी आईपी बनने के योग्य नहीं होगा यदि वह:

² अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग

³ UNCITRAL, दिवाला पर विधायी मार्गदर्शिका https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/05-80722_ebook.pdf

⁴ भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यवसायी) विनियम, 2016 के विनियम 4 और 5

- (i) नाबालिग है;
- (ii) भारत में निवासी नहीं है;
- (iii) किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है;
- (iv) एक अनुन्मोचित दिवालिया है;
- (v) विकृत दिमाग का घोषित किया गया है; या
- (vi) वह एक योग्य और उचित व्यक्ति नहीं है।

किसी व्यक्ति को उपयुक्त और उचित ठहराने के मानदंड में उसकी सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा, चरित्र, दोषसिद्धि की अनुपस्थिति और संयम आदेश और योग्यता का विश्लेषण शामिल होगा।⁵

एक आईपी के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होने के लिए, एक आवेदक को (क) दिवाला व्यवसायी अभिकरण के साथ नामांकन के लिए अपने आवेदन की तारीख से बारह महीने के भीतर सीमित दिवाला परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी; (ख) एक व्यवसायी सदस्य के रूप में नामांकन के बाद एक दिवाला व्यवसायी अभिकरण से एक पूर्व-पंजीकरण शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, (ग) निम्न को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा : (i) राष्ट्रीय दिवाला कार्यक्रम; (ii) स्नातक दिवाला कार्यक्रम; और (iii) निम्न का अनुभव है (क) विधि के क्षेत्र में दस साल, विधि में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद, (ख) प्रबंधन में दस साल, प्रबंधन में मास्टर डिग्री या प्रबंधन में दो साल का पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद, या (ग) प्रबंधन में पंद्रह साल, स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद या विधि द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान से; या (iv) निम्न के रूप में दस साल का अनुभव (क) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट, (ख) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में पंजीकृत कंपनी सचिव, (ग) भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के सदस्य के रूप में पंजीकृत लागत लेखाकार, या (घ) बार काउंसिल में नामांकित अधिवक्ता।⁶

⁵ आईपी विनियमों के विनियम 4

⁶ आईपी विनियमों के विनियम 5

हाल ही में, 22 जुलाई, 2021 से, अनुभव के संबंध में शर्त को विस्तृत किया गया है और प्रबंधन में पंद्रह वर्ष के अनुभव की आवश्यकता वाले पूर्ववर्ती प्रावधान में संशोधन करके इसे और अधिक उद्देश्यपूर्ण (जैसा कि ऊपर क्रमांक (ग)(iii) में दिया गया है) बनाया गया है।

2. एक कार्यालयधारक द्वारा कर्तव्य के उल्लंघन के लिए कंपनी / लेनदारों को उपलब्ध कार्रवाई के कारण

आईआरपी, वित्तीय लेनदार या परिचालन लेनदार द्वारा प्रस्तावित एवं न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया जाता है।⁷ सीओसी ऐसे नामित व्यक्ति के साथ जारी रह सकता है और उसे समाधान व्यवसायी के रूप में नियुक्त कर सकता है या यदि सीओसी आईआरपी के प्रदर्शन संतुष्ट नहीं है, तो उसे सीओसी की मीटिंग में 66% बहुमत वाले वोटिंग शेयरों के साथ एक अन्य समाधान व्यवसायी के साथ बदल सकता है।⁸ यदि किसी कारण से संतुष्ट नहीं है, तो सीओसी संहिता की धारा 27(2) के तहत वर्तमान आरपी को भी हटा सकता है और उसी प्रक्रिया का पालन करके एक नया आरपी नियुक्त कर सकता है। फिर नए आरपी का प्रस्तावित नाम एनसीएलटी को दिया जाता है। आईपी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए कई कारण हो सकते हैं, जैसे कर्तव्यों के उल्लंघन से लेकर उचित और समय पर कार्रवाई नहीं करना, शक्ति का दुरुपयोग या संहिता में उल्लिखित कर्तव्यों और प्रक्रियाओं के साथ चूक करना।

*इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम गोपाल कृष्ण राजू*⁹ में एनसीएलटी चेन्नई ने माना कि सुनवाई के लिए खुद को पेश करने के लिए अधिकरण से आईआरपी को तीन निर्देशों के बावजूद, आईआरपी जानबूझकर ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है और व्यक्तिगत उपस्थिति से बच रहा है और नोट किया - "आगे, यह रिकॉर्ड में है कि इंडियन ओवरसीज बैंक (आवेदक) ने आईआरपी को सीओसी की दूसरी बैठक आयोजित करने के लिए उसे बदलने और आरपी का प्रस्ताव देने के लिए पत्र भेजा था। उक्त पत्र के उत्तर में, आईआरपी ने यह कहते हुए उत्तर दिया है कि आवेदक उक्त प्रयोजन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है। कर्तव्यों का यह परित्याग प्रकृति में गंभीर है और इसलिए आईआरपी को समाधानव्यवसायी के रूप में आई एंड बी कोड, 2016 के प्रावधानों के तहत किसी भी समनुदेशन के लिए अयोग्य व्यक्ति घोषित किया जाता

⁷ संहिता की धारा 16

⁸ संहिता की धारा 22

⁹ 14 मार्च 2019 का आदेश

है।¹⁰ इस खोज के आधार पर, आईआरपी को समनुदेशन से हटा दिया गया था। आईआरपी/वर्तमान आरपी को हटाना और दूसरे आरपी के साथ प्रतिस्थापन इसलिए, अपने कर्तव्यों के गैर-प्रदर्शन के लिए आईआरपी/आरपी के खिलाफ लेनदारों/सीओसी के लिए उपलब्ध प्रथम स्तर का उपाय है।

आईपी विनियम, संहिता के तहत कर्तव्यों का निर्वहन करते समय आईपी से न्यूनतम व्यावसायिक कदाचार जोकि लागू आचार संहिता¹¹ में निर्धारित हैं। यह सीडी या लेनदारों को सत्यनिष्ठा और वस्तुनिष्ठता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता, पेशेवर क्षमता, तथ्यों की शुद्धता, समयबद्धता, सूचना रखने, गोपनीयता, पारिश्रमिक और लागत आदि के मापदंडों पर आईपी के कार्यों या चूक का पर्यवेक्षण या आकलन करने में सक्षम बनाता है, आईपी को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया का संचालन करने का निर्देश देता है। आईपी द्वारा कर्तव्यों और बाध्यताओं का निर्वहन करते समय गोपनीयता के उल्लंघन, उचित रिकॉर्ड बनाए रखने में देरी, कार्रवाई/प्रतिक्रिया आदि में देरी होने पर, इसके परिणामस्वरूप आचार संहिता का पालन नहीं किया जाएगा और संबंधित हितधारक को कार्रवाई का कारण प्रदान किया जाएगा।

131

एक गलत आईपी के मामले में, लेनदारों का निकाय आईबीबीआई के पास शिकायत दर्ज करके आईपी के खिलाफ संहिता की धारा 217 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है। आईबीबीआई द्वारा एक जांच प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है और परिणामस्वरूप, जांच रिपोर्ट के आधार पर, आईपी पर कारण बताओ सूचना जारी की जा सकती है।¹² इसके बाद, आईबीबीआई जांच के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए कारण बताओ सूचना के निस्तारन के लिए एक अनुशासनात्मक समिति का गठन करेगा।¹³ आईबीबीआई आरपी के खिलाफ अनुशासनात्मक और प्रशासनिक कार्रवाई के लिए प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

3. न्यायालय प्रक्रिया – न्यायालय दिवाला व्यवसायी को किस प्रकार देखता है

शोधन अक्षमता विधि सुधार समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिवाला व्यवसायी निर्णायक के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है।¹⁴ *एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम*

¹⁰ इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम गोपाल कृष्ण राजू, 2019 एससीसी ऑनलाइन एनसीएलटी 7401

¹¹ आईपी विनियमों के विनियम 7(2)(एच) के तहत पहली अनुसूची

¹² आईपी विनियमों का विनियमन 11

¹³ संहिता की धारा 220

¹⁴ शोधन अक्षमता कानून सुधार समिति की रिपोर्ट की धारा 4.4

<https://ibbi.gov.in/uploads/resources/BLRCReportVol1_04112015.pdf>

शिवम वाटर ट्रीटर्स प्राइवेट लिमिटेड¹⁵ मामले में मुंबई न्यायपीठ, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने माना कि एक आरपी न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में कार्य करता है और एक न्यायालय अधिकारी के रूप में इसके कार्यों का निर्वहन करता है। इस प्रकार न्यायालय अधिकारी के किसी भी गैर-अनुपालन या निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के कामकाज में बाधा अदालत की अवमानना होगी। एनसीएलटी¹⁶, की चंडीगढ़ न्यायपीठ द्वारा यह भी देखा गया कि दिवाला व्यवसायी आवेदक के अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं करता है, बल्कि उसका कर्तव्य आचार संहिता का पालन करना और आईबीबीआई द्वारा बनाए गए मानदंडों का पालन करना है।

जबकि न्यायालयों ने आईपी को न्यायालय का एक अधिकारी माना है, जो स्थानीय अधिकारियों और हितधारकों से बड़े पैमाने पर सहयोग मांगने में आईपी के कामकाज को सुचारू करता है, वही समय-समय पर आईपी द्वारा निर्णय लेने में देरी करता है जब सीडी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का निर्वहन करते हुए आईपी के लिए विवादित स्थितियों में महत्वपूर्ण निर्देशों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण से संपर्क करने के परिणामस्वरूप निर्णय लेने वाले प्राधिकारी पर कई मामलों के बैकलॉग/दबाव के कारण पर्याप्त देरी होती है। कर्तव्यों के निर्वहन में आईपी की सुविधा के लिए, संहिता उपबंध करती है कि एक बार आईआरपी नियुक्त होने के बाद, निगमित ऋणि के निदेशक मंडल को निलंबित कर दिया जाता है और तत्पश्चात सीडी का प्रबंधन आईआरपी के पास निहित होता है।¹⁷ इस कर्तव्य को निष्पादित करने के लिए, आईपी विभिन्न कार्यों को करने के लिए अधिकृत है जैसे कि वित्तीय जानकारी के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तक पहुंच¹⁸, खातों की किताबें और अन्य ऐसे दस्तावेज¹⁹, इसके नाम पर आवश्यक कृत्यों और कार्यों को निष्पादित करना²⁰ और ऐसी सभी कार्रवाइयां करना जो संहिता के अनुपालन के लिए आवश्यक हैं और इसलिए, स्वतंत्र और तेज वाणिज्यिक निर्णय लेने के लिए आईपी को सुविधा प्रदान करने के लिए एक अच्छा संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।

4. न्यायालय का रवैया (सामान्य स्थिति और प्री-पैक प्रशासन के दृष्टिकोण के विपरीत)

¹⁵ दिनांक 16 जनवरी, 2019 और 18 फरवरी, 2019 के आदेश

¹⁶ 2017 एससीसी ऑनलाइन एनसीएलटी 1423

¹⁷ संहिता की धारा 17(1)

¹⁸ Section 17(2)(c) of the Code

¹⁹ Section 17(2)(d) of the Code

²⁰ Section 17(2)(a) of the Code

आईपी की भूमिका को कई दिशाओं से देखा गया है और प्रशंसा और आलोचना दोनों प्राप्त हुई है। श्री कृष्णा एग्री प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम फीडेटिव्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड²¹, मामले में एनसीएलटी, कोलकाता न्यायपीठ ने 270 दिनों की विस्तारित अवधि के भीतर सीआईआरपी को कुशलतापूर्वक पूरा करने और समाधान आवेदक द्वारा उचित बाजार मूल्य से ऊपर की आस्तियों को सफलतापूर्वक अधिकार में लेने पर समाधान व्यवसायी की सराहना की। इसी तरह, एनसीएलटी न्यायपीठ ने वंदना गर्ग, आरपी ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया²² के मामले में एनसीएलटी न्यायपीठ के आदेश को उलट दिया, जिसमें आरपी के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी की थी और माना कि आरपी ने वित्तीय लेनदारों के अनुरोध पर वास्तविक तरीके से काम किया था और यह सुनिश्चित किया था कि निगमित ऋणि परिसमापन के लिए नहीं जाता है। इसलिए, उनके खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी अनुचित थी।

उपरोक्त उदाहरण के विपरीत, भारतीय स्टेट बैंक बनाम तटीय परियोजनाओं²³ के मामले में एनसीएलटी कोलकाता ने संहिता में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं करने के लिए आरपी और सीओसी की आलोचना की और उन्हें एक-दूसरे के साथ संवाद करते समय ढीले दृष्टिकोण रखने और संहिता के उद्देश्य का पालन न करने के लिए फटकार लगाई, जो कि समाधान और मूल्य का अधिकतमकरण है। इसी तरह, सनराइज पॉलीफिल्म्स प्रा. लिमिटेड बनाम पंजाब नेशनल बैंक²⁴, में एनसीएलटी अहमदाबाद ने आरपी और सीओसी की आलोचना की और नोट किया कि आरपी अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा क्योंकि उसने संहिता की धारा 25 के अनुसार संभावित समाधान आवेदकों को आमंत्रित नहीं किया था। इसके अलावा, इसने कंपनी के पुनरुद्धार के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्रिय रुचि नहीं लेने के लिए सीओसी को फटकार भी लगाई।

सीआईआरपी में नियंत्रण मॉडल में लेनदार के विपरीत, प्री-पैक एक देनदार के कब्जे वाले मॉडल का अनुसरण करता है, यानी, सीडी का प्रबंधन आरपी को हस्तांतरित नहीं किया जाता है, जब तक कि सीओसी द्वारा 66% बहुमत के साथ मतदान और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है। सीआईआरपी के विपरीत, जहां बोर्ड को निलंबित कर दिया जाता है, प्रीपैक में प्रबंधन में कोई बदलाव नहीं होता है और आरपी को यह सुनिश्चित करना होता है कि लेनदेन निष्पक्ष और पारदर्शी हो। आरपी प्री-पैक शुरू करने से पहले सभी कार्यों में सीडी का

²¹ CA(IB) No. 194/KB/2019, 964 & 848/KB/2019 in CP (IB) No. 187/KB/2018

²² Vandana Garg, RP of Jyoti Structures Ltd. v. State Bank of India, 2018 SCC OnLine NCLAT 660

²³ State Bank of India v. Coastal Projects, CP(IB) No. 593/KB/2017

²⁴ IA 27 of 2018 in C.P. (I.B) No.89/7/NCLT/AHM/2017

मार्गदर्शन करता है और योजना को अंतिम रूप देने में हितधारकों की सहायता करता है। आरपी को प्री-पैक के संचालन से संबंधित मुद्दों के संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दायर करने की शक्ति भी निहित है। प्री-पैक में आरपी और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की सीमित भूमिका होने के कारण, प्रशंसा या आलोचना का दायरा भी सीमित है।

5. विभिन्न प्रकार के कर्तव्य का उल्लंघन , उल्लंघन के लिए मानक और भंग के लिए प्रतिबंध

विनियमों और परिपत्रों के साथ पठित संहिता आईपी पर विभिन्न कर्तव्यों को लागू करती है जिसका उसे आरपी या परिसमापक या प्रशासक की विभिन्न क्षमताओं में पालन करने की आवश्यकता होती है।

आईपी को मुख्यतः चार प्रकार के कर्तव्य, आईआरपी या आरपी के रूप में करने होते हैं:

- (i) इस तरह का पहला कर्तव्य सभी सीओसी बैठकों को आयोजित करना और उनमें भाग लेना है।²⁵ वह आचार सीओसी बैठक आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। उसे प्रत्येक प्रतिभागी को बैठक की सूचना और कार्यसूची प्रदान करना होता है;²⁶
- (ii) दूसरा, आरपी का कर्तव्य है कि वह दावों का उचित मूल्यांकन करे और इसके परिणामस्वरूप, दावों की एक अद्यतन सूची बनाए रखे।²⁷ संहिता की धारा 18 (क) भी उसे निगमित ऋणि की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए निगमित ऋणि की संपत्ति, वित्त और संचालन से संबंधित सभी जानकारी एकत्र करने और सार्वजनिक घोषणा के अनुसार लेनदारों द्वारा प्रस्तुत सभी दावों को प्राप्त करने और मिलान करने के लिए अनिवार्य करती है।²⁸ अनुशासनात्मक समिति ने 13 अप्रैल, 2018 के आदेश में पाया कि आईआरपी ने न केवल दावेदार के दावे की अवहेलना की, बल्कि बार-बार अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद भी उसे जवाब नहीं दिया। वह दावेदार के साथ-साथ बोर्ड के अनुरोधों के प्रति असंप्रेषित बने रहे और इसलिए, यह उनके वैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन था;²⁹

²⁵Section 25(2)(f) of the Code

²⁶ Section 24(3) of the Code

²⁷ Section 25(2) (e) of the Code

²⁸ Section 18 of the Code

²⁹ Order dated April 13, 2018 (No. IBBI/Ref-Disc.Comm./02/2018)

https://ibbi.gov.in/webadmin/pdf/whatsnew/2018/Apr/DC_Dhaiivat_2018-04-13%2020:35:48.pdf

- (iii) तीसरा, आरपी को सूचना ज्ञापन तैयार करना होता है और प्रत्येक समाधान आवेदक को प्रासंगिक जानकारी और दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करनी होती है ताकि समाधान आवेदक उसके अनुसार समाधान योजना तैयार कर सके।³⁰ इस कर्तव्य में सीओसी बैठक में निगमित ऋणी से संबंधित दस्तावेजों, सूचनाओं और अभिलेखों को बनाए रखना और साझा करना शामिल है।³¹ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने *विजय कुमार जैन बनाम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक* के मामले में आरपी के इन कर्तव्यों के महत्व को दोहराया, जहां यह माना गया कि प्रत्येक प्रतिभागी सीओसी की प्रत्येक बैठक की सूचना का हकदार है। आरपी आगे बैठक की कार्यसूची प्रदान करने और सभी 'प्रासंगिक दस्तावेजों' तक पहुंच प्रदान करने के लिए बाध्य है जिसमें समाधान योजना के साथ-साथ प्रत्येक प्रतिभागी को भी शामिल किया गया है।³² इसलिए, मामले के तथ्यों के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आईपी कोड के उल्लंघन में था क्योंकि उसने निगमित ऋणी के निलंबित निदेशक के साथ समाधान योजना साझा नहीं की थी; और
- (iv) चौथा, आरपी को निम्नलिखित संव्यवहार का सीओसी में विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, यदि उसके द्वारा पाया जाता है :
- धारा 43 के तहत अधिमानी संव्यवहार;
 - धारा 45 के तहत कम-मूल्यांकित संव्यवहार;
 - धारा 50 के तहत उद्दापित प्रत्यय संव्यवहार; और
 - धारा 66 के तहत कपटपूर्ण संव्यवहार।

आरपी के साथ-साथ परिसमापक के पास इन संव्यवहार से बचने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के साथ आवेदन दाखिल करने का सर्वोपरि कर्तव्य है।³³

संहिता की धारा 35 उन कर्तव्यों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें परिसमापक को निर्वहन करने की आवश्यकता होती है यानी, परिसमापक को सभी लेनदारों के दावों को सत्यापित करने, ऋणी की संपत्ति पर नियंत्रण रखने, सीडी के व्यवसाय को उसके लाभकारी परिसमापन के लिए चलाने, सीडी की संपत्ति के संरक्षण और सीडी की बिक्री की प्राप्तियों के वितरण के लिए आवश्यक उपाय करने

³⁰ Section 29 of the Code

³¹ Section 25(2) (i) of the Code

³² *Vijay Kumar Jain V/s Standard Chartered Bank*, (2019) 20 SCC 455

³³ Sections 25(2)(j) and 35(1)(l) of the Code

का कार्य सौंपा गया है।³⁴ इसी तरह, एक प्रशासक व्यक्तियों के दिवाला समाधान, परिसमापन और शोधन अक्षमता के उद्देश्य से बनाए गए दिवाला और शोधन अक्षमता कोष को प्रशासित करने की भूमिका ग्रहण करता है।³⁵

कर्तव्य का उल्लंघन भंग और उल्लंघन के मानक

विभिन्न प्रकार के कर्तव्य उल्लंघनों में हितों का टकराव शामिल है जो कि संहिता की धारा 208 (2) (क) और आईपी विनियमों के विनियम 7 (2) (क) और (झ) के तहत कर्तव्य का उल्लंघन है। इनके अलावा, प्रकटीकरण करते समय उचित देखभाल और परिश्रम की कमी³⁶, बीजक के कर्तव्यों को निभाने में लापरवाही³⁷, दुर्भावनापूर्ण इरादे से कार्य करना³⁸, वैध प्राधिकरण के बिना समनुदेशन का दायित्व लेना³⁹, आचार संहिता की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को अपना अधिकार सौंपना⁴⁰, फर्म के नाम पर शुल्क बिल स्वीकार करना जहां केवल आरपी अपने नाम पर शुल्क प्राप्त करने का हकदार है⁴¹, यह भी कर्तव्य का भंग है।

136

संहिता के तहत विभिन्न प्रक्रियाओं में एक आईपी की केंद्रीय भूमिका के आधार पर, एक दिवाला व्यवसायी का अपने कर्तव्यको अत्यंत सावधानी और परिश्रम के साथ करना महत्वपूर्ण है। UNCITRAL आगे इस बात पर जोर देता है कि देखभाल का एक मानक स्थापित करना जिसके साथ दिवाला व्यवसायी अपने कर्तव्यों और कार्यों को करता है और दिवाला व्यवसायियों की व्यक्तिगत देयता का निर्धारण दिवाला कार्यवाही के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। UNCITRAL द्वारा निर्दिष्ट एक दिवाला व्यवसायी की देयता की सीमा एक मानक के बीच संतुलन सुनिश्चित करना है जो कर्तव्यों के सक्षम प्रदर्शन को सुनिश्चित करेगा और जो इतना कठोर है कि यह दिवाला व्यवसायी के खिलाफ विधि-मुकदमों को आमंत्रित करता है।⁴²

³⁴ Section 35 of the Code

³⁵ Section 224 of the Code

³⁶ Order dated July 22, 2021 (IBBI/DC/74/2021)

<https://ibbi.gov.in/uploads/order/0341ec9713c25e4bad8ef69fb6f11e64.pdf>

³⁷ Order dated August 9, 2021 <https://ibbi.gov.in/uploads/order/cb47a2c91437584ec33bd61bcc2b6adf.pdf>

³⁸ Clause 14, First Schedule, IP Regulations

³⁹ Regulation 7A of the IP Regulations

⁴⁰ Section 28(1)(h) of the Code

⁴¹ Order dated March 05, 2021 (ibbi/dc/68/2021)

<https://ibbi.gov.in/uploads/order/99021d25ea6922dc843d3c792ef85443.pdf>

⁴² UNCITRAL, Legislative guide on Insolvency, Page 183 https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/05-80722_ebook.pdf

दिवाला विधि को इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि दिवाला प्रतिनिधि की देयता में अक्सर दिवाला के बाहर विधि का आवेदन शामिल हो सकता है या, जहां आईपी एक व्यवसायी संगठन का सदस्य है, संगठन के प्रासंगिक व्यवसायी मानक।⁴³ भारत में, संहिता की धारा 206 आईपी के लिए दिवाला व्यवसायी अभिकरण के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य बनाती है।⁴⁴ नतीजतन, उन्हें ऐसे अभिकरणों द्वारा निर्धारित व्यवसायी और नैतिक आचरण के लिए मानक का पालन करना आवश्यक है। अनुशासन समिति ने एक आदेश⁴⁵ में देखभाल के मानक निर्धारित किए जिसका पालन करने के लिए आरपी कर्तव्य बाध्य है। यह माना गया कि आरपी को निष्पक्षता और परिश्रम के साथ सीआईआरपी का संचालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाधान योजना किसी विधि के उल्लंघन में नहीं है। उसे अपने वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पूर्ण स्वतंत्रता भी बनाए रखनी चाहिए। इसमें आगे कहा कि "एए एक आईपी के काम पर निर्भर करता है, क्योंकि दिवाला कार्यवाही ज्यादातर प्रकृति में प्रतिकूल नहीं है।" ऐसे एक उदाहरण में जहां आरपी कुछ खुलासे करते समय उचित सावधानी बरतने और उचित परिश्रम करने में विफल रहा, अनुशासन समिति ने आरपी पर जुर्माना लगाया और उसे संहिता के तहत नए समनुदेशन स्वीकार करने से रोक दिया।⁴⁶

उल्लंघन के लिए प्रतिबंध

यदि आईपी संहिता या नियमों या विनियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो अनुशासनात्मक समिति, संहिता की धारा 220 के तहत प्रदान की गई चेतावनी या कोई दंड या कोई अन्य कार्रवाई या निर्देश जो वह उचित समझे, प्रदान करके कारण बताओ सूचना का निपटान कर सकती है।⁴⁷ संहिता के तहत, यदि दिवाला व्यवसायी ने संहिता के किसी भी प्रावधान या किसी भी प्रासंगिक विनियमों का उल्लंघन किया है तो वह जुर्माना लगा सकता है जो (i) संबंधित व्यक्तियों को हुए नुकसान या संभावित नुकसान की राशि का तीन गुना; या (ii) इस तरह के उल्लंघन के कारण हुए गैरकानूनी लाभ की राशि का तीन गुना, जो भी अधिक होगा। हालांकि, अगर नुकसान का आकलन नहीं किया जा सकता है, तो लगाए गए जुर्माने की कुल राशि एक करोड़ रुपये

⁴³ UNCITRAL, Legislative guide on Insolvency, Page 183 https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/05-80722_ebook.pdf

⁴⁴ Section 206 of the Code

⁴⁵ Order dated November 12, 2018 (No. IBBI/DC/12/2018)

https://ibbi.gov.in/webadmin/pdf/whatsnew/2018/Nov/Order%20in%20the%20Matter%20of%20Martin%20S.%20K.%20Golla_2018-11-13%2014:37:09.pdf

⁴⁶ Order dated July 22, 2021 (No. IBBI/DC/74/2021)

<https://ibbi.gov.in/uploads/order/0341ec9713c25e4bad8ef69fb6f11e64.pdf>

⁴⁷ Regulation 13 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and Investigation) Regulations, 2017

से अधिक नहीं होनी चाहिए।⁴⁸ इसके अलावा, संहिता के तहत, बोर्ड ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिसने संहिता के किसी प्रावधान का उल्लंघन करके गैर-कानूनी लाभ या हानि को टाला हो, इस तरह के गैरकानूनी लाभ या हानि से बचने के बराबर राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक दिवाला व्यवसायी कारावास के अधीन होगा, जिसकी अवधि छह महीने तक हो सकती है, या जुर्माने के साथ जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा और अगर वह जानबूझकर संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो यह पांच लाख रुपये तक बढ़ाई जा सकती है।⁴⁹

अनुशासनात्मक समिति प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर प्रत्येक शिकायत का विश्लेषण करती है और इस प्रकार, उस विशिष्ट उल्लंघन की उग्रता और गंभीरता के आधार पर अलग-अलग प्रतिबंध करती है। इस प्रकार, अनुशासनात्मक समिति केवल एक चेतावनी प्रदान करके मामले का निपटारा कर सकती है कि आईपी को उचित देखभाल करनी चाहिए और संहिता⁵⁰ के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करते समय बेहद सावधान और मेहनती होना चाहिए या यहां तक कि अगर दिवाला व्यवसायी को निगमित ऋणी द्वारा वित्तीय लेनदार के लिए किए गए कुछ निपटान के बारे में पता नहीं था, तो प्रतिबंधों को प्रदान करते समय एक उदार दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिए।⁵¹ ऐसे मामलों में जहां आईपी द्वारा किए गए उल्लंघन की प्रकृति उग्र और गंभीर है, अनुशासनात्मक समिति आईपी को समनुदेशन⁵² से प्राप्त शुल्क के 10 प्रतिशत के बराबर जुर्माना देने का निर्देश दे सकती है और आगे, उसे किसी भी नए समनुदेशन को स्वीकार करने या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए संहिता के तहत सेवाएं प्रदान करने से रोक सकती है।⁵³

दिवाला व्यवसायी अभिकरण द्वारा आईपी के खिलाफ लगाए जा सकने वाले प्रतिबंधों को और अधिक कठोर और समान बनाने के लिए संशोधित किया गया है, जिसमें 28 जुलाई, 2021⁵⁴, के परिपत्र के तहत, बोर्ड ने अधिसूचित किया कि दिवाला व्यवसायी अभिकरण "जुर्माने की उत्तरोत्तर

⁴⁸ Section 220 (3) of the Code

⁴⁹ Section 70(2) of the Code

⁵⁰ Order dated April 16, 2021

(<https://ibbi.gov.in/uploads/order/429e28f26385420ea0676c74e7f93f13.pdf> ; Order dated September 17, 2021 ([ibbi/dc/77/2021](https://ibbi.gov.in/uploads/order/ae82e3b9e2db0ef038e69003cf11a7ad.pdf)) <https://ibbi.gov.in/uploads/order/ae82e3b9e2db0ef038e69003cf11a7ad.pdf>

⁵¹ Order dated July 8, 2021 (IBBI/DC/72/2021)

<https://ibbi.gov.in/uploads/order/fbe3335c2327ac029dd3f9592bfb66ed.pdf>

⁵² Order dated August 09, 2021 (ibbi/dc/75/2021)

<https://ibbi.gov.in/uploads/order/cb47a2c91437584ec33bd61bcc2b6adf.pdf>

⁵³ Order dated December 04, 2020 (ibbi/dc/51/2020)

<https://ibbi.gov.in/uploads/order/e4dbc09f8da57699c9b70e57ea47fc58.pdf>

⁵⁴ Circular dated July 28, 2021 (No. IBBI/IPA/43/2021)

<https://ibbi.gov.in/uploads/legalframework/c3d5d1bd7b451572b4dea0cfd7bcba3d.pdf>

प्रणाली लागू कर सकती हैं, जहां मामूली गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप मौद्रिक जुर्माना होगा और बड़े उल्लंघनों के परिणामस्वरूप मौद्रिक जुर्माना और अभिकरण से निष्कासन होगा।"

परिपत्र में उपबंध है कि 1,00,00 रुपये का जुर्माना या शुल्क का 25%, जो भी अधिक हो, का भुगतान दिवाला व्यवसायी द्वारा किया जाएगा यदि वह अन्य बातों के साथ-साथ संहिता और प्रासंगिक विनियम के तहत प्रकटीकरण, रिटर्न या अपर्याप्त या गलत प्रकटीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है। इसके अलावा, 2,00,000 रुपये का जुर्माना या शुल्क का 25%, जो भी अधिक हो, का भुगतान दिवाला व्यवसायी द्वारा किया जाएगा यदि वह अन्य बातों के साथ-साथ हितधारकों के साथ हितों के टकराव वाले समनुदेशन को स्वीकार करता है। इसी तरह आईपी द्वारा विभिन्न प्रकार के गैर-अनुपालनों के लिए मौद्रिक दंड प्रदान किया गया है जैसे रिकॉर्ड बनाए रखने में विफलता, न्यायनिर्णायक प्राधिकारण द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में विफलता, प्रासंगिक नियमों के तहत प्रदान किए गए तरीके से सार्वजनिक घोषणा करने में विफलता, अपात्र समाधान आवेदकों से समाधान योजना को अस्वीकार करने में विफलता और संहिता के तहत अपने कर्तव्यों में विभिन्न अन्य गैर-अनुपालन।

139

भारत में, आईपी पर व्यक्तिगत दायित्व की सीमा काफी हद तक नियमों द्वारा तय की जाती है और अपेक्षाकृत कठोर रहती है, जिसके तहत आईपी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा यदि निगमित व्यक्ति पर लागू विधियों के किसी भी प्रावधान का अनुपालन न करने के कारण कोई नुकसान या जुर्माना लगाया जाता है, यदि यह उसके आचरण के कारण है।⁵⁵ इसके अलावा भारत में, संहिता विशेष रूप से मौद्रिक दंड की सीमा उपबंध करती है जो कि संहिता⁵⁶ की धारा 220 के तहत और आईबीबीआई (मॉडल उप-नियम और दिवाला व्यवसायी अभिकरणों के शासी निकाय) विनियम, 2016 की अनुसूची के खंड 24 (2) (घ) के तहत किसी भी कर्तव्य के उल्लंघन या किसी भी विनियम के उल्लंघन के लिए निर्धारित की जा सकती है। हमने ऐसा कोई मामला नहीं देखा है, जहां समाधान व्यवसायी पर दायित्व थोपने की मांग की गई हो।

भाग ख - दिवाला व्यवसायियों के लिए ब्रिटिश विधिक व्यवस्था के तहत जवाबदेही

1. परिचय

⁵⁵ Circular no. 2 of 2018 issued by IBBI dated January 3, 2018
https://ibbi.gov.in/webadmin/pdf/legalframework/2018/Jan/CIRP_2_2018-01-03_18:42:00.pdf

⁵⁶ Section 220 of the Code

वह संदर्भ जिसमें प्रशासकों को आमतौर पर किसी कंपनी के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया जाएगा, का मतलब है कि उनकी स्थिति कानूनी जोखिम की एक महत्वपूर्ण कोटि के साथ है। प्रशासक अक्सर खुद को संकट में कंपनी का प्रबंधन करते हुए पाएंगे और उन्हें उन परिस्थितियों में तेजी से निर्णय लेने होंगे जहां कंपनी के सभी हितधारकों को वह नहीं मिलेगा जिसकी उन्होंने कंपनी से अपेक्षा की थी या उम्मीद की थी (शेयरधारकों, जिनके शेयरों का अब कंपनी में कोई मूल्य नहीं है, से सुरक्षित लेनदारों, जो केवल अपने उधार का हिस्सा वसूल कर सकते हैं, तक)।

यह भाग ख उस तरीके की पड़ताल करता है जिसमें हितधारकों द्वारा प्रशासकों के आचरण को चुनौती दी जा सकती है। भाग ख की धारा 2 प्रशासकों के कर्तव्यों का एक सिंहावलोकन निर्धारित करती है, जो कि उनका कर्तव्य है और न्यायालय यह आकलन करते समय कि क्या उन कर्तव्यों को **उल्लंघन** किया गया है विभिन्न सीमाएँ लागू करेगा। धारा 3 चुनौती के लिए तंत्र निर्धारित करती है जो उन हितधारकों के लिए उपलब्ध हो सकती है जहां उन कर्तव्यों को **उल्लंघन** किया जाता है। धारा 4 धारा 2 और 3 में पहचाने गए प्रमुख बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए हाल के तीन मामलों का सारांश प्रदान करती है। धारा 5 में प्रशासक के न्यायालय में अपने कर्तव्यों के अनुपालन को चुनौती देने की प्रक्रिया और व्यवसायियों के लिए निहितार्थ पर चर्चा की गई है। अंत में, धारा 6 उस नियामक ढांचे की रूपरेखा तैयार करती है जो दिवाला व्यवसायियों (प्रशासक सहित) पर लागू होती है और बताती है कि कैसे यह ढांचा प्रशासकों को उनके कर्तव्यों के प्रदर्शन में कदाचार के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए एक आधार प्रदान करता है।

प्रशासकों के कर्तव्य और उल्लंघनके लिए प्रतिबंध

प्रारंभिक बिंदु के रूप में, प्रशासक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति योग्य व्यवसायी दिवाला व्यवसायी होते हैं। इस तथ्य की मान्यता में कि उनके कई निर्णय व्यावसायिक निर्णय होंगे, न्यायालयों ने आम तौर पर उनके निर्णयने के प्रति कुछ हद तक सम्मान दिखाया है।⁵⁷

⁵⁷ Lightman & Moss, 12-008; *In re CE King Ltd* [2000] 2 BCLC 297, 302—3: “First, prima facie, what the administrators should do about [a particular] contract is a commercial decision. Secondly, at least in principle and in general, it is not for the court to interfere with such commercial decisions; those are to be left to the administrator. Thirdly, if the administrators are proposing to take a course which is based on a wrong appreciation of the law and/or is conspicuously unfair to a particular creditor or creditors or contractor of the company, then the court can and, in an appropriate case, should be prepared to interfere. I put it in that somewhat neutral way because even it is appropriate for the court to interfere, the actual course the court should take must inevitably depend on the actual facts and circumstances of the case.” *Goel v Grant / In re Meem SL Ltd (in administration)* [2017] EWHC 2688 (Ch): “The threshold for the court to interfere with the decision of an administrator regarding the sale of an asset is at least as high as it is in the case of a liquidator, given that administrators are typically appointed in order to achieve speedy results” (emphasis added) [37].

एक प्रशासक के पास कंपनी के अभिकर्ता के रूप में,⁵⁸ न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में न्यायालय के लिए,⁵⁹ और एक योग्य व्यवसायी, जो अधिकृत या व्यवसायी निकाय के सदस्य होते हैं, के रूप में⁶⁰ व्यवसायी कर्तव्य होते हैं। ये कर्तव्य अतिव्याप्त होते हैं।

प्रशासक के कई कर्तव्य वैधानिक हैं।⁶¹ एक प्रशासन की शुरुआत में, एक प्रशासक का कर्तव्य है कि वह उद्देश्यों के वैधानिक पदानुक्रम के अनुसार प्रशासन के उद्देश्य को निर्धारित करे, जैसा कि दिवाला अधिनियम 1986 की अनुसूची ख 1 के अनुच्छेद 3 में निर्धारित किया गया है:

- (i) कंपनी का एक चलित उधम के रूप में बचाव;
- (ii) कंपनी के समापन पर कंपनी के लेनदारों के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करने की संभावना होगी (पहले प्रशासन में रहे बिना); या
- (iii) एक या एक से अधिक सुरक्षित या अधिमान्य लेनदारों को वितरण करने के लिए संपत्ति की प्राप्ति।

महत्वपूर्ण रूप से, व्यवस्थापक जिस उद्देश्य को अनुसरण करने के लिए चुनता है, वह प्रभावित करेगा कि किन हितधारकों के हितों को प्राथमिकता दी जाती है और व्यवस्थापक के कर्तव्यों का मुख्य रूप से किसके लिए है: उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यवस्थापक पहले दो उद्देश्यों में से एक का चयन करता है, तो उसका कर्तव्य होगा कि वह समग्र रूप से कंपनी के लेनदारों के हित में कार्य करे।⁶² तुलना करके, यदि वह तीसरे वैधानिक उद्देश्य ("एक या अधिक सुरक्षित या अधिमान्य लेनदारों को वितरण करने के लिए संपत्ति की वसूली") का चयन करता है, तो उसका कर्तव्य संबंधित सुरक्षित या अधिमान्य लेनदार के प्रति होगा। उस स्थिति में, व्यवस्थापक का केवल यह दायित्व है कि वह समग्र रूप से कंपनी के लेनदारों के हितों को अनावश्यक रूप से नुकसान न पहुंचाए।⁶³ प्रशासक का निर्णय कि किस उद्देश्य का अनुसरण करना है, केवल तब चुनौती के अधीन है यदि निर्णय बदनीयत में लिया गया है या स्पष्ट रूप से विकृत किया गया था (इस अर्थ में कि कोई भी

⁵⁸ Insolvency Act 1986 (IA 1986), para 69 sch B1.

⁵⁹ IA 1986, para 5 sch B1.

⁶⁰ IA 1986, para 6 sch B1 and ss.390 and 390A IA 1986.

⁶¹ In addition to the statutory duties outlined below, an administrator has other duties as an officer of the company (for example in relation to employment and health and safety). The focus of [chapter] will be the duties specific to administrators. (Lightman & Moss, 12-055).

⁶² Para 3(2) sch B1.

⁶³ Para 3(4) sch B1.

उचित प्रशासक यह नहीं सोच सकता था कि वैधानिक पदानुक्रम में उच्चतर उद्देश्य का अनुसरण करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं था।⁶⁴

इसके अलावा, एक प्रशासक के पास कंपनी के प्रबंधन के संबंध में और प्रशासन के वैधानिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी आस्ति से अभिलाभ प्राप्त करने के लिए व्यापक वैधानिक शक्तियां और कर्तव्य होते हैं।⁶⁵ ये वैधानिक कर्तव्य एक प्रशासक के कई सामान्य विधि कर्तव्यों से निकटता से जुड़े हुए हैं। तीन प्रमुख सामान्य विधि कर्तव्य हैं (i) एक वैश्वासिक के रूप में प्रशासक के कर्तव्य; (ii) उचित देखभाल और कौशल के साथ कार्य करने के लिए प्रशासक का कर्तव्य; और (iii) *एकपक्षीय जेम्स* के तहत प्रशासक के कर्तव्य।

सबसे पहले, एक प्रशासक अपने अभिकर्ता के रूप में कंपनी के प्रति वैश्वासिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है। उन कर्तव्यों में निष्ठा का कर्तव्य, स्वतंत्र निर्णय लेने का कर्तव्य,⁶⁶ और हितों के टकराव से बचना शामिल है।⁶⁷ न्यायालय के लिए यह पता लगाने की शुरुआत है कि एक प्रशासक ने एक वैश्वासिक कर्तव्य का **उल्लंघन** किया है : न्यायालय “केवल हस्तक्षेप करेगा...अगर [प्रशासक ने] कुछ इतना अनुचित और बेतुका किया है कि कोई भी उचित व्यक्ति ऐसा नहीं करता।”⁶⁸ मामले की विधि में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां चुनौती देने वालों ने एक प्रशासक द्वारा वैश्वासिक कर्तव्य के उल्लंघन का आरोप लगाया है, उदाहरण के लिए, आरोपों के आधार पर कि एक प्रशासक ने अपने विवेकाधिकार को किसी विशेष हितधारी या सलाहकार के हित में लिया है⁶⁹; या अपनी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करते समय प्रासंगिक मामलों को ध्यान में रखने में विफल रहे हैं और अप्रासंगिक नहीं हैं।

प्रशासक के वैश्वासिक कर्तव्य का दायरा संशोधित किया जाएगा यदि वह प्रशासन के तीसरे उद्देश्य का अनुसरण करने का विकल्प चुनता है। उन परिस्थितियों में, प्रशासक पहले सुरक्षित या अधिमान्य लेनदारों के हितों को रख सकता है, हालांकि वह असुरक्षित लेनदारों को एक वैश्वासिक

⁶⁴ *Davey v Money* [2018] EWHC 766 (Ch) at [255]; *In Re Zinc Hotels* [2018] EWHC 1936 (Ch) at [98]

⁶⁵ Paras 59 and 70-72 sch B1 and sch 1.

⁶⁶ *Davey v Money* [2018] EWHC 766 (Ch) at [590]

⁶⁷ In *Davey v Money* [2018] EWHC 766 (Ch), the administrator's duty to use their powers for proper purposes was considered a fiduciary duty; whereas in *Re ARY Digital UK Ltd; Brewer v Iqbal* [2019] EWHC 182 (Ch) it was not: see [44].

⁶⁸ *Re Edenote Ltd* [1996] B.C.C. 718 (CA), 722.

⁶⁹ *Davey v Money* [2018] EWHC 766 (Ch) at [588]; *Re ARY Digital UK Ltd; Brewer v Iqbal* [2019] EWHC 182 (Ch).

कर्तव्य देना जारी रखेगा। इस संबंध में, एक सुरक्षित या अधिमान्य लेनदार के हितों के लिए एक प्रशासक द्वारा विवेकाधिकार का उपयोग, वैश्वसिक कर्तव्य का भंग हो सकता है।⁷⁰

दूसरा, एक प्रशासक का भी कंपनी के लिए कर्तव्य है कि वह अपने कार्यों के निष्पादन में उचित देखभाल और कौशल के साथ कार्य करे। यह एक व्यापक कर्तव्य है और प्रशासन के सभी पहलुओं में उत्पन्न होता है। न्यायालय के लिए यह पता लगाने की शुरुआत है कि एक प्रशासक ने इस कर्तव्य को **उल्लंघन** किया है, जहां उसका आचरण "साधारण, कुशल व्यवसायी" या "यथोचित कुशल और सावधान व्यवसायी" के मानक से नीचे आता है।⁷¹ यद्यपि यह एक वैश्वसिक कर्तव्य नहीं है, इस कर्तव्य को **उल्लंघन** करने वाले प्रशासकों द्वारा विफलताएं (जैसा कि नीचे चर्चा की गई है) वैश्वसिक कर्तव्य का **उल्लंघन** हो सकता है यदि, उदाहरण के लिए, वे विवेक का आत्मसमर्पण या प्रासंगिक मामलों को ध्यान में रखने में विफलता को भी शामिल करते हैं।

तीसरा, एक पक्षीय जेम्स के अधीन न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में एक प्रशासक का कर्तव्य है कि वह निष्पक्ष रूप से कार्य करे।⁷² जहां एक प्रशासक ऐसा करने में विफल रहता है, न्यायालय अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के अनुसार हस्तक्षेप कर सकता है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि *"न्यायालय अपने अधिकारियों को इस तरह से कार्य करने की अनुमति नहीं देगी कि यह स्पष्ट रूप से स्वयं न्यायालय के लिए कार्य करना गलत होगा।"*

हालाँकि, यह कर्तव्य न्यायालय द्वारा शायद ही कभी लागू किया जाता है, और इसका आवेदन बहुत तथ्य विशिष्ट होगा।⁷³ उदाहरण के लिए, यह वहां लागू हो सकता है, जहां सख्त विधिक स्थिति का पालन करने के लिए प्रशासक के आग्रह के परिणामस्वरूप अनुचित, बेईमान या अपमानजनक परिणाम होगा।⁷⁴ *लेहमैन ब्रदर्स ऑस्ट्रेलिया लिमिटेड (परिसमापन में) बनाम डाउन्स* में ऐसा ही मामला था, जहां गलत मुद्रा रूपांतरण दर को गलती से दावा निर्धारण विलेख में शामिल किया गया था, जिससे संपत्ति को नुकसान हुआ, और व्यवस्थापक ने विलेख के संशोधन करने के लिए सहमति नहीं दी। यह ज्ञात होने पर कि प्रशासक को सख्त विधिक स्थिति बनाए

⁷⁰ *Re One Blackfriars Ltd (In Liquidation) / Hyde v Nygate* [2021] EWHC 684 (Ch) at [230]-[231].

⁷¹ Lightman & Moss, 12-042.

⁷² Authority has been divided over whether the rule was limited to "unconscionable" behaviour or "unfair" behaviour: the Court of Appeal recently established that the test is one of fairness in *Lehman Brothers Australia Limited v Downs and others* [2020] EWCA Civ 321 at [68]. Given this finding, there is likely to be overlap between the application of the principle in *Ex parte James* and paragraph 74 of Schedule B1.

⁷³ *Lehman Brothers Australia Limited v Downs and others* [2020] EWCA Civ 321 at [68]-[69].

⁷⁴ Lightman & Moss, 12-044.

रखने की अनुमति देना एकपक्षीय जेम्स सिद्धांत का उल्लंघन होगा, अपीलीय न्यायालय ने त्रुटि को ठीक करने के लिए प्रतिपक्ष को राहत दी।

इसके अलावा, एक प्रशासक प्रशासन के दौरान आचरण के माध्यम से अन्य विधिक कर्तव्यों (और ऐसे ही संभावित व्यक्तिगत दायित्व) को ग्रहण कर सकता है। इस तरह के दायित्व को सामान्य विधिक सिद्धांतों के तहत स्थापित किया जा सकता है (जैसे लापरवाही या आर्थिक अपकृत्य में से एक के संबंध में, जैसे कि वैध साधन साजिश या अवैध साधन साजिश)। हालांकि, एक प्रशासक को एक हितधारकों के कर्तव्य को देने के लिए एक विशेष तरीके से कार्य करने की आवश्यकता होती है : यह प्रशासक के वैधानिक या सामान्य विधिक कर्तव्यों का एक स्वचालित हिस्सा नहीं है। जिम्मेदारी की धारणा के लिए परीक्षण एक उद्देश्य है, और प्राथमिक ध्यान प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, हितधारकों के साथ अपने व्यवहार में व्यवस्थापक द्वारा कही गई या की गई बातों पर होना चाहिए। विशेष रूप से, एक व्यवस्थापक को विशिष्ट प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता होती है जो हितधारी द्वारा निर्भर होते हैं, या विशेष परिस्थितियों या व्यवस्थापक और संबंधित हितधारी के बीच एक विशेष संबंध होने की आवश्यकता होती है।⁷⁵ हाल के उदाहरणों में जहां हितधारकों ने प्रशासकों के खिलाफ दावा करने में इस तरह के संबंधों पर जोर दिया है, उनमें शामिल हैं : (i) कंपनी की आस्ति का एक असफल खरीदार, जो लापरवाही से गलत बयानी में दावा करता है (पीजेएससी उरालकली बनाम राउली में);⁷⁶ और (ii) एक लेनदार जिसका कंपनी में हित कंपनी की आस्ति की बिक्री से प्रभावित था (फ्रेजर टर्नर लिमिटेड बनाम प्राइसवाटरहाउसकूपर्स एलएलपी)।⁷⁷ दोनों ही मामलों में, दावे विफल रहे। पीजेएससी उरालकली बनाम राउली में, कोर्ट ने संकेत दिया कि ऐसा कर्तव्य असामान्य होगा, यह टिप्पणी करते हुए कि :

मेरा मानना है कि वर्तमान जैसे तथ्यों पर प्रशासकों पर व्यक्तिगत देखभाल का कर्तव्य थोपना कंपनी के लेनदारों के हितों में कार्य करने के लिए प्रशासकों पर रखे गए एकचित कर्तव्य के प्रतिकूल होगा। कोई कभी नहीं कह सकता है, और ऐसे असाधारण मामले हो सकते हैं जहां प्रशासकों को तीसरे पक्ष के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए पाया जाएगा।

अंत में, इस बात की भी संभावना है कि हितधारक यह तर्क देने की कोशिश कर सकते हैं कि प्रशासकों ने या तो कंपनी को अपकृत्य करने के लिए प्रेरित करके या अवैध साधनों की साजिश

⁷⁵ *Fraser Turner Ltd v PricewaterhouseCoopers LLP* [2019] EWCA Civ 1290 at [70]-[71].

⁷⁶ *PJSC Uralkali v Rowley* [2020] EWHC 3442 (Ch)

⁷⁷ *Fraser Turner Ltd v PricewaterhouseCoopers LLP* [2019] EWCA Civ 1290

जैसे किसी अपकृत्य में सीधे भाग लेकर व्यक्तिगत दायित्व वहन किया है। ऐसे कई मामले हैं जिनमें बिक्री प्रक्रिया में प्रशासकों के आचरण को चुनौती देने वाली पार्टियों ने प्रशासकों और किसी अन्य पार्टी के बीच या बिक्री के संचालन को प्रभावित करने वाले पक्षों के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया या सुचित किया है।⁷⁸ हालांकि, इन उदाहरणों में न्यायालय ने यह सुझाव देते हुए इन आरोपों पर गंभीरता से विचार नहीं किया है, कि इस तरह के दावे के सफल होने के लिए कि एक प्रशासक ने अनुचित व्यवहार किया है, बाध्यकारी सबूत की आवश्यकता होगी।

2. न्यायालय में प्रशासकों को चुनौती देने के लिए तंत्र

प्रशासकों के आचरण को चुनौती देने के लिए दो प्रमुख वैधानिक तंत्र हैं, जैसा कि दिवाला अधिनियम 1986 की अनुसूची ख1 के अनुच्छेद 74 और 75 में निर्धारित किया गया है और नीचे उल्लिखित है। अनुच्छेद 74 और 75 के बीच मुख्य अंतर यह है कि अनुच्छेद 74 प्रशासन में कंपनी के प्रबंधन से संबंधित है, और अनुच्छेद 75 एक प्रशासक के कदाचार से संबंधित है।⁷⁹ जैसा कि नीचे दिया गया है, अनुच्छेद 74 आवेदनों में केंद्र यह है कि क्या आवेदक को अनुचित नुकसान हुआ है; एक प्रशासक द्वारा कदाचार एक महत्वपूर्ण कारक है लेकिन पूर्वापेक्षा नहीं है।⁸⁰ उस आधार पर, एक व्यक्तिगत लेनदार को अनुच्छेद 74 के तहत राहत मिलने की संभावना है।⁸¹ इसके विपरीत, जहां एक हितधारी (प्रतिष्ठा वाले) प्रशासक द्वारा कर्तव्य के उल्लंघन का दावा करना चाहता है, उपयुक्त मार्ग अक्सर अनुच्छेद 75 के तहत एक आवेदन होगा।⁸² अनुच्छेद 75 के तहत, राहत व्यक्तिगत उपचार प्रदान करने के बजाय, लेनदारों या अंशदाताओं के सामूहिक लाभ के लिए प्रशासनिक संपत्ति को बहाल करने के लिए निर्देशित है।⁸³

अनुच्छेद 75 के तहत चुनौतियां

ऊपर निर्धारित कई कर्तव्यों के संबंध में हितधारक चुनौती के लिए अधिक बार उपयोग किया जाने वाला वैधानिक तंत्र अनुसूची ख 1 का अनुच्छेद 75 है। अनुच्छेद 75 के तहत, आधिकारिक

⁷⁸ *Clydesdale Financial Services Ltd v Smailes* [2009] EWHC 1745 (Ch) at [31]; *Davey v Money* [2018] EWHC 766 (Ch) at [588]; *In Re Zinc Hotels* [2018] EWHC 1936 (Ch) at [119]-[129]; *Re ARY Digital UK Ltd; Brewer v Iqbal* [2019] EWHC 182 (Ch) at [95]-[96].

⁷⁹ *In re Coniston Hotel (Kent) LLP* [2013] EWHC 93 (Ch) at [69].

⁸⁰ *Lehman Brothers Australia Limited v Downs and others* [2020] EWCA Civ 321; *Four Private Investment Funds v Lomas* [2008] EWHC 2869 (Ch); *Fraser Turner Ltd v PricewaterhouseCoopers LLP* [2019] EWCA Civ 129, as discussed below.

⁸¹ *In re Coniston Hotel (Kent) LLP* [2013] EWHC 93 (Ch) at [69].

⁸² Lightman & Moss, 12-064.

⁸³ *In re Coniston Hotel (Kent) LLP* [2013] EWHC 93 (Ch) at [69].

आदाता, एक प्रशासक, एक परिसमापक, एक लेनदार या एक अंशदायी कंपनी के एक प्रशासक के आचरण की जांच के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है।⁸⁴ अनुच्छेद 75 के तहत आवेदन में यह आरोप लगाया जाना चाहिए कि व्यवस्थापक :

- (i) कंपनी के पैसे या अन्य संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया है या उसे रोक रखा है;
- (ii) कंपनी के पैसे या अन्य संपत्ति के लिए जवाबदेह बन गया है;
- (iii) कंपनी के संबंध में एक वैश्वसिक या अन्य कर्तव्य को **उल्लंघन** किया है; या
- (iv) दुराचार का दोषी पाया गया है।⁸⁵

इसलिए आचरण की एक विस्तृत विविधता को अनुच्छेद 75 के दायरे में चुनौती दी जा सकती है। विशेष रूप से, उचित देखभाल और कौशल का प्रयोग करने के लिए कर्तव्य के किसी भी **उल्लंघन** या वैश्वसिक कर्तव्य के किसी भी **उल्लंघन** को अनुच्छेद 75 चुनौती के माध्यम से उठाया जा सकता है। उन विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों के संबंध में न्यायालय जिन समीक्षा मानकों को लागू करेगा, वे ऊपर निर्धारित किए गए हैं। यदि अनुच्छेद 75 के तहत राहत के लिए एक आवेदन सफल होता है, तो न्यायालय के पास प्रशासक को धन या संपत्ति के भुगतान, पुनर्स्थापन या खाते का आदेश देने की; ब्याज का भुगतान करने की; या कर्तव्य के भंग या अपकरण के लिए मुआवजे के रूप में कंपनी की संपत्ति में एक राशि का योगदान करने की शक्ति है।

एक प्रशासक के लिए यह संभव है कि यदि वह अनुच्छेद 75 के तहत उत्तरदायी पाया जाता है, तो वह इस आधार पर दायित्व से राहत के लिए आवेदन कर सकता है कि उसने ईमानदारी से और उचित रूप से कार्य किया है, और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसे उचित रूप से दायित्व से क्षमा किया जाना चाहिए।⁸⁶

अनुच्छेद 74 के तहत चुनौतियां

इसके अलावा, एक लेनदार या प्रशासन में कंपनी का सदस्य अनुसूची ख 1 के अनुच्छेद 74 के तहत राहत के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है जहां :

- (i) प्रशासक कार्य कर रहा है या उसने आवेदक के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत तरीके से कार्य किया है (चाहे अकेले या कुछ या सभी अन्य सदस्यों या लेनदारों के साथ समन्वय में); या

⁸⁴ A broader range of stakeholders therefore have standing to make an application under paragraph 75 compared with paragraph 74. Para 75(2).

⁸⁵ Para 75(3).

⁸⁶ Companies Act 2006, s.1157; Lightman & Moss 12-067.

- (ii) प्रशासक इस तरह से कार्य करने का प्रस्ताव करता है जो आवेदक के हितों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाएगा (चाहे अकेले या कुछ या सभी अन्य सदस्यों या लेनदारों के साथ समन्वय में); या
- (iii) प्रशासक अपने कार्यों को उतनी जल्दी या कुशलता से नहीं कर रहा है जितना कि यथोचित व्यावहारिक है।

तो, अनुचित नुकसान क्या होगा? केस विधि के माध्यम से कुछ सिद्धांत सामने आए हैं, हालांकि अपीलीय न्यायालय ने हाल ही में दोहराया है कि अनुच्छेद 74 में एक व्यापक दायरा है, और न्यायालय जो परीक्षण लागू करेगा वह अनुचित है - मामले में स्थापित सिद्धांत उस परीक्षण को सीमित नहीं करते हैं।⁸⁷ फिर भी, मौजूदा मामला कानून के रूप में उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करता है कि क्या अनुचित नुकसान हो सकता है:

- (i) सबसे पहले, यह एक महत्वपूर्ण कारक होगा यदि प्रशासक दिवाला अधिनियम 1986 की अनुसूची ख 1 के तहत अपनी बाध्यताओं के अनुसार, या न्यायालय के एक आदेश के अनुसार, या समग्र रूप से लेनदारों के हितों में अपने कार्यों को सद्भावपूर्वक करने की अपनी बाध्यताओं के अनुसार कार्य कर रहे थे, तो यह एक महत्वपूर्ण कारक होगा : इसके विपरीत किसी भी सुझाव के बिना, यह संभावना नहीं है कि अनुच्छेद 74 के प्रयोजनों के लिए प्रशासक का आचरण अनुचित होगा।⁸⁸
- (ii) दूसरा, यदि प्रभावित लेनदारों या सदस्यों के प्रति असमान या विभेदक व्यवहार होता है, तो यह अनुचित नुकसान का संकेत हो सकता है, हालांकि इसे समग्र रूप से लेनदारों के हितों या प्रशासन के उद्देश्य को प्राप्त करने के संदर्भ में न्यायोचित ठहराया जा सकता है।⁸⁹ हालांकि अनुचित नुकसान के लिए प्रभावित लेनदारों या सदस्यों के प्रति विभेदक या भेदभावपूर्ण आचरण की आवश्यकता नहीं है,⁹⁰ कुछ अधिकार हैं कि - बिना किसी विभेदक या भेदभावपूर्ण आचरण के - यह दिखाना

⁸⁷ *Lehman Brothers Australia Limited v Downs and others* [2020] EWCA Civ 321 at [83].

⁸⁸ *Lehman Brothers Australia Limited v Downs and others* [2020] EWCA Civ 321 at [84] limits the question of whether the administrators are complying with their obligations to “a factor of great importance”, rather than breach being a prerequisite for intervention under paragraph 74, as established in *Four Private Investment Funds v Lomas* [2008] EWHC 2869 (Ch) at [39] and followed in *Fraser Turner Ltd v PricewaterhouseCoopers LLP* [2019] EWCA Civ 1290 at [76].

⁸⁹ *Hockin v Marsden* [2014] EWHC 763 (Ch) at [19]; *Goel v Grant / In re Meem SL Ltd (in administration)* [2017] EWHC 2688 (Ch) at [44(i)]

⁹⁰ *Lehman Brothers Australia Limited v Downs and others* [2020] EWCA Civ 321 at [83].

आवश्यक हो सकता है कि न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए प्रशासक का निर्णय प्रतिकूल है।⁹¹

- (iii) तीसरा, समग्र रूप से लेनदारों को नुकसान पहुंचाने वाले निर्णय के लिए वाणिज्यिक औचित्य की कमी इस अर्थ में अनुचित हो सकती है कि नुकसान वह नहीं है जिसके लिए उनसे भुगतने की उम्मीद की जानी चाहिए।⁹²
- (iv) अंत में, अनुच्छेद 74 के तहत एक उपाय केवल एक लेनदार के रूप में अपनी क्षमता में एक लेनदार के लिए उपलब्ध होगा : उदाहरण के लिए, एक लेनदार अनुच्छेद 74 के तहत राहत का हकदार नहीं होगा यदि नुकसान की शिकायत तीसरे पक्ष के साथ उसके संविदात्मक संबंधों से संबंधित है।⁹³

केवल लेनदारों या कंपनियों के सदस्यों के पास अनुच्छेद 74 के तहत एक आवेदन करने के लिए प्रतिष्ठा है, और (पहले दो पहलुओं के संबंध में) अनुचित नुकसान अकेले आवेदक या सभी लेनदारों या सदस्यों को प्रभावित कर सकता है। यदि अनुच्छेद 74 के तहत राहत के लिए एक आवेदन सफल होता है, तो न्यायालय के पास व्यापक शक्तियाँ होती हैं, जिसमें प्रशासक को एक निश्चित कार्रवाई करने या न करने या पूरी तरह से हटाने का निर्देश देना शामिल है।⁹⁴ अनुच्छेद 74 के तहत एक आवेदन का उपयोग प्रशासक को प्रस्तावित कार्रवाई करने से रोकने के लिए किया जा सकता है (साथ ही साथ की गई कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए)। इस तरह, यह एक निषेधाज्ञा के लिए एक आवेदन के समान हो सकता है और न्यायालय आवेदन को मंजूर करने का निर्णय लेने में समान सिद्धांतों पर भरोसा कर सकता है।⁹⁵ न्यायालय की शक्तियाँ न्यायालय को प्रशासक द्वारा प्रभावित लेनदार को मुआवजे का भुगतान करने का आदेश देने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त व्यापक हैं, हालाँकि यह अनुच्छेद 74 का उद्देश्य नहीं है।⁹⁶

अनुच्छेद 88 के तहत चुनौतियाँ

⁹¹ *Goel v Grant / In re Meem SL Ltd (in administration)* [2017] EWHC 2688 (Ch) at [44(ii)]

⁹² *Hockin v Marsden* [2014] EWHC 763 (Ch) at [19]

⁹³ *Fraser Turner Ltd v PricewaterhouseCoopers LLP* [2019] EWCA Civ 129 at [77].

⁹⁴ Para 74(4).

⁹⁵ For example in *In re Zinc Hotels, Zinc Hotels Investment v Beveridge* [2018] EWHC 1936 (Ch), the Court applied the American Cyanamid principles applicable to injunctions when considering an application by the shareholders under paragraph 74 to appoint an additional administrator.

⁹⁶ *Lightman & Moss*, 12-064; *In re Coniston Hotel (Kent) LLP* [2013] 2 BCLC 405, [36].

इसके अलावा, न्यायालय अनुसूची ख1 के अनुच्छेद 88 के तहत एक प्रशासक को हटाने का आदेश दे सकता है। अनुच्छेद 74 और 75 के विपरीत, अनुच्छेद 88 के तहत आवेदन करने के लिए प्रतिष्ठा हितधारकों की कुछ श्रेणियों तक सीमित नहीं है। हालाँकि, न्यायालय ने माना है कि प्रशासकों को केवल इसलिए हटाना आसान नहीं होना चाहिए क्योंकि उनका आचरण आदर्श से कम हो गया है।⁹⁷ नतीजतन, यह संभावना नहीं है कि ऊपर निर्धारित कुछ कर्तव्यों का **उल्लंघन** न्यायालय के लिए अनुच्छेद 88 के तहत एक प्रशासक को हटाने का आदेश देने के लिए पर्याप्त आधार होगा।

अनुसूची ख1 के अनुच्छेद 88 के तहत हटाए जाने वाले व्यवस्थापक का एक उदाहरण वेगास इन्वेस्टर्स IV एलएलसी बनाम शिनर्स के मामले में पाया जा सकता है। संबंधित कंपनी के प्रशासकों ने उन परिस्थितियों में प्री-पैक प्रशासन के माध्यम से आस्ति बेची थी जहां चिंता थी कि बिक्री कम मूल्य पर थी। जैसा कि प्रशासकों की फर्म ने प्री-पैक बिक्री पर सलाह दी थी, एक चिंता यह भी थी कि प्रशासकों के बीच हितों का टकराव था जो उन्हें प्रभावी ढंग से इस बात की जांच करने से रोकता था कि क्या उनकी फर्म ने अपनी पूर्व-नियुक्ति सलाह में लापरवाही की थी। प्रशासकों ने आवेदन की सुनवाई में आवेदन और उनके आचरण का विरोध किया, जिसे न्यायालय ने निष्पक्ष के बजाय रक्षात्मक पाया, और उनकी निष्पक्षता की कमी और हितों के टकराव को उजागर किया।⁹⁸ प्रशासकों को हटाने का आदेश देने से पहले, न्यायालय ने प्रशासकों की वृत्तियों की प्रतिष्ठा और ख्याति पर आदेश के प्रभाव पर विचार किया और क्या आदेश अनुचित आवेदनों को प्रोत्साहित करेगा।⁹⁹ यह निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि जब तक मुख्य कर्तव्यों के **उल्लंघन** या इस तरह के भंग के जोखिम का स्पष्ट सबूत नहीं है, तब तक न्यायालय अनुच्छेद 88 के तहत आवेदनों को मंजूर करने की संभावना नहीं रखता है।

3. केस स्टडी : कंपनी की आस्ति बेचने में वैश्वसिक कर्तव्य का उल्लंघन

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रशासक के वैश्वसिक कर्तव्यों और उचित कौशल और देखभाल का प्रयोग करने के लिए उसका कर्तव्य अतिव्याप्त हो सकते हैं। वैश्वसिक कर्तव्य के **उल्लंघन** को दर्शाने की शुरुआत अधिक है कि यह उचित कौशल और देखभाल का प्रयोग करने के लिए कर्तव्य का भंग दिखाना है। फिर, चुनौती देने वाले वैश्वसिक कर्तव्य के **उल्लंघन** को स्थापित करने का प्रयास क्यों करते हैं, जबकि परिस्थितियाँ वैश्वसिक कर्तव्य के **उल्लंघन** और कर्तव्य के **उल्लंघन** के लिए उचित कौशल और देखभाल का आरोप लगाने की अनुमति देती हैं? जैसा कि ब्रेवर

⁹⁷Vegas Investors IV LLC v Shimmers [2018] EWHC 186 (Ch)

⁹⁸Vegas Investors IV LLC v Shimmers [2018] EWHC 186 (Ch) at [27]-[33].

⁹⁹Vegas Investors IV LLC v Shimmers [2018] EWHC 186 (Ch) at [35]-[36].

बनाम इकबाल के हालिया मामले से दिखाया गया है, वैश्वसिक कर्तव्य के **उल्लंघन** का मतलब है कि कौशल और देखभाल के कर्तव्य के **उल्लंघन** के लिए उपलब्ध प्रतिपूरक उपचार के बजाय न्यायसंगत क्षेत्राधिकार में उपलब्ध पुनर्स्थापनात्मक या पुष्टिकर उपचार उपलब्ध हैं।¹⁰⁰ ब्रेवर बनाम इकबाल में, जहां कर्तव्य के उल्लंघन का मतलब था कि कंपनी की मुख्य संपत्ति एक कम मूल्य पर बेची गई थी, का निहितार्थ यह था कि न्यायसंगत मुआवजे का मूल्यांकन, **उल्लंघन** की तिथि के विपरीत, निर्णय की तिथि पर बिक्री मूल्य और आस्ति के मूल्य के बीच अंतर के रूप में किया गया था।¹⁰¹

ऐसे तीन हाल के मामले हैं जिनमें एक प्रशासक ने कंपनी की मुख्य आस्ति या आस्तियों को जिस मूल्य पर बेचा वह इस आधार पर अनुच्छेद 75 के तहत चुनौती का विषय थे कि प्रशासक (ओं) ने अपने वैश्वसिक कर्तव्यों और ऐसा करने में उचित कौशल और देखभाल करने के अपने दोनों कर्तव्यों का **उल्लंघन** किया था : डेवी बनाम मनी, ब्रेवर बनाम इकबाल और हाइड बनाम न्यागेट। ये मामले इस बात का एक दिलचस्प उदाहरण प्रदान करते हैं कि न्यायालय एक प्रशासक के आचरण का आकलन कैसे करेगा और क्या **उल्लंघन** से वैश्वसिक कर्तव्य का **उल्लंघन** शामिल होगा या नहीं। सिंहावलोकन में :

150

- (i) तीनों मामलों में, एक प्रशासक या प्रशासकों ने अपनी नियुक्ति के बाद कंपनी की मुख्य आस्ति का विपणन और बिक्री की, और बिक्री पर यह आरोप लगाया गया था कि वह कम मूल्य पर थी। डेवी बनाम मनी और हाइड बनाम न्यागेट दोनों ही विकास क्षमता के साथ लंदन की संपत्ति की बिक्री से संबंधित हैं, जहां मूल्य को प्रभावित करने वाले कई प्रकार के चर थे और मूल्यांकन पर विचारों की एक श्रृंखला थी। ब्रेवर बनाम इकबाल "ईपीजी" की बिक्री से संबंधित है, जो केबल या सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों पर दिखाए जाने वाले प्रोग्रामिंग शेड्यूलिंग जानकारी प्रदान करने वाले डिजिटल मेनू हैं।
- (ii) प्रत्येक मामले में, ऐसे आरोप थे कि प्रशासक संबंधित आस्ति के मूल्य का प्राप्य करने के लिए एक उचित बिक्री प्रक्रिया शुरू करने में विफल रहे थे, स्वतंत्र रूप से

¹⁰⁰ *Re ARY Digital UK Ltd; Brewer v Iqbal* [2019] EWHC 182 (Ch), applying *Bristol & West v Mothew* [1998] Ch 1 at [37], [55], [98]-[99].

¹⁰¹ Another consideration that may be important to a stakeholder seeking to challenge the conduct of an administrator as a breach of fiduciary duty (rather than a breach of the duty to exercise reasonable care and skill) is that such a breach may provide the basis for a claim in dishonest assistance and/or knowing receipt against a third party, whereas negligence will not.

कार्य करने में विफल रहे थे और आस्ति के मूल्य का ठीक से आकलन करने में विफल रहे थे।

- (iii) डेवी बनाम मनी कंपनी के एकमात्र हितधारक और निदेशक द्वारा एक आवेदन था। हाइड बनाम न्यागेट और ब्रेवर बनाम इकबाल कंपनियों के परिसमापकों द्वारा लाए गए आवेदन थे।
- (iv) ब्रेवर बनाम इकबाल में, प्रशासक ने ईपीजी का कोई मूल्यांकन प्राप्त नहीं किया। कंपनी के निदेशकों को आस्ति बेचने से पहले उन्होंने बहुत सीमित विपणन किया : उन्होंने सीमित विवरण के साथ, केवल सात दिनों के लिए आस्ति (ईपीजी, जो विशिष्ट और असामान्य थी) को "मशीनरी बिक्री" के तहत एक गैर-विशिष्ट अभिकर्ता की वेबसाइट पर सूचीबद्ध करने की व्यवस्था की, इस पर कोई सलाह मांगे बिना कि क्या उस तरह की आस्ति के लिए एक उचित प्रक्रिया थी या यह पता लगाने के लिए कि क्या एजेंट को उस तरह की संपत्ति बेचने का कोई अनुभव था।
- (v) डेवी बनाम मनी और हाइड बनाम न्यागेट में, प्रशासकों ने एक स्वतंत्र अभिकर्ता के समर्थन से कई महीनों में बिक्री प्रक्रिया को अंजाम दिया। ऐसे आरोप थे कि उन्होंने जानबूझकर अन्य लेनदारों के नुकसान के लिए सुरक्षित लेनदारों के ऋण के स्तर पर बिक्री मूल्य निर्धारित किया था।

(vi) इसके अलावा, डेवी बनाम मनी में, आवेदक ने आरोप लगाया कि जिस तरह से उन्होंने बिक्री की थी, प्रशासकों ने उसके प्रति व्यक्तिगत घृणा के कारण काम किया था।

प्रत्येक मामले में, न्यायालय ने मौजूदा अधिकारियों से प्राप्त विधि के निम्नलिखित प्रस्तावों के संबंध में, मौखिक गवाह और विशेषज्ञ साक्ष्य के आधार पर प्रशासकों के आचरण और बिक्री प्रक्रिया का विस्तृत तथ्यात्मक मूल्यांकन किया :

- (i) जहां एक आवेदक दावा करता है कि एक संपत्ति कम मूल्य पर बेची गई है, यह स्थापित करना होगा कि मूल्य के रूप में काल्पनिक विशेषज्ञ साक्ष्य पर विचार करने से पहले बिक्री प्रक्रिया में विफलता हुई है।¹⁰²
- (ii) एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में, कंपनी की आस्ति बेचते समय एक प्रशासक का कर्तव्य वैश्वासिक नहीं है : उनका कर्तव्य परिस्थितियों (जैसा कि प्रशासक

¹⁰²Re One Blackfriars Ltd (In Liquidation), Hyde v Nygate [2021] EWHC 684 (Ch) at [455].

यथोचित रूप से उन्हें मानता है) की अनुमति के अनुसार सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने के लिए उचित देखभाल करना है। दूसरे शब्दों में कहें तो, कर्तव्य परिस्थितियों की अनुमति के अनुसार सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करना एक पूर्ण कर्तव्य नहीं है, बल्कि ऐसा करने के लिए केवल उचित देखभाल करना है।

- (iii) प्रासंगिक परिस्थितियां वे हैं, जिन्हें व्यवस्थापक उचित रूप से उन्हें समझता है। उसे उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा क्योंकि उसकी धारणा गलत है, जब तक कि यह अनुचित न हो।¹⁰³
- (iv) हालांकि, एक प्रशासक की विफलताओं के लिए यह संभव है कि जिस तरह से वह बिक्री प्रक्रिया को अंजाम देता है, वह वैश्वसिक कर्तव्य के **उल्लंघन** के बराबर है, जहां यह निर्णय लेने (प्रासंगिक जानकारी को ध्यान में रखना, और अप्रासंगिक जानकारी को ध्यान में नहीं रखना) में विफलता के बराबर है। उदाहरण के लिए, ब्रेवर बनाम इकबाल में, प्रशासक को इस तरह से अपने वैश्वसिक कर्तव्य साथ ही साथ उचित देखभाल और कौशल का प्रयोग करने के कर्तव्य का **उल्लंघन** करते हुए पाया गया, जहां उसने कंपनी के निदेशकों को आस्ति बेचने से पहले मूल्यांकन प्राप्त नहीं किया था या उचित बिक्री प्रक्रिया नहीं की थी।

बिक्री प्रक्रिया का एक पहलू जो प्रत्येक मामले में जांच के अधीन था, वह था विपणन और विज्ञापन। किसी आस्ति को बिक्री के लिए विज्ञापित करने के लिए व्यवस्थापक के लिए कोई विधिक बाध्यता नहीं है : कर्तव्य सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने के लिए उचित देखभाल करना है, जिसमें अक्सर विज्ञापन शामिल होगा लेकिन हमेशा नहीं - यह तथ्य का प्रश्न होगा।¹⁰⁴ ब्रेवर बनाम इकबाल में, विपणन के लिए प्रशासक का सीमित दृष्टिकोण इस बात पर बिना किसी सलाह के लिया गया था कि क्या यह उस तरह की आस्ति के लिए एक उचित प्रक्रिया थी या यह पता लगाना था कि क्या अभिकर्ता को उस तरह की आस्ति बेचने का कोई अनुभव था। यह उनकी ओर से कर्तव्य का भंग था। इसके विपरीत, डेवी बनाम मनी और हाइड बनाम न्यागेट में, आवेदक ने विपणन के स्तर और दृष्टिकोण की आलोचना की। प्रशासकों ने बिक्री अभिकर्ताओं को नियुक्त किया था जो बाजार में अग्रणी अभिकर्ता नहीं थे, उनके प्रतिस्पर्धियों की अंतरराष्ट्रीय पहुंच नहीं थी, और केवल कुछ चुनिंदा संभावित बोलीदाताओं से संपर्क किया था। हालांकि, जबकि अन्य वृत्तियों ने अलग-अलग

¹⁰³ *Charnley Davies (No.2)* [1990] BCLC 760, applied in *Davey v Money* [2018] EWHC 766 (Ch) at [383]-[387].

¹⁰⁴ *Davey v Money* [2018] EWHC 766 (Ch) at [455].

निर्णय लिए होंगे, प्रशासकों का दृष्टिकोण अनुचित या अपर्याप्त नहीं था। परिणामस्वरूप, इन मामलों में न्यायालय ने पाया कि उचित देखभाल और कौशल का प्रयोग करने के कर्तव्य या वैश्वसिक कर्तव्य का कोई भंग नहीं हुआ था।

प्रशासक के आचरण की चुनौतियों में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा वह मूल्य है जिस पर एक प्रमुख आस्ति बेची गई थी। व्यवस्थापक के लिए मूल्य के बारे में विश्वसनीय जानकारी होना महत्वपूर्ण होगा, विशेष रूप से जहां आस्ति विशिष्ट या असामान्य हो। ब्रेवर बनाम इकबाल में, संपत्ति के किसी भी मूल्यांकन की मांग करने में प्रशासक की विफलता (और इसके बजाय निदेशक उनके लिए जो भुगतान करने को तैयार थे, उस पर भरोसा करना) कर्तव्य का **उल्लंघन** था।¹⁰⁵ हाइड बनाम न्यागेट में, प्रशासकों की आलोचना की गई थी कि वे उन परिस्थितियों में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए और अधिक मूल्यांकन की मांग नहीं कर रहे थे जहां बाजार अनिश्चित था और प्रशासकों के दो हालिया मूल्यांकन थे जो बहुत अलग थे। इन परिस्थितियों में, न्यायालय ने यह नहीं माना कि आगे मूल्यांकन की मांग किए बिना बिक्री प्रक्रिया को जारी रखने में प्रशासकों द्वारा कर्तव्य का **उल्लंघन** किया गया था। यह एक प्रशासक के मामले से अलग था जो मूल्य पर किसी भी या किसी भी अद्यतन जानकारी के बिना बाजार में आस्ति डालता है (जैसा कि ब्रेवर बनाम इकबाल में) : इसके बजाय, जहां बाजार अस्थिर है, मूल्य निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक यह है कि क्या विपणन प्रक्रिया सुदृढ़ थी और क्या उसने बाजार मूल्य हासिल किया।¹⁰⁶

153

सभी तीन मामलों में, चुनौती देने वाले ने आरोप लगाया कि प्रशासक स्वतंत्र रूप से कार्य करने में विफल रहे हैं, इसकी जगह कंपनी के बजाय अन्य हितधारकों के लिए अपने विवेकाधिकार का उपयोग कर रहे हैं और उन हितधारकों के हितों में कार्य कर रहे हैं। जहां ऐसा था, वह वैश्वसिक कर्तव्य का **उल्लंघन** होगा। इन आलोचनाओं की चर्चा से दो विषय उभर कर आते हैं। पहला, यह कि शुरुआत में ही प्रशासन के लिए रणनीति की रूपरेखा तैयार करना प्रशासक के विवेक पर अनुचित बंधन नहीं है।¹⁰⁷ दूसरी ओर, बिना किसी प्रश्न के कंपनी के निदेशकों या सुरक्षित लेनदारों द्वारा प्रस्तावित दृष्टिकोण को अपनाने के लिए विवेक का समर्पण अनुचित है।¹⁰⁸ दूसरा, जहां एक व्यवस्थापक संव्यवहार को समाप्त करने के लिए तेजी से कार्य करता है, यह अनुचित नहीं होगा जहां उसने मूल्य को अधिकतम करने के लिए उपलब्ध विकल्पों का गंभीरता से पता लगाया

¹⁰⁵ *Re ARY Digital UK Ltd, Brewer v Iqbal* [2019] EWHC 182 (Ch) at [82].

¹⁰⁶ *Re One Blackfriars Ltd (In Liquidation), Hyde v Nygate* [2021] EWHC 684 (Ch) at [322].

¹⁰⁷ See *Davey v Money* [2018] EWHC 766 (Ch) at [267]; *Re One Blackfriars Ltd (In Liquidation), Hyde v Nygate* [2021] EWHC 684 (Ch) at [277].

¹⁰⁸ *Re ARY Digital UK Ltd, Brewer v Iqbal* [2019] EWHC 182 (Ch) at [90].

है।¹⁰⁹ यह अनुचित होगा यदि वह उस समय सीमा के भीतर कंपनी के हितों के बजाय किसी तीसरे पक्ष के हितों के संदर्भ में कार्य कर रहा है।¹¹⁰

4. न्यायालय की प्रक्रिया

प्रशासकों के आचरण के लिए चुनौतियां (विशेषकर जब आवेदन पिछले निर्णयों की समीक्षा के लिए है, न कि प्रशासकों को कोई विशेष कार्रवाई करने से रोकने के लिए) किसी भी ब्रिटिश उच्च न्यायालय के मुकदमे की तरह लंबे समय तक चलने वाला होगा। आवेदन जारी होने और परीक्षण के बीच कई वर्षों का समय हो सकता है। परीक्षण स्वयं लंबा हो सकता है (उदाहरण के लिए, डेवी बनाम मनी और हाइड बनाम न्यागेट को कई हफ्तों तक चलने वाले परीक्षणों में सुना गया था)। मुकदमे से पहले, पार्टियों को गवाहों के बयानों का आदान-प्रदान करना होगा; मुकदमे में, उन गवाहों को मौखिक साक्ष्य देने और जिरह के अधीन होने की संभावना है। विशेषज्ञ साक्ष्य की आवश्यकता होने की संभावना है (उदाहरण के लिए, हाइड बनाम न्यागेट में, विशेषज्ञ गवाहों ने दिवाला अभ्यास, भूमि की बिक्री और विपणन के मुद्दों, मूल्यांकन के संबंध में और योजना के संबंध में साक्ष्य दिए)। दोनों पक्षों द्वारा मुकदमे से पहले दस्तावेजों का व्यापक खुलासा करने की भी संभावना है।

154

ऐसे आवेदनों को लाए जाने की सीमा अवधि सामान्यतः छह वर्ष होगी।¹¹¹ इसका मतलब यह हो सकता है कि विचाराधीन घटनाओं और परीक्षण के बीच काफी समय बीत सकता है। उदाहरण के लिए, ब्रेवर बनाम इकबाल में, आस्ति की बिक्री और इस संबंध में परीक्षण कि क्या व्यवस्थापक ने आस्ति बेचने में अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया था के बीच आठ साल थे। प्रासंगिक घटनाओं और मुकदमेबाजी के बीच समय में संभावित अंतर को देखते हुए, प्रशासकों के लिए उठाए गए कदमों और उनके निर्णय लेने को रिकॉर्ड करना महत्वपूर्ण है। जो लोग उस समय शामिल थे वे अब उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, और एक गति से और दबाव में हुई जटिल घटनाओं की व्यक्तियों की स्मृति बीतते समय के साथ प्रत्यक्ष रूप से अविश्वसनीय हैं।

¹⁰⁹ *Davey v Money* [2018] EWHC 766 (Ch) at [520]; *Re One Blackfriars Ltd (In Liquidation)*, *Hyde v Nygate* [2021] EWHC 684 (Ch) at [455].

¹¹⁰ *Re ARY Digital UK Ltd, Brewer v Iqbal* [2019] EWHC 182 (Ch) at [90].

¹¹¹ *Re Eurocruit Europe Ltd (In Liquidation)* [2007] EWHC 1433 (Ch)

5. विनियमन और विनियामक प्रवर्तन

उपरोक्त के अलावा, प्रशासकों को योग्य दिवाला व्यवसायी होने की आवश्यकता है। उनके पास आचरण के व्यवसायिक मानक हैं। यह एक कारण है कि न्यायालय प्रशासक के वाणिज्यिक और व्यवसायिक निर्णय को टालने के लिए तैयार है।

साथ ही कंपनी और लेनदारों के लिए जिम्मेदार कर्तव्यों के लिए प्रशासकों को उनके व्यवसायिक निकाय द्वारा जवाबदेह ठहराया जा सकता है। हाल के दो उदाहरणों में साइलेंट नाइट और कॉमेट के प्रशासक शामिल हैं। दोनों कंपनियों को प्रीपैक प्रशासन के माध्यम से बेचा गया था। दोनों व्यवस्थाओं में, प्रशासक की फर्म का कंपनी के अधिग्रहणकर्ता के साथ व्यवसायिक संबंध था। नियामक अधिकरण ने पाया कि, परिणामस्वरूप, प्रशासकों में निष्पक्षता की कमी थी और उनके व्यवसायिक निर्णय से समझौता किया गया था, जो व्यवसायिक मानकों और नैतिकता का उल्लंघन था।

155

दोनों ही मामलों में, कंपनी के अधिग्रहणकर्ता ने लाभ कमाया, जबकि लेनदारों को नुकसान हुआ। अवैतनिक करों और पेंशन योजना की कमी के कारण एक सार्वजनिक हित था, जो यह सुझाव दे सकता है कि इस मामले में इस तरह के सार्वजनिक हित होने पर नियामक हस्तक्षेप अधिक होने की संभावना है।

भाग C - निष्कर्ष

दिवाला व्यवसायियों की भूमिका जटिल और व्यापक है। विश्लेषण किए गए दो शासनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर प्रतीत होते हैं: सबसे पहले, दिवालिया व्यवसायी किसके प्रति उत्तरदायी है (इंग्लैंड के पास भारतीय शासन की तुलना में एक स्पष्ट उत्तर प्रतीत होता है) और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वाणिज्यिक निर्णयों पर दिवाला व्यवसायियों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका। इंग्लैंड शासन प्रशासकों को वाणिज्यिक निर्णय लेने के लिए बहुत व्यापक शक्ति प्रदान करता है, लेकिन लेनदारों के संबंध में प्रशासकों पर कर्तव्यों को भी लागू करता है ताकि यदि वे लेनदारों के हितों की रक्षा नहीं करते हैं तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जा सके। दूसरी ओर भारतीय शासन समाधान व्यवसायियों को लेनदारों के साथ निहित वाणिज्यिक ज्ञान के साथ "सुविधाप्रदाता" के रूप में देखता है। लेनदारों के समान व्यवहार और पारदर्शिता सहित निष्पक्षता दोनों न्यायालयों में सामान्य विषयों के रूप में दिखाई देती है।

156

यह आशा की जाती है कि भारत में समाधान व्यवसायियों के कर्तव्यों और भूमिकाओं को आगे परिभाषित किया जाएगा और इंग्लैंड और वेल्स में विकसित सिद्धांत इस तरह के विकास में सहायता कर सकते हैं।

दिवाला और परिसमापन में गोइंग कंसर्न सेल्स

पीयूष मिश्रा, युशान एनजी, कुशल भीमजानी और रजप्रीत लच्छर

दिवाला और परिसमापन में गोइंग कंसर्न सेल्स

पीयूष मिश्रा, पार्टनर, एलएंडएल पार्टनर्स

युशान एनजी, पार्टनर, मिलबैंक

कुशल भीमजानी, एसोसिएट, मिलबैंक

रजप्रीत लच्छर, एसोसिएट, मिलबैंक

परिचय

यह सुस्थापित तथ्य है कि दिवाला कानून व्यवस्थाओं के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सभी हितधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करना है।¹ [भारतीय] दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 ('आईबीसी') की प्रस्तावना में प्रावधान किया गया है कि "यह ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए समयबद्ध तरीके से कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, क्रेडिट की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सरकार के देय भुगतान की प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन सहित सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ('आईबीबीआई') की स्थापना करने, और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए एक अधिनियम है। न्यायालयों और ट्रिब्यूनलों ने आईबीसी की प्रस्तावना पर भरोसा किया है ताकि इसके उद्देश्यों का एक पदानुक्रम पढ़ा जा सके, जैसे संकल्प के बाद मूल्य को अधिकतम करना।² इसने अदालतों और न्यायाधिकरणों को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया है कि आईबीसी के तहत उद्यम के पुनर्वास के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए और केवल एक बार यह स्पष्ट हो जाए कि उद्यम का पुनर्वास नहीं किया जा सकता है, इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसलिए समापन पूर्ण अंतिम उपाय है।³ इस तरह की व्याख्या के कानूनी गुणों पर लोगों के अलग-अलग विचार हो सकते

¹ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, व्यवस्थित और प्रभावी दिवाला प्रक्रिया (1999) अध्याय 2, पृष्ठ 6 पर; विश्व बैंक, प्रभावी दिवाला और ऋणदाता / देनदार व्यवस्था के लिए सिद्धांत (2015), पृष्ठ 7 पर, दिवाला पर UNCITRAL विधायी गाइड (2005), सिफारिश 1 (बी) और (सी) और पृष्ठ 11।

² बिनानी इंडस्ट्रीज बनाम बैंक ऑफ बड़ौदा, 2018 एससीसी ऑनलाइन एनसीएलएटी 521, नंबर 17.

³ आर्सेलर मितल बनाम सतीश गुप्ता, (2019) 2 एससीसी 1, 83।

हैं, लेकिन यह आसानी से स्वीकार किया जाता है कि सभी हितधारकों के लिए मूल्य का अधिकतमकरण एक दिवाला समाधान प्रक्रिया या समापन के बजाय पुनर्वास के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। यह इस बुनियादी आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है कि किसी व्यवसाय के आवश्यक घटकों को एक साथ रखने से अधिक मूल्य प्राप्त किया जा सकता है, न कि उन्हें तोड़ने और टुकड़ों में निपटाने से।

एक संकटग्रस्त कंपनी का व्यावसायिक उपक्रम प्रभावी रूप से परिसंपत्तियों का एक संग्रह है, जिनमें से कुछ का मूल्य बकाया ऋण के निर्वहन की ओर जाता है। हालाँकि, इस तरह की परिसंपत्तियों के लिए विभिन्न लेनदारों की स्थिति के आधार पर, और इस तरह के उपाश्रय (जैसे सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों, व्यापार लेनदारों और अधिमान्य लेनदारों) का प्रयोग करने की क्षमता के आधार पर, दिवाला कानून के लेनदारों का सौदा सिद्धांत बताता है कि "ए कंपनी की संपत्ति का टुकड़े-टुकड़े में समापन के बजाय लेनदारों को परिसंपत्ति वितरण की सामूहिक और विनियमित औपचारिक योजना, कंपनी की शुद्ध संपत्ति मूल्य को संरक्षित करेगी।⁴ जैसा कि इस दृष्टि से देखा जा सकता है, "प्रशासन" की सामान्य कानून प्रणाली इस सिद्धांत का एक स्वाभाविक जननी है। इस संदर्भ में, प्रशासन की मौलिक प्रकृति के संबंध में लॉर्ड जस्टिस निकोल्स का यह कथन प्रासंगिक है:

"इसके विपरीत [समापन के लिए] किसी प्रशासन का इरादा केवल एक अंतरिम और अस्थायी शासन बनना है। एक सांस लेने की जगह होनी चाहिए, जबकि कंपनी, प्रशासक के रूप में नए व्यक्ति और नए प्रबंधन के तहत, एक या अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है। कंपनी के खिलाफ ऋण या अधिकार, मालिकाना या अन्यथा के प्रवर्तन पर एक स्थगन लगाता है ताकि प्रशासक को प्रस्ताव तैयार करने और उन्हें लेनदारों के सामने रखने और फिर लेनदारों द्वारा अनुमोदित किसी भी प्रस्ताव को लागू करने का समय दिया जा सके। कुछ मामलों में, समापन का पालन होगा। अन्य में, यह नहीं होगा।"⁵

जैसा कि विश्व बैंक का कहना है, किसी उद्यम का बचाव करने से नौकरियों का भी संरक्षण होता है, लेनदारों के साथ-साथ मालिकों के लिए बेहतर रिटर्न मिलता है, और उद्यम के पुनर्वास के

⁴ जैक्सन, "शोधन अक्षमता, गैर-शोधन अक्षमता पात्रता और लेनदारों का सौदा", (1982) 91 येल लॉ जर्नल;

⁵ री अटलांटिक कंप्यूटर सिस्टम्स पीएलसी, कोर्ट ऑफ अपील (सिविल डिवीजन) में - [1992] Ch. 505.

माध्यम से देश के लिए लाभ भी अर्जित होता है।⁶ यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय ढांचे की सिफारिश है कि कानून समापन और दिवाला कार्यवाही के बीच अदला-बदली का प्रावधान करें।

साथ ही, अव्यवहार्य उद्यमों का एक व्यवस्थित और त्वरित परिसमापन भी दिवाला प्रक्रिया के उद्देश्यों में से एक है। यह संसाधनों के अधिक कुशल आवंटन की अनुमति देता है और हितधारकों के लिए या कम से कम कुछ सुरक्षित लेनदारों के लिए बेहतर रिटर्न प्रदान कर सकता है। इस संबंध में प्रमुख निर्धारक तब होता है जब किसी उद्यम को अव्यवहार्य समझा जाता है। दिवाला कानून के विभिन्न उद्देश्यों और दिवाला में हितधारकों के प्रतिस्पर्धी हितों (जैसे, सुरक्षित और असुरक्षित लेनदार, काम करने वाले और इसी तरह) में अंतर्निहित तनाव हैं, और देश संबंधित क्षेत्राधिकार में मौजूदा बाजार, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन्हें संतुलित करने का प्रयास करते हैं।

यह उपरोक्त के आलोक में है कि किसी को आईबीसी का आकलन करना चाहिए और एक संकटग्रस्त कॉर्पोरेट देनदार के चिंता के आधार को संरक्षित करने पर जोर देना चाहिए। एक उदाहरण के रूप में कि अन्य क्षेत्राधिकार इस पहली तक कैसे पहुंचते हैं, निम्नलिखित पैराग्राफ में यूके की दिवाला प्रक्रियाओं पर चर्चा की गई है।

160

यूके में कॉर्पोरेट बचाव और पुनर्वास प्रक्रियाएं

कॉर्पोरेट बचाव उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, विभिन्न न्यायालयों ने (क) विभिन्न हितधारकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशिष्ट दिवाला समाधान प्रक्रियाओं का निर्माण किया है, उदाहरण प्री-पैक, प्रशासन और कंपनी स्वैच्छिक व्यवस्था (सीवीए), (ख) विशिष्ट क्षेत्रों या देनदारों (जैसे एसएमई या गैस और बिजली बाजार) के अनुकूल शासन बनाया, और (ग) ऐसे कानूनों का मसौदा तैयार किया या न्यायिक मिसाल कायम की जो एक बचाव या पुनर्वास दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही संकटग्रस्त संस्थाओं के लिए सफलता की संभावना को अधिकतम करती है (उदाहरण के लिए इप्सो फैक्टो क्लॉज से संबंधित कानून (संकटग्रस्त कंपनियों और वस्तुओं या सेवाओं के आवश्यक आपूर्तिकर्ताओं के बीच प्रमुख अनुबंधों की समाप्ति को रोकना))। पुनर्वास प्रक्रियाएं वाणिज्यिक हितधारकों को मूल्य को अधिकतम करने और कंपनी की संपत्ति को बिल्कुल कम कीमत पर बेचने

⁶ विश्व बैंक, प्रभावी दिवाला और ऋणदाता / देनदार व्यवस्था के लिए सिद्धांत (2015), पृष्ठ 8 पर। एलकॉन इंजीनियरिंग बनाम एनविरो बल्क, सी.पी. भी देखें। (आईबी) नंबर 1319/एमबी/2017 (एनसीएलटी मुंबई, 21.06.2021 को तय किया गया), 29 बजे।

के अंतिम उपाय से बचाने के सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत उद्देश्यों से समझौता करने के लिए प्रेरित करती हैं। इनमें से कुछ पर नीचे चर्चा की जाएगी।

बचाव और पुनर्वास प्रक्रियाएं उन प्रक्रियाओं से शुरू होती हैं जो दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान देनदार को अपने कब्जे में रखती हैं, जो अदालतों या दिवाला व्यवसायियों को प्रभारी बनाती हैं। उदाहरण के लिए, एक प्रशासन में एक योग्य दिवाला व्यवसायी संकटग्रस्त इकाई का नियंत्रण लेता है (चाहे ऐसी नियुक्ति शेयरधारकों, निदेशकों या एक लेनदार द्वारा की गई हो, जो एक योग्य फ्लोटिंग चार्ज धारक है), जबकि एक यूएस अध्याय 11 स्टाइल रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी प्रबंधन की देखरेख के लिए दिवाला व्यवसायियों को नियुक्त करने के बजाय वर्तमान प्रबंधन को यथावत रखता है।

यूके ने विशेष क्षेत्रों या "व्यवस्थात्मक रूप से महत्वपूर्ण" उद्योगों पर लागू 28 से अधिक विशिष्ट दिवाला ढांचे को बनाने के लिए कई बार कानून पारित किए हैं, जिनमें लेनदारों के अधिकार और रिटर्न पर सामान्य ध्यान व्यापार सेवाओं के निरंतर प्रावधान के (जैसे, ऊर्जा और बैंक) या अन्य व्यापक लक्ष्य साथ संतुलित है। उदाहरण के लिए, थोक गैस की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि के परिणामस्वरूप, यूके की "विशेष प्रशासन" व्यवस्था (जो उपयोगिताओं, रेलवे या अन्य संस्थाओं के लिए संशोधित दिवाला कानून लागू करती है, जिनके दिवालियेपन का व्यापक सार्वजनिक प्रभाव होता है) का 2021 में पहली बार बल्ब के पतन के दौरान टेस्ट किया गया।

जिस समय कानून को ऐतिहासिक रूप से पेश किया गया था (आखिरकार उपयोग में आने से एक दशक पहले), सरकार एक "कम संभावना लेकिन उच्च प्रभाव वाली घटना" के लिए प्रावधान कर रही थी, जो 2021 से यूरोप में ऊर्जा संकट के संदर्भ में भविष्यदर्शी साबित हुई है। ऊर्जा अधिनियम 2011 द्वारा विनियमित ऊर्जा आपूर्ति कंपनियों के लिए विशेष प्रशासन व्यवस्था के तहत, लेनदारों के बजाय राज्य के सचिव (या ऊर्जा नियामक ऑफगेम (गैस और बिजली बाजार का कार्यालय) इसकी सहमति से) अदालत को एक प्रशासक नियुक्त करने के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। जैसा कि ऊर्जा अधिनियम की धारा 96 में निर्धारित किया गया है, इस विशेष प्रशासन का "उद्देश्य" एक सामान्य प्रशासन से अलग है:

"95. एक ऊर्जा आपूर्ति कंपनी प्रशासन का उद्देश्य यह सुरक्षित करना है ... कि ऊर्जा आपूर्ति न्यूनतम लागत पर जारी रहे जो कि उचित रूप से व्यवहार्य है (2) वे साधन हैं ... कंपनी के अधीन कंपनी की चल रही प्रक्रिया के रूप में बचाव ईएससी प्रशासन आदेश"

यह व्यवस्थापक को समग्र रूप से लेनदारों के लिए मूल्य को पूरी तरह से अधिकतम करने की तुलना में व्यापक पहुंच उद्देश्य देता है और हितधारकों के पदानुक्रम में ऊर्जा आपूर्ति कंपनियों के ग्राहकों को प्राथमिकता देता है। यदि यह विशेष प्रशासन लागू नहीं होता, तो यह विशेष रूप से उन ऊर्जा उपभोक्ताओं को प्रभावित करता जो थोक बाजारों में तेजी के समय स्विचिंग के रूप में बल्ब के साथ निश्चित या सीमित अनुबंध पर थे, इसका मतलब नए अनुबंधों के तहत, उनके लिए उपलब्ध ऊर्जा की कीमतों में तेज वृद्धि होगी।

लाभकारी संस्थान और आईबीसी

लगभग सभी दिवाला व्यवस्थाएं संपत्ति के टुकड़े-टुकड़े की बिक्री के बजाय पुनः संगठन या समाधान की सुविधा के लिए कॉर्पोरेट देनदार के लाभकारी संस्थान की स्थिति को संरक्षित करने से संबंधित हैं। किसी भी दिवाला प्रक्रिया में मूल्य को अधिकतम करने के लिए कॉर्पोरेट देनदार का निरंतर संचालन महत्वपूर्ण है। यह अवधारणा कानूनों के विभिन्न प्रावधानों जैसे अधिस्थगन और बाद में प्रारंभ/अंतरिम वित्त में व्याप्त है।

आईबीसी और उसके तहत बनाए गए विनियमों में यह भी परिकल्पना की गई है कि समाधान पेशेवर कॉर्पोरेट देनदार के संचालन को एक लाभकारी संस्थान के रूप में प्रबंधित करेगा। अधिस्थगन के दौरान दिवालिया होने के आधार पर किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस या रियायत को समाप्त या निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, कॉर्पोरेट देनदार के संचालन के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को स्थगन के दौरान समाप्त या निलंबित नहीं किया जाएगा, जब तक कि अवधि के दौरान बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय को चलाने में समाधान पेशेवर द्वारा की जाने वाली लागत को एक लाभकारी संस्थान के रूप में दिवाला समाधान के रूप में माना जाता है जो पेमेंट वॉटरफाल में पहले स्थान पर हैं।⁷ समाधान योजना को एक लाभकारी संस्थान के रूप में समाधान प्रदान करना चाहिए। परिसमापन विनियम भी कॉर्पोरेट देनदार या उसके व्यवसाय (ओं) की बिक्री को एक लाभकारी संस्थान के आधार पर संदर्भित करता है।

लाभकारी संस्थान या गोइंग कंसर्न को आईबीसी के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसे एक मौलिक लेखांकन धारणा के रूप में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। भारतीय एएस-1

⁷ धारा 5(13), 5(23सी), 14(2ए), 20 और 54एच देखें।

(लेखा नीतियों का प्रकटीकरण) मानक नोट करता है कि उद्यम को आम तौर पर एक लाभकारी संस्थान के रूप में देखा जाता है, जो कि निकट भविष्य के लिए संचालन में जारी है। यह माना जाता है कि उद्यम का परिसमापन या संचालन के पैमाने को भौतिक रूप से कम करने का न तो इरादा है और न ही आवश्यकता है।

एक लाभकारी संस्था के रूप में बिक्री क्या है? यूनिस्ट्रल गाइड परिभाषा व्यवसाय की अलग-अलग संपत्तियों की बिक्री के विपरीत, "बिक्री को एक लाभकारी संस्था के रूप में" को पूरे या पर्याप्त हिस्से में किसी व्यवसाय की बिक्री या हस्तांतरण के रूप में परिभाषित करने में बहुत मददगार नहीं है। आईबीबीआई द्वारा 27 अप्रैल, 2019 को जारी कॉर्पोरेट परिसमापन प्रक्रिया पर चर्चा पत्र में यह स्पष्ट हो जाता है जब यह नोट करता है कि उद्यम की बिक्री एक लाभकारी संस्था के रूप में "सभी अनुबंधों, लाइसेंसों, रियायतों, समझौते, लाभ, विशेषाधिकार, अधिग्रहणकर्ता के अधिकार या हित सहित व्यवसाय, संपत्ति और देनदारियों का हस्तांतरण" शामिल है। " इसका आशय है कि परिसमापन में, एक 'लाभकारी संस्था' बिक्री का मतलब है कि केवल संपत्ति को स्थानांतरित किया जाता है और कॉर्पोरेट देनदार की देनदारियों को आईबीसी की धारा 53 के अनुसार तय किया जाना है। इसलिए अधिग्रहणकर्ता बिना किसी भार या शुल्क के संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेता है।⁹

- कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के संदर्भ में, गोइंग कंसर्न की अवधारणा ने (i) लेखापरीक्षा उद्देश्यों के अलावा बहुत अधिक समस्या पैदा नहीं की है क्योंकि लेखापरीक्षक सीआईआरपी की शुरुआत के बाद खतों में गोइंग कंसर्न धारणा को अर्हता प्राप्त करना चाहते हैं; और (ii) समाधान योजनाओं के मूल्यांकन पर, जहां गोइंग कंसर्न की शर्त का अर्थ यह समझा गया है कि योजना संपूर्ण कॉर्पोरेट देनदार के लिए होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि संपत्ति को पसंद के आधार पर नहीं चुना जा सकता है। व्यवसाय के सामान्य क्रम से बाहर पूंजीगत व्यय और परिसंपत्तियों की बिक्री, निश्चित रूप से, व्यवसाय को जारी रखने के संदर्भ से बाहर रखा गया है।
- यूके दिवाला कानून: कॉर्क रिपोर्ट और "बचाव संस्कृति"

⁸ भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, मसौदा विनियमों के साथ कॉर्पोरेट परिसमापन प्रक्रिया पर चर्चा पत्र, 3.2.1। भारतीय कर कानूनों के अंतर्गत गोइंग कंसर्न बिक्री की अवधारणा से संबंधित विभिन्न मामले हैं।

⁹ गौरव जैन बनाम संजय गुप्ता, सी.पी. (आईबी) संख्या 1239/एमबी/2018 (एनसीएलटी मुंबई, 09.03.2021 को तय किया गया), 25, 28 पर।

- हालांकि, ब्रिटेन में दिवाला कानून और प्रथाएं सदियों से मौजूद हैं (विभिन्न ऐतिहासिक कानून¹⁰ और केस कानून के माध्यम से), अधिकांश आधुनिक दिवाला कानून 1982 की कॉर्क रिपोर्ट (शोधन अक्षमता कानून और अभ्यास पर समीक्षा समिति की रिपोर्ट) से उत्पन्न हुए हैं। इसे 1977 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस रिपोर्ट का उद्देश्य यूके के दिवाला कानून में सुधार के लिए सिफारिशों का प्रस्ताव करना था और इसकी अध्यक्षता सर केनेथ रसेल कॉर्क ने की थी (जो कॉर्क गुली में भागीदार थे, यह ऐसी एक फर्म थी दिवाला में विशेषज्ञता के साथ-साथ एक योग्य लेखाकार थे)। सरकार के 1984 के श्वेत पत्र (शोधन अक्षमता कानून के लिए एक संशोधित ढांचा (1984) Cmnd 9175) के साथ रिपोर्ट ने IA 1986 के निर्माण में मदद की।
- रिपोर्ट ने निम्नलिखित सहित कई मुद्दों को उठाया:
- कानूनों को प्रशासित करने के लिए दिवाला न्यायालयों की एकीकृत प्रणाली की आवश्यकता;
- कि इच्छुक लेनदारों और हितधारकों को परिसमापक के चुनाव में अधिक से अधिक कहना चाहिए;
- कि कंपनी के पतन और विफलता के लिए उत्तरदायी समझे जाने वाले व्यक्तियों पर नया दंड लगाया जाना चाहिए; और
- कि कंपनियों के निदेशकों (जो कंपनी निदेशकों की अयोग्यता अधिनियम 1986 के लिए उत्पत्ति थी) पर जांच और बाधाओं का एक सेट पेश किया जाना चाहिए।

कॉर्क ने कई कंपनियों को विफल होने और दिवालिया होने की अनुमति देने पर चिंता व्यक्त की - वास्तव में, संकटग्रस्त कंपनियों के लिए सबसे आम परिणाम (पूर्व- IA 1986) प्राथमिक सुरक्षित लेनदारों के इशारे पर अपनी सुरक्षा को लागू करने और चार्ज की गई संपत्ति को प्राप्त करने के लिए एक रिसीवरशिप थी। इसके बाद ऋण की (आंशिक) पूर्ति के बाद कंपनी का परिसमापन कर दिया जाता था। यह स्पष्ट था कि रिसीवरशिप (एकमुश्त परिसमापन के लिए डिजाइन से अलग), एक अवांछनीय परिणाम के कारण कंपनियों में शायद ही कभी इस प्रक्रिया से बची, क्योंकि इसका उद्देश्य लेनदारों , विशेष रूप से फ्लोटिंग चार्ज रखने वाले प्रमुख लेनदारों को अधिकतम रिटर्न देना था।¹¹

¹⁰ 'व्यक्तिगत देनदारों के दिवालियेपन से संबंधित कानून 16वीं शताब्दी के मध्य से अंतराल पर अधिनियमित किए गए' अध्याय 1, खंड 5, (1-016) स्वीट एंड मैक्सवेल दिवाला का कानून 5वां संस्करण।)

¹¹ 'यूनाइटेड किंगडम में कॉर्पोरेट बचाव: अतीत, वर्तमान और भविष्य के सुधार' पॉल जे। उमर और जेनिफर ग्रांट।

इसलिए कॉर्क रिपोर्ट ने एक ऐसी बचाव प्रक्रिया बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जिसमें किसी दिवालिया कंपनी को एक लाभकारी संस्था के रूप में पुनर्वास की उच्च संभावना थी। कॉर्क का उद्देश्य ब्रिटिश दिवाला कानून में 'बचाव संस्कृति' को बढ़ावा देना था।¹² कॉर्क रिपोर्ट के दो मुख्य आधार कॉर्पोरेट दिवाला कानून में एक प्रशासक (एक परिसमापक के विपरीत) की अवधारणा को पेश कर रहे थे (और जिसका वैधानिक उद्देश्य कॉर्क के कंपनी बचाव पर ध्यान केंद्रित किया गया था) और असुरक्षित लेनदारों की चिंताओं को ऊपर उठाना, जिन्हें आमतौर पर कुछ भी नहीं मिलता था या अंत में बहुत कम मिला।

कॉर्क रिपोर्ट में दो नई या संशोधित प्रक्रियाओं के प्रस्ताव शामिल थे:

1) "प्रशासन", जिसके तहत संकटग्रस्त कंपनी अपने प्रबंधन के लिए एक बाहरी "प्रशासक" की नियुक्ति के लिए अदालत से एक आदेश मांग सकती है, चाहे व्यवसाय को बचाने के लिए, एक लाभकारी संस्था के रूप में इसके निपटान, या इसकी संपत्ति का निपटान, ताकि लेनदारों को परिसमापन के तहत प्राप्त होने वाले बेहतर रिटर्न के साथ प्रदान किया जा सके;

2) कंपनी स्वैच्छिक प्रशासन (सीवीए), जिसके तहत एक कंपनी, चाहे वह दिवालिया हो या नहीं या दिवालियेपन का सामना कर रही हो, अपने लेनदारों और सदस्यों के साथ अपने ऋणों को पूरा करने के लिए, निदेशकों द्वारा किए गए प्रस्ताव के लेनदारों द्वारा स्वीकृति के आधार पर व्यवस्था कर सकती है। कंपनी निदेशकों के नियंत्रण और "पर्यवेक्षक" के सामान्य पर्यवेक्षण के तहत व्यापार जारी रखने में सक्षम होगी। एक सीवीए के परिसमापन सहित प्रशासन के समान उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए न्यायालय की मंजूरी की आवश्यकता होगी।"¹³

दोनों योजनाओं को 1985 के दिवाला अधिनियम में लागू किया गया, बाद में 1986 के दिवाला अधिनियम में समेकित किया गया, और 1986 के दिवाला नियमों द्वारा विस्तार से लागू किया गया।¹⁴ IA 1986 के साथ, कंपनी निदेशक अयोग्यता अधिनियम 1986, दिवाला (इंग्लैंड और वेल्स) नियम 2016 और उद्यम अधिनियम 2002, यूके में विधायी ढांचे ने कॉर्क रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों को परिष्कृत (और बड़े हिस्से में लागू) किया।

आज, ब्रिटिश कानून दिवाला प्रक्रियाओं को मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: पहला, जिनके लिए डिज़ाइन किया गया है, या कम से कम वे जो चिंतन करते हैं, कंपनी के बचाव

¹² अध्याय 24-1, रिसेवर और प्रशासकों पर केर और हंटर 21वां संस्करण।

¹³ दिवाला कानून और व्यवहार पर समीक्षा समिति की रिपोर्ट (1982) Cmnd 8558।

¹⁴ व्यापार और उद्योग पर चयन समिति की दूसरी रिपोर्ट।

को एक लाभकारी प्रतिष्ठान के रूप में, और दूसरा, दिवाला प्रक्रियाएं जो मुख्य रूप से समाप्ति से संबंधित हैं किसी भी चल रहे व्यवसाय की, संपत्ति का पृथक्करण और वसूली और लेनदारों को उस बिक्री प्रक्रिया से प्राप्त किसी भी धन की वापसी।

ब्रिटेन कानून बचाव प्रक्रियाएं : लाभकारी संस्था

प्रशासन: प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी कंपनी को "राहत"¹⁵ दी जाती है ताकि उसे बचाया जा सके या पुनर्गठित किया जा सके या यदि आवश्यक हो, तो उसकी संपत्ति को प्राप्त किया जा सके। कंपनी को या तो प्रशासन के आवेदन के बाद अदालत के आदेश द्वारा, या (अधिक सामान्यतः), जहां नियुक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा होती है, कंपनी स्वयं या अर्हक फ्लोटिंग चार्ज के धारक द्वारा, साधारण फाइलिंग द्वारा अदालत में दस्तावेजों की संख्या (इसे अदालत के बाहर के मार्ग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें कोई अदालती सुनवाई शामिल नहीं होती है)। एक बार प्रशासन के अधीन होने के बाद, प्रशासक (आमतौर पर एक योग्य दिवाला व्यवसायी) नियुक्त किए जाते हैं। एक प्रशासक अदालत का अधिकारी होने के साथ-साथ कंपनी का एजेंट भी होता है। प्रशासक की नियुक्ति पर, एक स्थगन प्रभाव में आता है, जो कुछ अपवादों के अधीन, कंपनी या उसकी संपत्ति के खिलाफ लेनदारों द्वारा उकसाए गए किसी भी कार्रवाई को रोकता है जब तक कि प्रशासक की सहमति या अदालत इसकी अनुमति नहीं देती है।

वैधानिक डिजाइन द्वारा एक प्रशासन को निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है (प्राथमिकता के क्रम में क्रमबद्ध¹⁶):

1. "कंपनी को एक लाभकारी संस्था के रूप में बचाना;
2. कंपनी के लेनदारों के लिए समापन में होने की संभावना की तुलना में (प्रशासन में पहले के बिना) समग्र रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त करना; या
3. एक या अधिक सुरक्षित या अधिमान्य लेनदारों को वितरण करने के लिए [कंपनी की] संपत्ति की प्राप्ति करना, (यदि यह पहले दो उद्देश्यों में से किसी एक को प्राप्त करने के लिए उचित रूप

¹⁵ कॉर्पोरेट दिवाला: एक गाइड, प्रैक्टिकल लॉ यूके प्रैक्टिस नोट ओवरव्यू 8-107-3973।

¹⁶ इस पर कुछ विद्वानों की बहस है कि क्या कानून उद्देश्यों के पदानुक्रम को निर्धारित करता है।

से व्यावहारिक नहीं है और यह लेनदारों के हितों को अनावश्यक रूप से नुकसान नहीं पहुंचाएगा।¹⁷"

एक व्यावहारिक मामले के रूप में, प्रस्तावित प्रशासक सामान्य रूप से कंपनी के मामलों और वित्त की समीक्षा करेगा और नियुक्ति से पहले सलाह देगा जिसमें नियुक्ति का समय और तरीका भी शामिल है¹⁸ - ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह की नियुक्ति को स्वीकार करने में, नियमों के तहत प्रशासक को एक दृष्टिकोण बनाने की आवश्यकता होती है कि प्रशासक की राय में, नियुक्ति के परिणामस्वरूप "यह उचित रूप से संभव है कि प्रशासन के उद्देश्य को प्राप्त किया जाएगा"¹⁹। प्रशासक कंपनी और उसके व्यवसाय के दिन-प्रतिदिन के संचालन को संभालता है और प्रशासन को वैधानिक उद्देश्यों के अनुसार चलाता है, जिसे प्रशासक प्राप्त करने में सक्षम समझते हैं और उन प्रस्तावों के अनुसार जो वे लेनदारों को उनकी स्वीकृति देते हैं। 'प्रशासन के उचित उद्देश्य हैं, यह प्रस्तुत किया जाता है, लेनदारों के लिए व्यवसाय के मूल्य को अधिकतम करने की अवधारणा से जुड़ा हुआ है।²⁰

167

यदि कंपनी विशेष रूप से व्यथित है और उसके बचाव की बहुत कम संभावना है, तो प्रशासक कंपनी के व्यवसाय और संपत्ति को बेच देगा और कंपनी को परिसमापन या भंग कर दिया जाएगा। यदि इससे पहले प्रशासन समाप्त नहीं हुआ है, तो प्रशासन एक वर्ष के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा जब तक कि इसकी अवधि अग्रिम रूप से नहीं बढ़ा दी जाती।²¹

कंपनी स्वैच्छिक व्यवस्था (सीवीए): एक सीवीए कंपनी और उसके लेनदारों के बीच एक व्यवस्था है जिसे आईए 1986 के भाग 1 के तहत एक दिवाला व्यवसायी द्वारा कार्यान्वित और पर्यवेक्षित किया जाता है। एक सीवीए सभी असुरक्षित लेनदारों पर बाध्यकारी हो जाता है यदि और जब इसे उपयुक्त लेनदारों के बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाता है।²² इसका उपयोग अन्य प्रकार की दिवाला प्रक्रियाओं से बचने या पूरक (प्रासंगिक के रूप में) करने के लिए किया जाता है।

¹⁷ दिवाला अधिनियम, अनुसूची बी1 अनुच्छेद 3. करेन मैकमास्टर, सारा लेविन, लिनेट जानसेन और मैथ्यू फ़ॉटी, मिलबैंक एलएलपी: दिवाला समीक्षा: यूनाइटेड किंगडम - इंग्लैंड और वेल्स।

¹⁸ अध्याय 6-03, लाइटमैन एंड मॉस ऑन द लॉ ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड रिसीवर्स ऑफ़ कंपनीज़ छठा संस्करण

¹⁹ नियम 3.2 (1) (एच), दिवाला (इंग्लैंड और वेल्स) नियम 2016।

²⁰ अध्याय 2-02, टोटी, मॉस और सहगल: दिवाला।

²¹ अध्याय 24-3, रिसीवर और प्रशासकों पर केर और हंटर 21वां संस्करण।

²² अध्याय 24-3, रिसीवर और प्रशासकों पर केर और हंटर 21वां संस्करण।

इसका उपयोग प्रशासन के संयोजन में किया जा सकता है जहां एक अधिस्थगन कंपनी को सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों के साथ किसी भी प्रस्ताव पर सहमत होने के लिए राहत दी जाती है।

सीवीए की एक प्रासंगिक विशेषता यह है कि 'यह आईए 1986 के इस भाग I के लागू होने के लिए एक शर्त नहीं है कि कंपनी उन शर्तों की वैधानिक परिभाषाओं के भीतर "दिवालिया" या "अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ" होनी चाहिए²³ - यह स्पष्ट रूप से उन कंपनियों की मदद करता है जो दिवालिया होने के मामले में कोई रिटर्न नहीं मिलने से पहले तनाव में हैं। इस प्रक्रिया पर कॉर्क रिपोर्ट का फोकस एक कंपनी की लाभकारी संस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यों की तत्कालता को पहचानता है। सीवीए की शुरुआत कंपनी द्वारा ही की जाती है, जो अपनी नकदी प्रवाह की स्थिति का आकलन करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है और इस तरह राजस्व पर महामारी प्रेरित तनाव के दौरान एक शक्तिशाली उपकरण रहा है (विशेषकर व्यवसायों द्वारा वहन की जाने वाली संपत्ति से संबंधित लागतों के पुनर्गठन के संबंध में जो राजस्व उत्पन्न करने के लिए भौतिक उपस्थिति पर निर्भर हैं)।

168

व्यवस्था की योजना: व्यवस्था की योजना लेनदारों (या लेनदारों के किसी भी वर्ग) या सदस्यों (या सदस्यों के किसी भी वर्ग) के बीच एक समझौता या अन्य प्रकार की व्यवस्था है और कंपनी अधिनियम 2006 के भाग 26 के तहत बनाई गई है। यह व्यवस्था लेनदारों/सदस्यों के प्रत्येक वर्ग के उपयुक्त बहुमत सहमत होने पर अंततः बाध्यकारी होती है। IA 1986 के भाग I के तहत सीवीए के विपरीत, इस व्यवस्था की योजना को अदालत द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए, हालांकि सीवीए के समान एक योजना का उपयोग शोधनक्षम और अशोधनक्षम दोनों कंपनियों द्वारा किया जा सकता है।

जब किसी योजना को लेनदारों/सदस्यों के प्रासंगिक बहुमत और अदालत (प्रत्येक वर्ग के मूल्य में 75% और संख्या में बहुमत) द्वारा स्वीकृत किया जाता है, तो योजना सभी सदस्यों और लेनदारों को बाध्य करेगी, भले ही उन्हें प्रस्तावित व्यवस्था योजना की सूचना हो। फिर से, व्यवस्था की योजना का उपयोग अन्य दिवाला प्रक्रियाओं जैसे कि प्रशासन के साथ संयोजन में किया जा सकता है, जिससे एक स्थगन की तैनाती एक कंपनी को लेनदारों के साथ किसी भी प्रस्ताव पर सहमत होने के लिए "राहत" प्रदान कर सकती है।

²³ खंड 1, भाग 1 कंपनी स्वैच्छिक व्यवस्थाएं, सीली एंड मिलमैन: एनोटेटेड गाइड टू द इन्सॉल्वेंसी लेजिस्लेशन 24वां संस्करण। - 2021।

अधिस्थगन: भाग A1 अधिस्थगन एक ऐसी प्रक्रिया है जो IA 1986 के भाग A1 के तहत (कॉर्पोरेट दिवाला और शासन अधिनियम 2020 (CIGA 2020) द्वारा पेश किया गया) किसी कंपनी के निदेशकों को कंपनी के खिलाफ लेनदार कार्रवाई पर स्थगन लागू करने की अनुमति देता है। अधिस्थगन केवल 20 व्यावसायिक दिनों के लिए शुरू में लागू होने के बाद तक रहता है, लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है।

कंपनी निदेशकों के नियंत्रण में रहती है लेकिन उनके कार्यों की समीक्षा एक मॉनिटर (जो एक योग्य दिवाला व्यवसायी होना चाहिए) द्वारा की जाती है। अधिस्थगन के दौरान लेनदारों को कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया जाता है, और माल और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता कंपनी की आपूर्ति को रोकने के लिए उन्हें अधिकार देने के लिए समाप्ति के संविदात्मक अधिकारों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यह प्रक्रिया केवल एक अधिस्थगन है: इसमें लेनदार के दावों का समझौता, लेनदारों के लाभ के लिए संपत्ति की वसूली या किसी अन्य औपचारिक दिवाला प्रक्रिया की दिशा में कोई आवश्यक कदम शामिल नहीं है।

169

पुनर्रचना योजना: दिवाला वकीलों और व्यवसायियों के लिए उपयोग के लिए उपलब्ध नवीनतम उपकरण भाग 26A पुनर्गठन योजना है और अनिवार्य रूप से व्यवस्था की एक योजना के समान है लेकिन केवल वित्तीय कठिनाइयों में कंपनियों के लिए डिज़ाइन की गई है। यह प्रक्रिया सीआईजीए 2020 द्वारा शुरू की गई थी। विशेष रूप से, मतदान बहुमत की आवश्यकताएं व्यवस्था की किसी दूसरी योजना के लिए अलग हैं (योजनाओं के लिए प्रत्येक वर्ग के मूल्य में 75%, लेकिन, योजनाओं के विपरीत, कोई आवश्यकता नहीं है कि योजना प्रत्येक वर्ग में लेनदारों की संख्या में बहुमत से अनुमोदित हो)।

सबसे महत्वपूर्ण रूप से (मतभेदों के संदर्भ में), एक भाग 26A पुनर्गठन योजना "क्रॉस क्लास क्रैम-डाउन" के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि अदालत निम्नलिखित दोनों से संतुष्ट है तो मतदाताओं का एक असंतुष्ट वर्ग योजना को अवरुद्ध नहीं कर सकता है:

- असहमति वर्ग के किसी भी सदस्य का इससे बुरा नहीं होगा यदि योजना को मंजूरी नहीं दी गई होती उदाहरण के लिए, यदि परिसमापन होना था कोई बदतर" (प्रासंगिक विकल्प) ("परीक्षण नहीं)
- लेनदार या सदस्यों का एक वर्ग कम से कम 75% भुगतान प्राप्त कर सकता है या यदि उनका वास्तविक आर्थिक हित हो सकता है, यदि प्रासंगिक विकल्प का पालन किया गया और योजना के पक्ष में मतदान किया गया।

'प्री-पैक्स' पर यूके का कानून

एक 'प्री-पैक' का उपयोग विभिन्न न्यायालयों में उपलब्ध दिवाला प्रक्रियाओं के विभिन्न रूपों या समामेलन का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है और संकटग्रस्त कंपनियों के लिए एक बचाव योजना को लागू करने के लिए यूके और यूएस में एक तेजी से सामान्य उपकरण बन गया है। यूके में, उन्हें आमतौर पर एक प्रशासन के हिस्से के रूप में तैनात किया जाता है।

यूके इन्सॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन प्री-पैक को 'एक ऐसी व्यवस्था के रूप में वर्णित करता है जिसके तहत किसी कंपनी के व्यवसाय या संपत्ति के सभी या हिस्से की बिक्री एक प्रशासक की नियुक्ति से पहले एक खरीदार के साथ बातचीत की जाती है और प्रशासक या व्यवस्थापक तुरंत बाद, या कुछ ही समय बाद, या शीघ्र ही, नियुक्ति²⁴ करके बिक्री को प्रभावित करता है। यह कहा जाना चाहिए कि IA 1986 प्रशासक को बिक्री की व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है लेकिन स्पष्ट रूप से प्री-पैक प्रशासन के लिए प्रदान नहीं करता है।²⁵

170

आमतौर पर, प्री-पैक एक दोहरी प्रक्रिया है; सबसे पहले, इच्छुक पार्टियों के बीच एक पुनर्गठन पर बातचीत की जाती है और अपेक्षित हितधारकों के साथ सहमति होती है (यह आमतौर पर अनौपचारिक आधार पर होता है) और दूसरा, एक उपलब्ध औपचारिक दिवाला प्रक्रिया के माध्यम से पुनर्गठन समझौता लागू किया जाता है। यूके में, प्री-पैक अनिवार्य रूप से बिक्री लेनदेन होते हैं, जहां देनदार के व्यवसाय और परिसंपत्तियों को एक खरीदार को स्थानांतरित कर दिया जाता है और लेनदारों को किसी नई संरचना में शामिल किया जाता है, (इस हद तक कि बिक्री एक शेयर बिक्री है और उनके पास संरचनात्मक रूप से है उच्चतर दावे हैं), या पीछे छोड़ दिया जाता है।²⁶

उद्देश्य

हालांकि कोई भी दो पूर्व पैक एक समान नहीं होते हैं, अंतिम एक ही है, अर्थात्, उद्देश्य कॉर्पोरेट का उद्धार करना, राहत पहुँचाना, बचाव करना और एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में मुख्य व्यवसाय की निरंतरता को सुविधाजनक बनाना। यूके पुनर्गठन में 'रेस्क्यू कल्चर' बनाने में प्री-पैक एक आवश्यक साधन होता है। हालांकि IA 1986 इस प्रक्रिया को शुरू करने वाले पहले कानूनों में से एक था, एंटरप्राइज़ एक्ट 2002 ने प्रशासन प्रक्रिया में संशोधन करने और 'प्री-पैक' प्रशासनों के

²⁴ इन्सॉल्वेंसी प्रैक्टिस 16 और जैकलीन इनग्राम और युशान एनजी का स्टेटमेंट, ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग रिव्यू, द आर्ट ऑफ़ द प्री-पैक।

²⁵ आईए 1986 की अनुसूची 1, पैराग्राफ 2 और अनुसूची बी1।

²⁶ जैकलीन इनग्राम और युशान एनजी, ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग रिव्यू, द आर्ट ऑफ़ द प्री-पैक।

बढ़ते उपयोग को सक्षम करने में सहायता की: 'कंपनी को एक चल रही चिंता के रूप में बचाना' का अर्थ यह है कि 'कंपनी और जितना संभव हो सके उसके व्यवसाय' को बचाना है।²⁷

प्री-पैक की सामान्य विशेषताएं और लाभ

प्री-पैक का उपयोग करने वाले न्यायालयों में देखा जाने वाला एक सामान्य विषय यह है कि उनमें एक पुनर्गठन प्रस्ताव और समझौते की एक निजी (और सबसे अधिक बार असतत) बातचीत शामिल है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है, बातचीत प्रक्रिया के इस चरण में, इसमें कंपनी से संबंधित सभी हितधारक शामिल नहीं हो सकते हैं। इसे दो कारणों से समझाया जा सकता है; पहला, समय अक्सर गुणों और निष्कर्ष का होता है और उन पक्षों को सीमित करके जिनके हितों सीधे तौर पर सबसे अधिक जुड़े होते हैं, या जुड़े होंगे, पुनर्गठन प्रस्ताव के समझौते को तेज करने में मदद कर सकते हैं, और दूसरा, किसी भी पुनर्गठन समझौते को लागू करते समय बाद में आवश्यक सहमति के नियमों और प्रतिशत के कारण (आमतौर पर तीन तिमाहियों या 75b), कंपनी उन हितधारकों को समझाने में अपनी ऊर्जा और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहेगी जिनके पास बहुमत होगा।

171

उनकी लोकप्रियता काफी हद तक उनकी विवेकाधीन प्रकृति के कारण है क्योंकि यह निजी बाजार सहभागियों को एक औपचारिक औपचारिक दिवाला प्रक्रिया के विपरीत मीडिया के ध्यान से अनुपस्थित या लोगों की नज़र में सौदों पर सहमत होने का अवसर प्रदान करता है। यह संकटग्रस्त कंपनी की सद्भावना को यथासंभव लंबे समय तक बनाए रखने में भी मदद करता है। हाल के उदाहरणों में यूके में कई खुदरा आउटलेट शामिल हैं।

दूसरे, प्री-पैक का उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब देनदार द्वारा औपचारिक दिवाला प्रक्रिया पर खर्च किए जाने वाले समय को सीमित करना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक बार पुनर्गठन समझौते पर सहमति हो जाने के बाद, इसे अपेक्षाकृत जल्दी से लागू किया जा सकता है, अधिकांश मुद्दों और संभावित समस्याओं का अनुमान लगाया गया और चर्चा की। यह कई मायनों में देनदार इकाई और व्यापक समूह के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिवाला और दिवालियापन नकारात्मक अर्थ रखते हैं जो बदले में वित्तीय कठिनाइयों को बढ़ा सकते हैं और देनदार और उसके समूह में विश्वास को कम कर सकते हैं। प्री-पैक का मुख्य उद्देश्य आत्मविश्वास बनाए रखते हुए कंपनी में अपना महत्व और मूल्य बनाए रखना है।

²⁷ एंटरप्राइज एक्ट 2002, व्याख्यात्मक नोट्स: भाग 10 (दिवाला), पैराग्राफ 647647 और ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग रिव्यू, द आर्ट ऑफ द प्री-पैक।

इसके अतिरिक्त, देनदारों के लिए दीर्घावधि में प्री-पैक अधिक लागत-कुशल हो सकते हैं क्योंकि उन्हें बातचीत और समझौते के लिए केवल सीमित पक्षों की आवश्यकता होगी जो अंततः वित्तीय दबाव को कम करने में मदद करेंगे।

दिवाला व्यवसायी के पूर्व-पैक और कर्तव्य को लागू करना

एक प्री-पैक प्रशासन एक व्यथित कंपनी के निदेशकों के साथ शुरू होता है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति का आकलन करने और कार्रवाई के सर्वोत्तम पाठ्यक्रम पर सलाह देने के लिए एक दिवाला व्यवसायी की सेवाओं को संलग्न करने का संकल्प लेता है।

प्रारंभिक चरण में, दिवाला व्यवसायी व्यवसाय सलाहकार की भूमिका में होता है, लेकिन एक समझ है कि कंपनी के प्रशासन में जाने पर उसे प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, भले ही वह अपेक्षाकृत कम समय के लिए ही क्यों न हो। यह अप्रत्यक्ष रूप से दिवाला व्यवसायी पर IA 1986 और दिवाला विनियमों के तहत अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहने का कर्तव्य लागू होता है, यह एक ऐसा कर्तव्य है जो संकटग्रस्त कंपनी के सभी लेनदारों को निभाना होता है लेकिन प्रस्तावित खरीदार को नहीं। इसलिए, एक प्रशासनिक प्रक्रिया के वैधानिक उद्देश्य प्रारंभिक चरण में भी एक प्रासंगिक विचार हैं।

172

IA 1986 के तहत व्यवस्थापक को बिक्री की व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं और एक प्री-पैक बिक्री इन शक्तियों के अनुरूप है। एक पारंपरिक प्रशासन में, IA 1986 की परिकल्पना है कि प्रशासक जल्द से जल्द एक प्रस्ताव तैयार करेगा और उनकी नियुक्ति के बाद आठ सप्ताह से अधिक नहीं होगा, और लेनदारों को वोट देने के लिए इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करेगा।²⁸ हालाँकि, प्रशासक के पास प्रस्ताव के लेनदारों के अनुमोदन की आवश्यकता को दरकिनार करने की शक्ति है यदि वह यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक लेनदार को पूर्ण भुगतान किया जाएगा या असुरक्षित लेनदारों को कोई वितरण नहीं किया जाएगा।²⁹ साथ ही, प्रशासन के उद्देश्य को प्राप्त करने में, प्रशासक कुछ परिस्थितियों में लेनदारों के अनुमोदन के बिना कंपनी की संपत्ति को बेच सकता है, हालाँकि यदि संपत्ति पर एक निश्चित शुल्क है, तो निश्चित शुल्क के निर्वहन के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता होती है।

²⁸ आईए 1986 की अनुसूची बी1, पैराग्राफ 49(5)।

²⁹ आईए 1986 की अनुसूची बी1, पैराग्राफ 52।

प्री-पैक प्रशासन में, बिक्री की व्यवस्था प्रशासक के रूप में नियुक्त होने से पहले की जाती है (सलाहकार के विपरीत)।

एक बार जब एक पूर्व-पैक की गई बिक्री को पूरा करने का निर्णय लिया जाता है, तो अगला कदम असतत रूप से एक उपयुक्त खरीदार को ढूँढना होता है और बिक्री की शर्तों पर बातचीत करना होता है और यह अक्सर कंपनी के सुरक्षित लेनदारों (निदेशकों) ने पहले से ही संभावित खरीदारों से संपर्क कर लिया होता है और बिक्री की शर्तों पर अस्पष्ट रूप से सहमत हो चुके होते हैं।

बिक्री की शर्तों पर सहमति होने और प्रासंगिक दस्तावेज तैयार होने के बाद, दिवाला व्यवसायी को आधिकारिक तौर पर प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है और बिक्री नियुक्ति के तुरंत बाद या तुरंत समाप्त हो जाती है। प्रशासक की औपचारिक नियुक्ति अदालत के बाहर कंपनी में से किसी एक, निदेशकों या एक अर्हक अस्थायी प्रभार धारक (यदि कोई हो) द्वारा की जा सकती है।³⁰ एक बार जब प्रशासक पद ग्रहण कर लेता है, तो तत्काल कार्य सहमत शर्तों पर बिक्री को प्रभावित करना होता है। व्यवस्थापक कंपनी की बिक्री से प्राप्त प्रतिफल को लेनदारों को IA 1986 द्वारा प्रशासन प्रक्रियाओं के लिए निर्धारित प्राथमिकता के क्रम में वितरित करता है। वास्तव में, असुरक्षित लेनदारों को धन वापसी होने की संभावना नहीं होती है और केवल सुरक्षित और तरजीही लेनदारों को प्रशासन से पूँजी की वापसी होती है। कंपनी की बिक्री जल्दी से पूरी हो जाती है और इसके बाद इसके बाद कारोबार सामान्य संपन्न व्यापारिक संक्रियाओं के साथ फिर से शुरू हो जाता है।

मूल्यांकन

प्री-पैक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उचित विचार के निर्धारण के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा कंपनी का मूल्यांकन है जो कंपनी के मूल्य को दर्शाता है। यह सभी लेनदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिवाला व्यवसायी के कर्तव्य से रेखांकित होता है और यह सुनिश्चित करता है कि बिक्री उनके लिए सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करे। इसके अलावा, नियामक आवश्यकताएं हैं जो अब प्रकटीकरण नियम लागू करती हैं, जिसमें बिक्री के लिए अपनाई गई मूल्यांकन और विपणन रणनीति शामिल है।

³⁰ अनुसूची बी 1, पैराग्राफ 14 और 22 ।

कार्यान्वयन के बाद

प्री-पैक बिक्री के बाद, बेचने वाली इकाई को अक्सर एक शेल के रूप में छोड़ दिया जाएगा, केवल उन देनदारियों को आवासित किया जाएगा जिन्हें स्थानांतरित नहीं किया गया था। व्यवस्थापक निर्धारित करता है कि कंपनी के साथ क्या होगा। विकल्पों में इकाई का विघटन शामिल है जहां लेनदारों को वितरित करने के लिए कोई धन या संपत्ति नहीं होती है³¹, और सामान्यतः, कंपनी के लेनदारों का ऐच्छिक परिसमापन, कंपनी की ऐच्छिक व्यवस्था या व्यवस्था की योजना होती है।

आलोचना

हालांकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सीमित संख्या में हितधारकों को शामिल करने वाली शुरुआती बातचीत को एक लाभ के रूप में देखा जा सकता है, वार्ता और अंतिम पुनर्गठन समझौते से बाहर रखा गया एक हितधारक इसे अनुचित के रूप में देखेगा। यूके में, यह अक्सर सुरक्षित लेनदार होते हैं जिनके पास पुनर्गठन समझौते पर बातचीत करने में मुख्य रूप से बहुमत और अंतिम राय हैं और असुरक्षित लेनदार जो आमतौर पर 'आउट ऑफ मनी' होते हैं उन्हें पुनर्गठन और प्री-पैक प्रस्तावों का बहुत कम या कोई ज्ञान नहीं होता है। इन लेनदारों के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के सीमित अवसर होते हैं।

साथ ही पदाधिकारियों की निष्पक्षता की संभावना पर भी चिंता जताई है। यद्यपि वे वैधानिक दायित्वों और पेशेवर दिशानिर्देशों से बंधे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए बातचीत पर प्रभाव डाल सकते हैं कि अंतिम लेनदेन में इनका सम्मान किया जाएगा, क्योंकि एक पदाधिकारी बहुत जल्दी शामिल होता है, कोई यह तर्क दे सकता है कि वे सौदा प्रस्तावों की कोशिश करने और उन्हें सुविधाजनक बनाने की अधिक संभावना रखते हैं और इसलिए व्यापक तस्वीर और सभी संबंधित हितधारकों की पूर्ण निष्पक्षता खो देते हैं।

उनकी निरंतर लोकप्रियता के प्रकाश में, शेयर को संतुलित करने के लिए कानून और मार्गदर्शन जारी रहता है और संयुक्त दिवाला समिति ने प्री-पैक के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर व्यवसायी को कुछ मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ इनसॉल्वेंसी प्रैक्टिस 16 (एसआईपी 16) का विवरण जारी करता है।

³¹ अनुसूची बी1, पैराग्राफ 78.

एसआईपी 16:

- अनुशंसा करता है कि प्री-पैक प्रशासन में कार्यरत एक दिवाला व्यवसायी को यह प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए कि आईए 1986 के तहत एक प्रशासक के कर्तव्यों को पूरा किया गया है।
- प्री-पैक की गई बिक्री को प्रभावित करने और बिक्री पर बातचीत और व्यवस्था करने का निर्णय लेने में दिवाला व्यवसायियों को यथासंभव स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आवश्यकता पर बल देता है।
- बिक्री के लेन-देन के सात दिनों के भीतर, दिवाला व्यवसायी को प्री-पैक बिक्री के पीछे के तर्क का विस्तृत रिकॉर्ड, विकल्प, विपणन रणनीति और सौदे के बारे में अन्य विशिष्ट जानकारी रखने की आवश्यकता होती है।
- एसआईपी 16 यह भी सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकन और व्यापार के मजबूत विपणन की सिफारिश करता है कि लेनदारों के लिए सर्वोत्तम संभव मूल्य प्राप्त हो सके।

175

हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एसआईपी 16 का पालन करने में विफलता एक बिक्री को अमान्य नहीं करती है या स्वचालित रूप से दिवाला व्यवसायी द्वारा कदाचार की खोज में परिणाम नहीं देती है। दिवाला व्यवसायियों को मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा अलग से विनियमित किया जाता है जो नियमित रूप से आवश्यक मानकों के अनुपालन की निगरानी करते हैं और जहां उपयुक्त हो वहां अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं।

प्री-पैक रूलबुक में सबसे महत्वपूर्ण विकास प्रशासन (संबंधित व्यक्तियों के लिए निपटान आदि पर प्रतिबंध) विनियम 2021 की शुरुआत है जो 'संबंधित व्यक्तियों' को प्री-पैक बिक्री को नियंत्रित करता है (यानी, जो ऐतिहासिक रूप से कंपनी के उपक्रम और व्यवसाय में शामिल हैं, उदाहरण के लिए, शेयरधारक, निदेशक और प्रबंधक)। 'संबंधित' व्यक्तियों की परिभाषा के साथ प्रमुख बाजार चिंता यह है कि यह स्पष्ट रूप से सुरक्षित उधारदाताओं को बाहर नहीं करता है जो कंपनी की संपत्ति के लिए बोली लगा सकते हैं, या अन्यथा फंड खरीद सकते हैं।

फिर भी, नियम 'संबंधित व्यक्तियों' को बिक्री पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाते हैं, लेकिन असुरक्षित लेनदारों की चिंताओं को कम करने के लिए अतिरिक्त प्रक्रियाएं बनाते हैं, जो पूर्व-बिक्री वार्ता से बाहर हैं। जब तक पूर्व लेनदार अनुमोदन प्राप्त नहीं करता है, यदि कंपनी या 'सभी या इसकी सभी संपत्तियां' प्रशासन के पहले 8 हफ्तों के भीतर 'संबंधित व्यक्तियों' को बेच दी जाती हैं, तो प्रस्तावित

खरीदार को एक स्वतंत्र 'मूल्यांकनकर्ता' राय को कमीशन करना होगा। यह राय अन्य लेनदारों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए (कंपनी हाउस में सार्वजनिक रिकॉर्ड के मामले सहित)।

'मूल्यांकनकर्ता' राय में खरीदार का नाम (और कंपनी के साथ उनका कनेक्शन), खरीद मूल्य और एक बयान (कारणों के साथ) शामिल होना चाहिए कि मूल्यांकनकर्ता (या नहीं है) "संतुष्ट है कि प्रासंगिक संपत्ति के लिए प्रदान किया जाने वाला विचार और पर्याप्त निपटान के लिए आधार परिस्थितियों में उचित हैं"।³²

मूल्यांकनकर्ता की राय प्रशासक के लिए बाध्यकारी नहीं है (अर्थात्, यदि एक अवांछनीय निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, तो प्रशासक अभी भी बिक्री के साथ आगे बढ़ सकता है बशर्ते कुछ चरणों का पालन किया गया हो)। यह देखते हुए कि ये नियम अपेक्षाकृत नए हैं, यह देखा जाना बाकी है कि क्या व्यवस्थापक भविष्य में प्रक्रिया के दुरुपयोग को खत्म करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियमों को और अधिक मजबूती देंगे। अन्य ऐतिहासिक दिवाला कानूनों की तरह, संशोधनों पर एक राय बनाने से पहले कानून निर्माता इसका मूल्यांकन करेंगे कि व्यवहार में यह कैसे चलता है।

प्री-पैक को चुनौती देने का अवसर

यद्यपि व्यापार आपूर्तिकर्ताओं, लेनदारों और शेयरधारकों के लिए अवसर और साधन दिए जाने पर प्री-पैक बिक्री को चुनौती देने की संभावना है, वास्तव में, उन पार्टियों के लिए बहुत कम अवसर या प्रोत्साहन होता है जो बिक्री को चुनौती देने से असहमत होते हैं। इसके अलावा, अदालतों ने लेनदारों की मंजूरी के बिना किसी कंपनी की संपत्ति को अग्रिम रूप से बेचने की प्रथा को मंजूरी दे दी है और आम तौर पर वाणिज्यिक व्यवस्था को पलट नहीं देगी जब तक कि धोखाधड़ी या अनादक का मामला स्पष्ट रूप से नहीं बनता है।

इसके अतिरिक्त, प्रशासक के आचरण को चुनौती देना मुश्किल है (जहां यह एक चिंता का विषय है या कुछ हितधारकों को लगता है कि वे अनुचित हैं) क्योंकि विभिन्न नियमों और कानूनों के तहत प्रशासक को अपने व्यावसायिक निर्णय का प्रयोग करने के लिए महत्वपूर्ण विवेक दिया जाता है। ये कारक, चुनौती लाने की संभावित उच्च लागत के साथ, पीड़ित लेनदारों के लिए एक मजबूत निवर्तक के रूप में काम करते हैं।

³² प्रशासन (जुड़े व्यक्तियों के निपटान आदि पर प्रतिबंध) विनियम 2021, भाग 2, अध्याय 3, 71

उदाहरण के लिए, वी वेगास इन्वेस्टर्स एलएलसी और अन्य बनाम हेनरी शिन्स, फिनबार ओ'कोनेल और अन्य³³ मामले में चुनौतियां सफल रही हैं, आवेदक वीड इंटरएक्टिव के लेनदार थे जिन्होंने 1.75 मिलियन पाउंड में निदेशकों को कंपनी की पूर्व-पैकेज्ड बिक्री को चुनौती देने के लिए प्रशासकों के खिलाफ दावा किया था। लेनदारों ने प्रशासक को बदलने का अनुरोध किया।

यह निर्धारित किए बिना कि प्रस्तावित बिक्री वैध थी या नहीं, अदालत ने पाया कि एक स्वतंत्र पार्टी द्वारा जांच के लिए एक गंभीर मुद्दा था कि प्रस्तावित बिक्री कंपनी के सर्वोत्तम हित में थी या नहीं और क्या प्रशासक ने बिक्री की शर्तों से सहमत होने में अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया था।

ब्रिटिश कानून दिवाला प्रक्रिया: विफल कंपनियां

विघटन या परिसमापन : कंपनी को समाप्त करने या बंद करने के लिए अंतिम उपाय दिवाला प्रक्रियाएं हैं (हालांकि, यह एक असुरक्षित लेनदार के दृष्टिकोण से तर्क दिया जा सकता है, ये किसी संकटग्रस्त कंपनी पर दबाव डालने या मामलों को शीर्ष पर मजबूर करने के लिए सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीके हो सकते हैं)। प्रक्रियाओं के लिए एक परिसमापक की नियुक्ति की आवश्यकता होती है (जो एक दिवाला व्यवसायी होना चाहिए) और जो कंपनी की संपत्ति को इकट्ठा करेगा और बेचेगा और अंततः परिणामी नकदी या आय को वितरित करेगा (या कभी-कभी, विलायक स्थितियों में, संपत्ति को बेचे बिना वितरित कर सकता है) और , अंत में एक बार प्रक्रिया पूरी होने के बाद, कंपनी को भंग कर दें।

177

अंतिम परिसमापन आदेश दिए जाने से पहले कंपनी को अनंतिम परिसमापन में भी रखा जा सकता है। परिसमापन के दो प्रकार हैं:

- **अनिवार्य:** न्यायालय के आदेश से। यह याचिका द्वारा शुरू किया जाता है, आमतौर पर लेनदार द्वारा इस आधार पर कि कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ है
- **ऐच्छिक:** कंपनी के समाधान द्वारा।

नए यूके इन्सॉल्वेंसी लॉ डेवलपमेंट्स - कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी एंड गवर्नेंस एक्ट 2020 (सीआईजीए 2020) की शुरुआत

³³ 2018] ईडब्ल्यूएचसी 186 (अध्याय)।

नए कानून की शुरुआत दशकों से चर्चा में थी और सीआईजीए 2020 को आईए 1986 के बाद से यूके के पुनर्गठन कानून के सबसे बड़े झटके के रूप में घोषित किया गया है। हालांकि इसके कार्यान्वयन में अभी भी जल्दी है, लेकिन कई कंपनियां हैं जिन्होंने कोशिश की है सहित नई पुनर्गठन योजना का उपयोग करें:

- डीपओशन (री डीपओशन 1 यूके लिमिटेड और अन्य [2021] ईडब्ल्यूएचसी 138 (सीएच))
- वर्जिन एक्टिव (री वर्जिन एक्टिव होल्डिंग्स लिमिटेड और अन्य [2021] ईडब्ल्यूएचसी 814 (सीएच), री वर्जिन एक्टिव होल्डिंग्स लिमिटेड और अन्य [2021] ईडब्ल्यूएचसी 1246 (सीएच))
- गेटग्रुप (री गेटग्रुप गारंटी लिमिटेड [2021] ईडब्ल्यूएचसी 304 (सीएच), री गेटग्रुप गारंटी लिमिटेड [2021] ईडब्ल्यूएचसी 775 (सीएच))
- हरिकेन एनर्जी (री हरिकेन एनर्जी [2021] ईडब्ल्यूएचसी 1759 (सीएच))

क्रॉस क्लास क्रैमडाउन की शुरुआत सीआईजीए 2020 की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है और इसे यूएस चैप्टर 11 दिवाला कानून की कुछ विशेषताओं की नकल कहा जा सकता है। सीआईजीए 2020 वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाली कंपनी को यूके में व्यवस्था प्रक्रिया की मौजूदा योजना की तुलना में अधिक शक्तिशाली पुनर्गठन उपकरण प्रदान करता है।

यह कहा जा सकता है कि सीआईजीए 2020 ने मौजूदा दिवाला कानून और प्रशासन और प्री-पैक के उपयोग जैसे उपकरणों को बदलने के विरोध में वकीलों और चिकित्सकों के पुनर्गठन के लिए एक अतिरिक्त उपकरण प्रदान किया है। यह देखने के लिए एक दिलचस्प जगह है क्योंकि कानून विकसित होता है और अधिक कंपनियां नई पुनर्गठन योजना का प्रयास करने का विकल्प चुनती हैं।

चालू व्यवसाय के रूप में परिसमापन: भारतीय संदर्भ

आमतौर पर, परिसमापन या समापन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जो कंपनी के विघटन में अपनी संपत्ति की बिक्री के बाद समाप्त हो जाती है, जहां परिसमापक के पास कंपनी के व्यवसाय को चलाने की कोई शक्ति नहीं होती है, सिवाय इसके कि लाभकारी समापन³⁴ के लिए

³⁴ रॉय गुड, कॉर्पोरेट दिवाला कानून के सिद्धांत, स्वीट और मैक्सवेल, चौथा संस्करण, 2011, 1-39 पर; IBC की धारा 54, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 290(1) और 302।

आवश्यक है। हालाँकि, कुछ क्षेत्राधिकार व्यापार की बिक्री को परिसमापन में उपक्रम की बिक्री के रूप में मान्यता देते हैं।³⁵

भारत में एक सतत चिंता के आधार पर परिसमापन की उत्पत्ति, इलाहाबाद बैंक बनाम एआरसी होल्डिंग लिमिटेड एंड ओआरएस³⁶, पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक मामला से पता लगाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने आधिकारिक परिसमापक को निर्देश दिया था कि वह डिक्री किए गए ऋण और बिक्री की तारीख तक अर्जित ब्याज के बराबर आरक्षित मूल्य पर कंपनी को परिसमापन में चालू व्यापार के रूप में बेचे। आईबीसी के तहत चालू व्यापार के आधार पर कॉर्पोरेट देनदार की बिक्री का पहला उदाहरण माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ('एनसीएलटी'), गुजरात एनआरई कोक³⁷ में कोलकाता के आदेश में देखा गया था, जहां ट्रिब्यूनल ने परिसमापन को "ब्याज सहित कुल ऋण राशि" के बराबर आरक्षित मूल्य पर कॉर्पोरेट देनदार को चालू व्यापार के रूप में बेचने का निर्देश दिया था। दोनों मामलों में, अदालत ने अपने फैसले के पीछे प्रमुख कारकों में से एक के रूप में श्रमिकों और कर्मचारियों के हितों के लिए चिंता जाहिर किया।

179

2016 में आईबीसी की स्थापना के बाद से अब तक, 6 कॉर्पोरेट देनदार, अर्थात् - एम/एस इमैनुएल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, एम/एस केटीसी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, एम/एस विनविंड पावर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, एम/एस स्मैट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एम/एस सदरन ऑनलाइन बायो टेक्नोलॉजीज, और एम/एस टॉपवर्थ पाइप्स एंड ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड - को चालू व्यापार³⁸ के आधार पर परिसमापन के माध्यम से सफलतापूर्वक बचाया गया है। 290.03 करोड़ रुपए के परिसमापन मूल्य के विपरीत, 336.76 करोड़ रुपए का कुल वास्तविक मूल्य, स्पष्ट लाभ दर्शाता है कि परिसमापन के अन्य तरीकों पर चालू व्यापार बिक्री रूकी है।

आईबीसी की योजना और उसका विकास:

दिवाला संहिता दो चरणों वाली प्रक्रिया की परिकल्पना करती है, पहला कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया ('सीआईआरपी') और उसके बाद परिसमापन। सीआईआरपी प्रक्रिया के दौरान एक दिवाला पेशेवर नियुक्त किया जाता है, जिसके पास 'प्रशासनिक कार्य'³⁹ होते हैं और कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए, लेनदारों की समिति ('सीओसी') का अनुमोदन लेना होता है। दूसरी ओर, परिसमापन के

³⁵ दिवाला पर UNCITRAL विधायी मार्गदर्शिका (2005), पृष्ठ 30, 33 और 34 (ई) पर

³⁶ एआईआर 2000 एससी 3098, 16 पर।

³⁷ 2018 एससीसी ऑनलाइन एनसीएलटी 4072।

³⁸ आईबीबीआई, दिवाला और दिवालियापन त्रैमासिक समाचार पत्र (अप्रैल से जून, 2021), पृष्ठ 17 पर।

³⁹ वही

दौरान, परिसमापक एनसीएलटी की देखरेख में एक अर्ध-न्यायिक⁴⁰ कार्य करता है। सीओसी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, और 'हितधारक की परामर्श समिति' ('एससीसी') द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है जो अनुशासनात्मक कार्य करता है।

यदि कॉर्पोरेट देनदार के सीओसी द्वारा कोई समाधान योजना प्राप्त या अनुमोदित नहीं होती है, या यदि समाधान योजना एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित नहीं है, तो कॉर्पोरेट देनदार को परिसमापन में डाल दिया जाता है।⁴¹ सीओसी किसी भी समय, समाधान योजना की पुष्टि से पहले, कंपनी को परिसमापन में डालने का निर्णय ले सकता है और सीआईआरपी के अपनी कार्यप्रणाली को चलाने के लिए इंजार् नहीं कर सकता है, अगर उसका मानना है कि कॉर्पोरेट देनदार का पुनर्वास करना संभव नहीं है।⁴² दिवाला प्रक्रिया एक समयबद्ध तरीके से चलती है और आईबीबीआई ने पूरी प्रक्रिया के लिए मॉडल समयसीमा का एक विस्तृत सेट निर्धारित किया है। सीआईआरपी को एक सौ अस्सी दिनों में चलाया जाता है जिसे 330 दिनों⁴³ तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर, परिसमापन प्रक्रिया को एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना है।⁴⁴ आईबीसी ने मूल रूप से परिकल्पना की थी कि एक उद्यम का परिसमापन सामूहिक रूप से / पार्सल / मंदा की बिक्री / स्टैंडअलोन आधार पर अपनी संपत्ति की बिक्री के माध्यम से हो सकता है।

जैसा कि आईबीसी परिसमापन से पहले एक समाधान प्रक्रिया के लिए प्रदान करता है, ऐसा लगता है कि मूल्य अधिकतमकरण के साथ त्वरित और व्यवस्थित परिसमापन के परस्पर विरोधी दिवाला उद्देश्यों को संतुलित करता है, और इसकी प्रकृति से, जहां संभव हो, सफल पुनर्वास की अनुमति देता है।

हालांकि, अदालतें एक कदम आगे बढ़ गई हैं और वास्तव में यह माना जाता है कि परिसंपत्ति बिक्री⁴⁵ से पहले उद्यम को परिसमापन में पुनर्वास के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। यह दो न्यायिक नवाचारों के माध्यम से हासिल किया गया है। पहला मार्ग [भारतीय] कंपनी अधिनियम, 2013⁴⁶ की धारा 230 के तहत पुनर्गठन और परिसमापन की एक योजना के माध्यम से है। दूसरा, चालू व्यापार के आधार पर परिसमापन की अवधारणा है, जिसमें कॉर्पोरेट देनदार को संपूर्ण रूप से

⁴⁰ वही

⁴¹ आईबीसी की धारा 33(1)

⁴² [2018] EWHC 186 (Ch).

⁴³ धारा 12 आईबीसी एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के सीओसी के साथ पठित बनाम। सतीश कुमार गुप्ता, (2020) 8 एससीसी 531, 74 पर

⁴⁴ परिसमापन विनियमों के विनियम 44(1)।

⁴⁵ आर्सेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v. सतीश कुमार (2019) 2 एससीसी 83 पर।

⁴⁶ एस.सी. शेखरन वि. अमित गुप्ता व अन्य। 2019 एससीसी ऑनलाइन एनसीएलटी 517, 8 पर।

परिसमापन संपत्ति के हिस्से के रूप में बेचा जाता है, जिसमें मौजूदा कर्मचारियों का अधिग्रहणकर्ता को स्थानांतरण शामिल है।⁴⁷

परिसमापन के इन तरीकों को आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 ('परिसमापन विनियम') में संशोधनों के माध्यम से शामिल किया गया है जो अब प्रदान किया जाता है (i) कॉर्पोरेट देनदार की बिक्री को एक चालू व्यापार के रूप में ; और (ii) चालू व्यापार⁴⁸ के रूप में अपने व्यवसाय (व्यवसायों) की बिक्री। आईबीबीआई (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 ('सीआईआरपी विनियम') के विनियम 39सी के तहत, सीओसी को एक आकलन और सिफारिश करनी होगी कि परिसमापक पहले परिसमापन में कॉर्पोरेट देनदार या उसके व्यवसायों को चालू व्यापार के रूप में बिक्री का पता लगाए, जिसे फिर एनसीएलटी के सामने रिकॉर्ड पर रखा जाना चाहिए। दिवाला कानून समिति का विचार था कि परिसमापक को यह तय करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में रखा जाता है कि क्या बिक्री को चालू व्यापार के आधार पर करने का प्रयास किया जाना चाहिए।⁴⁹ इसलिए, विनियम यह प्रदान करते हैं कि परिसमापक एक स्वतंत्र राय भी बना सकता है और फिर पहली बार कॉर्पोरेट देनदार या उसके व्यवसायों को चालू व्यापार⁵⁰ के रूप में बेचने का प्रयास कर सकता है। केवल अगर परिसमापक परिसमापन शुरू होने की तारीख के नब्बे दिनों के भीतर कॉर्पोरेट देनदार या उसके व्यवसायों को चालू व्यापार के रूप में बेचने में विफल रहता है, तो वह परिसमापन के अन्य तरीकों को अपनाएगा।⁵¹

उपरोक्त परिवर्तन माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण ('एनसीएलएटी') के एक निर्णय से भी उत्पन्न होते हैं, जिसने वास्तव में, परिसमापन⁵² के लिए एक चरण-दर-चरण प्रक्रिया शुरू की। एक परिसमापक को पहले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अनुसार समझौता या व्यवस्था के माध्यम से परिसमापन को हल करने का प्रयास करना होता है। ऐसा न करने पर, परिसमापक को कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय को कर्मचारियों के साथ चालू व्यापार के रूप में बेचने की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में, उपरोक्त दोनों को एक साथ चलाया गया

⁴⁷ वाई. शिवराम वी. एस धनपाल और अन्या, सीए (एटी) (इंसोल।) 2018 की संख्या 224 (एनसीएलएटी नई दिल्ली, 02.27.2019 को निर्णय लिया गया), 13 पर।

⁴⁸ परिसमापन विनियमों के विनियम 32।

⁴⁹ भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला कानून समिति की रिपोर्ट (20 फरवरी, 2020)।

⁵⁰ परिसमापन विनियमों के विनियम 32क(1)।

⁵¹ परिसमापन विनियमों के विनियम 32क(4) ।

⁵² वाई. शिवराम वी. एस धनपाल और अन्या, सीए (एटी) (इंसोल।) 2018 की संख्या 224 (एनसीएलएटी नई दिल्ली, 27.02.2019 को निर्णय लिया गया) 13 पर।

है। उपरोक्त दोनों प्रक्रियाओं के विफल होने पर ही परिसमापक को परिसंपत्ति बिक्री के माध्यम से परिसमापन के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

परिसमापक को आमतौर पर नीलामी तंत्र के माध्यम से संपत्ति को बेचना होता है, जिसका अर्थ आमतौर पर ई-नीलामी होता है जब तक कि एनसीएलटी एक भौतिक नीलामी की अनुमति नहीं देता है, जैसा कि परिसमापन विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है।⁵³ परिसमापक एक आरक्षित मूल्य निर्धारित करता है जो नीलामी के विफल होने पर प्रत्येक बाद के दौर में एक पूर्वनिर्धारित प्रतिशत तक उत्तरोत्तर कम हो जाता है। उच्चतम बोली लगाने वाले को शेष राशि 90 दिनों के भीतर देनी होगी अन्यथा बिक्री रद्द कर दी जाएगी। पूरी राशि के भुगतान पर परिसमापक द्वारा एक 'बिक्री का प्रमाण पत्र' या बिक्री विलेख निष्पादित किया जाता है और बिक्री पूरी हो जाती है।

यद्यपि चालू व्यापार परिसमापन की प्रक्रिया के बारे में चिंताएं हैं और क्या वे आईबीसी⁵⁴ की योजना के भीतर फिट होते हैं, विभिन्न मामलों में उनका पालन किया गया है और चालू व्यापार व्यापार परिसमापन के यहीं रहने की संभावना है।

182

परिसमापन में चालू व्यापार बिक्री में समस्या :

यह प्रस्तुत किया जाता है कि चालू व्यापार बिक्री के की अपेक्षा परिसमापन विनियमों के तहत नीलामी प्रक्रिया परिसंपत्ति बिक्री की दिशा में अधिक सक्षम है। इन विनियमों की मूल संरचना में केवल परिसंपत्ति बिक्री की परिकल्पना की गई थी और यह बिक्री के तरीकों के तहत और सीओसी और एससीसी विचार-विमर्श के तहत केवल 'चालू व्यापार बिक्री' शब्द को जोड़ने के साथ अपरिवर्तित जारी रही है। हालांकि, चालू व्यापार की बिक्री परिसमापन में एक समाधान योजना की तरह है। यह विभिन्न मुद्दों को जन्म देता है:

विलंब: चूंकि बोली लगाने वाले को नीलामी में भाग लेना होता है और केवल एक संख्या में फ़ीड करना होता है, इसलिए तत्परता अधिक महत्व रखता है। हालांकि, परिसमापन विनियम बिक्री के पूरा होने के लिए केवल 90 दिनों की परिकल्पना करते हैं। इस प्रकार, परिसमापन में चालू व्यापार बिक्री के पहले दौर में शायद ही कभी आरक्षित मूल्य पर बोलियां आकर्षित होती हैं। यह इस तथ्य से और अधिक जटिल है कि बिक्री का प्रत्येक बाद का दौर कम आरक्षित मूल्य पर होगा (एक

⁵³ परिसमापन विनियमों की अनुसूची 1 के साथ पठित विनियम 33

⁵⁴ निवेश संपत्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण प्राइवेट लिमिटेड v. मोहन जेम्स एंड ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड I.A.1490/2020 कंपनी याचिका संख्या (आईबी) -590 (पीबी) / 2018 (एनसीएलटी नई दिल्ली, 16.09.2019 को तय किया गया), 2, 32-34 पर।

निर्धारित प्रतिशत तक - पहले, पच्चीस, और नियमों के अनुसार प्रत्येक बाद के राउंड में दस प्रतिशत) जो प्रारंभिक नीलामी प्रक्रिया की प्रतीक्षा करने के लिए बोली लगाने वालों को प्रोत्साहित करता है। प्रारंभिक समय सीमा के भीतर परिसमापन लगभग शायद ही कभी हासिल किया गया हो।

अनुपालन: चूंकि परिसमापन विनियमों में किसी योजना की परिकल्पना नहीं की गई है, इसलिए मौजूदा पूंजी को बट्टे खाते में डालने का तरीका, शेयर जारी करना और तरजीही आवंटन, कंपनी रजिस्ट्रार और कर अधिकारियों के साथ कॉर्पोरेट अनुपालन को अद्यतन करना जैसे सरल और आवश्यक कदमों पर स्पष्टता का अभाव है। . मामला सूचीबद्ध संस्थाओं में अधिक जटिलता प्राप्त करता है जहां प्रासंगिक सेबी नियमों में समाधान योजना के लिए विशिष्ट छूट की परिकल्पना की गई है, लेकिन परिसमापन के लिए नहीं।

देयता की रिंग फेंसिंग: परिसमापन विनियम तीसरे पक्ष के दावों के खिलाफ परिसंपत्तियों की किसी भी रिंग-फेंसिंग के लिए या विरासत के मामलों और पिछली देनदारियों की रिंग फेंसिंग के लिए प्रदान नहीं करते हैं जैसा कि सीआईआरपी के दौरान होता है। आम तौर पर, परिसंपत्ति की बिक्री के विपरीत, चालू व्यापार बिक्री के आधार पर बिक्री में देनदारियों के साथ संपत्ति का हस्तांतरण शामिल होता है। हालांकि इन मुद्दों को स्पष्ट करते हुए कुछ न्यायिक घोषणाएं की गई हैं और यह मानते हुए कि धारा 53 के तहत पिछली देनदारियां समाप्त हो जाएंगी, यह मुद्दा एक ग्रे क्षेत्र बना हुआ है।

आस्तियों का हस्तांतरण: एक चालू-संबंधित बिक्री में, यह अनिवार्य है कि एक सफल बोलीदाता बिक्री के प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति का कब्जा ले लेगा। परिसमापक के दायित्वों पर किसी भी समान स्पष्टता के बिना कब्जा लेने का दायित्व पूरी तरह से सफल बोलीदाता पर रखा गया है। वह तकनीकी रूप से बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि पर कार्य करना बंद कर देता है। कई मामलों में, एक कॉर्पोरेट देनदार की कई संपत्ति एक विशाल क्षेत्र में फैली हो सकती है, जो आमतौर पर विभिन्न तृतीय पक्षों के कब्जे में होती है। यह एक संभावित अधिग्रहणकर्ता के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या प्रस्तुत करता है, क्योंकि वे तीसरे पक्ष के परिसर से कॉर्पोरेट देनदार की सभी संपत्तियों को पुनर्प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं, जो बदले में कॉर्पोरेट देनदार की पुनर्वास प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेगा।

एनसीएलटी इस अवसर पर उठें हैं और उपरोक्त मुद्दों के संबंध में सफल बोली लगाने वाले को कुछ राहत दी है। एनसीएलटी के लिए समयसीमा में छूट प्रदान करना भी असामान्य नहीं है ताकि परिसमापक को एक आसान प्रक्रिया चलाने की अनुमति मिल सके, लेकिन इसके परिणामस्वरूप कई दौर में नीलामी हुई है और एक चालू व्यापार के रूप में परिसमापन में देरी हुई है।

हालांकि, यह ज्यादातर सफल बोली लगाने वाले पर छोड़ दिया गया है कि वह अग्रिम प्रतिफल का भुगतान करने के बाद और कुछ मामलों में, पूर्ण विचार के बाद एनसीएलटी से इन राहतों को प्राप्त करें। यह विरोधाभासी प्रतीत होता है, क्योंकि यदि कोई बोलीदाता इस तरह के परिसमापन में भाग लेने और पूरी राशि का भुगतान करने का विकल्प चुनता है, तो बिना किसी निश्चित राहत के, बोली मूल्य कम हो जाएगा। प्रक्रिया की निश्चितता और पूर्वानुमेयता मूल्य को अधिकतम करने की कुंजी है। उपरोक्त मुद्दों को हल करने के लिए, निम्नलिखित समाधानों पर विचार किया जा सकता है:

- ऐसे मामलों में आईबीसी के तहत ही राहत के मानकीकृत सीमित सेट को संहिताबद्ध किया जाता है। जबकि बोलीदाताओं को मामला-दर-मामला आधार पर एनसीएलटी से राहत दी जाती है, राहत के संहिताकरण से बेहतर मूल्य और बिक्री से अधिक बेहतर परिणाम सुनिश्चित होंगे। यह एक संभावित अधिग्रहणकर्ता की नजर में चालू व्यापार बिक्री की "छिपी हुई लागत" को समाप्त कर देगा और कॉर्पोरेट देनदार के मूल्य की तेजी से प्राप्ति की अनुमति देगा।
- सेबी (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2018, सेबी (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011, और सेबी (इक्विटी शेयरों का असूचीबद्ध होना) विनियम, 2009 जैसे संबंधित विनियमों में तदनुरूपी परिवर्तन किया जाता है, जिसमें परिसमापन को समाधान योजना के समान ही चालू व्यापार के रूप में मान्यता दी गई है।
- चालू व्यापार के रूप में परिसमापन में नीलामी के कई राउंड से बचा जाना चाहिए। ऊपर दिए गए दो परिवर्तनों के साथ यह आशा की जाती है कि प्रत्येक बाद के राउंड में आरक्षित मूल्य को कम करने की प्रक्रिया को बंद किया जा सकता है।
- परिसमापक को अधिग्रहण के पूरा होने में सहायता करने के लिए अनिवार्य होना चाहिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कॉर्पोरेट देनदार एक चालू व्यापार बना रहे, सभी सहायता प्रदान करने के लिए अनिवार्य होना चाहिए।

पुनर्गठन और दिवाला में व्यवस्था की योजनाओं का उपयोग करना

धनंजय कुमार, केट स्टीफेंसन और अभिषेक मुखर्जी

पुनर्गठन और दिवाला में व्यवस्था की योजनाओं का उपयोग करना¹

धनंजय कुमार, साझेदार, सिरिल अमरचंद मंगलदास
केट स्टीफेंसन किर्कलैंड और एलिस इंटरनेशनल एलएलपी
अभिषेक मुखर्जी, सलाहकार /Counsel, सिरिल अमरचंद मंगलदास

सार

यह लेख ऋण पुनर्गठन उपकरण के रूप में ब्रिटिश और भारतीय योजनाओं की व्यवस्था के उपयोग की पड़ताल करता है। यह भारतीय प्रणाली के लिए ब्रिटिश योजनाओं की प्रासंगिकता पर विचार करता है। फिर यह ब्रिटिश योजनाओं को उनकी प्रकृति, उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में एक ऋण पुनर्गठन उपकरण के रूप में उनके आधुनिक उपयोग मानता है। यह ब्रिटिश योजनाओं के कथित फायदे और नुकसान पर चर्चा करता है और फिर कुछ मौजूदा ज्वलंत विषयों में गहरा गोता लगाता है, जिसमें पुनर्गठन बाजार और न्यायपालिका ने औपचारिक अधिस्थगन की कमी, प्रकटीकरण और समय की पर्याप्तता सहित कई संभावित समस्याग्रस्त मुद्दों को अनुकूलित किया है (बाकी और अन्य मुद्दों में से)।

186

इसके बाद यह नए दिवाला कानून ढांचे के तत्वावधान में ऋण पुनर्गठन के लिए भारतीय योजनाओं की व्यवस्था को उनके प्रमुख पहलुओं, ब्रिटिश कानूनी ढांचे से प्रेरित नींव के साथ उत्पत्ति, योजनाओं की न्यायिक जांच की सीमा, ऋण पुनर्गठन उपकरण के रूप में इसके उपयोग को प्रभावित करने वाली सीमाओं और इसके संवर्धित, और इसकी संभावनाओं पर चर्चा करने पर विचार करता है। यह इस सुझाव के साथ समाप्त होता है कि भारत अपनी व्यवस्था की योजना के सुधार तत्वों पर कैसे विचार कर सकता है।²

¹ आर्सेलर मितल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सतीश कुमार (2019) 2 एससीसी 1 नंबर 83 पर।

² वही

भाग 1: परिचय

1.1 उद्देश्य और दायरा: यह लेख ऋण पुनर्गठन उपकरण के रूप में ब्रिटिश और भारतीय व्यवस्था की योजनाओं के उपयोग की पड़ताल करता है। यह सबसे पहले भारतीय प्रणाली के लिए व्यवस्था की ब्रिटिश योजनाओं की प्रासंगिकता पर विचार करता है। इसके बाद यह निम्नलिखित के संदर्भ में व्यवस्था की ब्रिटिश योजनाओं पर विचार करता है:

- a) उनकी प्रकृति और मूल;
- b) एक ऋण पुनर्गठन उपकरण के रूप में उनका विकास;
- c) आर्थिक रूप से परेशान कंपनियों (गैर-ब्रिटिश कंपनियों सहित) द्वारा उनके आधुनिक उपयोग;
- d) उनके कथित फायदे और नुकसान; और
- e) वर्तमान ज्वलंत विषय, जिसमें यह भी शामिल है कि कैसे पुनर्गठन बाजार और न्यायपालिका ने कई संभावित समस्याग्रस्त मुद्दों को अनुकूलित किया है।

1.2 इसके बाद यह निम्नलिखित के संदर्भ में व्यवस्था की भारतीय योजनाओं पर विचार करता है:

- a) उनकी प्रमुख विशेषताएं और प्रमुख प्रक्रियात्मक पहलू;
- b) उनकी उत्पत्ति ब्रिटिश कानून ढांचे से प्रेरित नींव के साथ;
- c) पारदर्शिता के तत्वों को मजबूत करके एक आत्मनिर्भर ढांचे में उनका विकास, भारत में बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ संरेखण को और अधिक लेनदार-अनुकूल बनाने के लिए और तेजी से अनुमोदन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए;
- d) अल्पसंख्यक हितधारकों के लिए सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं की न्यायिक जांच की सीमा;
- e) ऋण पुनर्गठन उपकरण के रूप में उपयोग को प्रभावित करने वाली उनकी सीमाएं; और
- f) भारत में नए दिवाला कानून ढांचे के तत्वावधान में ऋण पुनर्गठन के लिए इसके संवर्धित उपयोग के लिए सिफारिशों और संभावनाओं पर चर्चा करना।

1.3 इसमें सुझाव शामिल हैं कि भारत अपनी व्यवस्था की योजना के सुधार तत्वों पर कैसे विचार कर सकता है, और नए दिवाला ढांचा का उपयोग भी कर सकता है, योजनाओं को एक अन्य ऋण पुनर्गठन उपकरण के रूप में स्थापित करने के लिए जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली और उसके निगम, कॉर्पोरेट समुदाय को तनावग्रस्त संपत्तियों से बेहतर तरीके से निपटने में मदद करेगा।

1.4 यह लेख दिसंबर 2021 तक ब्रिटिश और भारतीय कानून के मामलों तक ही सीमित है।

भारतीय प्रणाली के लिए ब्रिटिश योजनाओं की प्रासंगिकता

1.5 जैसा कि हम योजना के लिए ब्रिटिश कानून ढांचे पर चर्चा से लेकर भारतीय कानून ढांचे तक इस लेखपेपर के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि, भारतीय कंपनी कानून की उत्पत्ति मोटे तौर पर ब्रिटिश समकक्ष से प्रेरित है एवं व्यवस्था की योजनाएं भी ढांचे के समान हैं। इसमें मूल और प्रक्रियात्मक दोनों पहलू शामिल हैं।

1.6 ऋण पुनर्गठन उपकरण के रूप में योजनाओं के उपयोग के संदर्भ में दोनों प्रणालियों का सामना करने वाले व्यावहारिक मुद्दे भी कुछ हद तक समान हैं। हालांकि, एक सफल योजना को समय पर पूरा करने के लिए कुछ मुद्दों को दरकिनार करने के लिए ब्रिटिश बाजार कुछ तकनीकों और आवश्यकता-आधारित प्रथाओं को लागू करने में सक्षम रहा है। हालांकि इन सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना भारतीय अधिकार क्षेत्र के लिए एक स्वागत योग्य दृष्टिकोण होगा, परन्तु, यह देखने की जरूरत है कि क्या भारतीय संदर्भ में तकनीकों को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है।

ब्रिटिश योजनाओं की व्यवस्था की प्रकृति

1.7 ब्रिटिश योजना की व्यवस्था कंपनी अधिनियम 2006 के भाग 26 के तहत एक औपचारिक वैधानिक 'कब्जे में देनदार' प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कंपनी अपने लेनदारों (और/या सदस्यों) के एक असंतुष्ट अल्पसंख्यक वर्ग को अदालत द्वारा स्वीकृत समझौते के लिए बाध्य कर सकती है।

1.8 यह लेख विशेष रूप से ऋणदाता योजनाओं पर केंद्रित है, जो दिवाला और वित्तीय संकट के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं; हालांकि, खासकर सूचीबद्ध कंपनियों के अधिग्रहण के संदर्भ में सदस्य योजनाएं काफी सामान्य हैं।

1.9 ब्रिटिश योजना की व्यवस्था के प्रमुख पहलुओं में शामिल हैं:

a) लचीला दायरा - कानून किसी योजना की विषय वस्तु को निर्धारित नहीं करता है, जो विभिन्न प्रकार के संभावित उपयोगों की अनुमति देता है (जैसा कि अनुच्छेद /पैराग्राफ 2.1 में खोजा गया है) और योजनाएं असहमत/ विरोधी सुरक्षित या अधिमान्य लेनदार को बाध्य करने में सक्षम हैं।

b) देनदार के नेतृत्व में - हालांकि कंपनी के अलावा किसी भी लेनदार या सदस्य, या कंपनी के परिसमापक या प्रशासक द्वारा एक योजना आवेदन किया जा सकता है³, व्यवहार में प्रक्रिया लगभग हमेशा कंपनी और उसके सलाहकारों के नेतृत्व में होती है², जैसा कि अनुच्छेद / पैराग्राफ 2.2 में देखा गया है।

c) वोटिंग - लेनदारों ने योजना के पूर्व एवं पश्चात के अपने अधिकारों के अनुसार वर्गों में वोट दिया; एक योजना के लिए प्रत्येक वर्ग में लेनदारों के वोटिंग के मूल्य के कम से कम 75 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुमत के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।⁴

d) प्रक्रिया निम्नानुसार चलती है: ⁵

(i) एक 'आयोजन सुनवाई' जिस पर अदालत विचार करती है कि लेनदारों के संबंधित वर्ग/वर्गों की बैठक/बैठकें बुलानी है या नहीं;

(ii) अदालत द्वारा बुलाई गई बैठक/बैठकों में मतदान। ;

(iii) बशर्ते कि योजना की बैठक (बैठकों) में लेनदारों की अपेक्षित बहुमत योजना को मंजूरी दे, एक 'स्वीकृति सुनवाई' जिस पर अदालत विचार करती है कि योजना को स्वीकृति दी जाए या प्रतिबंधित कर दिया जाये; और ⁶

(iv) कंपनी रजिस्ट्रार के पास अदालत का आदेश दाखिल करना, जिस पर योजना प्रभावी हो जाती है और योजना के अधीन सभी लेनदारों को बाध्य करती है। ⁷

(e) लेनदारों का चयन - केवल वे लेनदार जो योजना से समझौता करते हैं, वोट देने के हकदार हैं; "वित्तीय कठिनाई में एक कंपनी की कुछ के साथ समझौता या व्यवस्था का प्रस्ताव करने की

³ एससी शेखरन बनाम अमित गुप्ता और अन्य। 2019 एससीसी ऑनलाइन एनसीएलएटी 517, 8 बजे।

⁴ वाई. शिवराम बनाम एस. धनपाल और अन्य, सीए (एटी) (इंसोल।) 2018 की संख्या 224 (एनसीएलएटी नई दिल्ली, 27.02.2019 को निर्णय लिया गया), 13 बजे।

⁵ वही

क्षमता, (लेकिन सभी के साथ नहीं), उसके लेनदारों के समूह, भाग 26⁸के तहत योजना क्षेत्राधिकार की सबसे लचीली और मूल्यवान विशेषताओं में से एक है"; हालांकि, अदालत यह सुनिश्चित करना चाहेगी कि योजना में शामिल करने के लिए कंपनी का चयन मनमाना नहीं था या वर्ग में हेरफेर करने के इरादे से नहीं किया गया था।⁹

(f) व्यापक योग्यता - कोई भी कंपनी जो दिवाला अधिनियम 1986 के तहत बंद होने के लिए उत्तरदायी है एक योजना¹⁰का प्रस्ताव करने के लिए पात्र है, जिसमें विदेशी कंपनियां¹¹शामिल हैं⁷; हालांकि, अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग तब तक नहीं करेगी जब तक कि ब्रिटिश क्षेत्राधिकार¹² के लिए "पर्याप्त संबंध" न हो और योजना के प्रमुख क्षेत्राधिकार¹³ में पर्याप्त प्रभाव होने की उचित संभावना न हो।

ब्रिटिश योजनाओं की व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास

190

1.10 एक देनदार को हमेशा अपने लेनदारों के साथ ऋणों के निपटान के लिए व्यवस्था करने की अनुमति दी गई है जो किसी भी औपचारिकता से स्वतंत्र होगा एवं केवल उन लेनदारों के लिए बाध्यकारी होगा जिन्होंने समझौता करने के लिए सहमति व्यक्त की। लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं मुख्य रूप से धोखाधड़ी, अनुचित लेखांकन और उचित जानकारी और नोटिस की कमी के संदर्भ में ऐतिहासिक रूप से कठिनाइयों से भरी रही हैं।¹⁴

1.11 औपचारिक ढांचा प्रदान करने और दुरुपयोग को कम करने के प्रयासों में समय-समय पर वैधानिक प्रावधान बनाए गए थे। क्रमिक कंपनी अधिनियम (1870, 1908, 1948, 1985 और 2006 के) और व्यवस्था के कार्य अधिनियम (1887 और 1914 के) व्यवस्था की आधुनिक-दिन की योजना के विकास को चिह्नित करते हैं। कॉर्पोरेट संदर्भ में, ये शुरू में समापन के दौरान कंपनियों तक सीमित थे¹⁵और, विकास के माध्यम से, स्टैंड-अलोन/standalone, गैर-शोधन अक्षमता के लिए, कार्यवाही की व्यवस्था की योजना आज भी बनी हुई है।

⁶ परिसमापन विनियमों के विनियम 32ए (1)।

⁷ परिसमापन विनियमों के विनियम 32।

⁸ भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला कानून समिति की रिपोर्ट (20 फरवरी, 2020)।

⁹ वही

¹⁰ परिसमापन विनियमों के विनियम 32ए (1)।

¹¹ परिसमापन विनियमों के विनियम 32क (4)

¹² वही

¹³ वही

¹⁴ वही

¹⁵ वही

1.12 व्यवस्था की योजनाओं को ऐतिहासिक रूप से महंगा, जटिल और बोझिल देखा गया है।¹⁶

1.13 1990 के दशक के अंत में कई बीमा कंपनी के पुनर्गठन में योजनाओं के उपयोग के बाद, ब्रिटिश बाजार ने पिछले 20 वर्षों में ऋण पुनर्गठन उपकरण के रूप में योजनाओं के उपयोग को उत्तरोत्तर विकसित किया है - विशेष रूप से वैश्विक वित्तीय संकट के बाद में।

1.14 एक प्रमुख यूरोपीय पुनर्गठन उपकरण के रूप में व्यवस्था की योजना के उदय को कई कारकों ने प्रेरित किया जिसमें शामिल है

(a) गैर-दिवाला कार्यवाही के रूप में योजनाओं की प्रकृति - कई यूरोपीय देशों में ढांचे पर एक महत्वपूर्ण लाभ, कंपनियों को मूल्य हानिकारक दिवाला कार्यवाही से बचने में सक्षम बनाना -

(b) यूरोपीय बाजार में अधिकांश बैंक ऋण देने में शासी कानून के रूप में ब्रिटिश कानून की पसंद;

(c) गैर-ब्रिटिश कंपनियों के लिए इंग्लैंड के लिए "पर्याप्त सम्बन्ध/ कनेक्शन" के साथ योजनाओं की उपलब्धता (और अदालत के फैसले खोजने के लिए कि ब्रिटिश शासन कानून इस उद्देश्य के लिए सम्बन्ध/ कनेक्शन के माध्यम से पर्याप्त होगा)¹⁷;

(d) ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली की ताकत, इसकी केंद्रीकृत, कुशल अदालतों और अत्यधिक विशेषज्ञ न्यायपालिका के साथ; और

(e) ब्रिटिश पुनर्गठन बाजार में कानूनी और वित्तीय विशेषज्ञता, जो सौदे के बाद निरंतर सौदे पर विकसित हुई।

1.15 निगम/ कॉर्पोरेट दिवाला और शासन अधिनियम 2020 ने कंपनी अधिनियम 2006 (अन्य उपायों के बीच) के एक नए भाग 26A के रूप में एक नई "पुनर्गठन योजना" प्रक्रिया की शुरुआत की। पुनर्गठन योजना प्रक्रिया व्यवस्था की मौजूदा योजनाओं पर आधारित है, लेकिन कुछ प्रमुख अंतरों के साथ, जिनमें शामिल हैं:

(a) एक वित्तीय कठिनाइयों की पात्रता सीमा;

¹⁶ परिसमापन विनियमों के विनियम 32ए (1)।

¹⁷ परिसमापन विनियमों के विनियम 32ए (1)।

(b) अदालत की क्षमता एक योजना को मंजूरी देने के लिए जहां हर वर्ग ने इसे मंजूरी नहीं दी है (कुछ शर्तों के अधीन); और

(c) कोई "संख्यात्मकता" मतदान सीमा नहीं - एक वर्ग के भीतर कम से कम 75 प्रतिशत लेनदारों (या सदस्यों) के मतदान की मंजूरी उस वर्ग के लिए योजना को मंजूरी देने के लिए पर्याप्त है।

भाग 2: चर्चा

पुनर्रचना में ब्रिटिश योजनाओं का आधुनिक उपयोग

2.1 एक योजना में किसी कंपनी और उसके लेनदारों (या उनमें से किसी वर्ग) या सदस्यों (या उनमें से किसी भी वर्ग)¹⁸ के बीच "समझौता या व्यवस्था" के कुछ रूप शामिल होने चाहिए। "समझौता या व्यवस्था" शब्द की व्यापक रूप से अदालतों द्वारा व्याख्या की गई है¹⁹, जो एक पुनर्गठन संदर्भ में लेनदेन की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित करने के लिए योजनाओं के उपयोग की अनुमति देता है:

(a) ऋण के लिए ऋण / ऋण के लिए इक्विटी स्वेप (कभी-कभी, प्री-पैक प्रशासन के संयोजन में) - पुनर्रचना योजनाओं का विशाल बहुमत इस श्रेणी में आता है;

(b) "संशोधन और विस्तार" लेनदेन – उदाहरण.- पहली Apcoa योजना;

(c) ठहराव (एक वास्तविक पुनर्गठन से पहले सांस/ राहत लेने का समय खरीदने के लिए) – उदा.- Metinvest, DTEK;

(d) मुकदमेबाजी के दावों से समझौता – उदाहरण.- लेहमैन ब्रदर्स इंटरनेशनल यूरोप (प्रशासन में) और स्टीनहॉफ;

(e) पट्टों के तहत देनदारियों का समझौता²⁰ – उदाहरण.- तत्काल नकद ऋण और एमएबी लीजिंग (मलेशिया एयरलाइंस; विमान पट्टे की व्यवस्था);

¹⁸ धारा 895(1), कंपनी अधिनियम 2006।

¹⁹ हालांकि एक योजना जो लेनदारों के हितों से अधिक नहीं है, वह "समझौता या व्यवस्था" नहीं होगी: रेएनएफयू डेवलपमेंट ट्रस्ट [1972] 1 डब्ल्यूएलआर 1548 - यानी 'दे और ले' के कुछ तत्व होने की आवश्यकता है।

²⁰ हालांकि, व्यवस्था की एक योजना एक मकान मालिक को पट्टे के आत्मसमर्पण को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है क्योंकि यह एक मकान मालिक के मालिकाना अधिकारों में हस्तक्षेप करेगा:

(f) व्यापक उपभोक्ता निवारण दावों से समझौता – उदा.- गलत बिक्री देनदारियां, जैसे तत्काल नकद ऋण, एमिगो²¹ (जिसमें अदालत ने योजना को मंजूरी देने से इनकार कर दिया) और प्रोविडेंट फाइनेंस, या कर्मचारी दावे (उदाहरण के लिए, एस्बेस्टोसिस संदर्भ में, टी एन और केप पीएलसी);

(g) , जहां बीमा व्यवसाय रन-ऑफ में चला जाता है (व्यापक रूप से एक विलायक संदर्भ में उपयोग किया जाता है) बीमा अनुबंधों के तहत देनदारियों का समझौता करता है; और

(h) अधिग्रहण और विलय (व्यापक रूप से एक विलायक संदर्भ में उपयोग किया जाता है)।

2.2 कंपनी, एक लेनदार या एक शेयरधारक (या प्रशासक या परिसमापक यदि कंपनी प्रशासन या परिसमापन में है) द्वारा योजनाओं का प्रस्ताव किया जा सकता है।²² हालाँकि, व्यवहार में, योजनाएँ लगभग हमेशा कंपनी द्वारा ही प्रस्तावित की जाती हैं, दोनों प्रकटीकरण आवश्यकताओं के कारण और क्योंकि अदालत के पास ऐसी योजना को मंजूरी देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जहां कंपनी का अनुमोदन नहीं है।²³

री इंस्टैंट कैश लोन [2019] EWHC 2795 (Ch)। एक योजना केवल ऋणी/ऋणदाता के रूप में किरायेदार और मकान मालिक के बीच संबंधों को उनकी क्षमता में बदल सकती है।

²¹ Amigo वित्तीय आचरण प्राधिकरण ("FCA") द्वारा अधिकृत है; एफसीए ने योजना की मंजूरी का सफलतापूर्वक विरोध किया। प्रोविडेंट फाइनेंस की कुछ इसी तरह की उपभोक्ता निवारण योजना को बाद में अदालत ने मंजूरी दी थी; एफसीए ने एक बयान जारी कर यह स्पष्ट किया कि उसने प्रोविडेंट योजना का समर्थन नहीं किया और 10 अलग-अलग आपतियों को सूचीबद्ध किया, लेकिन उसने मंजूरी का सक्रिय रूप से विरोध नहीं किया क्योंकि 1. विकल्प एक आसन्न दिवाला था जिसमें निवारण लेनदारों को योजना के तहत कम मिलेगा और 2. प्रोविडेंट का उपभोक्ता ऋण प्रभाग अपना व्यवसाय जारी नहीं रख रहा था और निवारण लेनदारों की कीमत पर प्रोविडेंट समूह और उसके हितधारकों को कोई अनुचित लाभ नहीं हुआ। एफसीए योजनाओं और अन्य समान पुनर्गठन उपकरणों के लिए एफसीए के दृष्टिकोण के बारे में मार्गदर्शन पर परामर्श करने का इरादा रखता है, जिसमें कंपनी कानून के तहत व्यवस्था के माध्यम से समझौता करने के लिए फर्मों को शामिल करने की उम्मीद है।

²² सीमित देयता भागीदारी योजना प्रक्रिया को थोड़े संशोधित रूप में भी उपयोग कर सकती है।

²³ (या तो बोर्ड के माध्यम से या सामान्य बैठक में सदस्यों के साधारण बहुमत के माध्यम से): रे सेवॉय होटल लिमिटेड [1981] Ch 351 [365] देखें।

फायदे/ लाभ और नुकसान

2.3 सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है; निम्नलिखित उच्च-स्तरीय सारांश मुख्य रूप से योजना आवेदक के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है।

2.4 लाभ:

(a) दायरे में अत्यधिक लचीला - ऊपर अनुच्छेद/पैराग्राफ 2.1 देखें।

(b) असंतुष्ट लेनदारों को बाध्य करने के लिए "आज़माया और परखा हुआ" एक अत्यधिक प्रभावी समझौता।

(c) चूंकि व्यवस्था की योजना एक कंपनी अधिनियम प्रक्रिया है, और किसी भी "वित्तीय कठिनाइयों" पात्रता आवश्यकता (सीएफ./cf. नई पुनर्गठन योजना प्रक्रिया) की अनुपस्थिति को देखते हुए, एक औपचारिक योजना शोधन अक्षमता प्रक्रिया से कम कलंकित हो सकती है।

(d) कब्जे की प्रक्रिया में देनदार - मौजूदा निदेशक नियंत्रण में रहते हैं (हालांकि इसे लेनदारों द्वारा नुकसान के रूप में देखा जा सकता है, अगर वे मौजूदा प्रबंधन को देनदार की वित्तीय कठिनाइयों के लिए दोषी मानते हैं)।

(e) सुरक्षित और असुरक्षित दोनों लेनदारों को बाध्य करने की क्षमता और आवेदक के लिए यह चुनने के लिए कि कौन से लेनदार योजना से प्रभावित होंगे (सुरक्षा उपायों के अधीन - आगे पैराग्राफ 1.9 (e) देखें)।

(f) ब्रिटिश अदालतों को अत्यधिक सम्मान दिया जाता है और इसमें व्यवस्था की योजनाओं से निपटने में विशेष विशेषज्ञता वाले कई न्यायाधीश शामिल हैं।

(g) गैर-ब्रिटिश कंपनियों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध, बशर्ते उनका ब्रिटिश क्षेत्राधिकार से पर्याप्त संबंध हो; यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां देनदार तथाकथित "गिब्स में नियम" के कारण ब्रिटिश कानून द्वारा शासित ऋण से समझौता करना चाहता है, कि एक अनुबंध को केवल उसके शासी कानून के अनुसार छुट्टी दी जा सकती है या समझौता किया जा सकता है।²⁴

2.5 नुकसान:

²⁴ एंटनी गिब्स एंड संस बनाम ला सोसाइटी इंडस्ट्रीयल एट कमर्शियल डेस मेटौक्स (1890) 25 QBD 399। ब्रिटिश अदालत सामान्य कानून सिद्धांतों के तहत किसी विदेशी दिवाला-संबंधी निर्णय को तब तक

(a) योजना की बैठकों के अलावा दो अदालती सुनवाई की आवश्यकता, समय-सीमा और लागत पर परिणामी प्रभाव के साथ (हालांकि, अदालत योजनाओं की पर्याप्त जांच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है)।

(b) औपचारिक अधिस्थगन की अनुपस्थिति योजना की प्रक्रिया के दौरान देनदार की रक्षा के लिए - आगे के पैराग्राफ 2.7 और 2.8 देखें।

(c) एक असंतुष्ट वर्ग को बाध्य करने में असमर्थता - आगे के पैराग्राफ 2.13 और 2.14 देखें।

(d) अदालत की सुनवाई आपत्तियों के लिए एक तैयार मंच प्रदान करती है (इसके विपरीत) कुछ अन्य ब्रिटिश पुनर्गठन और दिवाला प्रक्रियाओं जैसे कि कंपनी की स्वैच्छिक व्यवस्था या प्रशासन) - असफल चुनौती की लागत किसे वहन करनी चाहिए, आगे के पैराग्राफ 2.36 से 2.38 देखें।

ब्रिटिश शासन के अनुभव: विशिष्ट व्यावहारिक मुद्दों का मूल्यांकन और समाधान

2.6 यह खंड विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर विचार करता है जो व्यवहार में उत्पन्न हुए हैं, और बताते हैं कि कैसे अदालतों, बाजार और/या विधायिका ने ऐसे मुद्दों को हल करने का प्रयास किया है। इनमें से कई ब्रिटिश पुनर्गठन बाजार में महत्वपूर्ण विषय बने हुए हैं (हालांकि कुछ, जैसे कि अंतिम लाभकारी धारकों द्वारा मतदान, अब अच्छी तरह से तय हो गए हैं)।

औपचारिक अधिस्थगन का अभाव

2.7 कंपनी के खिलाफ " मामले को सुलझाने से सम्बंधित /hold the ring" करने के लिए लेनदारों के दावों पर कोई औपचारिक वैधानिक अधिस्थगन नहीं है, जबकि यह एक ब्रिटिश योजना को लागू करना चाहता है। एक योजना के लिए समय-सीमा को देखते हुए (पैराग्राफ 2.15 देखें), इसमें एक लंबी अवधि लगती है जिस दौरान कंपनी लेनदार प्रवर्तन से असुरक्षित है।

मान्यता या प्रभावी नहीं दे सकती जब तक कि जिस पक्ष के खिलाफ आदेश दिया गया था, वह इसके अधीन था प्रासंगिक विदेशी कार्यवाही (ब्रिटिश निजी अंतरराष्ट्रीय कानून के मामले में): रुबिन बनाम यूरोफाइनेंस एसए और अन्य [2012] यूकेएससी 46।

2.8 हालांकि, निम्नलिखित समाधान मौजूद हैं (उपयोगिता के कथित क्रम में प्रस्तुत किया गया है):

(a) संविदात्मक ठहराव/ स्थिर/standstill व्यवस्था - "बंद करने की व्यवस्था" जो योजना कंपनी / समूह और योजना लेनदारों के बीच लगभग²⁵ हमेशा योजना शुरू करने से पहले दर्ज किए जाते हैं;

(b) अदालत के मामले प्रबंधन शक्तियों पर आश्रय - योजना कंपनी अदालत में आवेदन कर सकती है ताकि योजना को बढ़ावा देने के लिए कंपनी को सक्षम करने के लिए प्रवर्तन पर रोक लगाने की मांग की जा सके (अदालत की विवेकाधीन मामला प्रबंधन शक्तियों के माध्यम से)²⁶;

(c) प्रशासन- कंपनी प्रशासन के साथ, व्यवस्था की एक योजना को संभावित रूप से जोड़ सकती है, यह देखते हुए कि एक कंपनी प्रशासन में होने पर एक वैधानिक अधिस्थगन मौजूद है ; "हल्के स्पर्श प्रशासन/light touch administration" का पालन करके निदेशकों को दिन-प्रतिदिन के कार्यों के नियंत्रण में छोड़ दिया जाना भी संभव है। हालांकि, प्रशासन में प्रवेश एक महत्वपूर्ण, संभावित मूल्य-विनाशकारी कदम है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए; या

(d) नया स्टैंडअलोन अधिस्थगन- कॉर्पोरेट दिवाला और शासन अधिनियम 2020 ने एक नई स्टैंडअलोन अधिस्थगन प्रक्रिया²⁷ की शुरुआत की, जिसका संभावित रूप से व्यवस्था की एक योजना के समानांतर उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, इस अधिस्थगन की उपयोगिता विभिन्न कारकों के कारण सीमित है, जिनमें शामिल हैं:

(i) व्यापक पूंजी बाजार पात्रता के अपवाद को छोड़कर अधिकांश बांड जारीकर्ता /गारंटर को स्थगन के लिए पूरी तरह से अपात्र बनाते हैं

²⁵ एक उल्लेखनीय अपवाद के लिए, री पोर्ट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड देखें, जिसमें योजना कंपनी ने पहले नोटधारकों के तदर्थ समूह का समर्थन प्राप्त किए बिना व्यवस्था की एक योजना शुरू की थी, और आयोजित सुनवाई के बाद व्यवस्था की अपनी योजना को वापस लेने के लिए मजबूर किया गया था।

²⁶ उदाहरण के लिए सी एसेट्स लिमिटेड बनाम पीटी गरुड इंडोनेशिया (नंबर 2) [2001] 6 डब्ल्यूएलयूके 583; ब्लूक्रेस्ट मर्कटाइल बीवी वी वियतनाम शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप एफएमएस वर्टमैनेजमेंट एओआर वी वियतनाम शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप [2013] ईडब्ल्यूएचसी 1146 (कॉम); और रिवरसाइड CREM 3 लिमिटेड बनाम वर्जिन एक्टिव हेल्थ क्लब लिमिटेड [2021] EWHC 746 (Ch) (पुनर्गठन योजना के संदर्भ में)।

²⁷ कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी एंड गवर्नेंस एक्ट 2020 की धारा 1 ने इन्सॉल्वेंसी एक्ट 1986 में एक नया भाग A1 डाला।

(ii) बैंक सुविधाओं के संबंध में कोई भुगतान अवकाश नहीं है (या वित्तीय सेवाओं से जुड़े अनुबंध के तहत उत्पन्न होने वाले अन्य ऋण या देनदारियां)²⁸;

(iii) अधिस्थगन की प्रारंभिक अवधि - 20 व्यावसायिक दिन - यह अवधि सुरक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत कम है जितना एक योजना को लागू करने में लगता है (हालांकि वहां विभिन्न विकल्प मौजूद हैं, जिनके द्वारा अधिस्थगन अवधि को बढ़ाया जा सकता है); और

(iv) अधिस्थगन के दौरान त्वरण की अनुमति है और व्यवहारिक रूप से अधिस्थगन को समाप्त करने में इसकी संभावित आवश्यकता है।

संविधान

2.9 आयोजित सुनवाई में, अदालत इस बात पर विचार करेगी कि क्या लेनदारों (और/या सदस्यों) की एक से अधिक बैठकों की आवश्यकता है, और यदि ऐसा है तो उन बैठकों की उपयुक्त संरचना क्या है।²⁹

2.10 वर्ग गठन के लिए लंबे समय से स्थापित सिद्धांत यह है कि एक वर्ग को उन व्यक्तियों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए जिनके अधिकार इतने भिन्न नहीं हैं कि उनके लिए अपने सामान्य हित की दृष्टि से एक साथ परामर्श करना असंभव बना दे³⁰। "प्रत्येक मामले में उस प्रश्न का उत्तर उन अधिकारों के विश्लेषण- (i) पर निर्भर करेगा जिन्हें योजना के तहत जारी किया जाना है या उनमें बदलाव किया जाना है और (ii) नए अधिकार (यदि कोई हैं) जो योजना समझौता के माध्यम से देती है। या व्यवस्था, उन लोगों के लिए जिनके अधिकारों को जारी किया जाना है या उनमें बदलाव किया जाना है।"³¹ उस अभ्यास को करने में, यह लेनदारों के कानूनी अधिकार हैं, न कि उनके अलग वाणिज्यिक या अन्य हित, जो एक वर्ग के उपयुक्त संविधान को निर्धारित करते हैं।³² (स्वीकृति के स्तर पर इसके बजाय हितों को ध्यान में रखा जा सकता है।)

²⁸ दिवाला अधिनियम 1986 की धारा A18(3)(f) (संशोधित)।

²⁹ प्रैक्टिस स्टेटमेंट का पैराग्राफ 11 (कंपनियां: कंपनी अधिनियम 2006 के भाग 26 और भाग 26ए के तहत व्यवस्था की योजनाएं)।

³⁰ सॉवरेन लाइफ एश्योरेंस बनाम डोड [1892] 2 क्यूबी 573 [583] और रे यूडीएल होल्डिंग्स लिमिटेड [2002] 1 एचकेसी 172 [27] प्रति लॉर्ड मिलेट एनपीजे देखें।

³¹ रे हॉक इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड [2002] बीसीसी 300 [30] में प्रति चाडविक एलजे।

³² रे बीटीआर पीएलसी [1999] 2 बीसीएलसी 675, रे हॉक इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड [2001] 2 बीसीएलसी 480, रे यूडीएल होल्डिंग्स लिमिटेड [2002] 1 एचकेसी 172 184-185 प्रति लॉर्ड मिलेट एनपीजे।

2.11 अल्पसंख्यक समूह को वीटो का अनुचित अधिकार देने के जोखिम को देखते हुए अधिकारियों ने वर्गों के अनावश्यक प्रसार के प्रति भी सावधानी बरती है। जहां अधिकार दूसरों के अधिकारों के "पर्याप्त रूप से समान" हैं कि वे एक साथ उचित रूप से परामर्श कर सकते हैं, तो उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता होनी चाहिए।³³ जहां एक योजना को समापन के विकल्प के रूप में प्रस्तावित किया जाता है, सही दृष्टिकोण इस आधार पर स्थिति पर विचार करना है कि प्रासंगिक अधिकार वे हैं जो लेनदारों के पास समापन में होंगे।³⁴

2.12 वर्ग संविधान के मुद्दों पर मामला कानून बहुत व्यापक है, जिसका विस्तृत विवरण इस लेख के दायरे से बाहर है।

वर्तमान उद्देश्यों के लिए, यह नोट करना पर्याप्त है कि अदालतें ऐतिहासिक रूप से "वर्ग को भंग करने" के लिए धीमी रही हैं और, अवसर पर, संभावित वर्ग के मुद्दों को हल करने के लिए व्यावहारिक समाधानों पर विचार किया है।³⁵

एक असंतुष्ट वर्ग को बांधने में असमर्थता

2.13 जैसा कि उल्लेख किया गया है, प्रत्येक वर्ग में अपेक्षित बहुमत को ब्रिटिश योजना की एक व्यवस्था को मंजूरी देनी चाहिए, इससे पहले कि अदालत को इसे मंजूरी देने के लिए कहा जाए। अकेले योजनाएँ "पैसे से बाहर" कनिष्ठ हितधारकों के "क्रैमडाउन" को प्राप्त नहीं कर सकती हैं; इसमें नियंत्रण या इक्विटी कमजोर पड़ने का एक गैर-सहमति परिवर्तन शामिल है (क्योंकि शेयरधारकों के पास आमतौर पर नए शेयर जारी करने के संबंध में पूर्व-खाली अधिकार होते हैं, जो कि ऋण-के-इक्विटी स्वैप को इंजीनियर करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, और शेयरधारक वर्ग के पास योजना में शामिल होने पर वीटो की एक शक्ति होगी।

³³ रे हॉक इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड [2002] बीसीसी 300 [32] और [33]।

³⁴ वही [42] पर।

³⁵ उदाहरण के लिए, रे स्टैमकोर ट्रेड फाइनेंस लिमिटेड [2015] ईडब्ल्यूएचसी 2662 (सीएच) में [21]-[22], संभावित चिंताओं से बचने के लिए कंपनी को अपने प्रस्तावित वर्ग संविधान को समायोजित करने की अनुमति देता है कि कुछ अलग के साथ एक "एंकर शेयरधारक" पुनर्गठन के बाद के अधिकारों को एक अलग वर्ग का गठन करना चाहिए (और इस तरह एक विरोधी लेनदार द्वारा मंजूरी पर किसी भी तर्क से बचना चाहिए कि उनके वोट उस वर्ग के भीतर एंकर शेयरधारक के अनुचित समावेश से अधिक हो गए थे)।

2.14 तदनुसार, मौजूदा शेयरधारक सहमति या कुछ अन्य समाधान की आवश्यकता हो सकती है, जैसे:

(a) पूर्व-पैक प्रशासन बिक्री के साथ व्यवस्था की एक योजना (किसी भी बाध्य वरिष्ठ लेनदारों के लिए) को जोड़ना ओल्डको की सहायक कंपनियों में न्यूको के शेयर, अक्सर वरिष्ठ लेनदारों के बहुमत के स्वामित्व वाले होते हैं, जिससे ओल्डको में "पैसे से बाहर" जूनियर लेनदारों और/या इक्विटी को पीछे छोड़ दिया जाता है (जो प्रभावी रूप से एक बेकार खोल बन जाता है); न्यूको हस्तांतरित संपत्तियों के लिए वरिष्ठ लेनदारों के दावों को "क्रेडिट बिडिंग" द्वारा भुगतान करता है। इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, उदाहरण- MyTravel³⁶, IMO Carwash³⁷, McCarthy and Stone³⁸, WIND Hellas³⁹ और हाल ही में Swissport⁴⁰;

(b) रिसीवरशिप या शेयर प्रतिज्ञा प्रवर्तन के माध्यम से एक समान परिणाम प्राप्त करना; या

(सी) नई पुनर्गठन योजना प्रक्रिया का उपयोग, जिसके द्वारा अदालत एक ऐसी योजना को मंजूरी दे सकती है जिसे हर वर्ग ने मंजूरी नहीं दी है (कुछ शर्तों के अधीन)। केवल संभावना है कि असहमति वाले वर्ग बाध्य हो सकते हैं स्वाभाविक रूप से बातचीत को प्रभावित करते हैं। जिन मामलों में

अदालत ने आज तक एक असंतुष्ट वर्ग को बाध्य करने की अपनी शक्ति का प्रयोग किया है, वे हैं डीपओशियन⁴¹, स्माइल टेलीकॉम⁴², वर्जिन एक्टिव⁴³ और एमिकस फाइनेंस⁴⁴।

³⁶ *Re Mytravel Group plc* [2004] EWHC 2741 (Ch) (convening); [2005] 1 WLR 2365 (sanction)

³⁷ *Re Bluebrook Ltd and others* [2009] EWHC 2114 (Ch) (sanction)

³⁸ *Re McCarthy & Stone plc and another* [2009] EWHC 712 (Ch) (convening); [2009] EWHC 1116 (Ch) (sanction)

³⁹ *Re Hellas Telecommunications (Luxembourg) II SCA* [2009] EWHC 3199 (Ch) (administration application)

⁴⁰ *Re Swissport Fuelling Ltd* [2020] EWHC 1499 (Ch) (convening); [2020] EWHC 1773 (Ch) (sanction)

⁴¹ *Re DeepOcean I UK Ltd and others* [2021] EWHC 138 (Ch) (sanction)

⁴² *Re Smile Telecoms Holdings Ltd* [2021] EWHC 685 (Ch) (sanction)

⁴³ *Re Virgin Active Holdings Ltd and others* [2021] EWHC 1246 (Ch) (sanction)

⁴⁴ *Re Amicus Finance plc (in administration)* [2021] EWHC 3036 (Ch) (sanction)

समय

2.15 कानून व्यवस्था की योजनाओं के लिए स्पष्ट रूप से समयरेखा प्रदान नहीं करता है। हाल ही में एक न्यायिक अभ्यास वक्तव्य⁴⁵ में कहा गया है कि व्यवस्था की योजना (या पुनर्गठन योजना) के लिए आवेदक को, सुनवाई आयोजित करने से पहले, "योजना से प्रभावित किसी भी व्यक्ति को सूचित करने के लिए उचित रूप से खुले सभी कदम उठाने चाहिए" से संबंधित विभिन्न मामलों के बारे में योजना। जब तक अन्यथा अच्छे कारण न हों, इस तरह की नोटिस "योजना से प्रभावित व्यक्तियों को पर्याप्त समय में दी जानी चाहिए ताकि वे प्रस्ताव पर विचार कर सकें, उचित सलाह ले सकें और यदि सलाह दी जाती है, तो आयोजित सुनवाई में भाग ले सकें। पर्याप्त नोटिस क्या है यह सभी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

2.16 यह (a) वित्तीय रूप से परेशान देनदारों को अपने ऋण को तेजी से और कुशलता से पुनर्गठित करने की अनुमति देने और (b) प्रभावित लेनदारों को देनदार की योजनाओं के बारे में पर्याप्त नोटिस प्राप्त करने के बीच अदालत में पेश होने का एक प्रभावी अवसर पाने के लिए दर्शाता है।

200

2.17 संतुलन बनाने का प्रयास करते हुए, ब्रिटिश अदालत ने माना है कि:

(a) "पर्याप्त नोटिस क्या है यह सभी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। योजना जितनी अधिक जटिल या नवीन होगी, और योजना शुरू होने से पहले लेनदारों के साथ कम परामर्श किया गया है, उतना ही लंबा नोटिस आम तौर पर होना चाहिए।

(b) जब कंपनी वास्तविक वित्तीय संकट में हो एवं योजना को अत्यंत अत्यावश्यकता के रूप में आगे रखा जा रहा है, तो किसी चूक से बचने के लिए लेनदारों को बहुत अधिक सूचना देने का समय नहीं होता है ऐसे मामले में स्कीम कंपनी अदालत को यह समझाने में सक्षम हो सकती है कि नोटिस की अवधि को कम करने या प्रैक्टिस स्टेटमेंट से पूरी तरह से प्रस्थान करने का अच्छा कारण है; और ऐसे मामले में, किसी भी विरोधी लेनदार के पास एक अच्छा कारण होगा कि वह मंजूरी की सुनवाई से पहले एक वर्ग या क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्न उठाने में असमर्थ क्यों था। (c) लेकिन वास्तविक तात्कालिकता के साक्ष्य के अभाव में, प्रैक्टिस स्टेटमेंट होना चाहिए योजना लेनदारों को मामले पर विचार करने, सलाह लेने और, यदि वांछित हो, तो सुनवाई में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए आयोजित सुनवाई की पर्याप्त अवधि का पालन किया गया और नोटिस दिया गया

⁴⁵ प्रैक्टिस स्टेटमेंट (कंपनियां: कंपनी अधिनियम 2006 के भाग 26 और भाग 26ए के तहत व्यवस्था की योजनाएं, 30 जून 2020 से प्रभावी।

... अपर्याप्त सूचना पर एक जटिल या नई योजना के संबंध में एक आयोजित सुनवाई के अंतर्गत अदालत को लेनदारों के "बाउंस" करने के किसी भी प्रयास का पता लगाने के लिए अत्यधिक चपल होना चाहिए।⁴⁶

(d) "लेनदारों के साथ किसी भी पूर्व जुड़ाव की सीमा, लेनदारों के प्रासंगिक परिष्कार और कंपनी के किसी भी वित्तीय संकट की सीमा और, इस प्रकार, पुनर्गठन की तात्कालिकता उपयुक्त समय अवधि के लिए प्रासंगिक सभी कारक हैं।⁴⁷" कम नोटिस की आवश्यकता हो सकती है जहां निवेशक यथोचित रूप से परिष्कृत होते हैं (विशेषकर जहां देनदार को आसन्न वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है)। अधिकांश संकटग्रस्त योजनाओं में परिष्कृत वित्तीय लेनदार शामिल हैं⁴⁸। (यह पुनर्चना योजनाओं के साथ एक दिलचस्प अंतर पैदा करता है, क्योंकि असंतुष्ट वर्ग(वर्गों) को बाध्य करने की क्षमता पुनर्चना योजना के भीतर लेनदारों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करने की संभावना को खोलती है।)

(e) जहां लेनदारों के एक तदर्थ समूह ने पुनर्गठन शर्तों पर बातचीत की है किसी भी प्रस्ताव को लेनदारों के सामने रखे जाने से पहले, अदालत यह सुनिश्चित करने के लिए चिंतित रहेगी कि प्रभावित लेनदारों के व्यापक निकाय को पर्याप्त नोटिस दिया जाए। "आयोजन सुनवाई के लेनदारों को पर्याप्त नोटिस देने की आवश्यकता का व्यवहार में लेनदारों को नोटिस देने से कोई लेना-देना नहीं है जो पहले से ही किसी योजना पर बातचीत करने में शामिल हैं और / या जो पहले से ही योजना का समर्थन करने के लिए बंद हैं। आयोजन की सुनवाई की सूचना देने की आवश्यकता प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने और अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक शक्ति के उपयोग से उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए अदालत की आवश्यक भूमिका का हिस्सा है, जिसमें व्यवस्था की एक योजना अनिवार्य रूप से शामिल है। ...वह सुनवाई आयोजित करने के नोटिस की पर्याप्तता का सवाल इसलिए लेनदारों से योजना के समर्थन के स्तर से प्रभावित नहीं है जो पहले ही बंद हो चुके हैं। यह उन लोगों की स्थिति के संदर्भ में आंका जाता है, जिन्होंने लॉक नहीं किया है और जो

⁴⁶ रे इंडा किआट इंटरनेशनल फाइनेंस कंपनी बीवी [2016] बीसीसी 418 पर [28]-[30] प्रति स्नोडेन जे (जैसा वह तब था)।

⁴⁷ रे एमएबी लीजिंग लिमिटेड [2021] ईडब्ल्यूएचसी 152 (सीएच) प्रति जकारोली जे; यह भी देखें NN2 Newco Ltd [2019] EWHC 1917 (Ch) पर [22]-[23] प्रति नॉरिस जे।

⁴⁸ उल्लेखनीय अपवादों में उपभोक्ता निवारण लेनदारों की योजनाएं शामिल हैं (जैसे एमिगो लोन्स, रे ऑल स्कीम लिमिटेड [2021] ईडब्ल्यूएचसी 1002 (सीएच) (संयोजन) और [2021] ईडब्ल्यूएचसी 1401 (च) (मंजूरी) और प्रोविडेंट फाइनेंस, रे प्रोविडेंट एसपीवी लिमिटेड [2021]] EWHC 1341 (आयोजन) और [2021] EWHC 2217 (Ch) (मंजूरी)।

कंपनी द्वारा प्रस्तावित वर्गों के निर्माण का विरोध करना चाहते हैं।⁴⁹ ”

2.18 जहां अदालत संतुष्ट नहीं है कि योजना लेनदारों को पर्याप्त समय दिया गया है (उन्हें इस पर विचार करने के लिए सक्षम करने के लिए, उचित सलाह लेने के लिए और, यदि ऐसा सलाह दी जाती है, तो उपस्थित होने और आयोजित सुनवाई में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए), अदालत की व्यावहारिक प्रतिक्रिया भिन्न हो सकते हैं। यह हो सकता है:

(a) योजना लेनदारों को अलग-अलग आवेदन करने या संयोजक आदेश को अलग करने के लिए स्वतंत्रता दें,⁵⁰

(b) निर्देश दें कि योजना लेनदारों को मंजूरी सुनवाई में किसी भी प्रासंगिक मुद्दे को उठाने का अधिकार है; या⁵¹

(c) सबसे अधिक (और इसलिए अत्यधिक असामान्य रूप से), आयोजित सुनवाई में योजना की बैठकें बुलाने से इनकार करते हैं।⁵²

प्रकटीकरण की पर्याप्तता

2.19 (a) यह सुनिश्चित करने के बीच परेशानी हो सकती है कि (a) योजना लेनदारों को प्रस्तावित योजना के बारे में पर्याप्त स्तर की जानकारी प्राप्त हो और (b) वित्तीय रूप से परेशान देनदारों पर अत्यधिक-भारी प्रकटीकरण दायित्वों को लागू करने से बचना (कार्यान्वयन लागत और समय पर परिणामी प्रभाव के साथ)

⁴⁹ रे कलरऑज इन्वेस्टमेंट 2 एलएलसी और अन्य [2020] ईडब्ल्यूएचसी 1864 (सीएच) पर [46]-[47], प्रति स्नोडेन जे (जैसा वह तब था)।

⁵⁰ Re ColourOz Investment 2 LLC [2020] EWHC 1864 (Ch) के रूप में

⁵¹ अर्थात्- योजना लेनदारों पर प्रैक्टिस स्टेटमेंट के पैराग्राफ 10 में पहचाने गए प्रतिबंधों के अधीन नहीं होगा, जिसके तहत एक योजना लेनदार जो मंजूरी सुनवाई पर आपत्तियां उठाती है, जो आम तौर पर आयोजित सुनवाई में निर्धारित की जाएगी, से अच्छे कारण दिखाने की उम्मीद की जाएगी इसने इस मुद्दे को पहले चरण में क्यों नहीं उठाया। यह री स्विसपोर्ट फ्यूलिंग लिमिटेड [2020] ईडब्ल्यूएचसी 1499 (सीएच), रे हेमा यूके आई लिमिटेड [2020] ईडब्ल्यूएचसी 2219 (सीएच) और री पोर्ट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड [2021] ईडब्ल्यूएचसी 378 (सीएच) में अपनाया गया दृष्टिकोण था।

⁵² जैसा कि रे इंदह कीट इंटरनेशनल फाइनेंस कंपनी बी.वी. [2016] ईडब्ल्यूएचसी 246 (सीएच) में, जिसमें अपर्याप्त नोटिस, अपर्याप्त प्रकटीकरण और प्रस्तावित योजना के साथ अन्य मुद्दों के आधार पर आयोजित सुनवाई स्थगित कर दी गई थी।

2.20 प्रैक्टिस स्टेटमेंट में प्रावधान है कि व्याख्यात्मक बयान "सदस्य और/या लेनदार निर्वाचन क्षेत्र की प्रकृति सहित मामले की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त रूप और शैली में होना चाहिए, और परिस्थितियों के अनुसार संक्षिप्त होना चाहिए। ... योजना के वाणिज्यिक प्रभाव को स्पष्ट किया जाना चाहिए और सदस्यों और/या लेनदारों को ऐसी जानकारी प्रदान की जानी चाहिए जो उन्हें इस बारे में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए उचित रूप से आवश्यक हो कि योजना उनके हित में है या नहीं, और कैसे करना है योजना पर वोट करें। अदालत आयोजित सुनवाई में व्याख्यात्मक बयान की पर्याप्तता पर विचार करेगी। अदालत बैठक का आदेश देने से इंकार कर सकती है यदि वह समझता है कि व्याख्यात्मक विवरण उचित रूप में नहीं है। हालांकि, अदालत आयोजित सुनवाई में व्याख्यात्मक बयान को मंजूरी नहीं देगी, और यह योजना से प्रभावित किसी भी व्यक्ति के लिए मंजूरी सुनवाई में इसकी पर्याप्तता के मुद्दों को उठाने के लिए खुला रहेगा।"⁵³

2.21 उदाहरण के लिए जहां एक व्याख्यात्मक बयान की कमी पर विचार किया गया था, वहां इंदह किआट⁵⁴, सनबर्ड⁵⁵ और अमीगो⁵⁶ ऋण देखें।

2.22 एक और परेशानी उत्पन्न हो सकती है है जहां प्रासंगिक जानकारी अत्यधिक व्यावसायिक रूप से संवेदनशील होती है। "ऐसे मामले होंगे जिनमें जानकारी के प्रावधान के बीच एक कठिन संतुलन है, जिसके साथ लेनदारों को प्रदान करना उचित रूप से आवश्यक है, और गोपनीय जानकारी का खुलासा जो व्यापार पर एक महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।"⁵⁷

⁵³ प्रैक्टिस स्टेटमेंट के पैराग्राफ 14 और 15 (कंपनियां: कंपनी अधिनियम 2006 के भाग 26 और भाग 26 ए के तहत व्यवस्था की योजनाएं।

⁵⁴ रे इंडा किआट इंटरनेशनल फाइनेंस कंपनी बीवी [2016] ईडब्ल्यूएचसी 246 (सीएच), जिसमें स्नोडेन जे (तब वह थे) ने योजना बैठकें बुलाने से इनकार कर दिया।

⁵⁵ रे सनबर्ड बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड [2020] ईडब्ल्यूएचसी 2493 (सीएच), जिसमें स्नोडेन जे (जैसा कि वह तब था) ने इस आधार पर योजना को मंजूरी देने से इनकार कर दिया कि वह संतुष्ट नहीं थे कि एक उचित लेनदार एक सूचित निर्णय ले सकता था कि क्या योजना उसके हित में थी। (कंपनी हालांकि एक योजना में अपने दूसरे प्रयास में सफल रही: [2020] EWHC 3459 (Ch)।

⁵⁶ रे ऑल स्कीम लिमिटेड [2021] ईडब्ल्यूएचसी 1401 (सीएच) को [132-136] पर देखें, जिसमें माइल्स जे ने कहा कि योजना का व्याख्यात्मक विवरण योजना के लेनदारों को योजना के बारे में सूचित करने के लिए अपर्याप्त था और एक द्विआधारी प्रस्तुत करने में इसके यथार्थवादी विकल्प थे। योजना लेनदारों के लिए विकल्प और यह स्पष्ट नहीं करना कि किस आधार पर शेयरधारकों को अपना पूर्ण इक्विटी ब्याज बनाए रखना था (जबकि योजना लेनदार - उपभोक्ता निवारण दावेदार - 90% बाल काट रहे थे)।

⁵⁷ री स्माइल टेलीकॉम होल्डिंग्स लिमिटेड [2021] EWHC 395 (Ch) [49] पर, प्रति Trower J, एक पुनर्गठन योजना के संदर्भ में।

2.23 इस मुद्दे का एक व्यावहारिक समाधान - जो सूचना के प्रवाह को अनुचित रूप से बाधित होने से बचाता है - योजना लेनदारों⁵⁸ या उनके सलाहकारों⁵⁹ द्वारा एक साधारण लिखित गोपनीयता उपक्रम में प्रवेश है।

एसएमई/SMEs द्वारा उपयोग

2.24 व्यवस्था की योजनाएँ छोटे या मध्यम आकार के उद्यमों द्वारा उपयोग के लिए प्रत्यक्ष रूप से महंगी मानी जाती हैं (विशेषकर दो अदालती सुनवाई की आवश्यकता के आलोक में और संभावना है कि योजना कंपनी को किसी चुनौती की कुछ या सभी लागतों का भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है) - नीचे पैराग्राफ 2.36 से 2.38 देखें।

2.25 तदनुसार, एसएमई द्वारा योजनाओं का उपयोग दुर्लभ है; उल्लेखनीय अपवादों के लिए, सनबर्ड⁶⁰ देखें (यह देखते हुए कि कंपनी एक योजना में अपने पहले प्रयास में असफल रही) और, एक पुनर्गठन योजना के संदर्भ में, एमिकस फाइनेंस⁶¹।

204

2.26 योजनाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं (और, इससे भी अधिक) इसलिए, एसएमई द्वारा नई पुनर्गठन योजना। उदाहरण के लिए, ऊपर दिए गए पैराग्राफ 2.15 में उद्धृत प्रैक्टिस स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट इस संभावना को स्वीकार करता है कि "लाइटर टच" प्रलेखन परिष्कृत योजना लेनदारों से जुड़े सरल मामलों के लिए उपयुक्त हो सकता है, हालांकि इसे सावधानी के साथ संपर्क किया जाना चाहिए। एसएमई द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध कराए जाने के लिए टेम्पलेट पुनर्गठन योजना दस्तावेज तैयार करने के प्रयास भी चल रहे हैं।

तृतीय पक्ष विज्ञप्ति

2.27 व्यवस्था की योजनाओं के लिए तीसरे पक्ष के खिलाफ योजना लेनदारों के दावों को जारी करना आम बात है। प्रासंगिक तृतीय पक्षों में संभावित रूप से देनदार से संबंधित पक्ष (जैसे समूह

⁵⁸ जैसा कि री स्माइल टेलीकॉम होल्डिंग्स लिमिटेड [2021] ईडब्ल्यूएचसी 395 (सीएच) में [50]-[51], एक पुनर्गठन योजना के संदर्भ में।

⁵⁹ जैसा कि वर्जिन एक्टिव होल्डिंग्स लिमिटेड और अन्य [2021] ईडब्ल्यूएचसी 814 (सीएच) में, एक पुनर्गठन योजना के संदर्भ में।

⁶⁰ रे सनबर्ड बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड [2020] EWHC 2493 (Ch) (मंजूरी अस्वीकृत) और [2020] EWHC 3459 (Ch) (मंजूरी दी गई)।

⁶¹ रे एमिकस फाइनेंस पीएलसी (प्रशासन में) [2021] ईडब्ल्यूएचसी 2255 (सीएच) (आयोजन) और [2021] ईडब्ल्यूएचसी 3036 (सीएच) (मंजूरी)।

इकाइयां, शेयरधारक, निदेशक और अधिकारी या दिवाला कार्यालयधारक) और गैर-संबद्ध (जैसे कानूनी और वित्तीय सलाहकार, लेखा परीक्षक या बीमाकर्ता) शामिल हैं। जारी किए जाने वाले दावे संविदात्मक या कपटपूर्ण दावे हो सकते हैं और सुरक्षित या असुरक्षित हो सकते हैं।

2.28 अदालत ने व्यवस्था की एक योजना को मंजूरी देने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त किया है जो लेनदारों के दावों को तीसरे पक्ष के खिलाफ जारी करता है जो लेनदारों के समान नुकसान की वसूली के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। कंपनी के खिलाफ दावे - जैसे कि रिलीज कंपनी और उसके अपने लेनदारों के बीच व्यवस्था के लिए "केवल सहायक" है, और / या व्यवस्था को प्रभावी करने के लिए रिलीज "आवश्यक" है।⁶² वह परीक्षण सबसे स्पष्ट रूप से संतुष्ट है जहां योजना/योजना गारंटीकृत ऋणों से समझौता करती है और जहां, इस तरह की रिहाई के अभाव में, योजना(scheme)/योजना(plan) लेनदार द्वारा गारंटर की खोज (एक तथाकथित "रिकोशेट दावा") के बीच समझौता कमजोर होगा।

205

2.29 अदालत ने यह भी पाया है कि व्यवस्था की एक योजना को मंजूरी देने का अधिकार क्षेत्र है जो योजना / पुनर्गठन योजना और उनके कानूनी सलाहकारों की तैयारी, बातचीत या कार्यान्वयन में शामिल पक्षों के खिलाफ दावों को जारी करता है। अदालत ने माना है कि इस तरह के खंडों को योजना के लेनदारों को योजना की शर्तों को कम करने की अनुमति नहीं देने की आवश्यकता के द्वारा उचित ठहराया जा सकता है, और जो योजनाओं की एक नियमित विशेषता बन गई है।⁶³

2.30 इसके विपरीत, अदालत ने माना है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में तीसरे पक्ष के खिलाफ लेनदारों के दावों को जारी करने वाली व्यवस्था की एक योजना को मंजूरी देने का उसके पास अधिकार क्षेत्र नहीं है:-

(a) तीसरे पक्ष के खिलाफ अधिक मूर्त दावे- अदालत द्वारा दिए गए एक काल्पनिक उदाहरण लेने के लिए⁶⁴: एक स्वतंत्र वित्तीय के खिलाफ लापरवाही में एक योजना लेनदार द्वारा दावा

⁶² रे लेहमैन ब्रदर्स इंटरनेशनल (यूरोप) (प्रशासन में) [2009] ईडब्ल्यूसीए सीआईवी 1161 [63] और [65]; रे नोबल ग्रुप लिमिटेड [2018] ईडब्ल्यूसीए 3092 (सीएच) [24] और री इंस्टेंट कैश लोन्स लिमिटेड [2019] ईडब्ल्यूसीए 2795 (च) [24] भी देखें। इस बात पर कुछ बहस है कि क्या रिलीज के लिए "केवल सहायक" और "आवश्यक" दोनों होना आवश्यक है, या क्या यह "केवल सहायक" या "आवश्यक" हो सकता है। यह री गेटग्रुप गारंटी लिमिटेड [2021] ईडब्ल्यूसीए 304 (सीएच) में एक पुनर्गठन योजना के संदर्भ में उठाया गया था, लेकिन अंततः परीक्षण नहीं किया गया था।

⁶³ रे फार ईस्ट कैपिटल एसए [2017] ईडब्ल्यूसीए 2878 (च) [14] पर; रे नोबल ग्रुप लिमिटेड [2018] EWHC 3092 (Ch) [25] पर

⁶⁴ रे नोबल ग्रुप लिमिटेड [2018] EWHC 3092 (Ch) [26]

सलाहकार जिसने पहली बार में निवेश खरीदने के प्रति आगाह नहीं किया था, जिसका उद्देश्य निवेश के लिए भुगतान की गई मूल राशि और योजना के तहत प्रदान किए गए प्रतिफल के बीच अंतर की भरपाई करना था; और

(b) देनदार द्वारा उनकी ओर से ट्रस्ट पर रखी गई संपत्ति पर लेनदारों का मालिकाना अधिकार, क्योंकि यह देनदार के ऋण या दायित्व के संबंध में दावा नहीं है⁶⁵।

2.31 तदनुसार, व्यवहार में, यदि अदालत तीसरे पक्ष के रिलीज के मुद्दे पर बिल्कुल भी विचार करती है, तो इस पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है:

(a) क्या व्यवस्था को प्रभावी करने के लिए रिलीज "आवश्यक" हैं;

(b) क्या रिलीज कंपनी और उसके लेनदारों के बीच व्यवस्था के लिए "केवल सहायक" हैं;

(c) क्या तीसरे पक्ष के खिलाफ दावे योजना / योजना के तहत समझौता किए जाने वाले देनदार के खिलाफ मूल दावों से "निकट रूप से जुड़े" हैं; और

(d) क्या रिलीज नहीं देने से योजना/योजना लेनदारों को योजना/योजना की शर्तों को कमजोर करने की अनुमति मिल जाएगी।

2.32 इस तरह की रिलीज स्वचालित रूप से तीसरे पक्ष के खिलाफ लेनदारों के अधिकारों को परिवर्तित नहीं करती है। इसके बजाय, इस योजना में प्रासंगिक तृतीय पक्ष रिलीज को प्रभावित करने और तीसरे पक्ष को उनसे लाभान्वित करने के लिए एक कानूनी तंत्र शामिल होना चाहिए, जैसे:

(a) योजना की अवधि के लिए लेनदारों की ओर से एक वकील की नियुक्ति होगी उन कामों को करने के लिए जो योजना उन्हें करने के लिए बाध्य करती है; या (b) कंपनी के पक्ष में लेनदार द्वारा एक वाचा, तीसरे पक्ष के खिलाफ अधिकारों को जारी करने या बदलने के लिए, जो कि योजना की मंजूरी के बाद गैर-अनुमति देने वाले लेनदारों सहित कंपनी द्वारा अपने लेनदारों के खिलाफ लागू करने योग्य है।⁶⁶

⁶⁵ रे लेहमैन ब्रदर्स इंटरनेशनल (यूरोप) (प्रशासन में) [2009] EWCA Civ 1161

⁶⁶ रीगेटगुप गारंटी लिमिटेड [2021] ईडब्ल्यूएचसी 304 (सीएच) को [36-38] पर देखें, एक पुनर्गठन योजना के संदर्भ में।

अंतिम लाभकारी धारकों द्वारा मतदान

2.33 योजना ऋण में आमतौर पर वैश्विक रूप में जारी किए गए नोट शामिल होते हैं, जहां नोटों का कानूनी स्वामित्व पंजीकरण से गुजरता है और कानूनी मालिक एक सामान्य जमाकर्ता का नामिती होता है। इसलिए, एक प्रश्न उठता है कि क्या वैश्विक नोट का कानूनी स्वामी एकमात्र लेनदार है जिसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, या क्या अंतर्निहित लाभकारी नोटधारकों के पास यह अधिकार होना चाहिए।

2.34 यह मुद्दा कई योजनाओं में उत्पन्न हुआ है। अदालतों का मानना है कि एक योजना "स्पष्ट रूप से उन लोगों द्वारा विचार की जानी चाहिए जिनके पास ऋण में आर्थिक हित है, यानी अंतिम लाभकारी मालिक या मूलधन द्वारा"।⁶⁷ अब यह अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि यदि संबंधित उपकरण प्रदान करते हैं कि लाभकारी नोटधारक कुछ (यहां तक कि दूरस्थ) परिस्थितियों⁶⁸ में जारीकर्ता के खिलाफ प्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, तो अंतर्निहित लाभकारी नोटधारकों को कंपनी के "आकस्मिक लेनदारों" के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है⁶⁹, और व्यवस्था उन्हें वोट देने में सक्षम बनाने के लिए बनाया जाना चाहिए ताकि ऋण में अंतिम आर्थिक हित वाले लोगों को मताधिकार दिया जा सके।⁷⁰

⁶⁷ रे कैसल होल्डको 4 लिमिटेड और अन्य [2009] EWHC 3919 (Ch) [23] पर।

⁶⁸ अर्थात् एक निश्चित नोट जारी करने का आह्वान करते हुए, चूंकि एक निश्चित नोट जारीकर्ता द्वारा अंतिम लाभकारी स्वामी को देय प्रत्यक्ष भुगतान दायित्व का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसने कानूनी शीर्षक के लिए अपने लाभकारी हित का प्रभावी ढंग से आदान-प्रदान किया होगा।

⁶⁹ आकस्मिक लेनदारों को एक योजना के प्रयोजनों के लिए लेनदारों की परिभाषा में शामिल किया गया है: रे टी एंड एन लिमिटेड और अन्य देखें [2005] ईडब्ल्यूएचसी 2870 (सीएच)।

⁷⁰ उदा. सहित अनेक मामलों में अपनाए गए दृष्टिकोण रे द को-ऑपरेटिव बैंक पीएलसी [2013] EWHC 4072 (Ch) [36]-[40], रे नोबल ग्रुप लिमिटेड [2018] EWHC 2911 (Ch) [161]-[164], रे पेद्रा डायमंड्स US\$ ट्रेजरी पीएलसी [2020] ईडब्ल्यूएचसी 3565 (च) [16] और रे कैसल ट्रस्ट डायरेक्ट पीएलसी और अन्य [2020] ईडब्ल्यूएचसी 969 (च) [20]-[23]।

2.35 संबंधित व्यावहारिक बिंदुओं (नोबल⁷¹ और अन्य मामलों में सचित्र) में शामिल हैं:

(a) नोट्स ट्रस्टी योजना की बैठकों में मतदान नहीं करने का वचन दे सकते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई दोहरी गिनती नहीं है;

(b) एक ही ऋण के संबंध में एक से अधिक लेनदारों द्वारा वोट दिए जाने की स्थिति में, बैठक के अध्यक्ष को केवल उस व्यक्ति के वोटों की गणना करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है जिसके पास उस ऋण में अंतिम आर्थिक हित है; और

(c) जहां एक खाता सहभागी अपने स्वयं के खाते पर और/या एक या अधिक अंतिम लाभकारी स्वामियों की ओर से नोटों में रुचि रखता है, खाते के प्रतिभागी के वोटों को अंतर्निहित लाभकारी स्वामियों के वोटों को दर्शाने के लिए विभाजित किया जा सकता है।

208

एक असफल चुनौती की कीमत किसे वहन करनी चाहिए?

2.36 पिछले कुछ वर्षों में, औपचारिक चुनौती का सामना करने वाली योजनाओं के अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सफल चुनौतियाँ फिर भी दुर्लभ हैं।⁷²

2.37 ब्रिटिश मुकदमेबाजी में सामान्य नियम यह है कि लागत आमतौर पर घटना का अनुसरण करती है, अर्थात् "हारने वाला भुगतान करता है"। हालाँकि, पार्टियों की लागत का पुरस्कार अदालत के विवेक के लिए एक मामला है। एक योजना के संदर्भ में, परेशानी स्पष्ट है: आर्थिक रूप से संकटग्रस्त योजना कंपनी आमतौर पर "सफल" होती है और यह तर्क देगी कि उसे आमतौर पर "असफल" प्रतिद्वंद्वी की लागत का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, फिर भी प्रतिद्वंद्वीके तर्क वास्तविक और अदालत द्वारा योजना की उचित जांच सुनिश्चित करने में सहायक हो सकते हैं (और अदालत ने आपत्तियों के आलोक में योजना की शर्तों में कुछ समायोजन का आदेश दिया हो सकता है)।

⁷¹ रे नोबल ग्रुप लिमिटेड [2018] ईडब्ल्यूएचसी 2911 (च) [161]-[164] पर।

⁷² एक उल्लेखनीय अपवाद के लिए, एमिगो लोन्स देखें: रे ऑल स्कीम लिमिटेड [2021] ईडब्ल्यूएचसी 1002 (सीएच) (आयोजन) और [2021] ईडब्ल्यूएचसी 1401 (सीएच) (स्वीकृति)।

2.38 हमेशा की तरह, अदालतों ने एक उचित संतुलन बनाने की मांग की है। स्नोडेन जे (जैसा कि वह तब था) ने हाल ही में योजनाओं के संबंध में लागत के बारे में अधिकारियों की समीक्षा की और निम्नलिखित सिद्धांतों को बताया:⁷³

(a) सभी मामलों में लागत का मुद्दा अदालत के विवेक पर है।

(b) सामान्य नियम लागत के संबंध में [यूके सिविल प्रक्रिया नियमों के नियम 44.2 के तहत] आम तौर पर एक आवेदन के लिए कोई आवेदन नहीं होगा ... योजना बैठकें आयोजित करने या किसी योजना को मंजूरी देने के आदेश की मांग, क्योंकि कंपनी अदालत की मंजूरी चाहती है, न कि एक अन्य पक्ष के विरुद्ध कोई उपाय या राहत।

(c) योजना कार्यवाही के भीतर किए गए व्यक्तिगत आवेदनों के संबंध में यह जरूरी नहीं है (और इसलिए सीपीआर के तहत सामान्य नियम लागू हो सकता है)।

(d) योजना में लागत के संबंध में उचित आदेश निर्धारित करने में कार्यवाही, प्रासंगिक विचारों में शामिल हो सकते हैं,

i. अर्थात् सदस्यों या लेनदारों को किसी योजना से संबंधित वास्तविक मुद्दों को समय पर और उचित तरीके से प्रतिकूल लागत आदेशों के संपर्क पर चिंताओं से नहीं रोकना चाहिए;

ii. वह आदेश कंपनी को पेश होने वाले सदस्यों या लेनदारों की उचित लागत का भुगतान करने के लिए अदालत के समक्ष उचित चिंता के मामलों को पूरी तरह हवादार करने में सक्षम हो सकता है, जिससे प्रस्तावों की जांच में अदालत की सहायता हो सकती है; और

iii. कि अदालत को सदस्यों या लेनदारों को इस विश्वास में आपत्ति करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए कि आपत्ति की लागत किसी और द्वारा चुकाई जाएगी।

(e) अदालत आम तौर पर आपत्ति करने वाले सदस्यों या लेनदारों के खिलाफ प्रतिकूल लागत आदेश नहीं देती है जब उनकी आपत्तियां (हालांकि असफल) तुच्छ नहीं हैं और योजना की जांच में

⁷³ रे वर्जिन एक्टिव होल्डिंग्स लिमिटेड और अन्य [2021] EWHC 991 (Ch) [29] पर; रे विलियम हिल पीएलसी [2021] में नॉरिस जे [2021] ईडब्ल्यूएचसी 1347 (सीएच) [3] ने स्नोडेन जे के "सावधान सारांश" को लेनदारों और सदस्यों की व्यवस्था की योजनाओं के संबंध में "अब लागत मुद्दों को तय करने के लिए शुरुआती बिंदु" के रूप में वर्णित किया।

अदालत की सहायता करते रहे हैं। लेकिन अदालत इस तरह के प्रतिकूल लागत आदेश दे सकती है यदि परिस्थितियां उस आदेश को सही ठहराती हैं।

(f) ऐसा कोई सिद्धांत या अनुमान नहीं है कि अदालत योजना कंपनी को एक विरोधी सदस्य या लेनदार की लागत का भुगतान करने का आदेश देगी, जिसकी किसी योजना पर आपत्ति है असफल रहा। यह ऐसा कर सकता है यदि आपत्तियां तुच्छ नहीं हैं और इससे न्यायालय को सहायता मिली है; या यह लागतों के संबंध में कोई आदेश नहीं दे सकता है। हर मामले में फैसला सभी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।"

भारत

भाग 1: प्रस्तावना

समझौते की योजनाओं की प्रकृति

1.1 भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 ("सीए 2013") के अध्याय XV में समझौता, ठहराव और समामेलन ("योजना (ओं)") की योजनाओं से संबंधित उपबंध शामिल हैं, जिसमें किसी भी निगमित पुनर्गठन (समामेलन, निर्विलयन आदि के रूप में) और निगमित ऋण पुनर्गठन के लिए भी लेनदारों (या उसके वर्ग) / सदस्यों (या उसके वर्ग) / कंपनी के समापक द्वारा एक आवेदन किया जा सकता है और अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय कंपनी निधि अधिकरण ("एनसीएलटी") (कंपनी और योजना के हिस्से के रूप में शामिल किसी भी अंतरिती कंपनी पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले) की पीठ को प्रस्तुत किया जा सकता है।

1.2 यह अनुच्छेद सीए 2013 के तहत योजनाओं के ढांचे और वित्तीय परेशानी का सामना करने वाली कंपनियों के लिए एक पुनर्गठन उपकरण के रूप में इसके उपयोग पर केंद्रित है। समझौते की योजना पर ब्रिटिश विधि के समान, सीए 2013 के तहत योजना एक कब्जे-में-देनदार बचाव मॉडल निर्धारित करती है जिसमें बचाव प्रक्रिया के दौरान मौजूदा प्रबंधन विस्थापित नहीं होता है।

1.3 सीए 2013 के तहत योजना के प्रमुख पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हैं (जिनमें से प्रत्येक ब्रिटिश विधि में स्थिति को प्रतिबिंबित करता है) -

(क) *कार्यक्षेत्र पर कोई सीमा नहीं* - इस योजना को कंपनी के किसी भी लेनदार (या उसके वर्ग) / सदस्य (या उसके वर्ग) द्वारा बिना किसी अर्हता सीमा के, या कंपनी द्वारा स्वयं, किसी भी परिस्थिति में, शोधन अक्षमता या वित्तीय संकट के क्षेत्र सहित, और पुनर्गठन या ऋण पुनर्गठन सहित किसी भी उद्देश्य के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है।

(ख) *चरण-वार अनुमोदन* - यह योजना मुख्यरूप से एक त्रि-स्तरीय प्रक्रिया है, जिसमें *पहला चरण* एनसीएलटी को आवेदन प्रस्तुत करना, *दूसरा चरण* जिसमें प्रस्तावित योजना पर मतदान करने के लिए पणधारियों की बैठक शामिल है, और *तीसरा चरण* है, जहां योजना को इसके अनुमोदन के लिए एनसीएलटी को प्रस्तुत किया जाता है। एक विस्तृत प्रक्रिया इस अनुच्छेद के बाद के पैरा में निर्धारित की गई है।

(ग) कब्जे में देनदार - संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान, मौजूदा प्रबंधन किसी भी स्तर पर विस्थापित नहीं होता है, और कंपनी का प्रभारी बना रहता है, भले ही योजना का भाग्य लेनदारों/सदस्यों के अनुमोदन पर निर्भर करता है, जैसा भी मामला हो।

(घ) बाध्यकारी प्रभाव - एक बार जब योजना को एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, तो इसकी शर्तें सभी लेनदारों (असहमत), सदस्यों और कंपनी के लिए बाध्यकारी हो जाती हैं।

भारत में समझौते की योजना का इतिहास

1.4 भारत में कंपनी विधि को बड़े पैमाने पर यूनाइटेड किंगडम ("यूके") में कंपनी विधि पर मॉडल किया गया है, जिसमें भारत में अधिनियमित पहला कंपनी विधि है यानी संयुक्त स्टॉक कंपनी अधिनियम, 1850, ब्रिटिश कंपनी अधिनियम, 1844 पर आधारित है। इस विधान में सदस्यों/लेनदारों के साथ किसी भी समझौते/ठहराव⁷⁴ से संबंधित उपबंध नहीं थे।⁷⁵ हालांकि, 1866 और 1882 के कानूनों में कुछ उपबंधों को शामिल किया गया था जो एक कंपनी को लेनदारों के साथ ठहराव में प्रवेश करने की अनुमति देते थे, लेकिन केवल तब जब वह स्वेच्छा से समाप्त होने वाला था⁷⁶

1.5 1913 के कंपनी अधिनियम (1936 में व्यापक संशोधनों के साथ⁷⁷) के माध्यम से विधायी ढांचे में बाद के परिवर्तनों ने लेनदारों और शेयरधारकों / सदस्यों दोनों को एक ठहराव / समझौते में प्रवेश करने की अनुमति दी, हालांकि समापन के दौरान, जिसे न्यायालय की मंजूरी से पहले लेनदारों / सदस्यों की संख्या में एक साधारण बहुमत और लेनदारों / सदस्यों के मूल्य में तीन-

⁷⁴ 1850 में इंडिया कंपनी लॉ की समस्याएं, द्वारा आरएस रंगता, द अमेरिकन जर्नल ऑफ लीगल हिस्ट्री, भाग 6, संख्या 3, जुलाई, 1962, पृष्ठ 302 पर। यह भी ध्यान दें कि 1857 के संयुक्त स्टॉक कंपनी अधिनियम ने कंपनी को लेनदारों के साथ समझौते की योजना में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, हालांकि धारा 89 ने समापक को लेनदारों के ऋण / दावों से समझौता करने की अनुमति दी।

⁷⁵ ध्यान दें कि कंपनी अधिनियम, 1866 की धारा 152 में कहा गया है कि एक कंपनी, जो स्वेच्छा से समाप्त होने वाली है या होने वाली है, लेनदारों के साथ एक ठहराव में प्रवेश कर सकती है, जो कंपनी पर बाध्यकारी होगी, यदि इसे एक असाधारण संकल्प द्वारा अनुमोदन दिया गया है और लेनदारों की संख्या और मूल्य में तीन-चौथाई द्वारा सहमति दी गई है। कंपनी अधिनियम, 1882 की धारा 180 में भी इस आशय के समान उपबंध शामिल हैं।

⁷⁶ कंपनी कानून और अभ्यास, डॉ संजय कपूर और डॉ संजय धमीजा द्वारा, टैक्समैन, अगस्त, 2019, पृष्ठ 1 पर।

⁷⁷ कंपनी अधिनियम, 1913, धारा 153 (1913 का मूल अधिनियम)।

चौथाई द्वारा अनुमोदित किया जाना था।⁷⁸ इसके अलावा, समझौते की योजनाओं की प्रवर्तनीयता⁷⁹ और कार्यक्षमता को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न प्रक्रियात्मक सुरक्षोपायों को शामिल किया गया था।⁸⁰

1.6 तत्पश्चात्, 1943⁸¹ में न्यायमूर्ति कोहेन समिति की रिपोर्ट और तत्पश्चात् 1952⁸² में भाभा समिति की रिपोर्ट में सिफारिशों के अनुसरण में, कंपनी अधिनियम, 1956 ("सीए 1956") को (1965 में और संशोधनों के साथ) प्रस्तुत किया गया था जिसके द्वारा एक योजना प्रस्तुत करने और अनुमोदन प्रक्रिया में पारदर्शिता के तत्वों को सुदृढ़ किया गया था। उदाहरण के लिए, धारा 393 में योजना की बैठक के सभी उपस्थित लोगों को एक विवरण भेजने का उपबंध किया गया है, जिसमें ठहराव/समझौता की योजना के प्रभाव और विशेष रूप से कंपनी के निदेशकों, प्रबंध निदेशकों, सचिवों, प्रबंधक आदि के भौतिक हितों पर स्पष्टीकरण दिया गया है।⁸³ इसके अलावा, कंपनी के लिए न्यायालय को सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा करना अनिवार्य हो गया, जैसे कि इसकी नवीनतम वित्तीय स्थिति, कंपनी के अपने खातों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, किसी भी जांच कार्यवाही के लंबित होने आदि।⁸⁴

1.7 इसके बाद, निगमित विधि संरचना को सरल बनाने और इसे उदारीकृत भारतीय आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप लाने के उद्देश्य से, डॉ. जेजे ईरानी ⁸⁵("ईरानी समिति") के तहत कंपनी विधि समिति की रिपोर्ट को सीए 2013 के अधिनियमन को रास्ता देने के लिए स्वीकार कर लिया गया

⁷⁸ ध्यान दें कि कंपनी अधिनियम, 1913 की धारा 153 [कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1936 के द्वारा संशोधित] रजिस्ट्रार के साथ ठहराव / समझौता करने के लिए न्यायालय के आदेश की एक प्रति दाखिल करने के लिए प्रदान की गई थी और अदालतों को कंपनी के खिलाफ किसी भी अन्य मुकदमे की निरंतरता / प्रारंभ पर रोक लगाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई थीं।

⁷⁹ ध्यान दें कि कंपनी अधिनियम, 1913 की धारा 153क [1936 के कंपनी (संशोधन) अधिनियम, XXII द्वारा संशोधित] ठहराव की एक योजना के माध्यम से किसी कंपनी के उपक्रम के पूरे या हिस्से को दूसरे को हस्तांतरित करने के लिए प्रदान की गई है।

⁸⁰ कंपनी विधि संशोधन पर समिति की रिपोर्ट, जून 1945, महामहिम स्टेशनरी कार्यालय, पृष्ठ 89 पर।

⁸¹ पृष्ठ 170 पर कंपनी विधि समिति, 1952 का प्रतिवेदन, भाभा समिति का प्रतिवेदन।

⁸² कंपनी अधिनियम, 1956, धारा 393।

⁸³ कंपनी अधिनियम, 1956, धारा 391 (2) के परंतुक।

⁸⁴ पृष्ठ 2 पर कंपनी विधि, निगमित कार्य मंत्रालय, मई, 2005 से संबंधित विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन।

⁸⁵ भारत में एक ऋण पुनर्गठन उपकरण के रूप में समझौते की योजना: समस्याएं और संभावनाएं" देखें, उमाकंठ वरोटिल द्वारा, एनयूएस वर्किंग पेपर 2017/005, एनयूएस सेंटर फॉर लॉ एंड बिजनेस वर्किंग पेपर 17/02, मार्च, 2017, पृष्ठ 23 पर

था। उपबंधों में आमूल-चूल परिवर्तन के अलावा, सीए 2013⁸⁶ ने ठहराव/समझौते की योजना से संबंधित शासन में एक नए बदलाव को चिह्नित किया, जिसमें प्रमुख परिवर्तन यह है कि कंपनी के समापन के दौरान होने के बिना भी इस योजना में प्रवेश किया जा सकता है।⁸⁷ इसके अतिरिक्त, इस प्रक्रिया को लेनदार के अनुकूल और सुरक्षित बनाने के लिए कतिपय नए उपबंध शुरू किए गए थे, जैसे कि योजना⁸⁸ का समर्थन करते हुए एक हलफनामा दाखिल करने पर लेनदार की बैठकों को समाप्त करने के लिए संस्वीकृत प्राधिकारी/न्यायालय की शक्ति, योजना⁸⁹ पर आपत्तियां उठाने के लिए सीमा का विनिर्देश आदि। हालांकि, आश्चर्यजनक रूप से, अधिस्थगन से संबंधित उपबंध को सीए 2013 से बाहर रखा गया था, भले ही सीए 1956 की धारा 391 (6) ने न्यायालय को एक अधिस्थगन लागू करने का अधिकार दिया, एक बार आवेदन दायर किया गया था (नीचे परिच्छेद 2.3 (अ) देखें)।

1.8 इसके अलावा, अपने संविधान के संबंध में कानूनी बाधाओं का सामना करने के बाद 2016 में एक विशेष न्यायालय यानी एनसीएलटी की स्थापना की गई थी,⁹⁰ जो एक तेज अनुमोदन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सीए 2013 के तहत योजनाओं को स्वीकृति प्रदान के लिए क्षेत्राधिकार प्राधिकरण के रूप में माननीय उच्च न्यायालय की जगह ले रही थी। इस विकास को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 ("आईबीसी") के अधिनियमन के साथ भी पूरक किया गया था, इसके कई उपबंध 2017 के अंत में प्रभावी हो रहे थे। सीए 2013 के तहत योजनाओं के साथ आईबीसी के इंटरप्ले पर भी इस अनुच्छेद के बाद के अनुभागों में चर्चा की गई है।

⁸⁶ ध्यान दें कि सीए 1956 में इसी तरह का निर्माण हुआ था, हालांकि, भारत में अदालतों ने कई अवसरों पर, सीए 1956 के उपबंधों के तहत "घाव के लिए उत्तरदायी" शब्दों की व्याख्या की है क्योंकि यह इस तथ्य के बराबर नहीं है कि कंपनी को घायल कर दिया जाना चाहिए। तदनुसार, इस पहलू पर परस्पर विरोधी निर्णय हैं; कंपनी अधिनियम के लिए गाइड देखें, द्वारा ए रमैया, 19 वां संस्करण - खंड 2, अध्याय 15, पृष्ठ 64 पर।

⁸⁷ कंपनी अधिनियम, 2013, धारा 230 (9)।

⁸⁸ ध्यान दें कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 (4) के परंतुक में यह निर्धारित किया गया है कि योजना के खिलाफ आपत्तियां केवल उन व्यक्तियों द्वारा की जा सकती हैं जो कम से कम दस प्रतिशत नहीं हैं। शेयरधारिता या बकाया ऋण के रूप में कम से कम पांच प्रतिशत की राशि का नहीं है। कुल बकाया ऋण का।

⁸⁹ मद्रास बार एसोसिएशन वी। भारत संघ, एमएएनयू/एससी/0610/2015 (एससी); निगमित कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, अधिसूचना सं 2010-12 एस.ओ. 1934 (ई) और एस.ओ. 1935 (ई) दिनांक 1 जून 2016।

⁹⁰ कंपनी अधिनियम, 2013, धारा 230 (2) (सी)।

भाग 2:

एक ऋण पुनर्गठन तंत्र के रूप में कंपनी अधिनियम के तहत योजनाओं की चर्चा प्रक्रिया

2.1 ब्रिटिश विधि के समान, योजना के संबंध में एक आवेदन सीए 2013 की धारा 230 (1) के तहत कंपनी के लेनदारों (या उसके वर्ग) / सदस्यों (या उसके वर्ग) द्वारा, या कंपनी द्वारा स्वयं ("आवेदक"), क्षेत्राधिकार एनसीएलटी (यानी एनसीएलटी की पीठ जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी को शामिल किया गया है) के समक्ष किया जा सकता है। एनसीएलटी, कंपनी या किसी लेनदार या कंपनी के सदस्य के आवेदन पर, लेनदारों (या उसके वर्ग), या सदस्यों (या उसके वर्ग) की एक बैठक का आदेश दे सकता है, जैसा कि मामला हो सकता है, बुलाया जा सकता है, आयोजित किया जा सकता है और इस तरह से आयोजित किया जा सकता है जैसा कि एनसीएलटी निर्देश देता है।

2.2 योजना की स्वीकृति और कार्यान्वयन की प्रक्रिया (मोटे तौर पर ब्रिटिश विधि प्रक्रिया के समान होने के कारण) में तीन चरण शामिल होंगे, जैसा कि नीचे निर्धारित किया गया है:

215

(क) प्रथम चरण

आवेदक, सीए 2013 की धारा 230 (1) के तहत आवेदन दायर करते समय, दूसरों के बीच एक हलफनामे के तहत खुलासा करने के लिए भी आवश्यक है:

i. कंपनी की वित्तीय स्थिति

कंपनी से संबंधित सभी भौतिक तथ्यों, जैसे कंपनी की नवीनतम वित्तीय स्थिति, कंपनी के खातों पर नवीनतम लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और कंपनी के खिलाफ किसी भी जांच या कार्यवाही के लंबित होने का खुलासा आवेदन में किया जाना आवश्यक है।

ii. सहमति आवश्यकताएं

A. यदि योजना एनसीएलटी के समक्ष आवेदन करने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में अपने लेनदारों के प्रति कंपनी के ऋण दायित्वों का पुनर्गठन/परिवर्तन करने का प्रस्ताव करती है, तो योजना को मूल्य के आधार पर सुरक्षित लेनदारों के कम से कम 75% द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है।⁹¹ तथापि, जहां इस योजना में ऋण पुनर्गठन शामिल नहीं है और

⁹¹ ध्यान दें कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के मामले में आईसीआईसीआई लिमिटेड आरई, (2002) 36 एससीएल 682, ने कहा कि "लेनदारों की बैठक आवश्यक नहीं है जहां योजना केवल सदस्यों के बीच है। न्यायालय ने

लेनदारों (या किसी भी वर्ग) को इस योजना में एक प्रभावित वर्ग के रूप में पहचाना नहीं जाता है, तो उनके पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी⁹², जब तक कि प्रासंगिक ऋण अनुच्छेदन⁹³ के तहत सहमति आवश्यकताएं न हों। ऐसे मामलों में, केवल सदस्यों (या प्रासंगिक प्रभावित वर्ग) की स्वीकृति ली जाएगी।

- B. आवेदक को एनसीएलटी को लेनदारों/सदस्यों के वर्गीकरण और योजना के अनुमोदन के प्रयोजनों के लिए लेनदारों/सदस्यों के प्रत्येक वर्ग की पहचान किए जाने के आधार पर भी एनसीएलटी को बताना अपेक्षित है।⁹⁴ यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि सीए 2013 इस उद्देश्य के लिए लेनदारों के विशिष्ट "वर्गों" को निर्धारित नहीं करता है (उदाहरण के लिए वित्तीय लेनदार या परिचालन लेनदार जैसा कि आईबीसी के तहत वर्गीकृत किया गया है)। तथापि, यदि लेनदारों के अलग-अलग वर्गों की पहचान की जाती है (योजना के अंतर्गत प्रभावित/बिगड़ा हुआ वर्ग होने के कारण⁹⁵), तो लेनदारों के प्रत्येक वर्ग की बैठक में ऐसी योजना के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। भारतीय योजनाओं के लिए स्थापित प्रथा

कहा कि हालांकि न्यायालय लेनदारों के हितों का ख्याल रखने के लिए बाध्य है, लेकिन यह लेनदारों की बैठक बुलाने के लिए बाध्य नहीं है जहां प्रस्तावित ठहराव केवल सदस्यों के बीच है, और लेनदारों के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना नहीं है। कंपनी अधिनियम के लिए गाइड देखें, द्वारा ए रमेया, 19वां संस्करण - खंड 2, अध्याय 15, पृष्ठ 41 और 48 पर।

⁹² ध्यान दें कि, के मामले में रामको सुपर लेदर्स लिमिटेड बनाम धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड, (2009) 152 कॉम मामले 937, स्कीम की स्वीकृति के आदेश को संशोधित किया गया था ताकि इसे लेनदारों के अनुमोदन के अधीन बनाया जा सके क्योंकि प्रासंगिक ऋण अनुच्छेदन के तहत सहमति की आवश्यकता से संबंधित तथ्य पहले एनसीएलटी के ध्यान में नहीं लाया गया था।

⁹³ कंपनी (समझौता, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016, नियम 3 (4)।

⁹⁴ देखें सुप्रा नोट 85 पर; इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट में मिहिर मफतलाल मामला पामर की कंपनी कानून, 24 वें संस्करण से एक 'वर्ग' की अवधारणा से समर्थन प्राप्त किया और इसमें विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह माना गया कि "।"यदि साधारण शेयरधारकों के अधिकारों को बदलना है, लेकिन वरीयता शेयरों के उन लोगों को छुआ नहीं जाता है, तो सामान्य शेयरधारकों की एक बैठक आवश्यक होगी लेकिन वरीयता शेयरधारकों की नहीं।"

⁹⁵ आरई में: अरविंड मिल्स लिमिटेड [2002] 111 कॉम्प केस 118 (गुज), पैरा 13 और 15 पर। इसके अलावा, गुजरात उच्च न्यायालय ने, के मामले में मानेकचौक और अहमदाबाद मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, फिर से (1970) 40 कॉम्प केस 819 (गुज), ने देखा कि एक वर्ग "उन लोगों तक ही सीमित होना चाहिए जिनके अधिकार इतने असमान नहीं हैं कि उनके लिए अपने सामान्य हित के दृष्टिकोण से एक साथ परामर्श करना असंभव हो जाए।

लेनदारों को 'सुरक्षित लेनदारों' और 'असुरक्षित लेनदारों' के रूप में वर्गीकृत करने की रही है।

आरई के मामले में: अरविंद मिल्स लिमिटेड⁹⁶, जो ऋण पुनर्गठन के लिए एक योजना थी, न्यायालय ने कुछ विदेशी लेनदारों से इस आपत्ति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि कुछ भारतीय बैंकों के साथ एक मौजूदा मुकदमेबाजी के प्रकाश में हितों की समानता की अनुपस्थिति और हितों के टकराव को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक अलग वर्ग का गठन करने की आवश्यकता नहीं थी। न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के अनुपात पर निर्भर करते हुए *मिहीर एच मफतलाल बनाम। मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड* ("*मिहीर मफतलाल मामला*"⁹⁷) ने कहा कि "... कोई अलग वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं है जब तक कि एक समूह को योजना के तहत अलग तरह से व्यवहार नहीं किया जाता है।" और "... ऑब्जेक्टर्स को सुरक्षित लेनदारों के एक अलग वर्ग के रूप में माना जाने का हकदार नहीं होगा, वर्ग के भीतर एक वर्ग, क्योंकि ऑब्जेक्टर्स और अन्य सुरक्षित लेनदारों के बीच वाणिज्यिक हितों का कोई टकराव नहीं है, खासकर जब समान शर्तों के साथ एक ही योजना को सभी सुरक्षित लेनदारों को पेश किया गया है और आपत्तिकर्ता और अन्य सुरक्षित लेनदारों के बीच योजना में कोई अंतर नहीं किया गया है"।

iii. अन्य आवश्यकताएं

A. सीए 2013 के उपबंधों में यह सुनिश्चित करने के लिए कई अन्य आवश्यकताएं निर्धारित की गई हैं कि सभी हितधारकों के हितों की रक्षा की जाए और किसी भी अल्पसंख्यक हितधारीके प्रति पूर्वाग्रह से बचा जा सके। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं

- i. इस योजना में एक लेनदार उत्तरदायित्व विवरण शामिल होना चाहिए⁹⁸, जिसमें सहमति प्राप्त सुरक्षित लेनदार को कतिपय अभ्यावेदन देने की आवश्यकता होगी, जैसे (I) इसने प्रस्तावित पुनर्गठन योजना को पढ़ा और समझा है⁹⁹, (II) इसके साथ सहमत

⁹⁶ मिहीर एच. मफतलाल वी. मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड., (1997) 1 एससीसी 579.

⁹⁷ कंपनी अधिनियम, 2013, धारा 230 (2) (सी) (i) कंपनी (समझौता, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 4 के साथ पठित।

⁹⁸ कंपनी अधिनियम, 2013, धारा 230 (2) (सी) (iii)।

⁹⁹ कंपनी अधिनियम, 2013, धारा 230 (7) (ई)।

होना अपने सर्वोत्तम हित में है, और (III) यह योजना किसी भी सुरक्षित/असुरक्षित लेनदार आदि की कीमत पर प्रासंगिक सुरक्षित लेनदार को कोई कपटपूर्ण प्राथमिकता नहीं देती है। यह उचित खेल सुनिश्चित करने के लिए सहमति लेनदारों पर एक जिम्मेदारी डालता है।

- ii. इस योजना के साथ लेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट भी होनी चाहिए कि योजना के पुनर्गठन के बाद कंपनी की निधि आवश्यकताएं कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा ऐसे लेखा परीक्षकों को प्रदान किए गए अनुमानों के आधार पर तरलता परीक्षण के अनुरूप होंगी।¹⁰⁰
- iii. एनसीएलटी के पास असहमत शेयरधारकों को निकास प्रस्ताव प्रदान करने के लिए एक आदेश पारित करने की भी शक्ति है, अगर उसे लगता है कि योजना की शर्तों को प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक है (यानी न केवल उनके हितों की रक्षा करने के लिए बल्कि किसी भी होल्डआउट को रोकने के लिए भी)।¹⁰¹ इसके अलावा, इस योजना में एक अधिग्रहण प्रस्ताव शामिल हो सकता है, जिसमें शेयरों के तीन-चौथाई से कम नहीं रखने वाली कंपनी का कोई भी सदस्य पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता¹⁰² से मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ शेष शेयरों का अधिग्रहण करने के लिए एनसीएलटी को एक आवेदन कर सकता है। ऐसे में अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो उसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। धारा 230 के अंतर्गत असंतुष्ट लेनदार के ऋण के अधिग्रहण के लिए ऐसा कोई उपबंध उपलब्ध नहीं है।
- iv. एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा कंपनी के शेयरों और संपत्ति और सभी आस्तियों, मूर्त और अमूर्त, चल और अचल के संबंध में एक मूल्यांकन रिपोर्ट, योजना के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। मूल्यांकन का पहलू महत्वपूर्ण है क्योंकि योजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन उन लेनदारों द्वारा किया जाएगा जो आवेदन दाखिल करने का अनुमोदन करते हैं और एनसीएलटी यह मान लेगा कि लेनदारों ने इसे

¹⁰⁰ कंपनी अधिनियम, 2013, धारा 230 (11) कंपनी (समझौता, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 3 (5) और नियम 3 (6) के साथ पठित।

¹⁰¹ एन.ए.पी. अलागिरी राजा एंड कंपनी बनाम एन. गुरुस्वामी और अन्य। 1989 65 कॉम्प केस 758 एमएडी.

¹⁰² देखिए मिहीर मफतलालकेस पैरा 29 में।

अनुमोदित करने से पहले योजना की व्यवहार्यता की जांच की है।¹⁰³ जैसा कि मिहीर मफतलाल मामले में आयोजित किया गया है:

"न्यायालय के पास न तो विशेषज्ञता है और न ही कंपनी के सदस्यों द्वारा उपयोग किए गए वाणिज्यिक ज्ञान में गहराई से तल्लीन करने का अधिकार क्षेत्र है, जिन्होंने अपेक्षित बहुमत से योजना की पुष्टि की है। नतीजतन, उस हद तक कंपनी कोर्ट का क्षेत्राधिकार परिधीय और पर्यवेक्षी है और अपीलीय नहीं है।"

यह ध्यान दिया जाना चाहिए, जबकि ब्रिटिश अदालतें जहां आवश्यक हो, मूल्यांकन साक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करेंगी,¹⁰⁴ भारतीय अदालतों ने आमतौर पर इसकी जांच करने से परहेज किया है, इसे एक वाणिज्यिक पहलू माना जाता है जो अनुमोदन के लिए एक योजना की जांच करते समय अदालतों के दायरे में नहीं आता है।¹⁰⁵ यह कहने के बाद, अदालतें मूल्यांकन साक्ष्य को देख सकती हैं यदि यह मुद्दा किसी योजना की निष्पक्षता और तर्कसंगतता के निर्धारण के लिए जर्मन है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह एक धोखाधड़ी वाली योजना नहीं है (अंकित मितल मामले को देखें जैसा कि नीचे परिच्छेद 2.3 (सी) में संदर्भित है)।

दूसरा चरण

एनसीएलटी द्वारा आवेदन पर सुनवाई किए जाने पर, इस योजना को एनसीएलटी के निर्देशों के अनुसार बुलाई गई सदस्यों और लेनदारों के प्रत्येक वर्ग की बैठक में मतदान के लिए रखा जाएगा। एनसीएलटी लेनदार या लेनदारों के वर्ग की एक बैठक बुलाने के साथ वितरित कर

¹⁰³ अंग्रेजी अदालतों के लिए शुरुआती बिंदु एक प्रतिवादी परिप्रेक्ष्य से योजना पर विचार करना है यानी यदि योजना असफल हो जाती है तो क्या होगा। ऐतिहासिक रूप से, योजना कंपनियों ने सबसे अधिक बार जोर देकर कहा है कि योजना का एकमात्र विकल्प समापक है, और परिणामस्वरूप कंपनी पर एक समापक मूल्यांकन लागू किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि जूनियर लेनदारों (और शेयरधारकों) का कोई शेष आर्थिक हित है या नहीं। देखना 'ऋण पुनर्गठन में न्यायालय की भूमिका' द्वारा जेनिफर पायने, 77 कैम्ब्रिज एलजे 124 (2018)। प्रासंगिक विकल्प - और मूल्यांकन - अब नई पुनर्गठन योजना प्रक्रिया की शुरुआत के प्रकाश में अधिक बारीकी से विचार किया जा रहा है (भाग में, क्योंकि अदालत के लिए दो थ्रेशोल्ड शर्तों को एक योजना को मंजूरी देने के लिए अधिकार क्षेत्र है जिसे हर वर्ग ने अनुमोदित नहीं किया है, उस के संदर्भ में तैयार किया गया है (एक असंतुष्ट वर्ग का कोई भी सदस्य योजना के तहत किसी भी बदतर नहीं होगा जितना कि वे प्रासंगिक विकल्प में करेंगे)।

¹⁰⁴ मिहीर मफतलाल मामला, पैरा 40 पर।

¹⁰⁵ कंपनी अधिनियम, 2013, धारा 230 (9)।

सकता है जहां ऐसे लेनदार या लेनदारों का वर्ग, जिनके पास मूल्य से कम से कम 90% है, योजना के लिए शपथ पत्र के माध्यम से सहमत और पुष्टि करते हैं।¹⁰⁶

इसके अतिरिक्त, लेनदारों को बैठक के लिए नोटिस भेजे जाने के बाद, ऐसे प्राप्तकर्ताओं द्वारा इस योजना पर आपत्तियां की जा सकती हैं जिनके पास शेयरधारिता का कम से कम 10% नहीं है या जिनके पास कुल बकाया ऋण के 5% से कम नहीं है।¹⁰⁷ नोटिस को आयकर प्राधिकरणों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कंपनियों के रजिस्ट्रार, स्टॉक एक्सचेंजों, आधिकारिक समापक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग आदि¹⁰⁸ जैसे सांविधिक प्राधिकरणों को भी भेजा जाना आवश्यक है, जो नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर योजना के साथ अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, पंजीकृत कर सकते हैं और यदि 30 दिनों की अवधि के भीतर कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है, यह माना जाएगा कि संबंधित अधिकारियों को कोई आपत्ति नहीं है।

220

दूसरे चरण का एक महत्वपूर्ण पहलू योजना पर मतदान से संबंधित है, जिसके लिए सीए 2013 की धारा 230 (6) के उपबंध स्पष्ट रूप से लेनदारों के प्रत्येक वर्ग में मूल्य के आधार पर तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकांश व्यक्तियों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता को निर्दिष्ट करते हैं और सदस्यों के प्रत्येक वर्ग में, जैसा भी मामला हो, ऐसे वर्ग के संबंध में बुलाई गई बैठकों में।¹⁰⁹

तीसरा चरण

एक बार प्रत्येक बैठक में इस योजना को अनुमोदित कर दिए जाने के बाद, मूल्य में कम से कम तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकांश हितधारकों द्वारा, योजना के संबंध में एक आवेदन एनसीएलटी को प्रस्तुत किया जाना है, जिसमें इसके अनुमोदन की मांग की जाती है।¹¹⁰ एनसीएलटी द्वारा स्वीकृत किए जाने पर, यह योजना अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी, सभी लेनदारों, या लेनदारों के वर्ग या सदस्यों या सदस्यों के वर्ग और कंपनी के योगदानकर्ताओं पर

¹⁰⁶ कंपनी अधिनियम, 2013, धारा 230 (4) के परंतुक।

¹⁰⁷ कंपनी अधिनियम, 2013, धारा 230 (5) कंपनी (समझौता, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 के नियम 8 के साथ पठित।

¹⁰⁸ आइ: ऑटो स्टीयरिंग इंडिया प्रा. लि., [1977] 47 कॉम्प कैस 257 (दिल्ली); के. सुधाकर गुप्ता बनाम. इलेक्ट्रो थर्मिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड, [2004] 122 कॉम्प कैस 625 (एपी)।

¹⁰⁹ कंपनी (समझौता, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016, नियम 15।

¹¹⁰ कंपनी अधिनियम, 2013, धारा 230 (6)।

बाध्यकारी हो जाएगी।¹¹¹ तथापि, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि एनसीएलटी के पास योजना की स्वीकृति के समय और/अथवा उसके बाद¹¹² किसी भी समय, केवल योजना के मूल ताने-बाने या वाणिज्यिक ठहराव में परिवर्तन किए बिना इसके समुचित कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए इस योजना में संशोधन करने की शक्ति है।¹¹³

सीए 2013 के तहत योजना के उपबंधइस योजना की किसी भी रूपरेखा या डिजाइन को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करते हैं, जिसमें इसके लिए संरचना या ठहराव पर कोई प्रतिबंध शामिल है। इसलिए, एक योजना *अन्य बातों के साथ-साथ* एक कंपनी (उपक्रमों) के सभी उपक्रमों (या एक प्रभाग / उपक्रम¹¹⁴) के एक एकल इकाई में विलय के साथ (प्रचालनों के तालमेल को अनुकूलित करने की दृष्टि से)¹¹⁵ या निर्विलयन / हस्तांतरण के बदले हस्तांतरणकर्ता कंपनी को शेयर जारी करने के लिए प्रदान कर सकती है, और कंपनी की सभी या कतिपय देनदारियों को बुझाने के लिए भी प्रदान कर सकती है, बशर्ते प्रभावित वर्ग का अपेक्षित अनुमोदन विधिवत रूप से ले लिया गया हो। एक योजना एक साधारण विलय के लिए भी प्रदान कर सकती है, जिसमें विदेशी देश में लागू विधि के अनुपालन के अध्यक्षीन सीमा पार विलय भी शामिल है।¹¹⁶

*अपूर्व जे पारेख बनाम एसेन कंप्यूटर्स लिमिटेड*¹¹⁷के मामले में, जहां यह योजना केवल कंपनी की आस्तियों के निपटान और प्रमोटर्स और पूर्व निदेशकों की व्यष्टि देनदारियों को समाप्त करने की दृष्टि से प्रस्तावित की गई थी, उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और प्रभावित वर्गों से अपेक्षित सहमति प्राप्त किए बिना, न्यायालय ने ऐसी योजना को अनुमोदन देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा, योजना की संरचना की परवाह किए बिना, योजना के प्रस्तावक के लिए जो आवश्यक है वह मौजूदा देनदारियों के उपचार को निर्दिष्ट करना है। उदाहरण के लिए, *हेमाकुटा शुगर एंड एलाइड*

¹¹¹ कंपनी अधिनियम, 2013, धारा 231 (1)।

¹¹² यूनिक्स डेल्टा फोर्स सिक्वोरिटी प्राइवेट लिमिटेड बनाम सुमित सुविधाएं प्राइवेट लिमिटेड., [2012] 175 कॉम्प केस 318 (बीओएम); मेघल होम्स (पी) लिमिटेड बनाम श्री निवास गिरनी केके समिति और अन्या., (2007) 7 एससीसी 753.

¹¹³ जिंदल पाइप्स लिमिटेड, रे, (2008) 88 एससीएल 48 (सभी), अरविंद मिल्स लिमिटेड, रे, (2010) 155 कॉम्प मामले 449.

¹¹⁴ राजवंश डेवलपर्स पी लिमिटेड, रे, (2010) 98 एससीएल 268 (कार); कंपनी अधिनियम के लिए गाइड देखें, द्वारा ए रमैया, 19 वां संस्करण - खंड 2, अध्याय 15, पृष्ठ 129 पर।

¹¹⁵ ध्यान दें कि एक भारतीय कंपनी के साथ एक विदेशी कंपनी के समामेलन से संबंधित उपबंध और इसके विपरीत सीए 2013 की धारा 234 के तहत प्रदान किए गए हैं। यह भी देखें सुप्रा नोट 80 पर, पृष्ठ 130 पर।

¹¹⁶ (2006) 3 कॉम्प एलजे 321.

¹¹⁷ (2010) 99 सीएलजे 347 (कार).

*इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सालार जंग शुगर मिल्स लिमिटेड*¹¹⁸के मामले में, एनसीएलटी ने इस योजना को अव्यवहार्य पाया, क्योंकि इसमें यह निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि कामगारों और लेनदारों को मौजूदा देनदारियों का निर्वहन करने के लिए निधियां कैसे जुटाई जाएंगी। इसके अलावा, एक ऐसी योजना जिसमें कामगारों के दावे के संदर्भ में कोई प्रस्ताव या उपबंध नहीं है और किशतों में असुरक्षित लेनदारों के बकायों का 20% भुगतान करने का प्रस्ताव भी है, को एक वास्तविक योजना नहीं होने के रूप में आयोजित किया गया है , और इसके बजाय एक मुखौटा है।¹¹⁹

¹¹⁸ मधु फैब्रिक्स लिमिटेड बनाम क्षेत्रीय निदेशक [2013] 176 कॉम केस 368 (गुज)।

¹¹⁹ शोधन अक्षमता विधि सुधार समिति की अंतरिम रिपोर्ट, फरवरी, 2015 पृष्ठ 78 पर।

प्रमुख व्यावहारिक मुद्दे और सिफारिशें

2.3 ऐतिहासिक रूप से योजना प्रक्रिया को विभिन्न व्यावहारिकों कठिनाइयों से प्रभावित किया गया है यही कारण है कि CA1956 के तहत भी कंपनियों के योजनाओं में प्रवेश करने के ज्यादा उदाहरण नहीं थे,¹²⁰ तनावग्रस्त ऋण पुनर्गठन के उद्देश्यों के लिए अकेले छोड़ दें। यहां तक कि वर्तमान सीए 2013 के तहत, प्रक्रिया में कुछ कमियां हैं, जिन पर नीचे जोर दिया गया है, साथ ही संभावित परिवर्तनों के साथ जो ढांचे की दक्षता को अनुकूलित कर सकते हैं।

(क) अधिस्थगन की अनुपस्थिति

ऋण पुनर्गठन में, अधिस्थगन का तात्पर्य ऋण वसूली के लिए कंपनी के खिलाफ किसी लेनदार द्वारा कार्यवाही के प्रारंभ/ निरंतरता या प्रतिभूति के प्रवर्तन पर रोक या निषेध से है। अधिस्थगन क्षेत्राधिकारों में दिवाला विधियों में एक मानक विशेषता है, जो यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी के लिए ऋण समाधान प्रस्ताव / योजना को कंपनी या संबंधित लेनदारों को व्यक्ति लेनदारों द्वारा वसूली कार्यवाही के साथ काठी किए बिना सुचारु रूप से लागू किया जा सकता है और निर्धारित समाधान के लिए एक समान दृष्टिकोण का पालन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आईबीसी ढांचे में, एक बार जब एनसीएलटी दिवाला शुरू करने के लिए आवेदन को स्वीकार कर लेता है, तो यह अन्य बातों के साथ-साथ निगमित देनदार के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी कार्यवाही पर स्थगन भी लगाता है।¹²¹

223

योजनाओं के प्रयोजनों के लिए अधिस्थगन के स्पष्ट लाभों के बावजूद, सीए 2013 में स्पष्ट रूप से कोई उपबंध नहीं है जो एनसीएलटी को अधिस्थगन लागू करने का अधिकार देता है, एक बार

¹²⁰ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016, धारा 14 शोधन अक्षमता कानून सुधार समिति की रिपोर्ट, नवंबर, 2015, जिसके अनुसार आईबीसी अधिनियमित किया गया था, नोट करता है (क्रमशः पृष्ठ 78 और 118 पर) कि "एक दिवाला कानून होने के लक्ष्यों में से एक लेनदारों द्वारा ऋण संग्रह कार्यों के निलंबन को सुनिश्चित करना है, और देनदारों और लेनदारों को अपने अनुबंध पर फिर से बातचीत करने के लिए समय प्रदान करना है। इसके लिए एक अधिस्थगन अवधि की आवश्यकता होती है जिसमें लेनदारों द्वारा देनदारों के खिलाफ कोई संग्रह या अन्य कार्रवाई नहीं की जाती है।"..... "अधिस्थगन के पीछे की प्रेरणा यह है कि यह इकाई के लिए परिचालन जारी रखने के लिए अधिकतम मूल्य है, भले ही आईआरपी के दौरान व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जा रहा हो। आईआरपी की सार्वजनिक घोषणा के बाद व्यवसाय पर कोई अतिरिक्त जोर नहीं होना चाहिए। आईआरपी के दौरान अधिस्थगन के लिए आदेश न केवल ऋण वसूली कार्यों पर रोक लगाता है, बल्कि इकाई से वसूली के किसी भी तरीके के लिए पुराने मुकदमों, या नए मुकदमों से किसी भी दावे या अपेक्षित दावों पर भी रोक लगाता है।

¹²¹ कंपनी अपील (एटी) 2018 की संख्या 346 के साथ-साथ 2018 की कंपनी अपील (एटी) नंबर 347।

सीए 2013 की धारा 230 के तहत आवेदन दायर किया जाता है। तथापि, माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) ने *भारत संघ बनाम अवसंरचना पट्टा एवं वित्तीय सेवाएं एवं अन्य* के मामले में ¹²²सीए, 2013¹²³ की धारा 242(4) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया और मामलों की बहुलता से बचने और अधिकरणों के समय को संरक्षित करने के लिए स्थगन लगाया जो अन्यथा कई व्यक्ति अनुप्रयोगों के निर्णय में खर्च किए गए थे। यहां, एनसीएलएटी ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि आईबीसी के उपबंधों के तहत उपलब्ध अधिस्थगन सीए 2013 में मौजूद नहीं है, लेकिन एक अंतरिम आदेश के माध्यम से सीए, 2013 की धारा 242 (4) के तहत एक ही शक्ति का उपयोग किया जा सकता है।

यहां यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि भले ही सीए 1956 की धारा 391 (6) ने उपबंधों के तहत आवेदन दायर करने के बाद न्यायालय को अधिस्थगन¹²⁴ लगाने का अधिकार दिया, लेकिन अदालतें अधिस्थगन¹²⁵ लागू करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करने में बहुत सतर्क थीं। हैरानी की बात यह है कि इस उपबंध को सीए 2013 में शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण एनसीएलटी द्वारा अधिस्थगन /स्थगन का विवेकाधीन अधिरोपण प्रश्न से बाहर है। अधिस्थगन / स्थगन उपबंधों की अनुपस्थिति व्यक्ति लेनदारों द्वारा सुरक्षा के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई के डर को जीवित रखती है, जो अनिवार्य रूप से कंपनी के लिए लेनदारों के साथ एक ठहराव में प्रवेश करने में सक्षम होने के लिए मुश्किल बनाती है।¹²⁶

यदि एक स्वचालित रोक नहीं है, तो सीए 1956 के समान कुछ उपबंधों को शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें एनसीएलटी के पास व्यक्ति प्रवर्तन कार्यों पर रोक लगाने का अधिकार है, जिस तरह से एनसीएलटी को इस अधिकार का उपयोग करना चाहिए, उस पर पर्याप्त मार्गदर्शन के साथ मिलकर। विशेष रूप से, ब्रिटिश सांविधिक तंत्र भी स्थगन के लिए प्रदान नहीं करता है; इसके लिए व्यावहारिक समाधान इस अनुच्छेद के ब्रिटिश भाग के परिच्छेद 2.8 में शामिल हैं। यह देखने की जरूरत है कि क्या इन समाधानों (विशेषरूप से 'लॉक-अप ठहराव' और प्रशासन की कार्यवाही के हिस्से के रूप में एक योजना को कार्यान्वित करना) को भारतीय संदर्भ में कार्यान्वित किया जा

¹²²कंपनी अपील (एटी) 2018 की संख्या 346 के साथ-साथ 2018 की कंपनी अपील (एटी) नंबर 347।

¹²³ वही

¹²⁴ ध्यान दें कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 242 (4) ट्रिब्यूनल को कोई भी अंतरिम आदेश देने की अनुमति देती है जो वह ऐसे नियमों और शर्तों पर कंपनी के मामलों के संचालन को विनियमित करने के लिए उपयुक्त समझता है जो इसे न्यायसंगत और न्यायसंगत प्रतीत होता है।

¹²⁵ आल्प्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रे, (2012) 107 सीएलए 25 (सभी)।

¹²⁶ सुप्रा नोट 79, पृष्ठ 9 पर।

सकता है। कृपया आईबीसी कार्यवाही के तहत योजनाओं के उपयोग के संबंध में परिच्छेद 2.7 को देखें।

(ख) कोई निश्चित समय-सीमा नहीं

इस योजना के अनुमोदन की संपूर्ण प्रक्रिया विभिन्न मील के पत्थरों के लिए निर्धारित समय-सीमा से रहित है।

यद्यपि ठहराव की ब्रिटिश योजनाओं में कोई औपचारिक समयसीमा नहीं है, ब्रिटिश बाजार जितनी जल्दी हो सके सौदों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करता है, खासकर जहां कुछ "बर्निंग प्लेटफॉर्म" जैसे कि तरलता संकट होता है, जो एक समय सीमा बनाता है जिसके द्वारा योजना को लागू किया जाना चाहिए। समय पर ब्रिटिश मामले विधि का ध्यान केंद्रित किया गया है (और हाल ही में एक न्यायिक अभ्यास कथन¹²⁷) इसलिए यह सुनिश्चित करने पर है कि प्रक्रिया इतनी जल्दी नहीं है कि हितधारकों को प्रस्तावों पर विचार करने का उचित अवसर नहीं दिया जाता है (इस अनुच्छेद के ब्रिटिश भाग के परिच्छेद 2.15 से 2.17 देखें)।

225

इसके विपरीत, भारत में, समय-सीमा की अनुपस्थिति देरी के मुद्दे को जन्म देती है, जो पूर्ववर्ती सीए 1956 में भी मौजूद थी और परिणामस्वरूप अतीत में ऐसी प्रक्रियाओं के उपयोग को कम कर दिया गया था।¹²⁸ यहां तक कि ईरानी समिति ने पुनर्गठन और समापक के मुद्दों पर सिफारिशें निर्धारित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि पुनर्वास प्रक्रिया के लिए एक निश्चित समय सीमा मौजूद होनी चाहिए, जैसा कि तत्कालीन मौजूदा समय सीमा के विपरीत था, जो बहुत लंबा था और आस्तियों के मूल्य को काफी हद तक कम कर दिया था।¹²⁹

यह ध्यान रखना सार्थक है कि विधायिका ने निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक समग्र अनिवार्य समयरेखा के अलावा, प्रत्येक चरण में एक विस्तृत समय सीमा निर्धारित करने के लिए उपयुक्त पाया (एनसीएलटी द्वारा दिवाला आवेदन के प्रवेश के लिए समय सीमा सहित, आईबीसी के तहत निर्णायक प्राधिकरण होने के नाते), एक समग्र अनिवार्य समय सीमा के अलावा ("सीआईआरपी") आईबीसी के तहत ताकि समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

¹²⁷आईबीआईडी, पृष्ठ 30 पर।

¹²⁸ प्रैक्टिस स्टेटमेंट (कंपनियां: कंपनी अधिनियम 2006 के भाग 26 और भाग 26 ए के तहत समझौते की योजनाएँ), 30 जून 2020 से प्रभावी।

¹²⁹ सुप्रा नोट 113.

इसी प्रकार, योजना प्रक्रिया को भी कतिपय समय-सीमाओं से सुसज्जित किया जाना चाहिए, विशेषरूप से एनसीएलटी के लिए लेनदारों/शेयरधारकों की बैठक की अनुमति देने के लिए और स्वीकृति चरण में भी, जो यह सुनिश्चित करेगा कि प्रक्रिया अनावश्यक विलंब या प्रतिरोध से प्रभावित न हो और इस प्रक्रिया में हितधारकों का विश्वास बना रहे।

(ग) एनसीएलटी के हस्तक्षेप के लिए अत्यधिक गुंजाइश

सीए 2013 के उपबंध मोटे तौर पर एनसीएलटी को दो चरणों में योजना की वैधता की जांच करने के लिए प्राधिकृत करते हैं - पहला, आवेदन दाखिल करने के चरण में और दूसरा, योजना की अंतिम स्वीकृति/अस्वीकृति पर। कुल मिलाकर, एनसीएलटी के पास इस योजना की निष्पक्षता को देखने का व्यापक दायरा है,¹³⁰ ताकि लेनदारों के सभी वर्गों के संरक्षण को उचित ठहराया जा सके। इसके अलावा, एनसीएलटी को यह भी आश्वस्त किया जाना चाहिए कि बैठक में भाग लेने वाले व्यक्ति संबंधित वर्गों के निष्पक्ष प्रतिनिधि हैं और उन्हें अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए वैधानिक बहुमत द्वारा विवश नहीं किया गया है। इसके लिए एनसीएलटी बैठक के आयोजन के तरीके की समीक्षा भी कर सकता है और बैठक में अनियमित आचरण का कोई सबूत मिलने पर योजना को खारिज कर सकता है। *बिरला वीएक्सएल लिमिटेड*¹³¹ में, पुनः एनसीएलटी ने एक बैठक में एक असुरक्षित लेनदार को शामिल करने का आदेश दिया और इसे बाहर करने की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह उसी कंपनी की एक अन्य इकाई के लिए लेनदार था। एनसीएलटी ने अतीत में इस योजना के इच्छित उद्देश्य की जांच करने के लिए स्पष्ट निगमित उद्देश्य का पर्दा भी डाला है, जिसे यदि गलतपाया जाता है, तो एनसीएलटी द्वारा शुरू में ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।¹³²

226

इसके अतिरिक्त, सीए 2013 की धारा 230 (4) का परंतुक, जो एक लेनदार / शेयरधारक के लिए योजना पर आपत्ति करने में सक्षम होने के लिए एक सीमा निर्दिष्ट करता है, का उद्देश्य शेयरधारकों / लेनदारों द्वारा शेयरों की छोटी राशि या उधार देने वाले शेयरधारकों द्वारा होल्डआउट से बचने के लिए एक सुरक्षा के रूप में सेवा करना था।¹³³ जबकि, एक तरफ, एनसीएलटी ने बकाया ऋण के 5% से कम वाले लेनदारों को योजना पर आपत्ति करने से इनकार कर दिया है, लेकिन दूसरी ओर,

¹³⁰ सुप्रा नोट 78, पृष्ठ 144 पर।

¹³¹ भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016, विनियम 44ए

¹³² सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड, [2016] 74 taxmann.com 261।

¹³³ बिरला वीएक्सएल लिमिटेड, में आरइ, [2006] 66 एससीएल 69 (गुज।)।

एनसीएलएटी ने *अंकित मित्तल* मामले में, आश्चर्यजनक रूप से एक योजना¹³⁴ को अस्वीकार करने के लिए सांविधिक मानदंड में छूट दी है, यह कहते हुए कि यदि कोई आपत्ति आई है तो भले ही निर्धारित सीमा पूरी नहीं हुई हो, एनसीएलटी यह देखने के लिए बाध्य है कि क्या यह योजना¹³⁵ वाणिज्यिक निर्णय लेने वाले व्यवसाय के उचित विवेकी पुरुषों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित, निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित है।¹³⁶ उक्त निर्णय में एनसीएलएटी (पैरा 38 के तहत) ने मूल्यांकन/विनिमय अनुपात को इस आधार पर फिर से तैयार करने का भी आदेश दिया कि प्रारंभिक योजना में उन शेयरधारकों के लिए भुगतान प्रदान नहीं किया गया था जिनके शेयर योजना के संदर्भ में रद्द कर दिए गए थे और इस तरह के भुगतान की पेशकश केवल एनसीएलटी के हस्तक्षेप पर की गई थी, जिससे मूल्यांकन करने के तरीके पर सवाल खड़े हो गए थे।

इसके अलावा, एनसीएलटी को दाखिल करने के चरण में यह आकलन करना होता है कि योजना आवेदन को 75% सुरक्षित लेनदारों द्वारा अनुमोदित किया गया है, साथ ही आवश्यक खुलासे, जो पुन स्वीकृति की एक और सुनवाई के साथ होता है, जिसमें लेनदारों के प्रत्येक वर्ग की अपेक्षित सीमा की सहमति को इसकी निष्पक्षता के साथ देखा जाना अपेक्षित होता है। इस योजना की जांच के दो चरणों में जांच की एक और निरर्थक परत जुड़ गई है।¹³⁷

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, एक तरफ, प्रक्रिया में दुरुपयोग से बचने के लिए वैधानिक सुरक्षोपायों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, लेकिन दूसरी ओर, ऐसे सुरक्षा उपबंधों के उपयोग के दायरे को परिभाषित करना भी महत्वपूर्ण है, ताकि उपबंधों की गलत व्याख्या या मामले के विधियों में विचलन¹³⁸ से बचा जा सके और अनुमोदन प्रक्रिया में देरी से बचा जा सके। यही कारण था कि उच्चतम न्यायालय ने *मिहीर मफतलाल* मामले में इस योजना को मंजूरी देने में न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार की रूपरेखा निर्धारित की थी जिसमें कहा गया था कि यह योजना निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए लेकिन यह अदालतों को लेनदारों के वाणिज्यिक ज्ञान पर सवाल

¹³⁴ बेडरॉक लिमिटेड, में फिर से [2000] 101 कॉम्प कैस 343 (बोम.), पैरा 22 ए और 23 पर। यह भी देखें सेंट मैरी फाइनेंस लिमिटेड बनाम आर.जी. जय प्रकाश [1999] 22 एससीएल 337 (केर) और इंटीग्रेटेड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड वी. भारतीय रिजर्व बैंक और ओआरएस., (2015) पैरा 43 पर 13 एससीसी 772।

¹³⁵ सुप्रा नोट 80, पृष्ठ 26 पर।

¹³⁶ रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, सीएसपी 376ए से 2017 के सीएसपी 381 तक, 14 अगस्त 2017 (एनसीएलटी मुंबई बेंच) को फैसला किया गया।

¹³⁷ अंकित मित्तल बनाम अंकिता प्रतिष्ठा लिमिटेड, [2020] पैरा 33 पर 218 कॉम्प केस 79 (एनसीएलटी)। इसके अलावा कंपनी अधिनियम के लिए गाइड, ए रमैया, 19 वें संस्करण द्वारा - खंड 2, अध्याय 15, पृष्ठ 26 और 27 पर देखें

¹³⁸ सुप्रा नोट 113, पृष्ठ 77 पर।

उठाने की अनुमति नहीं देती है।¹³⁹ इसलिए, यह प्रासंगिक है कि एनसीएलटी और उसके बाद के अपीलीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, योजना को स्वीकृत/अस्वीकार करते समय सावधानीपूर्वक न्यायिक विवेक का प्रयोग करें, जिसके परिणामस्वरूप हितधारकों का इस मार्ग को बार-बार ऋण पुनर्गठन तंत्र के रूप में उपयोग करने का विश्वास बढ़ेगा।

(घ) ऋण पुनर्गठन मामलों में योजनाओं का सीमित उपयोग

विशेष रूप से, स्कीमों का उपयोग शायद ही कभी केवल ऋण पुनर्गठन उपकरण के रूप में किया गया है और ऋण पुनर्गठन के साथ निगमित पुनर्गठन के लिए उपयोग अधिक किया गया है, जो ऐसे निगमित पुनर्गठन का एक छोटा सा हिस्सा है। यह अनिच्छा मुख्य रूप से किसी योजना को अनुमोदित करने में लागतों, अनिश्चितताओं और विलंब के कारण होती है और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर प्रस्तावित विभिन्न ऋण पुनर्गठन उपकरणों पर भारतीय बैंकों की निर्भरता के कारण होती है।

228

प्रकटीकरण की पर्याप्तता

2.4 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भाभा समिति की रिपोर्ट द्वारा ठहराव समझौते की योजनाओं में संशोधन करने के लिए बताए गए प्रमुख कारणों में से एक योजना के बारे में पारदर्शिता और हितधारकों और न्यायालय को इसके प्रकटीकरण के बारे में था। न केवल सीए 1956 भौतिक तथ्यों के प्रकटीकरण पर जोर देता है, बल्कि सीए 2013 भी फाइलिंग चरण में अनिवार्य प्रकटीकरण निर्धारित करता है।

¹³⁹ इस अनुपात का अनुसरण विभिन्न निर्णयों में किया गया है जिसमें निम्नलिखित के मामले भी शामिल हैं मेघल होम्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम श्री निवास गिरनी केके समिति और अन्य।, [2007] 139 कॉम्प केस 418 (एससी), जिसमें उच्च न्यायालय ने कहा कि "हालांकि न्यायालय किसी कंपनी के शेयरधारकों के वाणिज्यिक ज्ञान पर अपील में नहीं बैठेगा, यह निश्चित रूप से विचार करेगा कि क्या उस कंपनी को पुनर्जीवित करने का वास्तविक प्रयास है जो समापक में चला गया है और क्या इस तरह का पुनरुद्धार सार्वजनिक हित में है और वाणिज्यिक नैतिकता के अनुरूप है." यह भी देखें इंटीग्रेटेड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड वी. भारतीय रिजर्व बैंक और ओआरएस., (2015) पैरा 43 पर 13 एससीसी 772।

2.5 प्रासंगिक तथ्यों का खुलासा न किए जाने के कारण एनसीएलटी द्वारा आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है। *मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड में*,¹⁴⁰ (*मोरपेन लेबोरेटरीज बनाम क्षेत्रीय निदेशक* 141में बरकरार रखा गया) आवेदक ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा जांच या इसके खिलाफ विभिन्न आपराधिक कार्यवाही के लंबित होने का खुलासा नहीं किया और इसलिए, सावधि जमा धारकों के साथ ठहराव की प्रस्तावित योजना को खारिज कर दिया गया था। मूल्यांकन रिपोर्ट की अनुपस्थिति, जिसका सीए 2013 के अनुसार खुलासा किया जाना अपेक्षित है, ने भी एनसीएलटी को सांविधिक उपबंधों का उल्लंघन करते हुए इस योजना को खारिज करने के लिए प्रेरित किया है।¹⁴²

2.6 दूसरी ओर, तथ्यों के प्रकटीकरण के आधार पर योजना पर आपत्तियों पर न्यायालयों द्वारा सावधानीपूर्वक विचार किया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात *लीज फाइनेंसिंग लिमिटेड* में¹⁴³, ऋणपत्र धारकों को आंशिक भुगतान के लिए एक योजना को स्वीकृति दे दी, भले ही अपर्याप्त प्रकटीकरण के आधार पर 2% ऋणपत्र धारकों द्वारा इसका विरोध किया गया था, क्योंकि आपत्तिकर्ता किसी भी वैधानिक उपबंधों का उल्लंघन नहीं दिखा सकते थे। इसके अलावा, लेखांकन मानकों के उल्लंघन की संभावना समझौते की योजना को सीधे अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती है। *हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड में*¹⁴⁴, पुनः, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हिस्सेदार शेयरधारकों और वित्तीय पुनर्गठन को शामिल करने वाली समझौते की योजना की अनुमति दी, जो कंपनी के अंतिम खातों में लागू लेखांकन मानक से विचलन के प्रकटीकरण के अधीन है।

¹⁴⁰ सुप्रा नोट 79, पृष्ठ 2, 28 और 31 पर।

¹⁴¹ [2018] 92 taxmann.com 296 (एनसीएलटी - सीएचडी.)।

¹⁴² 2019 एससीसी ऑनलाइन एनसीएलटी 426।

¹⁴³ गुंबद बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनूप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सीए/295 (पीबी)/सीए (सीएए) में 2017/26 (पीबी)/2017, 3 नवंबर 2017 को निर्णय लिया गया (एनसीएलटी नई दिल्ली)

¹⁴⁴ 2002) 36 एससीएल 838 (गुज)।

आईबीसी युग में योजनाओं का समकालीन उपयोग

2.7 आईबीसी के अधिनियमन, महत्वपूर्ण दिवाला विधि के रूप में, आईबीसी के तहत एक समाधान योजना ("योजना") को लागू करने के उद्देश्यों के लिए सीए 2013 के तहत योजनाओं के उपयोग के बारे में एक और दिलचस्प पहली जोड़ दी है। आईबीसी के तहत, एक इकाई निगमित देनदार के एक सफल समाधान आवेदक के रूप में उभरती है, जब इसके द्वारा प्रस्तावित योजना को लेनदारों की समिति के कम से कम 66% द्वारा स्वीकार किया जाता है और बाद में एनसीएलटी¹⁴⁵ द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यह अक्सर देखा गया है कि ऐसी योजनाओं में समाधान आवेदक की किसी अन्य कंपनी के साथ निगमित देनदार के विलय/समामेलन/निर्विलयन (व्यावसायिक उपक्रम) की योजना के लिए उपबंध शामिल हैं। यह भारतीय दिवाला बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 ("सीआईआरपी विनियम") के विनियमन 37 (सी) के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि एक योजना, एक निगमित देनदार के दिवाला समाधान के उपाय के रूप में, एक या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ निगमित देनदार के विलय या समेकन के लिए प्रदान कर सकती है।

230

2.8 ऐसी स्थिति में, एक प्रश्न उठता है कि क्या किसी योजना के अनुमोदन की प्रक्रिया (जैसा कि सीए 2013 की धारा 230-232 के तहत निर्धारित किया गया है), एक योजना के तहत प्रस्तावित किया जा रहा है (जो आईबीसी की एक विशेषता है), इस तथ्य के प्रकाश में योजना को लागू करने के लिए भी पालन करने की आवश्यकता है कि आईबीसी को दिवाला समाधान¹⁴⁶ के लिए एक स्व-निहित विधि के रूप में माना जा रहा है और अन्य सभी मौजूदा विधियों पर इसका ओवरराइडिंग प्रभाव पड़ता है। किसी भी असंगति का मामला¹⁴⁷।

¹⁴⁵ [2009] 94 एससीएल 1; रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, में पुनः [2009] 94 एससीएल 219 (बोम)।

¹⁴⁶ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016, धारा 30 धारा 31 के साथ पठित।

¹⁴⁷ लक्ष्मी पट सुराणा बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, (2020) एससीसी ऑनलाइन एससी 1187। इसी तरह का निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया था स्विस् रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड वी। भारत संघ, 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 73 और इबीआईएक्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड वी. एड्यूकॉम्प सॉल्यूशन लिमिटेड और एनआर., 2020 के सीए नंबर 3224 में 13 सितंबर 2021 को निर्णय दिनांकित

2.9 एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने *भारतीय स्टेट बैंक बनाम वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड*¹⁴⁸ के हाल के मामले में सीए 2013 के लागू उपबंधों का सहारा लिए बिना समाधान योजना के हिस्से के रूप में विलय की योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति दी, जिसमें कहा गया है कि आईबीसी निगमित संस्थाओं के संबंध में शोधन अक्षमता के विषय पर एक संपूर्ण कोड है और अपने आप में पूरा है। एनसीएलटी ने *एडलवाइस एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम सिनर्जीज डोरे ऑटोमेटिव लिमिटेड और अन्य*¹⁴⁹ के मामले में एनसीएलटी के फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें माननीय एनसीएलटी ने आईबीसी¹⁵⁰ की धारा 30 (2) (ई) के स्पष्टीकरण का उल्लेख करते हुए, यह माना कि अनुरोधकर्ता का तर्क (एनसीएलटी के अनुमोदन के लिए योजना दायर करते समय सीए 2013 की धारा 230-232 के उपबंधों के अनुपालन के बारे में नहीं) के संबंध में, आईबीसी की धारा 30 (2)¹⁵¹ का उल्लंघन करने के रूप में माना जाना चाहिए, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि योजना केवल विलय का प्रस्ताव करती है जो सीआईआरपी विनियमों के विनियमन 37 के अनुसार है और आईबीसी का इसकी धारा 238 के कारण अन्य विधानों के उपबंधों पर ओवरराइडिंग प्रभाव पड़ता है। तदनुसार, एनसीएलटी ने माना कि विलय की योजना का उपबंध करने वाली योजना का अनुमोदन विधि के लागू उपबंधों के अनुसार है और इसे प्रभावी किया जा सकता है।

2.10 एनसीएलटी ने *वाई शिवराम प्रसाद बनाम एस. धनपाल*¹⁵² के एक अन्य मामले में कहा है कि एनसीएलटी, आईबीसी के तहत समापक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में कार्यान्वित की जा रही किसी भी योजना से निपटने के दौरान, आईबीसी के तहत एक निर्णायक प्राधिकरण की दोहरी भूमिका निभा सकता है, अर्थात्, सीए 2013 की धारा 230 के तहत आदेश पारित करने के लिए एक न्यायाधिकरण के रूप में। तदनुसार, यह योजना पर आपत्तियों को सुन सकता है और यह मूल्यांकन करने के बाद आईबीसी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में किसी योजना को अनुमोदित/अस्वीकार भी कर सकता है कि क्या यह योजना आईबीसी¹⁵³ के उद्देश्यों के अनुरूप है और निगमित देनदार के पुनरुद्धार के लिए भी फायदेमंद है। इस संबंध में, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापक प्रक्रिया) विनियम, 2016 में विनियमन 2ब¹⁵⁴ पेश किया गया था, जिसमें अपेक्षित समय-सीमा के अनुसार आईबीसी के उपबंधों के तहत समापक के दौरान योजनाओं को दर्ज करने की अनुमति दी गई थी।

2.11 तदनुसार, यह देखा गया है कि एनसीएलटी (आईबीसी के तहत निर्णायक प्राधिकरण के रूप

¹⁴⁸ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016, धारा cb

¹⁴⁹ एमएएनयू/एनसी/1501/2021

¹⁵⁰ 2018 एससीसी ऑनलाइन एनसीएलटी 1005।

में कार्य करना) योजना के भाग के रूप में प्रस्तावित योजनाओं के लिए समकक्ष अनुमोदन आदेश पारित करने की दोहरी भूमिका निभाता है, जो आईबीसी की धारा 30 (2) (ई) के स्पष्टीकरण के तहत प्रदान किए गए शेयरधारकों के अनुमोदन की ठहराव के प्रकाश में सीए 2013 की धारा 230 के तहत निगमित देनदार के लिए क्षेत्राधिकार न्यायाधिकरण है।¹⁵⁵ इसके अलावा, निगमित देनदार के लिए एक अलग लेनदारों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि योजना को निगमित देनदार के वित्तीय लेनदारों के 66% के अपेक्षित बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है, जो निगमित देनदार के अन्य सभी लेनदारों (परिचालन और असहमति सहित) पर बाध्यकारी है।¹⁵⁶

2.12 यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शेयरधारकों और लेनदारों की सहमति से वितरण केवल निगमित देनदार (सीआईआरपी के तहत होने के कारण) के लिए उपलब्ध होने के लिए कहा जा सकता है, हालांकि, यह समाधान आवेदक के लिए नहीं कहा जा सकता है, जिसने योजना दायर की है क्योंकि इसे सीए 2013 की धारा 230-232 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने और अपने शेयरधारकों और लेनदारों के अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है। यह कहने के बाद, एनसीएलटी से एक अलग अनुमोदन की आवश्यकता नहीं हो सकती है यदि समाधान आवेदक निगमित देनदार इकाई के समान क्षेत्राधिकार एनसीएलटी के तहत आता है।

¹⁵¹ ध्यान दें कि धारा 30 (2) (ई) के लिए स्पष्टीकरण निम्नानुसार पढ़ता है - खंड (ई) के प्रयोजनों के लिए, यदि कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या किसी अन्य कानून के तहत शेयरधारकों के किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तो इस समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के लिए समाधान योजना के तहत कार्यों का कार्यान्वयन, ऐसा अनुमोदन माना जाएगा कि यह दिया गया है और यह उस अधिनियम या कानून का उल्लंघन नहीं होगा।

⁷⁷ ध्यान दें कि, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 30 (2) (ई) के अनुसार, एक योजना को लागू कानून के उपबंधों के अनुपालन में होना चाहिए।

782019 एससीसी ऑनलाइन एनसीएलटी 172।

¹⁵² ध्यान दें कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ 'आस्तियों के मूल्य का अधिकतमकरण', और 'सभी लेनदारों के हितों का संतुलन' शामिल है।

¹⁵³ अधिसूचना सं 100 द्वारा सम्मिलित किया गया। आईबीबीआई/2019-20/जीएन/आईजी047, दिनांक 25 जुलाई, 2019 (25-07-2019 से)।

¹⁵⁴ सुप्रा नोट 143

¹⁵⁵ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016, धारा 31 (1)।

¹⁵⁶ एनाटेनियम होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड वी.एम/एस.एस.एस.एस.एस.एनए यूनिवर्सल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और ओआरएस., कंपनी अपील (एटी) (सीएच) (आईएनएस) 2021 की संख्या 07।

2.13 जटिलता का एक और स्तर उस स्थिति में उत्पन्न होता है जहां क्षेत्राधिकार एनसीएलटी निगमित देनदार और समाधान आवेदक / हस्तांतरणी कंपनी के लिए समान नहीं है। ऐसे मामले में, सभी संभावनाओं में, समाधान आवेदक/हस्तांतरणी को योजना के तहत प्रस्तावित योजना के लिए अपनी स्वयं की क्षेत्राधिकार एनसीएलटी पीठ से अलग से अनुमोदन (या उसमें छूट) लेना पड़ सकता है। *एनाटेनियम होल्डिंग्स*¹⁵⁷ मामले में एनसीएलटी के फैसले में, बेंच ने एनसीएलटी द्वारा प्रतिपादित स्थिति की पुष्टि की कि "... अनुमोदित समाधान योजना अनुमोदित संकल्प योजना से उत्पन्न होने वाली किसी भी सांविधिक दायित्वों/देयताओं को किसी प्रकार की छूट का अर्थ नहीं लगाएगी और इसे प्रासंगिक विधियों के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारियों के अनुसार निपटाया जाएगा। इस निर्णायक प्राधिकारी का यह विचारणीय मत है कि यदि समाधान योजना में कोई छूट मांगी जाती है, तो वह संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदन के अध्यक्षीन होगी। परवीन बंसल बनाम अमित स्पनिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड¹⁵⁸ के मामले में एनसीएलटी की प्रधान पीठ ने भी ऐसा ही विचार रखा था। यद्यपि इन मामलों ने विशेष रूप से योजना के तहत प्रस्तावित योजना से संबंधित नहीं किया था, लेकिन इन मामलों द्वारा निर्धारित कानूनी सिद्धांत समान रूप से सीए 2013 की धारा 230-232 के तहत योजनाओं और आवश्यकताओं के अनुपालन पर लागू होगा, जो एक अलग विधि है, और आईबीसी के साथ कोई असंगतता नहीं है, आईबीसी के ओवरराइडिंग प्रभाव का तर्क उपलब्ध नहीं हो सकता है।

2.14 एक अन्य मुद्दा जिसने कर्षण प्राप्त किया, वह आईबीसी के तहत समापक से गुजरने वाले निगमित देनदारों के लिए प्रस्तावित योजनाओं के लिए आईबीसी की धारा 29अ की प्रयोज्यता थी। आईबीसी की धारा 29अ के अनुसार, कुछ व्यक्तियों (जैसे प्रमोटर, निगमित देनदार के नियंत्रण में व्यक्ति, आदि) को सीआईआरपी के तहत एक समाधान योजना प्रस्तुत करने से रोक दिया जाता है। हालांकि, जनवरी, 2020 में भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता बोर्ड (समापक प्रक्रिया) विनियम, 2016 में संशोधन के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया था, जिसके बाद विनियमन 2 बी ने निगमित देनदार के समापक के दौरान भी प्रस्तावित किसी भी योजना के लिए आईबीसी की धारा 29अ के आवेदन को विशेष रूप से सुनिश्चित किया था। उपर्युक्त संशोधन एक असफल संवैधानिक चुनौती से भी गुजरा, जहां उच्चतम न्यायालय ने संशोधन की संवैधानिकता को बरकरार रखा।¹⁵⁹

¹⁵⁷ सीपी नंबर (आईबी) 131 (पीबी)/ 2017 में सीए नंबर 360 (पीबी) 2018। आगे ध्यान दें कि एनसीएलटी ने कहा कि योजना में मांगी गई राहतों और रियायतों, जो कुछ अन्य प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में निहित हैं, केवल संबंधित प्राधिकारियों से मांगी जा सकती हैं।

¹⁵⁸ अरुण कुमार जगतरामका बनाम जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और एएनआर। (2019 की सिविल अपील संख्या 9664)।

¹⁵⁹ वही

भाग 3: समापन टिप्पणियां

सीए 2013 के तहत योजना तंत्र भारत में एकमात्र औपचारिक कब्जे में देनदार वाला मॉडल बना हुआ है जो निगमित और ऋण पुनर्गठन को प्राप्त करने के लिए बहुत लचीलापन प्रदान करता है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्गठन उपकरणों (आस्ति वर्गीकरण सहनशीलता का लाभ उठाने के लिए) और हाल ही में आईबीसी (लेनदार-चालित प्रक्रिया होने के नाते) की ओर लेनदार समुदाय के झुकाव/निर्भरता ने योजना ढांचे को कुछ समय के लिए पीछे हटना बना दिया है। यह वर्तमान ढांचे में विभिन्न मुद्दों (जैसा कि पहले चर्चा की गई है) के कारण भी है, जिन पर भारतीय सांसदों के ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस ढांचे को मजबूत करना महत्वपूर्ण है ताकि हमारे पास सॉल्वेंट/दिवालिया ऋण पुनर्गठन के लिए एक मजबूत तंत्र हो सके जिससे दिवाला धुंधलका क्षेत्र में आने से पहले और प्रवर्तकों के नियंत्रण को दूर करने की आवश्यकता जिसको जबरन दिवाला की गोली को गले से उतारने के बिना किया जा सके वास्तव में, कुछ बदलावों (जैसे कि एक बैठक आयोजित करने के लिए आवेदन दाखिल करने पर स्थगन लगाना, एनसीएलटी द्वारा अनुमोदन सहित प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक समय-सीमा निर्धारित करना) के साथ, यह तंत्र मूल्य अधिकतमीकरण के लिए सभी हितधारकों के लिए सबसे अच्छा संभव उपकरण बन सकता है और भारतीय निगमित समुदाय के आत्मविश्वास को मजबूत करेगा और उद्यमशीलता को भी बढ़ावा देगा।

यहां तक कि अपने वर्तमान रूप में भी, योजना तंत्र प्री-पैक के माध्यम से एक योजना को कार्यान्वित करके आईबीसी के साथ मिलकर कार्य कर सकता है जो न केवल किसी योजना को प्रतिबंधित होने से बचाएगा बल्कि तेजी से कार्यान्वयन में भी मदद करेगा। हालांकि, ऐसा होने के लिए, विधायिका को सभी निगमित देनदारों के लिए लागू प्री-पैक फ्रेमवर्क बनाने की आवश्यकता होगी।

लेखकों के बारे में

लेखकों के बारे में

अभिषेक मुखर्जी, सिरिल अमरचंद मंगलदास के मुंबई कार्यालय में शोधन अक्षमता और रीस्ट्रक्चरिंग प्रैक्टिस ग्रुप में एक काउंसलर हैं। वह प्रमुख बैंकों और वित्तीय संस्थानों (भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय) के साथ-साथ कॉर्पोरेट समूहों, पदधारकों और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को ऋण पुनर्गठन, सुरक्षा प्रवर्तन, संरचित वित्तपोषण, ऋण वसूली, बैंकिंग और दिवाला मामलों, और अन्य तनावग्रस्त परिसंपत्ति स्थितियों के तहत सलाह देते हैं। इसमें दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता भी शामिल है।

च्यू जिंग वेई, एलन एंड ग्लेडहिल एलएलपी के वरिष्ठ सहयोगी हैं। उनके मुख्य क्षेत्र, मुकदमेबाजी और पुनर्गठन और शोधन अक्षमता हैं। वह शोधन अक्षमता और दिवाला, बैंकिंग विवाद, निदेशकों के कर्तव्यों का उल्लंघन, शेयरधारकों के विवाद, और ऋण वसूली (सुरक्षा प्रवर्तन सहित) सहित विविध मामलों पर निगमों, वित्तीय संस्थानों और शोधन अक्षमता पेशेवरों को नियमित रूप से सलाह देते हैं। जिंग वेई ने किंग्स कॉलेज लंदन से एलएलबी (ऑनर्स) डिग्री (प्रथम श्रेणी) के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की, और सफलतापूर्वक चार्टर्ड सर्टिफाइड एकाउंटेंट्स एसोसिएशन को पूरा किया है।

क्लेटन चांग वॉंग, पार्टनरशिप एलएलपी के रीस्ट्रक्चरिंग और शोधन अक्षमता प्रैक्टिस में एक वरिष्ठ सहयोगी हैं। क्लेटन ने कई पुनर्गठन और शोधन अक्षमता मामलों में देनदारों और लेनदारों को सलाह दी है, जिसमें अदालत की निगरानी में पुनर्गठन और सीमा पार तत्वों और अरबों डॉलर में लेनदेन मूल्यों को शामिल करने वाले सहमतिपूर्ण वर्कआउट शामिल हैं। उन्होंने शोधन अक्षमता से संबंधित लेनदेन जैसे संकटग्रस्त व्यापार और संपत्ति की बिक्री पर भी सलाह दी है और परिसमापक और न्यायिक प्रबंधकों जैसे दिवाला कार्यालयधारकों के लिए काम किया है।

क्रेग मॉंटगोमरी, फ्रेशफील्ड्स ब्रुकहॉस डेरिंगर एलएलपी के लंदन कार्यालय में विवाद समाधान प्रैक्टिस और पुनर्गठन और शोधन अक्षमता प्रैक्टिस में पार्टनर हैं। क्रेग की एक

व्यापक प्रैक्टिस है, जिसमें कई मामलों पर सलाह दी जाती है, जिसमें विवादास्पद पुनर्गठन और शोधन अक्षमता मामले शामिल हैं, विशेष रूप से सीमा पार के मुद्दों को शामिल करना। वह विमानन विवादों और पुनर्गठन में भी विशेषज्ञ हैं। वह इनसोल इंटरनेशनल के फेलो भी हैं।

धनंजय कुमार, सिरिल अमरचंद मंगलदास के मुंबई कार्यालय में शोधन अक्षमता प्रैक्टिस ग्रुप में पार्टनर हैं। वह ऋणदाताओं (भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय), देनदारों के साथ-साथ कार्यालयधारकों को ऋण पुनर्गठन, सुरक्षा प्रवर्तन, बैंकिंग और भी मामलों पर सलाह देते हैं, जिसमें दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता भी शामिल है। धनंजय इनसोल इंटरनेशनल के फेलो हैं और भारत में पुनर्गठन / शोधन अक्षमता (बैंड 2) के लिए उनके नाम का चैंबर्स एशिया पैसिफिक 2022 में उल्लेख किया गया है।

हमराज सिंह, सिरिल अमरचंद मंगलदास के मुंबई कार्यालय में वित्तपोषण अभ्यास समूह में एक वरिष्ठ सहयोगी हैं। उनका रिस्ट्रक्चरिंग और शोधन अक्षमता पर खास फोकस है। वह बैंक, वित्तीय संस्थानों, दिवाला पेशवरों और कॉर्पोरेट्स को उच्च मूल्य और जटिल वित्तपोषण लेनदेन पर सलाह देते हैं। उन्होंने विभिन्न हितधारकों को गंदे दर्जन मामलों सहित कॉर्पोरेट दिवाला और ऐतिहासिक मामलों की परिसमापन प्रक्रियाओं पर भी सलाह दी है।

केट स्टीफेंसन, लंदन में स्थित किर्कलैंड और एलिस इंटरनेशनल एलएलपी के यूरोपीय पुनर्गठन समूह में भागीदार हैं। केट के पास पुनर्गठन और शोधन अक्षमता का व्यापक अनुभव है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पुनर्गठन और शोधन अक्षमता के सभी रूपों में रणनीतिक निवेशकों, देनदारों, लेनदारों और शोधन अक्षमता व्यवसायियों को सलाह देना शामिल है।

केनेथ लिम, एलन एंड ग्लेडहिल एलएलपी के भागीदार हैं। उनके प्रमुख अभ्यास क्षेत्र, मुकदमेबाजी, पुनर्गठन और शोधन अक्षमता और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता हैं। उनके पास

जटिल विवादास्पद मामलों में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करने का पर्याप्त अनुभव है और वह नियमित रूप से परिसमापन, न्यायिक प्रबंधन, प्राप्ति, व्यवस्था की योजनाओं और जटिल बहु-क्षेत्राधिकार पुनर्गठन के संबंध में उधारदाताओं और शोधन अक्षमता पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शीर्ष कानूनी प्रकाशनों द्वारा पुनर्गठन और शोधन अक्षमता और विवाद समाधान में उनकी विशेषज्ञता के लिए केनेथ की लगातार सिफारिश की जाती है।

मिरियम फ़र्लेली, फ़ेशफ़ील्ड्स ब्रुऔस डेरिंगर एलएलपी के लंदन कार्यालय में विवादों, मुकदमेबाजी और मध्यस्थता प्रैक्टिस ग्रुप में एक सहयोगी है। मिरियम जटिल वाणिज्यिक मुकदमेबाजी, नियामक जांच और विवादास्पद पुनर्गठन और शोधन अक्षमता मामलों पर काम करती है।

नीति शिखा, इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी (आईएसपीपी) की एसोसिएट डीन हैं। आईएसपीपी में शामिल होने से पहले, उन्होंने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत एक थिंक टैंक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, सेंटर फॉर इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के प्रमुख के रूप में काम किया था। उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर से पीएचडी और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यूके से एलएलएम किया है। वह प्रतिष्ठित हेग छात्रवृत्ति की प्राप्तकर्ता हैं और उन्होंने हेग अकादमी, नीदरलैंड में निजी अंतरराष्ट्रीय कानून में कोर्स किया है। उन्होंने भारत और सिंगापुर के विभिन्न कानून और बिजनेस स्कूलों में अकादमिक पदों पर कार्य किया है। वह आईएसपीपी के अकादमिक सलाहकार बोर्ड और भारत के अग्रणी थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के सलाहकार बोर्ड में कार्य करती हैं। वह इन्सॉल्वेंसी रिसर्च फाउंडेशन की बोर्ड सदस्य भी हैं। उन्होंने प्रमुख पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में व्यापक रूप से प्रकाशित किया है और दो प्रमुख पुस्तकें भारत में कॉर्पोरेट शासन के बदलते प्रतिमान और कॉर्पोरेट शासन: सिद्धांत और नीतियां लिखी हैं। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के लिए वित्त पोषित अनुसंधान किया है और दिवाला और शोधन अक्षमता कानूनों पर सरकार को नीतिगत जानकारी प्रस्तुत की है। उनकी रुचि के मुख्य क्षेत्र कंपनी कानून, शोधन अक्षमता कानून, कॉर्पोरेट प्रशासन और कानून और नीति हैं।

सिम क्वान कियाट, राजा और टैन सिंगापुर एलएलपी के पुनर्गठन और शोधन अक्षमता प्रैक्टिस ग्रुप के प्रमुख हैं। उन्हें चैंबर्स एशिया-पैसिफिक (बैंड 1), हूज़ हू लीगल (साउथ ईस्ट एशिया), एशिया पैसिफिक लीगल 500, आईएफएलआर 1000, एशिया लॉ लीडिंग लॉयर्स और बेस्ट वकीलों में पुनर्गठन और शोधन अक्षमता के क्षेत्र में ख्याति और मान्यता प्राप्त है। क्वान कियाट नियमित रूप से ऋण पुनर्गठन, न्यायिक प्रबंधन, परिसमापन, और स्थानीय और विदेशी दोनों कंपनियों से जुड़े रिसीवरशिप में देनदारों, उधारदाताओं और शोधन अक्षमता कार्यालय धारकों के लिए सलाह और कार्य करते हैं।



शोधन अक्षमता: वर्तमान एवं भविष्य

विचार नेतृत्व पुस्तिका

एफसीडीओ और आईबीबीआई
का संयुक्त प्रकाशन



भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

Insolvency and Bankruptcy Board of India

7th Floor, Mayur Bhawan,
Shankar Market, Connaught Circus,
New Delhi, India 110001

www.ibbi.gov.in